दैनिक जलते दीप

जयपुर, गुरुवार 2 मई 2024

माननीय का विभत्स आचरण

सार्वजनिक जीवन में व्यक्ति का आचरण बहुत मायने रखता है। मगर विचित्र है कि बहुत सारे राजनेता इस तकाजे का ध्यान रखना जरूरी नहीं समझते। कर्नाटक में हासन सीट से जनता दल (सेक्युलर) के सांसद प्रज्वल रेवन्ना इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। उन पर करीब तीन हजार महिलाओं का यौन शोषण करने, उन्हें धमकाने और प्रताड़ित करने के गंभीर आरोप हैं। उनके दुराचार के वीडियो सार्वजनिक हुए और मामला तूल पकड़ने लगा तो उसकी जांच के लिए राज्य सरकार ने विशेष जांच दल गठित कर दिया। जांच दल का गठन होते ही रेवन्ना देश छोड़ कर भाग गए। उधर पार्टी ने उन्हें निलंबित भी कर दिया है। बताया जा रहा है कि वे यहां से सीधे जर्मनी गए और वहां से यूरोप के किसी देश में छिप गए हैं। इस बार रेवन्ना भाजपा के साथ गठबंधन में चुनाव लड़े थे। इसलिए विपक्षी दलों ने न केवल जद (सेकु), बल्कि भाजपा और प्रधानमंत्री पर भी निशाना साधना शुरू कर दिया है। इस राजनीतिक विवाद के बीच जद (सेकु) की कोर समिति ने रेवन्ना को पार्टी से निलंबित कर दिया है। मगर लगता नहीं कि इतने भर से जद (सेकु) और भाजपा को कोई राहत मिलने वाली है, क्योंकि रेवन्ना पर लगे आरोप बहुत गंभीर और महिलाओं के सम्मान से जुड़े हैं। हालांकि रेवन्ना ने सार्वजनिक हुए सारे वीडियो को फर्जी और साजिश के तहत तैयार किया बताया है। बताया जा रहा है कि चुनाव से कुछ दिनों पहले ये वीडियो पेन ड्राइव में भर कर बड़ी तेजी से लोगों के बीच फैलाए जाने लगे। मगर मामले पर कानूनी कार्रवाई के लिए कदम तब उठाया गया जब रेवन्ना के घर में काम करने वाली एक अधेड़ सहायिका ने उसके और उसके पिता के खिलाफ आरोप लगाया। प्रज्वल रेवन्ना के पिता भी जद (सेकु) से विधायक हैं। हालांकि इन मामलों के बारे में जानकारी लोगों को बहुत पहले से थी। भाजपा के एक नेता ने तो कहा है कि उन्हें एक वर्ष पहले ही ये वीडियो उपलब्ध हो गए थे और उन्होंने रेवन्ना को चुनावी टिकट देने से केंद्रीय समिति को रोका था, मगर उस पर ध्यान नहीं दिया गया। यह भी जानकारी आई है कि रेवन्ना खुद करीब एक वर्ष पहले इसी मामले में अदालत से स्थगन आदेश ले आए थे। यानी मामला बिल्कुल ताजा नहीं है। हैरानी की बात है कि न केवल इस प्रकरण को दबा-छिपा कर रखा गया, बल्कि रेवन्ना को फिर से लोकसभा चुनाव के मैदान में उतार दिया गया। यह बेहद भयावह है कि रेवन्ना ने किसी भी आयु और वर्ग की महिला को नहीं बख्शा। घरेलू सहायिकाओं, सरकारी अधिकारियों-कर्मचारियों, पार्टी कार्यकर्ताओं से लेकर हर तरह की महिलाओं का यौन शोषण किया। वे खुद इसलिए अपनी घिनौनी हरकत का वीडियो बनाते थे, ताकि उनके आधार पर वे उन महिलाओं को डरा-धमका कर चुप रहने को बाध्य कर सकें। हालांकि यह किसी राजनेता या रसूखदार व्यक्ति का पहला और अकेला मामला नहीं है, मगर चिंताजनक बात यह है कि एक व्यक्ति खुद सांसद रहते हुए ऐसा वीभत्स कृत्य कर रहा था। राजनेता सार्वजनिक मंचों से महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान की बातें करते नहीं थकते, मगर जब उन्हीं के बीच ऐसा कोई व्यक्ति नजर आने लगता है, तो उसे बचाने या ढंक-छिपा कर रखने का प्रयास करने लगते हैं। अब देखना है कि केंद्र और राज्य सरकार किस तरह मामले की निष्पक्ष जांच कराती तथा रेवन्ना को वापस लाकर उसके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करती हैं।

भारत के खिलाफ नशे की साजिश

हाल ही में एक पाकिस्तानी नौका से छह सौ करोड़ मूल्य की 86 किलोग्राम हेरोइन की बरामदगी भारत में नशे के बढ़ते कारोबार में विदेशी साजिश का खुलासा करती है। वैसे यह अकेली घटना नहीं है, हाल ही के वर्षों में अरबों रुपये के नशीले पदार्थों की बरामदगी हुई है। दरअसल, कई देशों के सत्ता प्रतिष्ठानों की मिलीभगत से नार्को-आतंकवाद के एक बड़े पैटर्न को अंजाम दिया जा रहा है। निश्चित तौर पर यह साजिश हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये एक गंभीर चुनौती है। पुराने अनुभव बताते हैं कि जम्मू-कश्मीर व पंजाब में नशे के कारोबार से अर्जित धन को आतंकवाद के पोषण में लगाया गया। आतंकवादियों को हथियार व पैसा उपलब्ध कराया गया। पिछली मई में भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी और नौसेना के साझे मिशन के जरिये केरल तट पर ढाई हजार किलोग्राम नशीला पदार्थ बरामद किया गया। जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत पंद्रह हजार करोड़ रुपये बतायी गई थी। यह देश में बरामद अब तक की सबसे बड़ी नशे की खेप थी। गत माह गुजरात के तट पर साठ पैकेट ड्रग्स ले जा रही एक नौका को जब जब्त किया गया तो छह पाकिस्तानी चालक दल के सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। इसी तरह फरवरी में पोरबंदर तट पर पांच विदेशी नागरिकों को चरस व 3300 किलोग्राम नशीले पदार्थों के साथ पकड़ा गया था। दरअसल, इस नशे के कारोबार की शुरुआत अक्सर अफगानिस्तान से होती है, जहां अफीम व हेरोइन का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। नशे का यह कारोबार अब अफगान सरकार की आय का बड़ा स्रोत भी है। बहरहाल, हालिया घटनाक्रम समुद्र के जरिये मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिये गंभीर उपायों की जरूरत बताता है। जिसके लिये मजबूत कानून, प्रवर्तन एजेंसियों की भागीदारी, कुशल खुफिया-साझाकरण तंत्र, नौसेना व तटरक्षक बलों में तालमेल तथा आतंकरोधी दस्ते के जरिये निगरानी तंत्र को मजबूत बनाने की जरूरत है। यह भी विचारणीय प्रश्न है कि ये नशीले पदार्थ किस तरह व कहां भारत में बेचे जा रहे हैं। नशीले पदार्थों के मांग पक्ष को भी संबोधित करने की जरूरत है। नशीली दवाओं की रोकथाम के साथ ही पुनर्वास कार्यक्रमों में निवेश किया जाना चाहिए। साथ ही नशे के खिलाफ युवाओं के बीच जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है। उन उपायों को लागू करना होगा जो युवाओं को नशे से दूर रखने में मददगार हो सकें। जब भी नशे की कोई बड़ी खेप बरामद होती है तो हमारी चिंता बढ़ जाती है। कल-परसो ही पंजाब में नशे की एक बड़ी खेप के साथ ड्रग मनी व अन्य अवैध सामान बरामद किए गए। इस काले धंधे में अभियुक्त व्यक्ति ही नहीं, उसकी बेटी व दामाद भी लिप्त थे। यह नशे का सामान पाकिस्तान के रास्ते भारत पहुंच रहा था। सवाल उठता है कि यदि इतने बड़े पैमाने पर नशीले पदार्थों की बरामदगी न होती तो कितने युवा नशीले पदार्थों का सेवन करके पथभ्रष्ट होते? देश का कितना धन विदेशों को चला जाता? इस नशे से मिलने वाला धन कालांतर में आतंकवाद व अपराध की दुनिया को मजबूत करता। हाल ही के दिनों में नशीले पदार्थों की भारी मात्रा में बरामदगी इस बात की ओर इशारा करती कि देश में नशीले पदार्थों की खपत लगातार बढ़ रही है। जो निश्चित रूप से देश की युवा शक्ति को पतन के मार्ग की ओर ले जा रही है। देखा गया है कि नशीले पदार्थों का सेवन करने वाले युवा कालांतर महंगा नशा जुटाने के लिये अपराध की दुनिया में उतर जाते हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण ही है कि पंजाब व देश के अन्य भागों में हर साल हजारों युवा नशे की ओवरडोज से मौत की गिरफ्त में आ जाते हैं। ऐसे में देश के भविष्य को बचाने के लिये हमें राष्ट्रीय स्तर पर अतिरिक्त सुरक्षा उपाय करने होंगे। पिछले वर्ष पंजाब में ड्रोन के जरिये नशीले पदार्थ भारत लाये जाने के तमाम मामले प्रकाश में आए। कई ड्रोन मार गिराये गए और भारी मात्रा में नशीले पदार्थ व हथियार भी बरामद किये गए। इन हालात में सुरक्षातंत्र को मजबूत करने, नशा मुक्ति अभियान चलाने व नशेड़ियों के पुनर्वास के लिये गंभीर प्रयास करने की जरूरत है।

प्रसंगत: कल कभी नहीं आता

राम-रावण युद्ध समाप्त हो चुका था। रावण मृत्यु शय्या पर पड़ा अंतिम सांसें गिन रहा था। तभी उसने देखा कि लक्ष्मण उसकी ओर चले आ रहे हैं। लक्ष्मण उसके निकट आए और बोले, 'मेरे भाई श्रीराम आपसे ज्ञान की बातें सीखना चाहते हैं।' आश्चर्य में भरकर रावण बोला, 'तुम्हारे भाई सर्वज्ञ हैं। मैं उन्हें क्या सिखा पाऊंगा। और फिर मैं तो उठकर चल भी नहीं सकता। मैं उनके पास कैसे पहुंच पाऊंगा।' लक्ष्मण ने कहा, 'आप इसकी चिंता न करें। मैं श्रीराम को यहां लेकर आ जाऊंगा।' श्रीराम आए। उनसे रावण ने विनम्रतापूर्वक कहा, 'हे सूर्यवंश के गौरव! मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मैं राक्षस हूं, मैं आपको क्या सिखा पाऊंगा।' राम ने कहा, 'यह सच है कि तुम राक्षस हो, परंतु यह भी सच है कि तुम एक शक्तिशाली और बुद्धिमान शासक रहे हो। तुम्हें अच्छे और बुरे का ज्ञान है। मैं यह ज्ञान तुमसे प्राप्त करना चाहता हूं।' रावण ने उन्हें उपदेश देना शुरू किया, 'अच्छे कार्यों को कभी नहीं टालना चाहिए। हो सकता है कि टालने के कारण उन कार्यों को करने का कभी अवसर ही न आए। मैंने सोचा था कि नरक का मार्ग बंद करवा दूंगा, ताकि किसी को परलोक में दुःख न भोगने पड़ें। दूसरा काम समुद्र के खारे पानी को निकाल कर उसे दूध से भर देने का था। तीसरा काम धरती से स्वर्ग तक सीढ़ी बनाने का था, जिससे पापी-पुण्यात्मा सभी स्वर्ग तक पहुंच सकें।' इतना कहकर रावण रुका। मृत्यु निकट होने के कारण उसकी बोलने की शक्ति कम होती जा रही थी। हांफते हुए वह बोला, 'इन तीनों कार्यों को मैं कल पर टालता रहा और कल तो कभी आता नहीं। मैं इन कर सकने वाले कार्यों को कभी कर नहीं पाया।' रावण फिर थोड़ा ठहरकर बोला, 'अच्छे कार्यों को टालना जितना बुरा है, बुरे कार्यों को टालना उतना ही अच्छा। मां सीता का हरण करने में मैंने तत्परता दिखाई, लेकिन वह मुझे टाल देना चाहिए था।'

विदेशी मीडिया की नकारात्मक रिपोर्टिंग

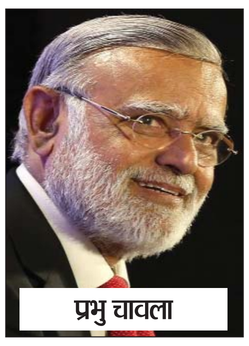

प्रभु चावला

पश्चिमी नेताओं के साथ अपने दोनों कार्यकाल में अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। लेकिन ऐसा पश्चिमी मीडिया के साथ नहीं है, जो उनके लिए कभी दबंग शासक, तो कभी तानाशाह जैसी संज्ञाओं का इस्तेमाल करता है। उनकी सरकार ने ऐसे शाब्दिक हमलों का जवाब पारंपरिक मीडिया के प्रति तिरस्कार के भाव से दिया है, जिसका आवरण राष्ट्रीय श्रेष्ठता का नया विश्वास तथा पश्चिमी मीडिया के प्रति अस्वीकार है।

कुछ दिन पहले राहुल गांधी के भारतीय-अमेरिकी सलाहकार सैम पित्रोदा, जो उनके पिता के भी सलाहकार रह चुके हैं, ने मोदी को निशाना बनाने के लिए पश्चिमी मीडिया की हालिया सुर्खियों को हथियार बनाया। व्हाट्सएप संदेशों और मीम के प्रसार के इस दौर में समाचार ऐसी चीज है, जिसे सजा-संवार कर पेश किया जा रहा है। किस खबर को आगे रखा जायेगा और क्या सुर्खियां होंगी, यह तय करने का अधिकार मीडिया में कुछ चुनींदा लोगों को ही होता है। जैसे-जैसे चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे कुछ सुर्खियां, इंटरव्यू और टीवी बहसों के क्लिप खबर बनती जा रही हैं।

इसलिए अचरज की बात नहीं कि पित्रोदा ने दुनियाभर की मीडिया की 50 से अधिक सुर्खियों को सोशल मीडिया पर पेश किया। भाजपा के अनुसार, इनमें मोदी के प्रति नफरत और भारतीय संस्थाओं के लिए अपमान झलकता है। बीते कुछ महीनों में सबसे अधिक सुर्खियां न्यूयॉर्क टाइम्स, गार्डियन, इकोनॉमिस्ट, फाइनेंशियल टाइम्स, एलए टाइम्स, रॉयटर, ला मोंद, टाइम और ब्लूमबर्ग से चुनी गयी हैं। सभी में संदेश समान था, मानो ये सब एक ही सोच से निर्देशित हों।

मतदाताओं को प्रभावित करने के इरादे से सोशल मीडिया में पित्रोदा द्वारा इन्हें पोस्ट किया गया था। एक्स पर उनके पोस्ट को कुछ ही दिन में पांच लाख से अधिक लोगों ने देखा। इसे कांग्रेस समर्थकों ने साझा तो किया ही, संघ परिवार के लोगों ने भी समाचार संस्थाओं की साख गिराने के उद्देश्य से पोस्ट को आगे बढ़ाया। पित्रोदा द्वारा चुनी गयीं कुछ सुर्खियां इस प्रकार हैं- 'भारत का मोदीकरण लगभग पूरा' (टाइम), 'असंतोष को अवैध बनाने से लोकतंत्र को नुकसान' (गार्डियन), 'प्रगतिशील दक्षिण द्वारा मोदी का अस्वीकार' (ब्लूमबर्ग), 'मदर ऑफ डेमोक्रेसी की हालत ठीक नहीं' (फाइनेंशियल टाइम्स), 'मोदी के झूठों का मंदिर' (न्यूयॉर्क टाइम्स), 'भारतीय लोकतंत्र नाममात्र का' (ला मोंद), 'मोदी का अनुदारवाद भारत की आर्थिक प्रगति को बाधित कर सकता है' (इकोनॉमिस्ट), 'भारत में लोकतंत्र में कमी को देखते हुए पश्चिम अपने संबंधों की समीक्षा कर सकता है' (चैथम हाउस), 'मोदी और भारत के तानाशाही की ओर अग्रसर होने पर बाइडेन चुप क्यों हैं' (एलए टाइम्स)।

जब लगभग सभी बड़े अंतरराष्ट्रीय प्रकाशन ऐसी बातें लिख रहे थे, तो उनके साथ भारत में कार्यरत विदेशी पत्रकार भी जुड़ गये। भाजपा इसे मोदी को बदनाम करने और उन्हें नुकसान पहुंचाने का अभियान बताती है। ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के दक्षिण एशिया ब्यूरो की प्रमुख अवनी डियास ने यह दावा करते हुए भारत छोड़ दिया कि उन्हें वीजा नहीं दिया गया, जिससे उन्हें चुनाव कवर करने का मौका नहीं मिला।

सरकार ने उनके दावों को खारिज कर दिया। फिर भी 30 विदेशी पत्रकारों ने एक बयान जारी कर कहा कि भारत में विदेशी पत्रकारों के लिए वीजा और भारत के प्रवासी नागरिकों के लिए पत्रकार परमिट से जुड़ी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। फ्रांसीसी पत्रकार वेनेसा डाउनैक ने भी सरकार पर विवादित रिपोर्टिंग के लिए उनका प्रवासी भारतीय कार्ड रद्द करने का आरोप लगाया था।

स्पष्ट रूप से सरकार विदेशी मीडिया की रिपोर्टिंग से असहज है। घरेलू मीडिया की स्थिति बिलकुल अलग है। सरकार का मानना है कि ये रिपोर्ट तथ्यों पर आधारित नहीं हैं और इनमें तोड़-मरोड़कर विचार पेश किये जा रहे हैं, न कि असली खबर। भारतीय चुनाव में पश्चिमी मीडिया की बहुत ज्यादा दिलचस्पी को हमेशा घरेलू मामलों में दखल के रूप में देखा गया है। जब उनके नकारात्मक रिपोर्टों के दबाव में इंदिरा गांधी नहीं आयीं, तो अमेरिकी मीडिया ने उन्हें भी निशाना बनाया था।

जब वाजपेयी सरकार के समय भारत ने परमाणु परीक्षण किया, तो पश्चिमी मीडिया ने भारत को शांति का खलनायक बता दिया था। उसने भारत पर गरीबी उन्मूलन के बजाय परमाणु हथियारों पर खर्च करने का आरोप लगाया। कुछ अपवादों को छोड़ दें, तो विदेशी पत्रकार रिकॉर्ड जीडीपी वृद्धि के बावजूद भारत के गर्त में जाने की भविष्यवाणी कर रहे हैं। उनकी आलोचनात्मक रिपोर्टिंग का कुछ आधार हो सकता है, पर वही पश्चिमी संस्थान चीन और रूस समेत कई देशों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हो रहे हमलों की अनदेखी कर रहे हैं। एक वरिष्ठ भाजपा नेता का कहना है कि वे पत्रकार पहले निष्कर्ष निकालते हैं और बाद में उसकी पुष्टि के लिए तथ्य खोजते हैं।

अपने पूरे करियर में अमेरिकी मीडिया से नजदीक रहे विदेश मंत्री जयशंकर को भी ऐसी रिपोर्टों में खामियां दिखी हैं। उन्होंने कहा है कि विदेशी मीडिया को लगता है कि हमारे चुनाव में वे भी राजनीतिक खिलाड़ी हैं। उनकी बात में दम है। इधर मीडिया विचारधारात्मक आधार पर पक्ष लेने लगा है। अमेरिका में भी मीडिया ट्रंप के समर्थन और विरोध में विभाजित है। मोदी अपने को पक्षपाती मीडिया का सबसे बड़ा पीड़ित मानते हैं।

उनके समर्थक आरोप लगाते हैं कि एक 'चायवाला' के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री बनने को अभिजात्य और अनुदार विदेशी मीडिया पचा नहीं सका है।

पश्चिमी मीडिया पश्चिम में यहूदी समुदाय पर हो रहे तीखे हमलों की अनदेखी करता है, पर भारत से रिपोर्टिंग करते समय मोदी की आलोचना में व्यस्त रहता है। प्रधानमंत्री ध्यान आकर्षित करना पसंद करते हैं, पर अपनी शर्तों पर। इंदिरा गांधी की तरह वे चुनींदा मीडिया को ही प्रश्रय देते हैं।

मीडिया से उनका बैर उनके गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में अनुभव से जन्मा है। पश्चिमी मीडिया ने उन्हें अपमानित करते हुए यह सुनिश्चित किया कि उन्हें अमेरिकी वीजा न मिले। प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने पश्चिमी और घरेलू मीडिया को कुछ दूर रखा है। उन्होंने एक दशक में एक भी संवाददाता सम्मेलन नहीं किया है।

अभी वे लगातार तीसरा जनादेश मांग रहे हैं। हर ताकतवर नेता मीडिया का इस्तेमाल करना चाहता है। गलत खबरों के प्रसार से ऐसे नेताओं को फायदा होता है। यही काम भारत और अन्य देशों में विदेशी मीडिया कर रहा है। **(लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं द न्यू इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के एडिटोरियल डायरेक्टर है)**

पाक क्यों चाहता भारत से कारोबारी संबंधों की बहाली

– आर.के. सिन्हा

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ने अपने देश की रसातल में जा रही अर्थव्यवस्था की स्थिति पर विचार करने के लिए बीती 26 अप्रैल को अपने मुल्क के उद्योगपतियों से कराची में मुलाकात की। वहां सवाल-जवाब का लम्बा दौर भी चला। इस दौरान पाकिस्तान के चोटी के उद्योगपति और आरिफ हबीब ग्रुप के चेयरमेन आरिफ हबीब ने शाहबाज शरीफ से पुरजोर गुजारिश की कि पाकिस्तान भारत के साथ अपने व्यापारिक संबंध तुरंत बहाल करें।

पाकिस्तान के अंग्रेजी के मशहूर अखबार दि डॉन ने गुरुवार (25 अप्रैल, 2024) को इस खबर को प्रमुखता के साथ छापा भी है। उस वक्त वहां पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और देश के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के समधी इशाक डार भी मौजूद थे। डार के बेटे की शादी नवाज शरीफ की बेटी से हुई है। डार ने पिछले महीने ही कहा था कि उनका मुल्क भारत से व्यापारिक संबंध बहाल करना चाहता है।

उधर, भारत का मानना है कि व्यापार को द्विपक्षीय संबंधों के सामान्यीकरण के एक हिस्से के रूप में देखा जाना चाहिए। इसके लिए, पाकिस्तान को आतंकवाद पर लगाम लगाना होगा। वहां चल रही आतंकवाद की फैक्ट्रियों को तुरंत बंद करना होगा। भारत का यह भी मानना है कि आतंकवाद के मुद्दे पर ठोस कदम उठाए बिना व्यापार शुरू करना संभव नहीं है।

दरअसल पाकिस्तान के नेताओं की भारत के साथ व्यापार शुरू करने की इच्छा कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था गंभीर संकट से जूझ रही है। यह सब जानते हैं। भारत के साथ व्यापार, विशेष रूप से चीनी और कपास जैसे उत्पादों का आयात बंद होना, पाकिस्तान के लिए महंगा पड़ रहा है। क्योंकि, उसे ये उत्पाद दुबई जैसे देशों से मंगवाने पड़ते हैं। पाकिस्तान के व्यापारिक समुदाय का मानना है कि भारत के साथ सीधा व्यापार आर्थिक विकास को गति दे सकता है। अफ़गानिस्तान और ईरान के साथ तनावपूर्ण संबंधों ने भी पाकिस्तान की आर्थिक समस्याओं को और बढ़ा दिया है। यह भी देखना होगा कि ईरान के नेता की हालिया इस्लामाबाद यात्रा से दोनों देश कितने करीब आते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार दोनों देशों के सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। व्यापार, राजनीतिक मुद्दों पर व्यापक और सार्थक चर्चा के लिए भी एक प्रारंभिक कदम हो सकता है। हालांकि दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों में जल्द ही सुधार की संभावना भी नहीं है, क्योंकि अभी तो भारत में लोकसभा चुनाव का दौर चल रहा है। इस बीच, भारत को पाकिस्तान के साथ व्यापारिक संबंधों की बहाली करने से कोई बहुत लाभ नहीं होगा। अगर दोनों पड़ोसियों में व्यापारिक संबंध स्थापित होते हैं, तो इससे पाकिस्तान को ही बड़ा लाभ होगा। पाकिस्तान के लिए कठमुल्लों पर लगाम लगाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। आने वाले समय में दोनों देशों के नेताओं के बीच राजनीतिक इच्छाशक्ति और ठोस कदम ही इस गतिरोध को तोड़ सकते हैं। भारत की चिंता बहुत वाजिब है। भारत सरहद के उस पार से होने वाले आतंकवाद का भुक्तभोगी रहा है। इसलिए वह कोई भी कदम बहुत सोच-समझकर ही उठाएगा। अब पाकिस्तान लाख चाहें पर, पर भारत उससे व्यापारिक संबंधों को लेकर कतई उत्साहित नहीं है। पाकिस्तान ने ही भारत के साथ अपने आर्थिक संबंधों को खत्म कर लिया था जब नरेंद्र मोदी सरकार ने 2019 में जम्मू- कश्मीर से संविधान की धारा 370 को खत्म कर दिया था। तब से पाकिस्तान के कुछ नेता कहते रहते हैं कि जब तक धारा 370 की बहाली नहीं होगी तब तक वह भारत से संबंध बहाल नहीं करेंगा। हालांकि अब जम्मू-कश्मीर में धारा 370 की बहाली होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। इस बारे में सारा देश एक तरह से सोचता है। और, पकिस्तान हो या कोई अन्य विदेशी मुल्क, वहां की सरकार या अवाम को भारत के अंदरूनी मामलों में दखल को मोदी जी तो हरगिज बर्दास्त नहीं करेंगे। पहले की सरकारों की कमजोरी से ही अबतक ऐसा होता रहा है। पिछले दिनों पाकिस्तान में शाहबाज शरीफ की प्रधानमंत्री के रूप में ताजपोशी के बाद यह तय ही था कि वहां भारत से व्यापारिक संबंध शुरू करने की पहल चालू होगी। खराब आर्थिक नीतियो और सेना के भारी बजट के कारण पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था तार- तार हो चुकी है। वह विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ), सऊदी अरब, चीन वगैरह के आगे मदद की आस में हर वक्त कटोरा लेकर खड़ा रहता है। पाकिस्तान अपने निर्यात को भी बढ़ाना चाहता है। लेकिन आतंकवादी मुल्क से आयात करेगा कौन? विश्व बैंक ने 2018 में अनुमान लगाया था कि अगर पाकिस्तान का भारत के साथ व्यापार अपनी क्षमता तक पहुँच जाता है तो उसका निर्यात लगभग 25 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है।

पाकिस्तान में पूर्व भारतीय उच्चायुक्त और प्रसिद्ध पुस्तक एंगर मैनेजमेंटः द ट्रबल्ड डिप्लोमैटिक रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान के लेखक अजय बिसारिया कहते हैंः अगर भारत-पाकिस्तान में तिजारती संबंध शुरू होते हैं तो पाकिस्तान के कपड़ा और फार्मास्युटिकल क्षेत्रों को तगड़ा लाभ होगा। एक बात शीशे की तरह से साफ है कि सोशल मीडिया के इस दौर में पाकिस्तान का अवाम पड़ोसी भारत की जीवन के सभी क्षेत्रों में विकास की रफ्तार को बारीकी से देख रहा है। पाकिस्तान तो बिजली और आटे की किल्लत, बेरोजगारी और महंगाई की मार से त्राहि-त्राहि कर रहा है। इस पृष्ठभूमि में पाकिस्तानी नेतृत्व भारत के साथ कारोबारी संबंध स्थापित करने का ख्वाब देख रहा है। हां, यह तो मानना होगा कि चाहे नवाज शरीफ हों या फिर उनके अनुज और देश के मौजूदा प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ कारोबार के महत्व को तो अच्छी तरह समझते हैं। ये खुद भी कारोबारी हैं। शरीफ परिवार का स्टील बिजनेस है। इनकी कंपनी के भारत के प्रख्यात स्टील कारोबारी सज्जन जिंदल की कंपनी जिंदल साउथ-वेस्ट (जेएसडब्ल्यू) से कारोबारी संबंध रहे हैं। शरीफ जानते हैं कि अब दुनिया युद्ध के रास्ते पर नहीं चल सकती है, क्योंकि; युद्ध विनाश का पर्यायवाची है। उनके सामने भारत-चीन का शानदार उदाहरण है। ये दोनों दिग्गज एशियाई मुल्क अपने जटिल सीमा विवाद को सुलझाने की चेष्टा करते हुए भी आपसी व्यापार को आगे लेकर जा रहे हैं। वर्तमान में दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार 100 अरब रुपये के आसपास पहुंच रहा है। पाकिस्तान की भारत के साथ तिजारत की चाहत पूरी हो सकती है, अगर वह आतंकियों की गोद से मुक्त होकर भारत की चिंताओं का समाधान करे। **(लेखक वरिष्ठ संपादक, स्तंभकार और पूर्व सांसद हैं)**

मिलावट इतनी कि शुद्ध खाएं, फिर भी बीमार हो जाएं

डेढ़ साल की राबिया को क्या पता था कि जब वह पटियाला से ननिहाल के लाड़-प्यार की मिठास से भरी चॉकलेट लुधियाना आकर खाएगी तो उसकी जान पर बन आएगी। दुर्भाग्य से इस लाड़-प्यार के रिश्तों के बीच बेरहम बाजार आ गया। बाजार जो सिर्फ मुनाफे का पीर है। कोई मासूम मरे या जीये, उसकी बला से। चॉकलेट खाकर बच्ची बहुत बीमार हो गई। बड़े अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने किसी जहरीली चीज खाने की बात कही। बात चॉकलेट की आई, रैपर देखा गया तो चॉकलेट की एक्सपाइरी डेट छह महीने पहले खत्म हो चुकी थी। यह दुखद संयोग ही है कि पिछले दिनों पटियाला में ही जन्मदिन पर ऑनलाइन मंगवाए गए केक को खाने से एक 'बर्थडे गर्ल' की मौत हो गई थी। जांच पड़ताल के बाद पता चला था कि किसी बेकरी का मालिक दूसरी जगह से अलहदा नाम से बेकरी का सामान ऑनलाइन बेच रहा था। पक्की बात है, ये कानून से बचने-बचाने की तरकीब थी। इस चाकलेट व केक बेचने वाली दुकानों का इलाका पटियाला में पीली सड़क के आसपास का ही है। यह संयोग ही है कि पिछले कुछ अरसे से देश में कई ऐसे खुलासे हुए, जिनमें बताया गया कि दशकों से हम जिन उत्पादों को तंदुरुस्ती संवारने वाला मानते आ रहे थे, वे तो सेहत के लिये नुकसानदायक निकले। पहले खुलासा हुआ कि बॉर्नविटा व सेरेलेक्स में बहुराष्ट्रीय कंपनियां आवश्यकता से अधिक शूगर मिलाकर विकासशील व गरीब मुल्कों के बच्चों के जीवन से खिलवाड़ कर रही हैं। यह भी खुलासा हुआ है कि व्यंजनों को लजीज बनाने, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने व पाचन सुधारने वाले कुछ कंपनियों के मसालों में सेहत को नुकसान पहुंचाने वाले तत्व पाये गए हैं। मसालों को सुरक्षित रखने के लिये कीटनाशक जैसे पदार्थ मिलाए गए हैं। भारत में तो लोग जैसे-तैसे इन्हें खा ही रहे हैं अब तो दुनिया के कई मुल्कों में भी दो भारतीय मसाला कंपनियों की साख पर सवाल उठाये जा रहे हैं। सिंगापुर व हांगकांग का दावा है कि दो भारतीय कंपनियों के मसाला पैकेटों में सेहत के लिये हानिकारक पदार्थ पाए गए हैं। सैकड़ों सालों से भारत की पहचान रहे मसाले न केवल रोगनाशक बल्कि इम्यूनिटी बढ़ाने वाले भी होते हैं। याद करें कि कोरोना संकट में इन मसालों ने ही देश के लोगों का मनोबल बनाये रखने में खासी मदद की। आये दिन हम मिलावटी खानपान की चीजों की बरामदगी की खबरें पढ़ते हैं। कुछ लोग बीमार होते हैं, कुछ अपना जीवन गवां बैठते हैं। लेकिन सुनने में नहीं आया कि किसी हादसे के बाद किसी की जवाबदेही तय करके बड़ी सजा दी गई हो। ऐसी सजा जो दोषियों के लिये सबक का फैसला साबित हो। आज आखिर बचा ही क्या है बिना मिलावट के? दूध, बेसन, घी, पनीर, खोया, दवाइयां, दैनिक जरूरत की चीजें आटा, चावल व दालें भी मिलावट की चपेट में हैं। यहां तक कि पानी तक में मिलावट है। इस मिलावट का ही असर है कि कम उम्र में लोग बड़ी उम्र की बीमारियों से पीड़ित होने लगे हैं। जिन अधिकारियों व कर्मचारियों पर खाने-पीने की चीजों की निगरानी की जिम्मेदारी है, वे होली-दीवाली पर दिखावटी अभियान चलाकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लेते हैं और जेबें भी भर लेते हैं। कुछ स्थानों पर छापेमारी होती है और कुछ जगह नमूने भरे जाते हैं। फिर ढाक के वही तीन पात। होना तो यह चाहिए कि शासन-प्रशासन ऐसे सख्त कदम उठाये कि कोई फिर से मिलावट करने का दुस्साहस न कर सके। वैसे लोगों को सचेत करने की भी जरूरत है। यह कैसी अजीब स्थिति है कि अब तक हम जिन प्रॉडक्ट को दशकों से सेहत के लिये वरदान मानते रहे हैं, अब खुलासा हुआ कि वे तो सेहत के लिए नुकसानदायक हैं। ऐसे कई देसी-विदेशी उत्पादों के खुलासे एक साथ हुए। इसी कड़ी में उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है कि राज्य सरकार ने पतंजलि आयुर्वेद के 14 उत्पादों का निर्माण लाइसेंस निलंबित किया है। राज्य सरकार की ओर से बताया गया है कि स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी की ओर से भ्रामक प्रचार मामले में दिव्य फार्मेसी और पतंजलि आयुर्वेद के उत्पाद मामलों में यह कार्रवाई की गई है। जो भी हो, सुप्रीम कोर्ट ने इस साल न्यायिक जिम्मेदारी का नमूना पेश किया। जिस तरह पतंजलि आयुर्वेद के कर्ताधर्ताओं की क्लास लगाई, उसे पूरे देश ने देखा और मीडिया के जरिये आम लोगों ने महसूस किया। लेकिन अदालत ने इसमें याचिका दायर करने वाली आईएमए को भी नहीं बख्शा। अदालत ने सख्त लहजे में कहा कि एक उंगली यदि बाबा रामदेव की तरफ उठी तो चार तुम्हारी तरफ भी उठी हैं। तुम्हारा दामन भी पाक साफ नहीं है। नाराज न्यायाधीशों ने कहा कि आखिर कौन दवा कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए महंगी-महंगी दवाएं लिखता है? इसी बीच खबर आई कि बच्चों के लिये स्वास्थ्यवर्धक बताये जाने वाले बॉर्नविटा की पड़ताल में पता चला कि उसमें चीनी की मात्रा यूरोपीय व अमेरिकी देशों में बेचे जाने वाले उत्पाद के मुकाबले काफी ज्यादा थी। चीनी की यह मात्रा एशिया व अफ्रीका के गरीब मुल्कों में बेचे जाने वाले बॉर्नविटा में भारत से भी ज्यादा थी। लेकिन यूरोप व अमेरिकी देशों में बॉर्नविटा में यह मात्रा स्वास्थ्य मानकों के अनुरूप ही रही। बाद में कंपनी ने दावा किया कि भारत में बेचे जाने वाले बॉर्नविटा में चीनी की मात्रा तीस प्रतिशत कम कर दी गई है। कभी संपन्न वर्ग के बच्चों का पसंदीदा स्वास्थ्यवर्धक पेय बताये जाने वाला बॉर्नविटा स्टेटस सिंबल माना जाता था। बड़े मोहक व भ्रामक विज्ञापन इसकी तारीफ में गढ़े जाते रहे हैं।

– नरेश कौशल

https://t.me/AllNewsPaperPaid

दैनिक इबादत
सम्पादकीय

तर्कहीन बयानों से जूझती चुनावी राजनीति

भारत में एक समय ऐसा भी था जब राजनीति से आम जनमानस का विश्वास समाप्त होता जा रहा था। राजनीतिक दलों से जो अपेक्षा थी, सब जनता की इन अपेक्षाओं पर पानी फेरते दिखाई दे रहे थे। उस समय देश की यह अवधारणा बन गई थी कि अब भारत की राजनीति ऐसे ही चलती रहेगी। लेकिन 2014 के बाद देश ने एक नई राजनीति का साक्षात्कार किया। एक ऐसी राजनीति जिसमें सपने भी थे और एक उम्मीद भी थी। आज इस समय को दस वर्ष का समय व्यतीत हो गया है। सपने पूरे हुए या नहीं, मूल्य एवं उसे परीक्षण का विषय है, लेकिन आज की राजनीति बदली हुई दिखाई देती है, यह अवश्य ही कहा जा सकता है। लेकिन आज भी जिस प्रकार से सत्ता प्राप्त करने की लालसा लेकर राजनीतिक दल राजनीति कर रहे हैं, वह प्रथम दृष्टया यही परिलक्षित कर रहे हैं कि राजनीतिक दलों के पास अपने कोई स्थायी सिद्धांत नहीं हैं। विपक्ष के दल वर्तमान केंद्र सरकार को घेरने के लिए कई प्रकार के राजनीतिक दांव पेच खेल रहे हैं, वहीं सत्ता धारी दल भाजपा भी किसी भी तरीके से पीछे नहीं कही जा सकती। इस प्रकार की राजनीति के चलते देश का आम जनमानस निश्चित रूप से भ्रम की अवस्था में है। सारे दल अन्य दलों से अपने आपको बेहतर बताने की राजनीति कर रहा है। इसके लिए कुछ राजनीतिक दल अपने हिसाब से तर्क भी दे रहे हैं। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि इस बार विपक्षी दलों के राजनेता सधे हुए कदमों से अपनी पारी को अंजाम दे रहे हैं। क्योंकि पिछले लोकसभा चुनावों के दौरान जिस प्रकार से कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सार्वजनिक रूप से चोर कहने का दुस्साहस किया गया, उससे कांग्रेस की फ़जीहत हो गई थी, इतना ही नहीं राहुल गाँधी को माफ़ी भी मांगनी पड़ी। इस बार परिदृश्य बदला हुआ है। विपक्ष के नेता सरकार को लक्ष्य करके आलोचना कर रहे हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि इन आलोचनाओं में भी वह धार नहीं है कि वह अकेले दम पर सरकार बनाने का सामर्थ्य पैदा कर सकें। देश में अब दो चरणों में मतदान संपन्न हो चुके हैं, बचे हुए पांच चरणों के मतदान के लिए जोर आजमाइश की जा रही है। चुनावी रैलियों में राजनेताओं के बयानों की व्याख्या निकालने का क्रम भी चल रहा है। किसी बड़े मुद्दे पर समाचार चैनलों पर बहस भी होती है। इन बहस में सभी नेता अपने हिसाब से अर्थ निकाल कर बहस करते हैं। कोई किसी के कम नहीं दिखता, लेकिन इन बहस में लगभग विवाद जैसी स्थिति बनती दिखाई देती है। एक दूसरे से लड़ने की मुद्रा में आने वाले यह राजनेता शायद इस बात को भूल जाते हैं कि इसे जनता भी देख रही है और आज की जनता यह भी जानती है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। इसके बाद भी आम समाज का एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो इन चर्चाओं को सुनकर भ्रमित भी होते होंगे। विरोधी पक्ष को यह भी समझना चाहिए कि भारत में लोकतंत्र तभी तक जीवित है, ज़ब तक जनता की राय को महत्व दिया जाएगा। जनता के सही बात रखना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं आना चाहिए जिससे जनता भ्रमित हो। अन्यथा यह लोकतंत्र की भी हार होगी।

फेक वीडियो का चुनावी धमाल

– बाल मुकुन्द ओझा

इंटरनेट की आभासी दुनिया में आज कल फेक न्यूज और फेक वीडियो का चलन बहुत तेजी से चल रहा है। लोकसभा चुनाव में फेक न्यूज़ और फेक वीडियो की भी एंट्री हो गई है। चुनावों के दौरान इनका बहुतायत से उपयोग या दुरूपयोग हो रहा है। कहीं भी कांट छांट कर फेक न्यूज़ या वीडियो बनाना बहुत आसान हो गया है। लोकतंत्र के लिए यह कृत्य बहुत घातक है, इससे हमारे लोकतंत्र की जड़े कमजोर होती है और आमजन में भय और गलत धारणाएं बनती है। यह टैक्नोलॉजी का जमाना है जिसमें असली-नकली में भेद करना मुश्किल है। फेक न्यूज़ और वीडियो में नेता की आवाज़ हूबहू दिखाई जाती है ऐसे में क्या सही और क्या गलत है इसका फर्क करना आसान नहीं है। आजकल बच्चे से बुजुर्ग के हाथ में मोबाइल है। इसका ज्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं और कुछ लोगों के फोन में सोशल मीडिया ऐप्स इंस्टॉल होते हैं। ऐसे ही कई ऐप हैं जैस ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वाले ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता है कि वह जो न्यूज पढ़ रहे हैं वो सच्ची है या झूठ। कभी कभी फेक न्यूज को इस तरह से प्रजेंट किया जाता कि वह सच्ची खबरों को भी पीछे छोड़ देती हैं। नकली वीडियो कुछ ही सेकेन्ड में लाखों लोगों तक पहुंच जाता है और लोग इस सच मानकर फॉरवर्ड कर देते हैं। इसलिए ये भयानक खेल है। लोकतन्त्र के लिहाज़ से खतरनाक खेल हैं।चूंकि लोगों के पास वीडियो की असलियत को जानने का तो कोई ज़रिया नहीं हैं, इसलिए कम से कम आप इतना कर सकते हैं कि बिना सोचे समझे किसी वीडियो को फॉरवर्ड न करें, वरना मुसीबत में पड़ सकते हैं क्योंकि आईटी एक्ट बहुत सख्त हैं। अमित शाह का नकली वीडियो जानबूझ कर सोची समझी रणनीति के तहत फैलाया गया क्योंकि जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश और बिहार तक कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और आरजेडी के नेताओं ने रैलियों में कहना शुरू कर दिया कि बीजेपी ने दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के आरक्षण को खत्म करने की तैयारी कर ली है। अगर मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो आरक्षण खत्म हो जाएगा।

आजकल देश के गृह मंत्री अमित शाह का यह फेक वीडियो बहुत चर्चा में है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु की एक चुनाव रैली में कहा कि तीसरी बार केन्द्र में बीजेपी की सरकार आएगी तो जहां जहां असंवैधानिक तौर पर मुस्लिम आरक्षण लागू है, उसे खत्म किया जाएगा। लेकिन उनके वीडियो की एडिटिंग की गई। 'मुस्लिम' शब्द हटाकर 'दलित आदिवासी' जोड़ दिया गया। यानि अमित शाह को ये कहते हुए दिखाया गया कि बीजेपी की सरकार आएगी तो असंवैधानिक तौर पर लागू दलित, पिछड़े और आदिवासियों का आरक्षण तुरंत खत्म कर देगी। चूंकि आवाज अमित शाह की थी, एडीटिंग इतनी सफाई से की गई कि किसी भी सुनने वाले को लगेगा कि अमित शाह ने यही कहा कि बीजेपी की सरकार आरक्षण को खत्म करेगी। इस वीडियो को सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म्स पर खूब वायरल किया गया। इसके बाद बीजेपी हरकत में आई, पुलिस एक्शन भी हुआ, चुनाव आयोग से शिकायत भी हुई, बड़े-बड़े नेताओं ने कैंपेन के दौरान इसकी हकीकत बताई लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस वीडियो का तेलंगाना से क्या कनेक्शन है? चूंकि अमित शाह का ये वीडियो तेलंगाना में कांग्रेस की स्टेट यूनिट के ऑफिशियल हैंडल से शेयर करके पोस्ट किया गया, इसलिए, दिल्ली पुलिस की टीम हैदराबाद में कांग्रेस दफ्तर में पहुंची। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। इसलिए दिल्ली पुलिस ने रेवंत रेड्डी को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा है। रेवंत रेड्डी के अलावा तेलंगाना कांग्रेस के नेता सतीश, नवीन, शिवाशंकर और अस्मा तस्लीम को भी नोटिस भेजा गया है। इन सभी लोगों से अपने मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक गजेट्स साथ लाने को कहा गया है। इन पर आईटी एक्ट और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने और समाज में विद्वेष फैलाने की कोशिश की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। अमित शाह ने गुवाहाटी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि उनके भाषण का फेक वीडियो बनवाने में कांग्रेस का हाथ है। इससे पूर्व सोशल मीडिया पर बॉलीवुड एक्टर आमिर खान का एक वीडियो काफी वायरल हुआ जिसमें आमिर खान सभी भारतीयों के बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपये आने वाले नरेंद्र मोदी के पुराने बयान की आलोचना कर रहे हैं। इस वीडियो को कांग्रेस के कई समर्थकों ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है। हालांकि जब वेबसाइट बूम ने इस वीडियो की पड़ताल की तो ये वीडियो डीप फेक पाया गया। दरअसल इस वायरल वीडियो में आमिर खान की आवाज को नकली ऑडियो जोड़ा गया है।

(वरिष्ठ लेखक एवं पत्रकार, मॉडल टाउन, मालवीय नगर, जयपुर)

लोकसभा चुनाव में मुद्दों को नया विमर्श दें

वर्ष 2024 के चुनावों में हम सात में से तीसरे चरण की ओर बढ़ रहे हैं,लेकिन अभी तक भाजपा की चुनावी थीम सामने नहीं आई है, विपक्षी दलों के घोषणा पत्रों या चुनावी बयानों की चीरफाड ही होती हुई दिख रही है। आतंकवादियों और दुश्मनों को उनके घर में घुसकर मारने की बात करने वाली भाजपा के बयानों में चीन पूरी तरह गायब है और पाकिस्तान का जिक्र भी बहुत कम है।

– ललित गर्ग –

लोकसभा चुनावों के प्रचार अभियान में एक आवाज बहुत धीमी पर एक वजन और पीड़ा के साथ सुनने को मिल रही है कि इस चुनाव को येन-केन-प्रकारेण जीतने के सभी जायज एवं नाजायक प्रयोग हो रहे हैं, लेकिन नैतिकता, मूल्य एवं आदर्श की बात कहीं भी सुनाई नहीं दे रही है। देश का राजनीतिक भविष्य तय करने वाले इन चुनावों में एक और विडम्बना देखने को मिल रही है कि राष्ट्र विकास के मुद्दों एवं आजादी के अमृतकाल को अमृतमय बनाने की कोई चर्चा नहीं है। देश को दिशा देने एवं कोई नया विमर्श खड़ा करने का नेताओं के पास अभाव है, जो अपने-आप में एक त्रासदी है। मतदाताओं की लोकतंत्र के महाकुंभ में भागीदारी का घटना भी एक चिन्ता का सबब है। जबकि किसी भी राष्ट्र के जीवन में चुनाव सबसे महत्त्वपूर्ण घटना होती है। यह एक यज्ञ होता है। लोकतंत्र प्रणाली का सबसे मजबूत पैर होता है। विभिन्न राजनीतिक दल आरक्षण का मुद्दा खड़ा करके जहां अल्पसंख्यकों को अपनी ओर खींचने की कोशिश करते हुए भाजपा को आरक्षण विरोधी बता रहे हैं और गृहमंत्री अमित शाह के आरक्षण विषयक बयान को तोड़-मेरोड कर झूठे एवं फेक वीडियो के माध्यम से भाजपा के चरित्र को धुंधला रहे हैं, वहीं आम महिलाओं के डर का सहारा लेते हुए उनके मंगल सूत्र और स्त्री धन को छीन लिए जाने की बात कही जा रही है। सैम पित्रोदा के विरासत कर संबंधी बयान से आम जनता के धन को हथियाने की बातें भी हो रही है। लेकिन प्रश्न है कि क्या कांग्रेस पार्टी के सत्ता में आने की संभावना है? सत्ता के सिंहासन पर अब कोई राजपुरोहित या राजगुरु नहीं अपितु जनता अपने हाथों से तिलक लगाती है। चुनाव अभियान तीसरे चरण की ओर अग्रसर हैं। सब राजनैतिक दल अपने-अपने 'घोषणा-पत्र' को ही गीता का सार व नीम की पत्ती बता रहे हैं, जो सब समस्याएं मिटा देगी तथा सब रोगों की दवा है। एक-दूसरे की नीतियों एवं योजनाओं की आलोचना चुनाव का हिस्सा बनी हुई है और बनना भी चाहिए। लेकिन एक-दूसरे पर भीषण एवं भद्दे आरोप लगाना, लोकतंत्र की मर्यादा का उल्लंघन है। परंतु मौजूदा चुनाव प्रचार में राष्ट्रीय एकता एवं सामाजिक समरसता के ताने-बाने को क्षति पहुंचाने की चेष्टा का होना दुर्भाग्यपूर्ण है। सभी दल भाषणों में नैतिकता की बातें करते हैं और व्यवहार में अनैतिकता को छिपा रहे हैं। चुनाव आयोग के आंकड़ों की ही बात करें तो पिछले सप्ताह तक ही आचार संहिता उल्लंघन की 200 से अधिक शिकायतें आ चुकी है। जिनमें से 169 शिकायतों पर आयोग ने कार्रवाई की है। शिकायतों के आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। वास्तव में इन चुनावों में नेताओं ने भाषा एवं भावों को इतना बदरंग, अशालीन एवं भोंथरा कर दिया है कि शर्म-सी महसूस होती है। दागी उम्मीदवारों के दागों का पर्दापाश होना भी इन चुनावों का हिस्सा है। कथित तौर पर प्रज्वल रेवन्ना से जुड़े वीडियो क्लिप प्रसारित होने से देखा गया है कि महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा की घटना हुई है। रेवन्ना के खिलाफ शिकायत कुछ महिलाओं के शोषण तक ही सीमित नहीं है, अब अनेकों शिकायतें सामने आएगी और हर शिकायत को ईमानदारी से परखना होगा। सबसे ज्यादा गंभीर बात तो यह है कि आरोपी जर्मनी भाग गया? अगर रेवन्ना दोषी हैं तो उन्हें कानून का सामना करना चाहिए। अगर वह कानून से भागेंगे तो इससे उनकी पार्टी और एनडीए दोनों को ही नुकसान होगा। रेवन्ना देश के पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा के पौत्र है और उन पर लगे आरोप बहुत ही गंभीर और शर्मनाक है। सत्ता का किसी भी प्रकार का दुरुपयोग ज्यादा समय तक लाभकारी नहीं होता है। हमारा समाज ऐसे मुकाम पर आ गया है, जहां हम किसी महिला के साथ न ज्यादती की सुन सकते हैं और न किसी को करने दे सकते हैं। बात प्रज्वल रेवन्ना एवं बृजभूषण शरण सिंह तक सीमित नहीं हैं, विशेषत: चुनाव में ऐसे मुद्दों का उठना प्रासंगिक है, जिससे उम्मीदवारों को अपने गिरेबार में झांकने का अवसर मिलता है। राजनीतिक दलों को भी उम्मीदवारों का चयन करते हुए उनके चरित्र की परख गहराई से करनी ही चाहिए।

वर्ष 2024 के चुनावों में हम सात में से तीसरे चरण की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी तक भाजपा की चुनावी थीम सामने नहीं आई है, विपक्षी दलों के घोषणा पत्रों या चुनावी बयानों की चीरफाड ही होती हुई दिख रही है। आतंकवादियों और दुश्मनों को उनके घर में घुसकर मारने की बात करने वाली भाजपा के बयानों में चीन पूरी तरह गायब है और पाकिस्तान का जिक्र भी बहुत कम है। निश्चित ही भाजपा जीत की ओर अग्रसर है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन सुनिश्चित जीत के साथ सुनिश्चित भविष्य की बात भी होनी ही चाहिए। हकीकत में चुनाव में अनेक उतार-चढ़ाव के बावजूद मोदी का जादू चल रहा है, ऐसी अनेक वजहों से 2024 असाधारण रूप से बिना सशक्त मुद्दे के ही गतिमान है। आश्चर्य की बात यह है कि हमारी राष्ट्रीय राजनीति के मौजूदा दौर के सबसे बड़े जादूगर नरेंद्र मोदी ने अब तक इन चुनावों के लिए कोई सशक्त मुद्दा नहीं पेश किया है जो पहले से सातवें चरण तक चल सके। हर चुनावी चरण एवं सभा में एक नया मुद्दा उभर रहा है, जो कुछ दूर चल कर पृष्ठभूमि में चला जाता है। भाजपा की ओर से इन चुनावों में मोदी ही मुद्दा है। चुनाव अभियान का आरंभ करते हुए कहा गया कि नरेंद्र मोदी ही भारत को अधिक ऊंचा वैश्विक कद दिला रहे हैं। भारत मंडपम में जी 20 शिखर बैठक को भुनाने की कोशिश हुई। लेकिन यह भी मुद्दा चुनावी गणित में फिट नहीं हुआ। महिला मतदाताओं को लुभाने का दांव भी चला। निर्वाचन वाली संस्थाओं में महिलाओं के आरक्षण के लिए आनन-फानन में पारित कानून इसका हिस्सा था। लेकिन भाजपा के चुनाव प्रचार में इसका जिक्र भी नहीं सुनने को मिल रहा है। इन चुनावों में भी पार्टी के उम्मीदवारों में महिलाओं की हिस्सेदारी 16 फीसदी है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को भी चुनावों के लिहाज से गर्म मुद्दा माना गया था। इसके बावजूद विभिन्न राज्यों में भाजपा के नेताओं के चुनाव भाषणों पर नजर डालें तो पता चलता है कि उनमें इस पर जोर या इसका जिक्र नहीं है। यह मुद्दा हाल में तब उठा जब ऐसे संकेत मिले कि राहुल और प्रियंका गांधी राम मंदिर जा सकते हैं। कुछ सप्ताह पहले भारत रत्न की घोषणा का मुद्दा भी दूर तक नहीं चल सका। ऐसी अनेक उपलब्धियां एवं ऐतिहासिक कार्य हैं, जो मोदी के कद को ऊंचा तो बनाते हैं, लेकिन चुनाव की दिशा को एकदम एवं दूर तक प्रभावित नहीं कर पा रहे हैं। बात राज्यों की हो या केन्द्र की, भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग पर चुनावों में चर्चा होनी ही चाहिए। भारत के मतदाता मिलकर सरकारों को जवाबदेह ठहराने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। लेकिन मौजूदा लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में मतदान 2019 की तुलना में 7 प्रतिशत कम हुआ है। यह एक चिंताजनक संकेत है और चुनावी प्रक्रिया से मतदाताओं के अलगाव को दर्शाता है। यह भाजपा के मतदाताओं में चली आई आत्मसंतुष्टि की ओर भी संकेत करता है, जो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के तीसरे कार्यकाल को लेकर आश्वस्त हैं। हालांकि, इसका एक और पहलू यह भी है कि 2023 में, प्यू रिसर्च सेंटर ने भारतीय मतदाताओं का एक सर्वेक्षण किया था, जिसमें पता चला था कि 85 प्रतिशत लोगों ने भारत में सैन्य शासन या निरंकुश नेता का समर्थन किया था। क्या शासन के अच्छे तरीके के रूप में लोकतंत्र के समर्थन में गिरावट का ही परिणाम कम होता मतदान है? अगर मतदाता लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपना विश्वास खो रहे हैं तो यह भारत के लोकतंत्र और भविष्य के लिए चिंताजनक संकेत है। इससे निर्वाचित नेता भी जनता के प्रति जवाबदेही से मुक्त होने लगेंगे। भारत के मतदाताओं को समझना चाहिए कि पिछले सतहत्तर वर्षों में देश की सफलता उसके लोकतंत्र की सफलता पर ही आधारित रही है। इसलिये मतदाता को जागरूक होकर अधिकतम मतदान करना चाहिए। साथ-ही-साथ मतदाता अगर बिना विवेक के आंख मूंदकर मत देगा तो परिणाम उस उक्ति को चरितार्थ करेगा कि 'अगर अंधा अंधे को नेतृत्व देगा तो दोनों खाई में गिरेंगे।'

(लेखक, पत्रकार, स्तंभकार, सरस्वती कुंज अपार्टमेंट 25 आई. पी. एक्सटेंशन, पटपड़गंज, दिल्ली)

कांग्रेस के लिए अभिशाप बनती दल-बदल की राजनीति

– राकेश अचल

दल-बदल को लोकतंत्र का सबसे बड़ा अपराध मानकर कांग्रेस की तत्कालीन सरकार के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने दल-बदल के खिलाफ क़ानून की नींव रखी और संयोग देखिये कि आज यही दल-बदल कांग्रेस के लिए अभिशाप और भाजपा के लिए वरदान बन गया है। आज दल-बदल राष्ट्रहित में किया जाने वाला सबसे बड़ा सद्कर्म बनता जा रहा है। आपकी आप जानें किन्तु मुझे शुरू से दल-बदलू पसंद नहीं हैं। मैं दल-बदल को प्रश्रय देने वालों के भी खिलाफ हूं। दल-बदल चाहे कोई भी दल करे या कराये मुझे देशद्रोही लगते है। लेकिन मेरे लगने या न लगने से क्या होता है ? मैं यानि आम जनता दल-बदल को मूकदर्शक की तरह टुकुर-टुकुर देखने, सहने के लिए अभिशप्त है। जब राजनीतिक दल ही दल-बदल को सबसे बड़ी योग्यता मानते हों तो बेचारा आम आदमी इसके खिलाफ खड़ा होकर कर भी क्या सकता है। मैं आपको दल-बदल के इतिहास में नहीं ले जाऊँगा। गूगल पर विकिपीडिया खंगालने के लिए भी नहीं कहूंगा क्योंकि इससे दल -बदल की सेहत पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। दल-बदल एक अनवरत, सतत, सनातन कार्य है। त्रेता से होता आ रहा है और कलियुग में तो दल-बदल इतना सुगम हो गया है जितना कि दिल-बदलना। दल बदलने में दिल बदलने से भी कम समय लगता है। इंदौर में कांग्रेस के प्रत्याशी किन्हीं बम साहब के दल-बदल ने ये प्रमाणित कर दिया है। लोग मेडिकल टूरिज्म के लिए दुनिया के कोने-कोने से भारत आते है पर अब मुझे लगता है कि भविष्य में दुनिया के तमाम राजनीतिक दल अपने यहां दल-बदल करने के लिए गुरुदीक्षा लेने भारत आया करेंगे। भारत किसी और मामले में विश्व गुरु हो या न हो किन्तु दल-बदल के मामले में तो ब्रह्मंड गुरु बन चुका है। भारत में लोकतंत्र की सेहत के लिए दल-बदल एक अनिवार्य प्रक्रिया है। जो दल जितना ज्यादा दल-बदल कराएगा उसे उतना मजबूत और लोकतांत्रिक माना जाएगा। एक दल का दुष्ट -पापी दूसरे दल में आते ही दुष्टता और अपने पापों से मुक्त हो जाता है। अर्थात दल-बदल पाप मोचन का सबसे सरल, सुगम और सुबोध तरीका है। हमारे यहां बड़े-बड़े सूरमाओं ने, राजे-महाराजों ने दल-बदल किये हैं, बम टाइप के साधारण लोग उनके सामने कहाँ लगते हैं। आज मान्यता हो गयी है कि जिसने अपने राजनीतिक जीवनकाल में दल-बदल नहीं किया उसने समझो कि कुछ नहीं किया। दल के प्रति निष्ठावान बने रहने से क्या मिलता है आखिर ? दल-बदल कीजिये तो नगद नारायण के साथ ही टिकिट, मंत्री पद और न जाने क्या-क्या मिलता है। मैं अगर सत्ता में होता या तीसरी बार सत्ता में आने की तैयारी कर रहा होता तो अपने चुनाव घोषणा पत्र में दल-बदल को राजधर्म की मान्यता दिलाने के लिए दल-बदल क़ानून को ही समाप्त करने का वचन देता। वचन देता ही नहीं उसे प्राण-पण से निभाता भी। आप सोचकर देखिये कि दल-बदल के फायदे कितने हैं और नुकसान कितने ? गुणा-भाग करने के बाद आप जो हासिल पाएंगे वो लाभ ही निकलेगा हानि नहीं। दल -बदल में सुविधा ये है कि आप इसे जितनी बार करना चाहें कर सकते हैं। दल-बदल के लिए किसी शैक्षणिक योग्यता की जरूरत नहीं। इसके लिए जरूरी है आपका किसी एक दल से ऊबना या किसी एक दल से मुक्ति पाना। मैं अपने ऐसे कुछ मित्रों को जानता हूँ जिन्होंने एक से ज्यादा बार दल बदल किया। दल -बदल का आध्यात्मिक पक्ष ये है कि इसे घाट-घाट का पानी पीना कहते हैं। आप याद कीजिये कि ये देश पहली बार दल-बदल से नहीं गुजर रहा। लंकापति रावण के भाई विभीषण दल-बदल का आदर्श उदाहरण है। वे दल-बदल न करते तो मुमकिन है कि कभी भी लंकापति नहीं बन पाते। विभीषण ने समझदारी से, होशियारी से, हिकमत अमली से काम लिया और सद्गति को प्राप्त हुए। आज भी दल-बदल करने वाला सबसे पहले विभीषण जी का आभार प्रकट करता है। करना भी चाहिए, क्योंकि यदि विभीषण ने सत्ता-सुख पाने का ये आसान तरीका ईजाद न किया होता तो अधिकांश दलों में लोग चप्पलें घिसते-घिसते मर जाते लेकिन सत्ता सुख हासिल नहीं कर पाते ।शरणागत को ही गति मिलती है ।आजकल तो राजनीतिक दलों ने अपने-अपने यहां शरणार्थी शिविर खोल रखे हैं। दल -बदल का हासिल ये है कि ये महंगे चुनाव खर्च से मुक्ति दिलाता है। अब जैसे इंदौर में, खजुराहो में या सूरत में कांग्रेस और सपा के प्रत्याशियों ने जिस साधुवाद से दल बदल किया उसका कितना ज्यादा लाभ इस गरीब देश को हुआ। जनता चुनाव प्रचार की कांय-कांय से बची। सड़कें विद्रूप होने से बचीं और केंद्रीय चुनाव आयोग का अमला चुनावी इंतजाम करने से, हल्दी लगी और न फिटकरी फिर भी रंग चोखा ही आया। भगवान करे कि भारत जैसे लोकतंत्र में दल-बदलुओं को हमेशा परम पद की प्राप्ति हो। दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की जगह दल-बदलुओं कि लिए संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की जाये ।दल -बदलुओं को वे सारी सुविधाएं और सम्मान मिलना चाहिए जो किसी परमवीर चक्रधारी या भारतरत्न का तमगा गले में लटकाने वाले को हासिल हैं। मैं तो कहता हूँ कि तमाम दल-बदलुओं का मृत्योपरांत अंतिम संस्कार भी राजकीय सम्मान के साथ किया जाना चाहिए। पार्टी के प्रति निष्ठावान नेताओं और कार्यकर्ताओं को आत्मचिंतन कर पता लगाना चाहिए कि उन्हें उनकी निष्ठा के बदले आखिर मिलता क्या है ? दल -बदलू वो सम्मान पल भर में हासिल कर लेता है जो एक निष्ठावान कार्यकर्ता या नेता पूरी उम्र किसी दल की सेवा करने के बाद भी प्राप्त नहीं कर पाता। आपको बता दूँ कि दल-बदल करना बेहद आसान सद्कर्म है। बस अपने गले में पड़ा पुराना गमछा उतार फेंकिए और नया गमछा डाल लीजिये ।सामने वाले के सामने कृतज्ञ भाव से झुकिए, गुलदस्ता लीजिये या दीजिये। एक ग्रुप फोटो खिंचवाइये और बस हो गया दल बदल। दल-बदल के साथ ही आपको घर की बैठक में लगीं पुरानी तस्वीरें भी बदलना पड़ती हैं। लेकिन ये मंहगा सौदा नहीं है। इसके लिए किंचित बेशर्मी की चादर ओढ़ना पड़ती है और आपका चश्मा मय नंबर और फ्रेम के बदल जाता है। (विभूति फीचर्स)

चुनाव का जो रुझान दिखाई दे रहा है,उसमें प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के प्रति गंभीर नाराजगी का भाव महसूस नहीं होता। यदि सरकार बदलने के लिए मतदान होना था,तो लबालब भीड़ पोलिंग स्टेशनों के अंदर-बाहर दिखाई देती और मतदान भी 70 फीसदी से ज्यादा होता। कांग्रेस के पास काडर,बूथ कार्यकर्ता और मतदाता को पोलिंग स्टेशन तक पहुंचाने वाले संगठन की कमी देखी जाती रही है,लेकिन मतदाताओं का ऐसा सैलाब भी गायब है,जो 400 पार के जनादेश को सुनिश्चित कर दे।

कम मतदान से चिंतित राजनीतिक दल

– राजेश माहेश्वरी

देश में इस समय आम चुनाव का माहौल है। देश में सात चरणों में हो रही लोकसभा चुनावी प्रक्रिया के तहत अभी तक दो चरण के लिए वोटिंग हो चुकी है। दोनों चरणों में वोटिंग 2019 के मुकाबले कम हुई। इससे तमाम राजनीतिक दल, उम्मीदवार और खुद चुनाव आयोग भी इस बात को लेकर चिंतित नजर आ रहा है कि आखिर लोग वोट देने घरों से क्यों नहीं निकल रहे? क्या इसके पीछे तेज गर्मी बड़ा कारण है या फिर वोटरों में उदासीनता या फिर कुछ और। पहले चरण के कम मतदान के बाद राजनीतिक दलों और नेताओं अपनी चुनावी सभाओं में ज्यादा से ज्यादा मतदान करने का आह्वान किया था, लेकिन दूसरे चरण में भी आशनुरुप कम मतदान ही देखने को मिला। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश जहां से 80 सांसद देश की संसद में पहुंचते हैं, वहां देश के अन्य राज्यों की तुलना में कम मतदान रिकार्ड हुआ। पहले चरण में कम वोटिंग होने की वजह से नतीजों को लेकर सियासी दलों की धुकधुकी भी बढ़ गई है। वहीं बीजेपी नेताओं का दावा है कि उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में नए रिकॉर्ड बनाएगा। इसके अलावा मोदी सरकार की वापसी की उम्मीदों का दावा भी किया गया है। उत्तर प्रदेश में 19 अप्रैल को पहले चरण में प्रदेश में कुल 61.11 फीसदी मतदान हुआ था। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में इन आठ सीटों पर 66.41 प्रतिशत मतदान हुआ था। पिछले चुनाव के मुकाबले पहले चरण की इन सीटों पर करीब 5.39 फीसदी कम वोट पड़े हैं। यूपी की 8 सीटों पर दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को हुआ। इस दौरान वोटिंग प्रतिशत 55.39 रहा। पिछले आम चुनाव में इन सीटों पर 62.18 प्रतिशत वोट पड़े थे । इस हिसाब से साल 2024 के चुनाव में दूसरे चरण में पिछले चुनाव के मुकाबले 6.79 प्रतिशत कम वोटिंग हुई है। दरअसल 2019 के दूसरे चरण में जिन सीटों पर भाजपा जीती थी, उन पर 3 फीसदी तक मतदान कम हुआ है। जो सीटें कांग्रेस ने जीती थीं, उन पर 5-10 फीसदी मतदान घटा है। हिंदी पट्टी के प्रमुख राज्यों में मतदान औसतन 7 फीसदी तक घटा है। ये राज्य ही भाजपा के दुर्गनुमा चुनावी गढ़ हैं। क्या यह घटा हुआ मतदान भाजपा के खिलाफ एक 'खामोश चुनावी लहर' है? सवाल यह भी है कि फिर यह लहर किस राजनीतिक दल के पक्ष में है? कांग्रेस ने तो 300 सीटों पर भी उम्मीदवार नहीं उतारे हैं और गठबंधन के तौर पर 'इंडिया' छिन्न-भिन्न स्थिति में है। तो फिर जनादेश कैसा होगा और केंद्र सरकार का स्वरूप भी कैसा होगा? वैसे तो इस बार के लोकसभा चुनाव का खास ट्रेंड यह दिख रहा है कि हर जगह मतदान में या तो पिछली बार के मुकाबले कमी आ रही है या उसके आसपास मतदान हो रहा है। लेकिन हैरानी की बात है कि जिन सीटों पर पार्टियों के बड़े नेता चुनाव लड़ रहे हैं या पार्टियों ने ग्लैमर का तड़का लगाने के लिए फिल्मी सितारों आदि को उतारा है उन सीटों पर भी मतदान करने में लोगों ने ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई है। दूसरे चरण की 88 सीटों में से ज्यादातर वीआईपी सीटों पर औसत से कम या पिछली बार से कम मतदान हुआ है। यह ट्रेंड केरल से लेकर उत्तर प्रदेश तक एक समान रूप से देखने को मिला है। केरल की तिरुवनंतपुरम सीट को बहुत हाई प्रोफाइल माना जा रहा है कि क्योंकि कांग्रेस के शशि थरूर लगातार चैथी बार जीतने के लिए लड़ रहे हैं तो भाजपा ने केंद्रीय मंत्री और कारोबारी राजीव चंद्रशेखर को लड़ाया है। लेकिन 2019 के 74 फीसदी के मुकाबले 2024 में सिर्फ 64 फीसदी मतदान हुआ। इसी तरह मेरठ में भाजपा ने रामायण सीरियल में राम की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल को उतारा है। लेकिन वहां 2019 के 64.29 के मुकाबले 2024 में 59 फीसदी मतदान हुआ। राहुल गांधी की वायनाड सीट पर 73 फीसदी से कुछ ज्यादा वोट हुआ, जबकि 2019 में, जब राहुल गांधी पहली बार वहां चुनाव लड़ने पहुंचे थे तब वहां 80.37 फीसदी मतदान हुआ था। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की जोधपुर सीट पर 2019 में 69 फीसदी वोट हुआ था, जबकि इस बार 64 फीसदी मतदान हुआ है। मथुरा में भाजपा की हेमामालिनी की सीट पर तो 2019 के मुकाबले करीब 14 फीसदी वोट कम पड़े हैं। वहां सिर्फ 49 फीसदी मतदान हुआ है, जबकि पिछली बार 63 फीसदी के करीब वोट पड़े थे। चुनाव का जो रुझान दिखाई दे रहा है, उसमें प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के प्रति गंभीर नाराजगी का भाव महसूस नहीं होता। यदि सरकार बदलने के लिए मतदान होना था, तो लबालब भीड़ पोलिंग स्टेशनों के अंदर-बाहर दिखाई देती और मतदान भी 70 फीसदी से ज्यादा होता। कांग्रेस के पास काडर, बूथ कार्यकर्ता और मतदाता को पोलिंग स्टेशन तक पहुंचाने वाले संगठन की कमी देखी जाती रही है, लेकिन मतदाताओं का ऐसा सैलाब भी गायब है, जो 400 पार के जनादेश को सुनिश्चित कर दे। कम मतदान होने के पीछे क्या वोटरों में बढ़ती उदासीनता तो नहीं। इसमें कुछ वोटर वोट देना ही नहीं चाह रहे। तो कुछ वोटर ऐसे हैं, जिन्हें पार्टी या उम्मीदवार की जीत-हार पक्की लग रही है। ऐसे में वह वोट देने ही नहीं निकल रहे। जानकारों भी यही मानते हैं कि कम वोटिंग के पीछे यह एक कारण लगता दिखाई दे रहा है। हालांकि, अभी इसका विश्लेषण होना बाकी है। लेकिन कम वोटिंग के पीछे वोटरों में वोटिंग के प्रति उदासीनता होना दिख रहा है। खासतौर से बड़े राज्यों में जहां कहीं पिछले कुछ समय से नेताओं ने पार्टी बदली तो कहीं पैराशूटर उम्मीदवार आ धमके। इससे भी वोटरों में उदासीनता आई। महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में कुछ ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है। कहीं ईवीएम में सेटिंग के डर से तो नहीं हुआ कम मतदान। इस मामले में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार इस मामले में स्पष्ट बोल चुके हैं कि ईवीएम से वोट देने की प्रक्रिया एकदम सुरक्षित है। ईवीएम से वोटिंग एकदम सुरक्षित है। इस पर भरोसा रखिए। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने एक फैसले में ईवीएम और वीवीपैट के मिलान की अर्जी खारिज करते हुए कहा था कि याचिकाकर्ता द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है। इसमें ईवीएम और वीवीपैट में वोट मिलान मिसमैच हुआ हो। पहले दो चरण में कम वोटिंग होने से राजनीतिक दलों की चिंता बढ़ गई है। भाजपा ने अपने प्रचार अभियान को अधिक तेज कर दिया है। आने वाले चरणों में पार्टी की कोशिश ज्यादा मतदान कराने की होगी ताकि वह बड़े लक्ष्य को हासिल कर सके। इसके साथ ही विपक्षी दलों ने अपनी चुनावी रणनीति को बदल दिया है। बहरहाल तीसरे चरण के मतदान के मद्देनजर भाजपा ने अपनी रणनीति बदलने का फैसला लिया है। करीब 500 नेता और पदासीन कार्यकर्ता मतदान वाले क्षेत्रों में तैनात किए जाएंगे। वे सुबह और शाम में मुख्य चुनाव केंद्र को रपट देंगे कि मतदाता की स्थिति क्या है? तीसरे चरण में अपने कोटे के मतदाताओं के वोट डलवाने को भाजपा ने कमर कस ली है। क्या कम मतदान का सबब यही है? हम इस सवाल से सहमत नहीं हैं। वहीं मतदाताओं को भी यह समझना चाहिए कि लोकतंत्र के इस महापर्व में हरेक वोट बहुमूल्य है। देश में एक वोट से हार जीत के कई प्रसंग हैं। एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी तो राजस्थान में कांग्रेस के दिग्गज नेता एक वोट की वजह से ना केवल विधायक बनने से चूक गए। बल्कि उसी एक वोट की वजह से वह मुख्यमंत्री की कुर्सी तक आज तक नहीं पहुंच पाए।

(लेखक राज्य मुख्यालय पर मान्यता प्राप्त स्वतंत्र पत्रकार हैं)

https://t.me/AllNewsPaperPaid

संपादकीय

" आप जो कर रहे हैं, यदि वह सही है, तो उसके बारे में कभी भी भयभीत नहीं होना चाहिए। -रोजा पार्क्स

एस्ट्राजेनेका ने भले यह स्वीकारा हो कि उसकी वैक्सीन से दुर्लभ मामलों में कुछ दुष्प्रभाव हो सकते हैं, पर ध्यान रहे कि महामारी के मुश्किल दौर में व्यापक परीक्षणों के बाद उसे मंजूरी दी गई थी, जिसमें जोखिम का अनुपात भी दस लाख पर एक का है। ऐसे में, पूरे मामले को तर्कशीलता के साथ देखने की जरूरत है।

घबराने की बात नहीं

एस्ट्राजेनेका कंपनी, जिसके वैक्सीन को भारत में कोविशील्ड के रूप में उत्पादित किया गया, की ब्रिटेन की अदालत में इस स्वीकारोक्ति के बाद कि उनकी वैक्सीन से दुर्लभ मामलों में रक्त के थक्के जमने जैसे दुष्प्रभाव हो सकते हैं, दुनिया भर में एक बार फिर आशंकाएं और सवाल उठने लगे हैं, हालांकि इनमें से ज्यादातर निर्मूल ही हैं। मामला यह है कि 2021 में कोविशील्ड की डोज लेने के बाद इंग्लैंड के जेमी स्कॉट के दिमाग में खून का थक्का जमा और उनका दिमाग स्थायी तौर पर क्षतिग्रस्त हो गया। तब एस्ट्राजेनेका ने वैक्सीन के इस्तेमाल से ऐसे किसी नुकसान को सख्ती से नकार दिया था। विवाद यह है कि जब 2021 के अंत तक चिकित्सा जगत ने भी बेहद दुर्लभ मामलों (दस लाख मामलों में एक) में ही सही, लेकिन वैक्सीन के दुष्प्रभाव को स्वीकार लिया था, तब एस्ट्राजेनेका को इसे स्वीकारने में तीन साल क्यों लगे। यह चौंकाने वाली बात है कि पश्चिमी देशों, खासकर इंग्लैंड में वैक्सीन के दुष्प्रभावों को झेलने वाले हर पांच में से एक व्यक्ति की मौत हुई है और इसलिए इस वैक्सीन का इस्तेमाल वहां नहीं हो रहा है। फिर भी दुनिया भर के विशेषज्ञों व नीति नियंताओं ने माना है कि इसके दुष्प्रभावों की तुलना में फायदे कहीं ज्यादा हैं। नहीं भूलना चाहिए कि इसने पहले ही साल में साठ लाख से ज्यादा लोगों की जानें तो बचाई ही, ऐसे दौर में जब प्रति दस लाख आबादी में करीब 15 हजार लोगों की जान खतरे में बताई जा रही थी, तब यही वैक्सीन थी, जिसने महामारी के जोखिम को 90 फीसदी तक घटा दिया था। भारत की स्थिति इंग्लैंड से अलग है। भारत में वैक्सीन की 200 करोड़ से ज्यादा खुराकें दी गईं, जिनमें से करीब 175 करोड़ कोविशील्ड की थीं। इसके बावजूद अब तक खून के थक्के जमने के मामले आधा फीसदी से भी कम मिले हैं। दरअसल, कोविड के वक्त भी वैक्सीन को लेकर कई अफवाहें सुनने में आई थीं, जिनकी जड़ में गलत जानकारियां थीं। यह समझना चाहिए कि कोरोना हो या फिर कोई

दूसरी बीमारी, पिछली दो सदियों में टीकाकरण ने मानवता की जो सेवा की है, उसे देखते हुए इनके महत्व को नकारा नहीं जा सकता। जहां तक सवाल दुष्प्रभावों का है, तो कोई भी टीका या दवा पूरी तरह से जोखिम मुक्त नहीं होता। मगर यह ध्यान रखना चाहिए कि महामारी के मुश्किल दौर में व्यापक परीक्षणों के बाद वैक्सीन को मंजूरी दी गई थी, जिसमें जोखिम का अनुपात भी दस लाख पर एक का है। ऐसे में, पूरे मामले को बगैर किसी पूर्वाग्रह के तर्कशीलता के साथ देखने की जरूरत है।

औरत क्या चाहती है

स्त्री क्या चाहती है, इस बारे में न पुरुष जानने की कोशिश करता है, न ही समाज को इसकी परवाह है। स्त्री किस तरह अपना जीवनयापन करना चाहती है? मुझे लगता है कि ज्यादातर स्त्रियों में अभी तक यह सोच विकसित नहीं हो पाई है कि अपनी तरह से जीवन जीने का क्या अर्थ है।

वर्ष 1991 में मैंने *निमंत्रण* नाम से एक उपन्यासिका लिखी थी, जिसमें स्त्री शोषण और पुरुषतंत्र की भयावहता के बारे में बताया गया था। *निमंत्रण* लिखने के कारण मुझे अनेक लोगों की निंदा-आलोचना सुननी पड़ी थी। कुछ लोगों के मुताबिक, वह पोर्नोग्राफी थी, जिसमें यौन संबंधों का खुला चित्रण था। बस, फिर क्या था, चारों ओर मेरी बदनामी कर दी गई। मेरी बदनामी फैलने लगी। कहा गया कि मैं पोर्नोग्राफी लिखती हूं। मेरी उस उपन्यासिका में आखिर था क्या?

कहानी यह थी कि अट्ठारह साल की किशोरी एक सुदर्शन युवक के प्रेम में पड़ जाती है। जबकि वह युवक उस तरुणी के दायरे से बहुत दूर है। तरुणी उस युवक को रोज चिट्ठी लिखती है, जिसमें वह अपना प्रेम निवेदन करती है। लेकिन युवक के पास वे चिट्ठियां पहुंचती ही नहीं। आखिरकार जब युवक को किशोरी के उससे एकतरफा प्रेम का पता चलता है, तब दो दिन प्रेम का अभिनय कर एक दोपहर को वह उसे अपने घर लंच के लिए आमंत्रित करता है। किशोरी सज-धजकर अपने प्रेमी के लिए कीमती उपहार खरीदकर उसके यहां पहुंचती है। वहां युवक और उसके सात दोस्त थे। वे सब उससे बलात्कार करते हैं।

तसलीमा नसरीन
चर्चित लेखिका

सामूहिक बलात्कार के बाद अंदर और बाहर से गंभीर रूप से घायल वह किशोरी घर लौटते हुए मन ही मन सोचती है कि पिता जब उससे पूछेंगे कि कहां गई थी, तब वह झूठ नहीं बोलेगी। उन्हें बता देगी कि वह किसी के निमंत्रण पर उसके घर गई थी। उपन्यासिका यहीं खत्म हो जाती है। उसमें बलात्कार के जो ब्योरे दिए गए थे, स्त्री-विरोधियों ने उसे पोर्नोग्राफी कहा था। समाज में जब स्त्री विरोधियों की संख्या बढ़ जाती है, तब औरतों के शोषण को स्वाभाविक समझ लिया जाता है। ऐसे तत्वों के लिए बलात्कार भी स्वाभाविक घटना है।

निमंत्रण की कहानी काल्पनिक नहीं थी। हालांकि समाज का एक वर्ग मानता है कि इस तरह की घटनाएं नहीं होतीं। दूसरा वर्ग यह तो मानता

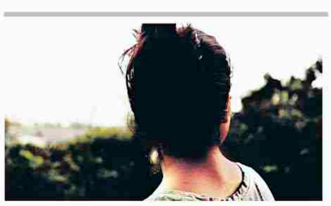

है कि इस तरह की घटनाएं होती हैं, लेकिन उसका कहना है कि इसके लिए महिलाएं ही दोषी हैं। वे क्यों दोषी हैं, इसकी वजह भी बताई जाती है। दोष यह है कि वे प्रेम में पड़ती ही क्यों हैं? वे पुरुषों के पास जाती ही क्यों हैं? जाने पर तो उनके साथ गलत होगा ही। जो लोग बलात्कार का शिकार होने वाली महिलाओं पर ही बलात्कार की जिम्मेदारी डाल देते हैं, वे चाहते हैं कि लड़कियां घर से बाहर न निकलें, किसी के प्रेम में न पड़ें, किसी पर भरोसा न करें और किसी के निमंत्रण पर उसके यहां या उसके साथ न जाएं। वे महिलाओं को तो जिम्मेदार ठहरा देते हैं, लेकिन पुरुष की आंखों में उंगली डालकर नहीं कहते कि महिलाओं के साथ अत्याचार करने का पुरुषों को कोई अधिकार नहीं है। यह अजीब है कि घर से बाहर तक लड़कियों-महिलाओं के साथ गलत बर्ताव और यौन हिंसा को अंजाम तो पुरुष देते हैं, लेकिन इन सबके लिए जिम्मेदार महिलाओं को ठहराया जाता है। पुरुषवर्चस्ववादी समाज में पुरुषों की बर्बरता को कमतर करके दिखाने या उन्हें निर्दोष बताने की प्रवृत्ति पुरानी है।

जिन लोगों ने *निमंत्रण* की कहानी को मनगढ़ंत बताया था, उन्हें छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की एक खबर से अवगत कराना चाहती हूं, जहां सोलह वर्षीय एक किशोरी के साथ उसके प्रेमी और उसके दो साथियों ने मिलकर बलात्कार किया। तीन युवाओं ने किशोरी को पूरी रात एक परित्यक्त घर में बंधक बनाकर रखा था। सुबह घर लौटी किशोरी ने पिता को सारी बातें बताईं, तो घरवालों ने थाने में रिपोर्ट लिखवाई। *निमंत्रण* नाम की उपन्यासिका मैंने लड़कियों-महिलाओं को सजग करने के लिए लिखी थी। मैं महिलाओं को यह बताना चाह रही थी कि उन्हें पुरुषों के जाल में नहीं फंसना चाहिए। इसमें संदेह नहीं कि शिक्षा ने आज की बहुत-सी स्त्रियों को जिस तरह आत्मनिर्भर बनाया है, उसी तरह उन्हें सजग भी किया है। लेकिन सभी स्त्रियां शिक्षित और सजग नहीं हैं, इसलिए वे पुरुषों के जाल में आसानी से फंस जाती हैं। हालांकि अनेक शिक्षित और आत्मनिर्भर स्त्रियां भी पुरुषों के धोखे और यौन अत्याचार का शिकार होती हैं। मौजूदा 21वीं सदी में भी स्त्रियों की यह दुर्दशा है, तो इसके लिए पुरुषवादी सोच जिम्मेदार है।

लेकिन मैं यहां यह भी बताना चाहती हूं कि शिक्षा ने स्त्रियों के प्रति अनेक पुरुषों की भी सोच बदली है। *निमंत्रण* उपन्यासिका में भी पुरुषों के लिए संदेश था, और मेरा मानना है कि उसे पढ़कर अनेक पुरुषों ने भी स्त्रियों के प्रति संवेदनशील व्यवहार करने के बारे में सीखा या सोचा होगा। लेकिन पुरुषों की बड़ी आबादी की सोच नहीं बदली है, इसी कारण महिलाओं के साथ होने वाली यौन हिंसा की घटनाएं कम होने का नाम ही नहीं ले रहीं। इस उपमहाद्वीप में धर्म या मजहब का महत्व सामाजिक-राजनीतिक जीवन में बहुत बढ़ा है। देखने वाली बात यह है कि इसके बावजूद स्त्रियों के साथ होने वाली यौन हिंसा की घटनाओं में कमी नहीं आई है।

पुरुष चाहता है, स्त्री उसके हिसाब से चले। समाज चाहता है कि स्त्री उसके मुताबिक चले। स्त्री क्या चाहती है, इस बारे में न पुरुष जानने की कोशिश करता है, न ही समाज को इसकी परवाह है। स्त्री क्या चाहती है? मुझे लगता है कि स्त्री की चाह अब भी स्पष्ट नहीं हो पाई है।

स्त्री किस तरह अपना जीवनयापन करना चाहती है? मुझे लगता है कि ज्यादातर स्त्रियों में अभी तक यह सोच विकसित नहीं हो पाई है कि अपनी तरह से जीवन जीने का क्या अर्थ है। यह स्वाभाविक भी है। पुरुष रचित धर्म, पुरुष रचित समाज और पुरुष रचित पुरुष तंत्र जिस तरह स्त्रियों को चलाते रहे हैं, स्त्रियां उसी तरह संचालित होती रही हैं। स्त्रियों की खुशी, उसके सपने और उसके सुख वही हैं, जो पुरुष उसे बताता है। यह आकस्मिक नहीं है कि ज्यादातर स्त्रियों की खुशी उनके पुरुषों की खुशियों में है। ज्यादातर स्त्रियों के सपने उनके पुरुषों से जुड़े हैं। ठीक इसी तरह स्त्रियों का सुख उनके पुरुषों के साथ होने और उन्हें सुखी रखने में है।

कहीं भी स्त्रियों को स्वतंत्रता नहीं है। पुरुष, परिवार और समाज यह कल्पना तक नहीं कर सकते कि स्त्रियों का जीवन पुरुषों के जीवन से अलग या स्वतंत्र भी हो सकता है। जब तक इस तरह की सोच नहीं बदलेगी, तब तक इस बारे में सोचा भी नहीं जाएगा कि आखिर औरत चाहती क्या है?

जीवन धारा

संत तुकाराम

मनुष्य जीवित परमात्मा का मंदिर होता है, जिसमें हमें परमात्मा को खोजना और पाना है। देवता भी मनुष्य शरीर पाने के लिए तरसते हैं, क्योंकि प्रभु भक्ति केवल मनुष्य जीवन में ही हो सकती है।

ईश्वर को पा लेना ही असली सुख है

मन को हमेशा खुश रखना चाहिए। यही सब सिद्धियों का मूल है। यही बंधन और मोक्ष का भी कारण है। इसलिए मन को वश में रखकर ही असली सुख प्राप्त हो सकता है। असली सुख यानी प्रभु की भक्ति, ईश्वर को पाना। हालांकि यह बात कहने में जितनी सहज है, व्यवहार में उतनी ही कठिन भी है। पर असंभव नहीं। ईश्वर से बार-बार यही प्रार्थना करनी चाहिए कि वह मन को वश में रखने की शक्ति दे, वरना मन की निरंकुशता जीवन को कठिन और अशांत बनाती है। ऐसे में मन हानि पहुंचाता है। इसका कारण यह है कि मन के भीतर ही सांसारिक प्रपंच भरा है, भक्ति तो केवल बाहर ही दिखती है। यह मन ही है, जिसने ईश्वर की भक्ति के मार्ग में काम, क्रोध, लोभ जैसे अवरोध खड़े कर दिए हैं। ये अवरोध पर्वतों से भी बड़े हैं। ऐसे में ईश्वर इनके दूसरी तरफ रह जाते हैं। इसी का नतीजा है कि हम ईश्वर तक पहुंच नहीं पाते, क्योंकि इन अवरोधों को लांघने का कोई रास्ता हमें नजर नहीं आता। और ऐसा मन की चंचलता के कारण होता है। मन की चंचलता अज्ञानता का परिणाम होती है। ज्ञान के अभाव में मन की चंचलता बढ़ती जाती है और वह विषयों की तरफ ही भागता रहता है।

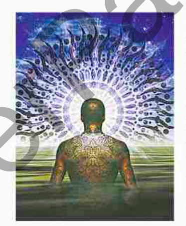

धन, काम, यश और अहंकार अध्यात्म-मार्ग में बड़ी बाधा होते हैं। पहली बात तो यह कि इस मार्ग पर चलने वाले यात्री ही थोड़े होते हैं। और फिर जो होते भी हैं, उनमें से ज्यादातर धन की लिप्सा में ही गायब हो जाते हैं। इसके बाद बचे लोग कामवासना की खाई में गिर जाते हैं और इससे भी बच कर जो निकल जाते हैं, वे यश और अहंकार का शिकार हो जाते हैं। और जो लोग इन तीनों खाइयों से बच जाते हैं, उन्हीं के लिए अध्यात्म का रास्ता खुला होता है।

कई जन्मों और पुण्य कर्मों के बाद आत्मा को मनुष्य जन्म मिलता है। इसलिए जन्म-मरण के चक्र से छुटकारा पाने के लिए मन को ईश्वर की भक्ति में लगाना चाहिए। एक बार मनुष्य जीवन का अंत हो जाए तो यह फिर नहीं मिलता। इसलिए इसे सार्थक बनाने का एक ही मार्ग है और वह है ईश्वर की भक्ति, जो मन को वश में रखने से ही मिल सकती है।

मनुष्य जीवित परमात्मा का मंदिर होता है, जिसमें हमें परमात्मा को खोजना और पाना है। देवता भी मनुष्य शरीर पाने के लिए तरसते हैं, क्योंकि प्रभु भक्ति केवल मनुष्य जीवन में ही हो सकती है। इसलिए जब मनुष्य जन्म मिल ही गया है, तो प्रभु का नाम जपो और परम सुख प्राप्त करो। परमात्मा की खोज में लोग तीर्थयात्रा करते हैं या फिर पहाड़ों पर या जंगलों में चले जाते हैं। लेकिन तीर्थयात्रा भर से मन के भीतर शांति, दया या भक्ति का भाव तो उत्पन्न नहीं होता। तीर्थों में तो केवल पानी होता है और पत्थर की नदियां। जबकि संतों में ईश्वर वास करते हैं। इसलिए प्रभु के दर्शन के लिए किसी तीर्थ पर जाने की जरूरत नहीं है, उसके दर्शन तो संतों के भीतर ही हो जाते हैं।

परमात्मा की खोज...

सूत्र

साधारणतया लोग ईश्वर को पाने की विधि से अनजान होते हैं। परमात्मा की खोज में वे तीर्थ यात्रा करते हैं या फिर पहाड़ों पर या जंगलों में चले जाते हैं। और ऐसे में लोगों को लगता है कि तीर्थ कर लेने भर से उन्होंने ईश्वर को पा लिया। लेकिन तीर्थयात्रा भर से मन के भीतर शांति, दया या भक्ति का भाव तो उत्पन्न नहीं होता।

दूसरा पहलू

वैक्सीन इसलिए दी जाती है, ताकि वह रोगजनक के एंटीजन से जुड़कर उसे बेअसर कर दे।

लाखों जिंदगियां बचाने वाले टीके पर संदेह ठीक नहीं

मुझे नहीं लगता कि कोविशील्ड टीका लगवाने वालों को डरने या चिंतित होने की जरूरत है। असल में, किसी भी वैक्सीन के अंदर एंटीजन होता है, जिसकी प्रकृति प्रोटीन की हो सकती है। जैसे कोविशील्ड में सार्स कोव-2 का एंटीजन, स्पाइक प्रोटीन था। वैक्सीन जब शरीर में लगाई जाती है, तो वह की कोशिका से एंटीबॉडीज का निर्माण करती है। यह एंटीबॉडी वायरस के एंटीजन से जुड़कर या तो उसके प्रभाव को कम करता है या उसे खत्म कर देता है। वैक्सीन इसलिए दी जाती है, ताकि वह रोगजनक के एंटीजन से जुड़कर उसे बेअसर कर दे। शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली पैथोजन के खिलाफ टी कोशिका का निर्माण करती है, जो संक्रमित कोशिका को नष्ट करती है और वायरस के हमले से हमें बचाती है। शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को रोगजनक को खत्म करने के लिए पर्याप्त एंटीबॉडी बनाने में कुछ समय लगता है। ऐसे में वैक्सीन रोगजनक का पता लगाने और उसे तुरंत बेअसर करने के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रेरित करके एंटीबॉडी के निर्माण के समय को कम करती है। साइड इफेक्ट सिर्फ वैक्सीन के ही नहीं, दवाओं के भी होते हैं, जो हल्के से लेकर गंभीर स्तर तक के हो सकते हैं। जैसे कि, जब टीका लगाया जाता है, तो अक्सर हल्का बुखार होता है और टीका लगाए जाने वाली जगह पर सूजन या लाल चकत्ते हो जाते हैं। ये हल्के दुष्प्रभाव के लक्षण हैं, जो जल्दी खत्म हो जाते हैं।

डॉ. सुनीत कुमार सिंह
डॉ. बीआर आंबेडकर सेंटर फॉर बायोमेडिकल रिसर्च, नई दिल्ली के निदेशक एवं वायरोलॉजिस्ट

जब किसी दवा या वैक्सीन का दुष्प्रभाव कम होता है और लाभ ज्यादा होते हैं, खासकर जब कोई विषाणुजनित महामारी के नियंत्रण के लिए कोई दवा न हो, तो उसका उपयोग करने में परेशानी नहीं है।

जब किसी दवा या वैक्सीन का दुष्प्रभाव कम होता है और लाभ ज्यादा होते हैं, वह भी तब, जब कोई विषाणुजनित महामारी फैली हो और नियंत्रण के लिए कोई दवा न हो, तो उसका उपयोग करने में परेशानी नहीं है। हालांकि, कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी ने कुछ लोगों में रक्त का थक्का जमने (थ्रोम्बोसिस विथ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम-टीटीएस) जैसी जानकारी को साझा किया है, क्योंकि यह वैक्सीन एडीनोवायरस पर आधारित थी। इसलिए इसमें अभी और अध्ययन की जरूरत है। पर इस तरह का दुष्प्रभाव टीका लगने के चार से छह हफ्तों के भीतर होता है। अब, जबकि लोगों को कोविशील्ड टीका लगाए महीनों हो गए हैं, तो उसके दुष्प्रभावों को लेकर डरने की जरूरत नहीं है। फिर भी अध्ययन की आवश्यकता है। सहरुग्णता वाले व्यक्तियों में साइड इफेक्ट का प्रभाव ज्यादा हो सकता है। पर लाखों जिंदगियां बचाने वाले संपूर्ण टीकाकरण अभियान पर संदेह करना ठीक नहीं है।

आंकड़े

सेवाओं का निर्यात

भारत सिर्फ वस्तुओं का ही नहीं, बल्कि सेवाओं का भी निर्यात करता है, जिनमें सबसे ज्यादा निर्यात आईटी सेवाओं का किया जाता है।

सेवा	प्रतिशत
आईटी	72%
परिवहन	11%
यात्रा	8%
वित्त, बीमा	3%
निर्माण	1%

स्रोत: DBIE, RBI

संत ने कहा, जब तू मुझे नहीं धकेल सकता, तो बता मेरा मालिक (भगवान) भला कैसे मुझे खाई में गिरने देगा! वह तो गिरे हुए लोगों को उबारता है।

ईश्वर पर विश्वास

अंतर्यात्रा
संकलित

ऋषिकेश में गंगा के किनारे एक संत रहते थे। वह जन्मांध थे, पर वह हर शाम के समय पहाड़ों पर भ्रमण करने के लिए निकल जाते थे। एक दिन एक शिष्य ने उनसे पूछा, आप हर रोज इतने ऊंचे पहाड़ों पर भ्रमण हेतु जाते हैं। वहां खाइयां भी हैं। आपको दिखाई नहीं देता। क्या आपको डर नहीं लगता? कभी पांव लड़खड़ा गए तो?

संत ने उस समय कुछ नहीं कहा और शाम को शिष्य को भी अपने साथ ले गए। संत ने शिष्य से कहा, जैसे ही कोई गहरी खाई आए, तो बताना। दोनों चलते रहे और जैसे ही गहरी खाई आई, शिष्य ने बताया कि गहरी खाई आ चुकी है। संत ने कहा, मुझे इसमें धक्का दे दे। इतना सुनते ही शिष्य सकपका गया। उसने कहा, मैं आपको धक्का कैसे दे सकता हूं? आप तो मेरे गुरुदेव हैं, मैं तो किसी शत्रु को भी नहीं धकेल सकता।

संत ने फिर कहा, मैं कहता हूं कि मुझे इस खाई में धक्का दे दो। यह मेरी आज्ञा है और मेरी आज्ञा की अवहेलना करोगे, तो नर्क में जाओगे।

शिष्य ने कहा, मैं नर्क भोग लूंगा, मगर आपको खाई में नहीं धकेल सकता।

तब संत ने कहा, जब तू मुझे नहीं धकेल सकता, तो बता मेरा मालिक भला कैसे मुझे खाई में गिरने देगा। वह तो गिरे हुए लोगों को उबारता है। वह पल-पल हमारे साथ है।

आज का इतिहास

कला और फिल्म से जुड़ी दो बड़ी घटनाओं का गवाह

इतिहास में दो मई का दिन कला और फिल्म से जुड़ी दो बड़ी घटनाओं के लिए दर्ज है। भारतीय सिने जगत के निर्माता, निर्देशक और लेखक सत्यजीत रे का जन्म दो मई को ही हुआ था। महान चित्रकार लिओनार्दो द विंची आज ही के दिन इस दुनिया को अलविदा कह गए थे।

1519 में महान चित्रकार लिओनार्दो दा विंची का निधन। 1921 में पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न और ऑस्कर अवॉर्ड से अलंकृत फ.ल्मि निर्माता, निर्देशक और लेखक सत्यजीत रे का जन्म। 1924 में नीदरलैंड ने सोवियत संघ को मान्यता देने से इनकार कर दिया।

1933 में जर्मनी में हिटलर ने मजदूर संघों पर प्रतिबंध लगा दिया। 1945 में इटली में मौजूद जर्मन सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया।

ई-कचरे से खतरे में धरती

अगर दुनिया भर के ई-कचरे को ट्रकों में भरकर, उन्हें कतार में खड़ा किया जाए, तो ये भूमध्यरेखा के चारों ओर एक लाइन बना सकते हैं।

ऋषभ मिश्रा
पर्यावरण

वर्तमान तकनीकी और डिजिटल युग में इलेक्ट्रॉनिक कचरा (ई-वेस्ट) पूरी दुनिया में एक चुनौती के रूप में उभर कर सामने आया है। हम सबके पास मोबाइल फोन, टीवी, लैपटॉप जैसे बहुत से इलेक्ट्रॉनिक सामान हैं, जिन्हें खराब हो जाने पर हम कचरे में डाल देते हैं। पर इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की बढ़ती चाहत हमारे वातावरण का गला घोंट रही है।

ई-कचरे पर संयुक्त राष्ट्र की 'द ग्लोबल ई-वेस्ट मॉनीटर- 2024' रिपोर्ट के मुताबिक, वैश्विक स्तर पर सालाना 6.2 करोड़ टन इलेक्ट्रॉनिक कचरा पैदा हो रहा है। वर्ष 2010 के बाद से इसमें 82 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। अगर ई-कचरा ऐसे ही बढ़ता रहा, तो वर्ष 2030 तक 32 फीसदी की वृद्धि के साथ बढ़कर यह 8.2 करोड़ टन पर पहुंच सकता है। ई-कचरा प्रति वर्ष 23

लाख टन की दर से बढ़ रहा है। जिन इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों ने हमारी जिंदगी को आसान बनाया, अब वे ही हमारी जिंदगी में जहर घोल रहे हैं। ई-कचरे की असली समस्या तब शुरू होती है, जब इसका सही तरीके से संग्रहण (कलेक्शन) और पुनर्चक्रण (रीसाइक्लिंग) नहीं होता है, जिससे मिट्टी, पानी और हवा जहरीली हो रही है। बहुत से ऐसे देश हैं, जहां ई-कचरा बड़ी मात्रा में निकलता है, लेकिन उसके संग्रहण एवं पुनर्चक्रण का उचित प्रबंधन नहीं किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक, 2022 में उत्पन्न हुए ई-कचरे का सिर्फ 22.3 प्रतिशत हिस्सा ही एकत्रित और पुनर्चक्रित हो पाया था। वर्ष 2030 तक इसके संग्रहण और पुनर्चक्रण की दर घटकर सिर्फ 20 फीसदी रह जाएगी। दुनिया का करीब एक तिहाई यानी 2,000 करोड़ किलोग्राम ई-कचरा खिलौनों, माइक्रोवेव ओवन, वैक्यूम-क्लीनर और ई-सिगरेट जैसे छोटे उपकरणों से पैदा हो रहा है। जिस तरह से जलवायु परिवर्तन पूरी दुनिया की समस्या है, ठीक उसी तरह से ई-कचरा भी पूरे विश्व की समस्या है। दुनिया में ई-कचरे की मात्रा कितनी ज्यादा है, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि अगर इस ई-कचरे को 40 मीट्रिक टन क्षमता के ट्रकों में भरा जाए, तो इसके लिए करीब 15.5 लाख से ज्यादा ट्रकों की जरूरत पड़ेगी। इन ट्रकों को कतार में खड़ा किया जाए, तो ये भूमध्यरेखा के चारों ओर एक लाइन बना सकते हैं। वैश्विक स्तर पर ई-कचरे की रीसाइक्लिंग की दर मात्र 12 फीसदी है। बड़ी मात्रा में ई-कचरे को नदियों, समुद्रों में बहा दिया जाता है, जिससे पर्यावरण के साथ-साथ जीव-जंतुओं को भी नुकसान हो रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट 'चिल्ड्रन ऐंड डिजिटल कनेक्टेड साइट' के मुताबिक, 1.29 करोड़ महिलाएं ई-कचरे से जुड़े क्षेत्र में काम करती हैं। ये महिलाएं या तो ई-कचरा जमा करती हैं या पुनर्चक्रण के काम में लगी हुई हैं। ई-कचरे के संपर्क में आने पर इन महिलाओं की सेहत पर तो असर पड़ता ही है, उनके गर्भ में पलते अजन्मे बच्चे पर भी असर पड़ता है। इसी तरह करीब 1.8 करोड़ बच्चे और किशोर, जिनमें से कई पांच वर्ष से भी कम उम्र के हैं, भी इस काम में जुटे हुए हैं। ई-कचरे में मौजूद सीसा और पारा इन बच्चों की दिमागी क्षमता को नुकसान पहुंचा सकता है। ई-कचरे के पुनर्चक्रण से न केवल पर्यावरण बचेगा, बल्कि इससे कीमती धातुएं भी बचाया जा सकता है। जैसे, वर्ष 2022 में जो ई-कचरा इकट्ठा हुआ, उसमें 7.50 लाख करोड़ रुपये की बहुमूल्य धातुएं थीं। भारत पूरी दुनिया में ई-कचरा पैदा करने के मामले में तीसरे नंबर पर है। वर्ष 2021 से 2022 तक भारत में 16 लाख टन ई-कचरा पैदा हुआ था। वर्ष 2030 तक भारत में 1.4 करोड़ टन ई-कचरा होने का अनुमान है। हालांकि भारत ने इससे निपटने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। देश में नई स्क्रैप पॉलिसी के तहत सरकार ने वर्ष 2022 में मोबाइल फोन, लैपटॉप, फ्रिज, टीवी, एसी समेत 134 इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उपयोग की अंतिम तिथि (एक्सपायरी डेट) तय कर दी। इसके बाद इनका उपयोग बंद करना होगा।

Special arrangements by Amar Ujala

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेन्ट्स प्रा.लि. के लिए मुद्रक, प्रकाशक समीर माहेश्वरी द्वारा नवभारत प्रेस, नवभारत भवन, प्रेस कॉम्प्लेक्स, जी.ई.रोड, रायपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। प्रधान संपादक : समीर माहेश्वरी, संपादक : राजेश आर. जोशी* (पी.आर.बी. कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिये जिम्मेदार)
■ रायपुर फोन : 0771-4343434, 2535555-66-77, ■ भुवनेश्वर : 0674-2380511/2380518 ■ बिलासपुर : 07752-230591, 407748, 224563 ■ वर्ष 65 ■ अंक 76 (रजि.नं. 13045/59 आरएनआई), पो. रजिस्टर्ड नं. छ.ग./रायपुर संभाग/61/2022-24 ■ भिलाई फोन : (0788) 2294181, 4030655

हमारा शरीर क्षण भगुर है। इस पर स्थिर शरीर से हम जितना शुभ कार्य करें, उतना अच्छा है। जिस प्राणी के जीवन का ध्येय ही सेवा है उस के लिए अभिशाप कुछ भी नही, सब वरदान है। -अज्ञात

लोकतंत्र के लिए खतरा है 'वोट जिहाद'

लोकसभा चुनाव की गर्मी में कई लोगों की सच्चाई बाहर आती दिख रही है। झूठे आरोप-प्रत्यारोप से लेकर राजनीति के लिए धर्म और संप्रदाय की सांगठनिक क्षमता का किस प्रकार लाभ लिया जा रहा है, यह आम लोगों के लिए समझने योग्य है। मुस्लिम समुदाय पर अकसर यह आरोप लगता है कि वह रणनीतिक मतदान करता है। कुछ खास लोगों के प्रभाव में और उनके संकेत पर एक ही पार्टी के पक्ष में मतदान किया जाता है। इसलिए मुस्लिम समुदाय कांग्रेस सहित कुछ अन्य दलों के लिए 'वोटबैंक' बनकर रह गए। काल्पनिक बातों को भय दिखाकर या सांप्रदायिक विचारों को सहारा लेकर मुस्लिम मतदाताओं को विशेषतौर पर भाजपा के विरुद्ध लामबंद किया जाता है। यही कार्य मारिया आलम खान करते हुए वीडियो में रिकॉर्ड हुई हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद की भतीजी मारिया ने उत्तरप्रदेश के फर्रुखाबाद में चुनाव प्रचार के दौरान वोट जिहाद की अपील की है। वह समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार नवल किशोर शाक्य के लिए समर्थन मांग रही थीं। उन्हें वीडियो में यह कहते हुए सुना जा सकता है कि "वोट जिहाद महत्वपूर्ण है, हम सभी को वोट जिहाद करना चाहिए"। मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोपों में डूबी कांग्रेस की ओर से मारिया के सांप्रदायिक बयान पर अब तक कठोर टिप्पणी नहीं आई है। जरा सोचिए, यदि इसी प्रकार का आह्वान भाजपा के किसी नेता ने हिन्दुओं से किया होता, तब बुद्धिजीवियों की 'चाय की प्याली' में किस प्रकार का उबाल आया होता। लेकिन 'वोट जिहाद' के खुले आह्वान पर सांप्रदायिकता के विरुद्ध स्वयं को योद्धा बताने वाले 'वीर' भी जुबानी खर्च करने में कांप रहे हैं। उनके लड़खड़ाते कदम बताते हैं कि वे सांप्रदायिकता के विरुद्ध नहीं अपितु हिन्दू एकजुटता या हिन्दू मुखरता के विरोधी हैं। अन्यथा इस वीडियो के सामने आने के बाद मारिया आलम खान से लेकर सलमान खुर्शीद, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस तक की जमकर आलोचना की जानी चाहिए थी। उनसे सवाल पूछे जाने चाहिए थे। मजेदार बात यह है कि 'वोट जिहाद' पर अभी चुप्पी साधकर बैठे ये लोग उस समय बहुत वाचाल हो उठेंगे, जब देश का साधारण नागरिक 'वोट जिहाद' की मानसिकता पर प्रश्न उठाना शुरू कर देगा। तब ये इस 'वोट जिहाद' की अवधारणा को फर्जी और हिन्दू संगठनों द्वारा प्रस्तुत की हुई बताने का भरसक प्रयास करेंगे। जबकि मारिया आलम खान ने मुसलमानों की एकमुश्त वोट करने की प्रवृत्ति या फिर एक नये प्रकार के मतदान को 'वोट जिहाद' की संज्ञा दी है। जैसे 'लव जिहाद' शब्द का उपयोग सबसे पहले केरल के उच्च न्यायालय ने किया। कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंदन सहित अन्य नेता भी मानते हैं कि केरल में 'लव जिहाद' एक खतरनाक रूप ले चुका है। लेकिन आज जब 'लव जिहाद' पर चर्चा चलती है तब इसे हिन्दू संगठनों का प्रोपेगेंडा बताकर सच्चाई पर पर्दा डालने का प्रयास किया जाता है। आवश्यकता है कि समय रहते सच को स्वीकार किया जाए। यदि आज 'वोट जिहाद' की मानसिकता को नहीं समझा गया तो आगे चलकर यह भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बड़ा खतरा बन जाएगी। अच्छा होगा कि मुस्लिम समाज के समझदार लोग आगे आएं और 'वोट जिहाद' की मानसिकता का विरोध करें। याद रखें कि वोट जिहाद की अपील इसलिए भी की जा रही है क्योंकि दो चरणों में मतदान का प्रतिशत कम रहा है। ऐसे में सांप्रदायिक ताकतें मुस्लिम मत प्रतिशत बढ़ाकर परिणाम अपने पक्ष में लाना चाहते हैं। समाज के प्रबुद्ध वर्ग को समझना होगा कि निर्वाचन के प्रति उनकी निष्क्रियता ऐसी ताकतों को जीतने का अवसर दे सकती है। इसलिए लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भूमिका का निर्वहन करें। मतदान अवश्य करें। मतदान की प्रक्रिया में हिस्सा लेकर 'वोट जिहाद' की ताकत को कम किया जा सकता है।

लोकसभा चुनाव की गर्मी में कई लोगों की सच्चाई बाहर आती दिख रही है। झूठे आरोप-प्रत्यारोप से लेकर राजनीति के लिए धर्म और संप्रदाय की सांगठनिक क्षमता का किस प्रकार लाभ लिया जा रहा है, यह आम लोगों के लिए समझने योग्य है। मुस्लिम समुदाय पर अकसर यह आरोप लगता है कि वह रणनीतिक मतदान करता है। कुछ खास लोगों के प्रभाव में और उनके संकेत पर एक ही पार्टी के पक्ष में मतदान किया जाता है।

अमृत कलश

गुरु कृपा और साधना

चूंकि गुरु प्रत्यक्ष हैं, इसलिए साधक उन्हें मनुष्य मानकर, उनके वचनों को वाक्य मानकर और उनकी कृपा को स्वभाव मानकर प्रायः अवज्ञा भी कर देता है। जबकि सबसे कठिन साधना और सबसे सरल साधन यही है कि जो प्रत्यक्ष उपलब्ध है उसी में अप्रत्यक्ष, निर्गुण तत्व को शिरोधार्य किया जाए। इससे ज्ञान और भक्ति की एकरूपता अनायास ही सिद्ध हो जाती है। गुरु का स्मरण करके एकाग्र हुआ जा सकता है। वाणी की साधना गुरु की स्तुति करके करनी चाहिए। गुरु को नमन करके विनम्रता का अभ्यास करना चाहिए। उनके गुणों को गीत बनाकर उन्हीं के गुणों का गायन करने से ब्रह्म रूप अगुण और भगवान रूप सगुण की साधना में दिव्यता आ जाती है। जलेबी में मिठास और शक्कर अलग-अलग नहीं होते। मिठास शक्कर को ही सिद्ध करती है। उसी तरह गुरु में अगुण एवं सगुण दोनों परिव्याप्त होता है। हम अपनी मान्यताओं और अपेक्षाओं के वशीभूत होने के कारण गुरु के सगुण स्वरूप में भेद रहित व्यावहारिक रूप में दिखाई देने वाली भिन्नता में भेदभाव मानकर गुरु से ही विभक्त हो जाते हैं, लिहाजा न तो हम सगुणोपासना कर पाते हैं और न ही निर्गुण की उपासना कर पाते हैं।

साधक के अंतःकरण में किसी वस्तु को कठिनाई और पुरुषार्थ से प्राप्त करने पर उसका अहंकार ही तुष्ट होता है कि मैंने कितनी मेहनत और अपने बल पर यह उपलब्धि प्राप्त की है। इसी कारण वह सहजता एवं सरलता से उपलब्धि ACT तात्विक नहीं मान पाता । साधक ऐसी स्थिति में प्रलोभनों में पड़कर सांसारिक वस्तुओं को ही जीवन का चरम लक्ष्य मानकर भटक जाता है। जबकि साधना उस ईश्वर के लिए ही की जाती है कि जो हमें प्राप्त तो है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा । भक्ति का फल भक्ति है, ज्ञान का फल ज्ञान है और दोनों को प्राप्त करने के लिए किए जा रहे प्रयास का नाम कर्म या साधना है। यही गुरु कृपा है।

-स्वामी मैथिलीशरण

बोध कथा

देवगुरु और देवराज

मध्यप्रदेश जब राज्य बना तब प्रश्न उठा कि किस नेता को प्रथम मुख्यमंत्री पद की बागडोर सौंपी जाये? किसी एक नाम पर सर्वसम्मति नहीं बनी। तीन नाम उभर कर सामने आये- पहला पंडित माखनलाल चतुर्वेदी, दूसरा पंडित रविशंकर शुक्ल और तीसरा पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा। कागज़ के तीन टुकड़ों पर ये नाम अलग-अलग लिखे गए। तीनों पुड़ियां आपस में खूब फेंटी गयी, फिर एक पुड़िया निकाली गयी जिस पर पंडित माखनलाल चतुर्वेदी का नाम अंकित था। इस प्रकार तय पाया गया कि वे नवगठित मध्यप्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री होंगे। तत्कालीन दिग्गज नेता माखनलाल जी के पास दौड़ पड़े। सबने उन्हें इस बात की सूचना और बधाई भी दी कि अब आपको मुख्यमंत्री के पद का कार्यभार संभालना है। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी ने सबको लगभग डांटते हुए कहा कि मैं पहले से ही शिक्षक और साहित्यकार होने के नाते 'देवगुरु' के आसन पर बैठा हूं। मेरी पदावनति करके तुम लोग मुझे 'देवराज' के पद पर बैठाना चाहते हो जो मुझे पूरी तरह अस्वीकार्य है। उनकी इस असहमति के बाद रविशंकर शुक्ल को नवगठित प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया।

विपक्ष और उसका गठजोड़ मोदी सरकार को कितनी चुनौती दे पाएगा, 4 जून को स्पष्ट हो जाएगा

क्या बिखरा विपक्ष, मोदी सरकार का विकल्प बन सकता है?

बलबीर पुंज
'ट्रिस्ट विद अयोध्या: डिकोलोनाइजेशन ऑफ इंडिया' के लेखक

आई.एन.डी.आई गठबंधन, भाजपा नीत एन.डी.ए. को सशक्त और मजबूत टक्कर देने की स्थिति में है? विरोधी गठजोड़ में सबसे बड़ा दल- कांग्रेस है, जिसका अपना घर ही संभला हुआ लग नहीं रहा है। 18वें लोकसभा निर्वाचन में अभी तक बिना चुनाव लड़े कांग्रेस अपने कुप्रबंधन के कारण- सूरत (गुजरात) और इंदौर (मध्यप्रदेश) सीटों को गवां चुकी है।

क्या आई.एन.डी.आई गठबंधन, भाजपा नीत एन.डी.ए. को सशक्त और मजबूत टक्कर देने की स्थिति में है? विरोधी गठजोड़ में सबसे बड़ा दल- कांग्रेस है, जिसका अपना घर ही संभला हुआ लग नहीं रहा है। 18वें लोकसभा निर्वाचन में अभी तक बिना चुनाव लड़े कांग्रेस अपने कुप्रबंधन के कारण- सूरत (गुजरात) और इंदौर (मध्यप्रदेश) सीटों को गवां चुकी है। कांग्रेस सहित अन्य विरोधी इसे भाजपा द्वारा 'लोकतंत्र की हत्या' बता रहे है। सच तो यह है कि इस बार कई प्रत्याक्षियों को कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। नामांकन वापस लेने के अतिरिक्त पार्टी के कुछ उम्मीदवार अपने टिकट तक वापस कर चुके है। दिलचस्प बात तो यह है कि आई.एन.डी.आई गठबंधन के अन्य घटक भी अपने सबसे बड़े सहयोगी पार्टी कांग्रेस की आफत बढ़ा रहे है। केरल में वामपंथी दल, प.बंगाल में तृणमूल द्वारा कांग्रेस को सीधी चुनौती- इसका प्रमाण है। इस पूरे प्रकरण में दिल्ली और पंजाब का मामला बहुत ही रोचक है।

दिल्ली में अरविंदर सिंह लवली ने प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पद से यह कहते हुए इस्तीफा दे दिया कि आम आदमी पार्टी ('आप') के साथ पार्टी का गठबंधन गलत है। कांग्रेस के दो और पूर्व विधायक भी इसी प्रकार की आपत्ति जताकर पार्टी छोड़ चुके है। कांग्रेस का अंतर्कलह भी एक बार फिर सड़क पर है। पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी लवली को विश्वासघाती कह रहे है। वही लवली की आलोचना करने पर कांग्रेस के पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद के साथ लवली समर्थकों ने धक्का-मुक्की कर दी।

वास्तव में, कांग्रेस और 'आप' का एक साथ आना विरोधाभास का परिचायक है। मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा आदि राज्यों में कांग्रेस का सीधा भाजपा से मुकाबला है। परंतु कई राज्य है, जहां कांग्रेस ने उन्हीं दलों के साथ गठजोड़ किया है, जिन्होंने उसके जनाधार में सेंध लगाकर ही अपना राजनीतिक अस्तित्व बनाया है-सपा, डीएमके, आरजेडी आदि इसके उदाहरण है। ऐसे ही दलों में से एक- 'आप' भी है, जिसने दिल्ली में 2015 से न केवल उसे विधानसभा की तालिका में शून्य पर पहुंचा दिया, साथ ही पंजाब और गुजरात के चुनावों में भारी क्षति पहुंचाई है।

'आप'-कांग्रेस का दिल्ली के अतिरिक्त गुजरात, हरियाणा, गोवा और चंडीगढ़ में भी 'गठबंधन' है। परंतु दोनों पार्टियों के बीच राजनीतिक प्रतिस्पर्धा कैसी है, यह पंजाब की राजनीति से स्पष्ट है। गत दिनों पंजाब विधानसभा के सत्र में मुख्यमंत्री भगवंत मान और कांग्रेसी नेता-प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा न केवल एक-दूसरे से तू-तड़ाक पर उतर आए थे, साथ ही दोनों पार्टियों के विधायकों के बीच हाथापाई की नौबत तक पहुंच गई थी। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, परंतु बाजवा का दावा है कि मुख्यमंत्री मान ने अपने पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल की आबकारी घोटाले में गिरफ्तारी के बाद जश्न मनाया था।

दिल्ली में गठबंधन होने के बाद भी कांग्रेस-'आप' में सब ठीक नहीं है। यहां लवली के त्यागपत्र और अन्य नेताओं के पार्टी छोड़ने से पहले 'आप' ने अपने प्रचार अभियान को अपने कोटे की चार सीटों तक ही सीमित रखा हुआ है। आखिर इतनी कटुता होने के बाद भी दोनों दल दिल्ली में गठबंधन करने को क्यों विवश हुए? इसका उत्तर 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजों में मिलता है, जिसमें भाजपा सभी सात सीटें प्रचंड बहुमत के साथ जीतने में सफल रही थी। तब भाजपा के खिलाफ दिल्ली में कांग्रेस और 'आप' ने अलग-अलग चुनाव लड़ा था। वर्ष 2014 में भाजपा को 46 प्रतिशत, तो 2019 में 57 प्रतिशत मत प्राप्त हुए थे। कांग्रेस-'आप' के शीर्ष नेतृत्व को आशंका थी कि यदि इस बार भी वे अलग-अलग लड़े, तो इससे भाजपा को ही लाभ मिलेगा। ऐसा ही अस्वाभाविक गठजोड़ वर्ष 2013 में तब भी देखने को मिला थी, जब 'आप' ने अपनी धुर-विरोधी कांग्रेस के साथ मिलकर दिल्ली में सरकर बनाई थी, जो मात्र 49 दिन में ही बिखर गई। वास्तव में, पंजाब को छोड़कर कांग्रेस और 'आप' का अस्वाभाविक गठजोड़ का एकमात्र उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कैसे भी सत्ता से हटाना है। क्या वर्तमान परिप्रेक्ष्य में नकारात्मक राजनीति का कोई स्थान है?

कांग्रेस जहां अपनी मौलिक गांधीवादी राष्ट्रवादी-सनातन विचारधारा को तिलांजलि देकर वामपंथ को आत्मसात कर चुकी है, वही वर्ष 2011-12 में गांधीवादी अन्ना हजारे द्वारा प्रदत्त भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के गर्भ से 'आप' का उदय हुआ है, जो दिल्ली में गांधीवादी सिद्धांतों के प्रतिकूल जाकर शराब आपूर्ति को सुलभ और सस्ता बनाने का भरसक प्रयास कर चुकी है, जिसमें अब उसके शीर्ष नेताओं पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप है। कुछ वर्ष पहले केजरीवाल कई राजनीतिज्ञों का इस्तीफा मात्र एक आरोप पर मांग लिया करते थे। उन्हें वंशवाद आदि मुद्दों पर पानी पी-पीकर कोसते थे। वही केजरीवाल आज न केवल उन्हीं नेताओं में अपना सहयोगी ढूंढते है, पार्टी के समर्पित नेताओं के स्थान पर अपनी पत्नी को आगे करके वंशवाद प्रेरित राजनीति को आगे बढ़ाते है और जेल में बंद होने व न्यायालय की सख्त टिप्पणियों के बाद भी मुख्यमंत्री पद को नहीं छोड़ते है। यह विडंबना नहीं है, तो क्या है?

जब 'आप' का जन्म हुआ, तब उसके नेताओं ने दावा किया कि वे राजनीतिक शुचिता, नैतिकता, ईमानदारी के नए आयाम गढ़ेंगे और सुविधाओं से युक्त सरकारी आवास, सरकारी वाहन आदि नहीं लेंगे। परंतु यह सब छलावा निकला। न केवल अन्य राजनीतिक दलों की भांति आप के मंत्रियों-विधायकों ने सरकारी आवास, वाहन-सुविधा और सुरक्षा आदि को अंगीकार किया, साथ ही बतौर मुख्यमंत्री, केजरीवाल ने अपने सरकारी आवास के विलासी नवीनीकरण पर लगभग 45 करोड़ रुपये व्यय होने पर गुरेज भी नहीं किया। इतना ही नहीं, बकौल आरोप, दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत को आवंटित सरकारी आवास पर उस गैर-राजनीतिक विजय नायर को रहने की छूट दे दी गई, जो दिल्ली आबकारी नीति घोटाले का आरोपी भी है। अब इस प्रकार के विरोधाभासों से भरा वर्तमान विपक्ष और उसका गठजोड़ मोदी सरकार को कितनी चुनौती दे पाएगा, यह 4 जून को मतगणना के बाद स्पष्ट हो जाएगा।

यह लेखक के निजी विचार है

चुनावी राजनीति में जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को लिया जाना चाहिए

जलवायु परिवर्तन और भारतीय चुनाव

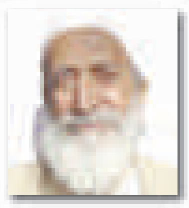

कुलभूषण उपमन्यु
जल-जंगल-जमीन के मुद्दों के पैरोकार

संयुक्त राष्ट्र संघ की विश्व मौसम विज्ञान संस्था ने एशिया में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों पर एक रिपोर्ट गत सप्ताह जारी की है, जिसमें यह बात सामने आई है कि वैश्विक तापमान वृद्धि का प्रभाव एशिया में विश्व औसत से ज्यादा पड़ रहा है। इस क्षेत्र में कई देशों में आज तक का अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है, जिसके कारण इस महाद्वीप में 2023 में 90 लाख लोग बाढ़ और तूफान से प्रभावित हुए। दो हजार लोग काल का ग्रास बन गए। जलवायु परिवर्तन ने बाढ़, सूखे और तूफानों की घटनाओं को न केवल बढ़ाया है बल्कि उनकी भयानकता को भी बढ़ाया है, जिसका दुष्प्रभाव वहां के समाज, अर्थ व्यवस्था, और मानव जीवन पर पड़ा है।

जलवायु परिवर्तन के मुख्य सूचकों जैसे कि जमीनी तापमान में वृद्धि, ग्लेशियरों का पिघलना, और समुद्र के जलस्तर के बढ़ने से बिगड़ती हुई स्थिति का पता चल रहा है। 1960-1990 के दौर के मुकाबले तापमान वृद्धि की दर लगभग दुगुनी हो गई है। 2023 में जहां एक ओर सूखा पड़ा वहीं दूसरी ओर भयानक बाढ़ आई। चीन की बाढ़ और भारत में सूखे से 65 बिलियन डॉलर का आर्थिक नुकसान होने का अनुमान लगाया गया है। चीन में 140 वर्षों का वर्षा का रिकार्ड टूट गया।

वहीं दक्षिण पश्चिमी चीन भारी सूखे की चपेट में रहा। भारत में लू के कारण 100 लोगों की मौत हो गई और सिक्किम का तीस्ता-3 बांध बाढ़ की चपेट में आकर ध्वस्त हो गया और 100 लोग अपनी जान गंवा बैठे। बढ़ते तापमान के कारण इस तरह की घटनाओं के बढ़ने की संभावना है। भारत और बांग्लादेश में लू की संभावनाओं में 30 गुणा वृद्धि की आशंका पैदा हो गई। एशिया के तेज गति से बढ़ते तापमान के चलते इसके ग्लेशियर भी खतरे में पड़ गए हैं। मुख्य 22 ग्लेशियरों में से 20 में भारी नकारात्मक बदलाव पाए गए हैं। यानी ग्लेशियरों के पिघलने की गति तेज हुई है। तापमान वृद्धि से समुद्र का जल भी ज्यादा गर्म हो रहा है जिसके कारण भारी बारिश और समुद्री तूफानों का खतरा बढ़ा है। पिछले चार दशकों में अरब सागर में समुद्री तूफानों की संख्या में डेढ़ गुणा वृद्धि हुई है और तूफानों की घातकता भी बढ़ी है।

जुलाई और अगस्त 2023 में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण भूस्खलन के कारण हुई भारी तबाही का भी रिपोर्ट में जिक्र किया गया है ,जिसको भारत सरकार ने आपात स्थिति घोषित किया। इन स्थितियों से निपटने के लिए आपदा प्रबन्धन के विषय में भी काफी कुछ करने की जरूरत पर रिपोर्ट में प्रकाश डाला गया है। हालांकि भारत ने इस विषय में

कुछ मानकों पर अच्छी प्रगति की है फिर भी काफी कुछ किए जाने की जरूरत है। पूर्व चेतावनी व्यवस्था में सुधार करके आपदाओं में होने वाली हानि को 30 प्रतिशत तक कम किया जा सकता है।

रिपोर्ट में आर्थिक असमानता के चलते जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के और ज्यादा चिंताजनक होने की बात कही गई है। जाहिर है कि बढ़ते तापमान का प्रत्यक्ष डंक उन गरीब लोगों को भुगतना पड़ता है जिनके पास आवास की व्यवस्था नहीं है, या जिन्हें दैनिक मजदूरी पर निर्भर रहना पड़ता है, या वह किसान जिनकी फसल खुले में में ईश्वर भरोसे रहती है। उनके लिए जलवायु अनुकूलन व्यवस्था खड़ी करना भी संभव नहीं होता। बढ़ते तापमान से फसलों की उत्पादकता पर भी विपरीत प्रभाव पड़ने के कारण खाद्य सुरक्षा पर भी खतरा पैदा होने की संभावना बन सकती है।

पिछले 15 वर्ष में भारत में 3 लाख हेक्टेयर वन भूमि का उपयोग इस तरह की बृहदाकार योजनाओं के लिए बदला जा चुका है और यह क्रम सतत रूप से जारी है। इतनी चिंताजनक स्थिति के बावजूद वर्तमान आम चुनाव में यह मुद्दा जनता के बीच महत्वपूर्ण नहीं बन सका है। पर्यावरण से जुड़े दिवसों पर चेतना रैली निकालने, कुछ अच्छे नारे लगाने, भाषण प्रतियोगिता आयोजित करने, या ज्यादा से ज्यादा चुनाव मैनिफेस्टो में पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से जुड़े वादे उछालने तक हम सीमित होते जा रहे हैं। राजनीतिक दल भी जन चेतना जगाने के इस मौके का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं।

आम मतदाता निजी आर्थिक लाभ से ज्यादा सोचने को तैयार नहीं है। इस लिए राजनीतिक दल भी इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लेते हैं। हिमालय के नाजुक परिस्थिति संतुलन के दृष्टिगत यह मामला हिमालय में और भी ज्यादा संगीन हो जाता है। किन्तु हम प्राकृतिक आपदा का बहाना गढ़कर आत्मसंतुष्टि कर लेते हैं या खुद को धोखा देते रहते हैं। जबकि हम सब समझते हैं कि जलवायु परिवर्तन मानव निर्मित गलतियों का नतीजा है। फिर भी हम न तो आत्मसंयम से अनावश्यक वस्तुओं, पदार्थों के उपयोग से बचना चाहते हैं न ही सरकारों के सामने अपनी पर्यावरण विषयक चिंताओं को रख कर दबाव बना कर नीतिगत बदलाव की मांग रखना चाहते हैं। सरकारें अपने आप विकास को सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर से नाप कर आगे बढ़ती हैं उन्हें पर्यावरण जैसे मुद्दे उतने लुभावने नहीं लगते। दुनिया भर में सरकारें जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर टालमटोल करते हुए, शर्माते हुए कुछ थोड़ा बहुत कार्य करती रहती हैं। कुछ गंभीरता जब आपदाएं आती हैं तब दिखाई देती है। धीरे-धीरे प्रकृति के ऊपर दोषारोपण करके समस्या भूल जाते हैं।

इस बार कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने ही इस मुद्दे पर कुछ लक्ष्य अपने चुनाव घोषणा पत्र में रखे हैं। किन्तु पिछले अनुभव के आधार पर ज्यादा आशा नहीं जगती है। शिमला में 2009 में जलवायु कॉन्क्लेव हुआ था, उसके साथ ही हिमालयी परिस्थिति तंत्र को बचाने के लिए कुछ लक्ष्य तय किए गए थे। किन्तु दोनों प्रमुख दलों को पर्याप्त समय मिलने के बावजूद विशेष प्रगति इस दिशा में नहीं हो सकी। वैश्विक स्तर और हिमालय के स्तर पर जलवायु परिवर्तन की चुनौती के कारण बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं के चलते अब समय आ गया है जब कि इस मुद्दे पर आम जनता और राजनीतिक दलों को चुनावी राजनीति के केंद्र में जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण के मुद्दे को लिया जाना चाहिए, ताकि सरकार गठन के बाद इस मुद्दे पर समुचित कार्य किया जा सके और सरकारों की जवाबदेही भी तय हो।

समय बोध

आखिर क्यों दहक रहे हैं पहाड़ के जंगल?

अभिषेक कुमार सिंह
विज्ञान लेखक

मशहूर पर्यटन स्थल नैनीताल आग से घिरा हुआ हैयहां वायुसेना के हेलिकॉप्टर आग बुझा रहे हैंबीते साल (2023 में) उत्तराखंड के जंगलों में आग लगने की 85 घटनाएं हुई थीं

चार-पांच साल पहले 2019-20 में जब ब्राजील के अमेजन जंगलों में आग उतरी थी, तो पूरी दुनिया में मानो हाहाकार मच गया था। कहा जाने लगा था कि जो जंगल दुनिया की 20 फीसदी ऑक्सीजन पैदा करते हैं, उनका यूं झुलसना तमाम अनहोनियों की आहट है। अमेजन की आग आखिर बुझ गई। बात आई-गई हो गई. लेकिन हमारे देश में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय इलाकों के जंगल हर साल झुलसते हैं। इस साल भी उत्तराखंड के गढ़वाल-कुमाऊं के जंगल विनाशक आग से झुलस रहे हैं।

लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं है।

पता चला है कि मशहूर पर्यटन स्थल नैनीताल आग से घिरा हुआ है। यहां वायुसेना के हेलिकॉप्टर आग बुझा रहे हैं। लेकिन बुझने के बाद आग फिर लग जाती है। इस बार उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल में पौड़ी, रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी, देहरादून और कुमाऊं मंडल में नैनीताल के अलावा बागेश्वर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और चंपावत जिले के जंगल आग की लपटों में घिरे हुए हैं। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक बीते साल (2023 में) उत्तराखंड के जंगलों में आग लगने की 85 घटनाएं हुई थीं, जबकि इस बार आग लगने की घटनाओं में 300 प्रतिशत का इजाफा हुआ है।

उत्तराखंड में 38 हजार वर्ग किमी में जंगल (फॉरेस्ट एरिया) है जो इस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 71 फीसदी हिस्सा है। ऐसे में यहां आग में घिरे जंगल बड़ी चुनौती बन जाते हैं।

वनक्षेत्रों में लगी आग को बुझाना आसान नहीं होता क्योंकि इससे पैदा होने वाले धुएं के कारण दृश्यता (विजिबिलिटी) बेहद कम हो जाती है, इसलिए हेलिकॉप्टरों के जरिये विशाल बाल्टियों से पानी लाकर उसे बुझाने की कोशिश करना बेहद जोखिम वाला काम बन जाता है। वैसे तो ऐसी हर जगह, जहां मानसून और सर्दियों में बारिश होती है और गर्मियों में सूखा मौसम रहता है, वहां आग लगती रहती है। बारिश की वजह से पेड़-पौधे खूब बढ़ जाते हैं। गर्मियों में झाड़ियां और घास-फूस सूखकर आग लगने का माहौल तैयार कर देते हैं। प्राकृतिक रूप से जंगलों में लगने वाली आग से वहां के पेड़-पौधों को निपटने का तरीका मालूम है। कहीं पेड़ों की मोटी छाल बचाव का काम करती हैं तो कहीं आग के बाद जंगल को फिर से फलने-फूलने का हुनर आता है।

आरक्षण की चुनावी आग

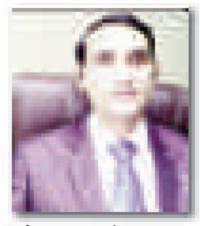

प्रो. डॉ. विवेक सिंह

चुनाव कोई भी हो आरक्षण एक ज्वलंत चुनावी मुद्दे के रूप में अवश्य सामने होता है। इस चुनाव में भी आरक्षण के मुद्दे पर सत्तापक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर चुनावी वार और पलटवार कर रहे हैं। विपक्षी पार्टियां जहां यह कह रही हैं कि यदि बीजेपी सत्ता में पुनः स्थापित होती है तो आरक्षण खत्म कर देगी वहीं बीजेपी इस बात से साफ इन्कार कर रही है। राहुल गांधी आरक्षण की सीमा को 50% के पार ले जाने की चुनावी वादे कर रहे हैं ।

आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है जिस पर आजादी के बाद से ही बहस हो रही है। किसी भी मुद्दे पर चर्चा होने से उसे अधिक गहराई से समझा जा सकता है। ऐसा कोई सामाजिक वर्ग नहीं है जिस पर आरक्षण का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव ना पड़ता हो। वर्तमान समय में छिड़ी आरक्षण पर बहस को सकारात्मकता के साथ देखना चाहिए।

संविधान में आरक्षण की व्यवस्था अनिश्चित समय के लिए नहीं किया गया था अतः आरक्षण की समीक्षा समय समय पर होनी ही चाहिए। संविधान की भावना यह कभी नहीं थी कि आरक्षण जाति के आधार पर दिया जाए बल्कि आरक्षण देने का आधार सामाजिक और शैक्षणिक बराबरी था। आरक्षण का प्रावधान 10 साल के लिए था और संविधान निर्माता भी इस पक्ष में थे कि आरक्षण व्यवस्था ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलना चाहिए। आरक्षण की व्यवस्था पिछले 75 वर्षों से लगातार चल रही है और अगर ऐसी ही राजनीति चलती रही तो अगले 75 वर्षों तक अनवरत चलती रहेगी। आरक्षण का लाभ एक वर्ग विशेष लगातार ले रहा है, जिनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी उन्हें इस आरक्षण व्यवस्था का अभी तक ज्यादा लाभ नहीं मिला है।

आरक्षण जाति पर आधारित है। आरक्षण जाति व्यवस्था को और समृद्ध कर रही है। आरक्षण का अधिकार जाति और धर्म के स्थान पर आर्थिक आधार होना चाहिए क्योंकि गरीबी जाति को देखकर नहीं आती है। गरीबी जाति विशेष या वर्ग विशेष की नहीं होती है, गरीबी बस गरीबी होती है। आजादी के इतने वर्षों के बाद यह सोच कि गरीबी जाति विशेष में है, भ्रामक और तर्कों से परे है। 1947 का भारत और भारतीय समाज 2024 से बिल्कुल अलग था। आरक्षण की वर्तमान स्थिति की समीक्षा के उपरांत ही इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि इसे जारी रखना चाहिए या नहीं।

आरक्षण की व्यवस्था पिछड़ों को सामाजिक बराबरी के लिए थी ना की चुनावी अखाड़े के लिए एक मुद्दे के रूप में। भारत में आरक्षण एक राजनीतिक विवशता है। जातिगत समीकरण को साधे बिना चुनावी वैतरणी पार करना लगभग असंभव है। आजादी के इस अमृत काल में आरक्षण की वर्तमान स्थिति और इसकी प्रासंगिकता जानना आवश्यक है।

आरक्षण कोई मूलभूत अधिकार नहीं है, उद्देश्य की पूर्ति के उपरांत या अप्रासंगिक होने की स्थिति में संविधान में संशोधन करके आरक्षण को आसानी से हटाया जा सकता है। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में यह बात उठी थी कि जिन जातियों या लोगों को आरक्षण का फायदा मिल चुका है उनको आरक्षण छोड़ देना चाहिए। यह विमर्श का विषय होना चाहिए कि आईएएस, आईपीएस या अन्य बड़े सरकारी या गैर सरकारी पद पर पहुंच जाने के बावजूद, आरक्षण का फायदा ले चुके लोगों द्वारा अपने बच्चों के लिए भी आरक्षण का फायदा लेते रहना कितना उचित है।

आरक्षण की व्यवस्था पिछड़ों को सामाजिक बराबरी के लिए थी ना की चुनावी अखाड़े के लिए एक मुद्दे के रूप में। भारत में आरक्षण एक राजनीतिक विवशता है। जातिगत समीकरण को साधे बिना चुनावी वैतरणी पार करना लगभग असंभव है। आजादी के इस अमृत काल में आरक्षण की वर्तमान स्थिति और इसकी प्रासंगिकता जानना आवश्यक है। आरक्षण की वृहद समीक्षा जितनी जल्दी हो उतना ही देश और सर्व समाज के लिए अच्छा होगा।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

त्रूदो की रणनीति

खालिस्तानियों को समर्थन

कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन त्रूदो की टोरंटो में एक आयोजन में उपस्थिति के समय खालिस्तान-समर्थक नारे लगाए गए। भारत ने इस घटना का विरोध किया है। इस बार टोरंटो में हुए एक आयोजन में खालिस्तान-समर्थक नारेबाजी ने भारत और कनाडा के बीच राजनयिक तनाव पैदा कर दिया है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन त्रूदो भी इस आयोजन में उपस्थित थे, जिससे लगता है कि कनाडा सरकार ने इस कृत्य को स्वीकृति दी है। घटना के बाद कनाडा सरकार की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। इसके बाद भारत ने नई दिल्ली में कनाडा के राजनयिक को तलब कर इस घटना पर अपनी घोर असहमति दर्ज कराई। सांस्कृतिक विविधता तथा समावेशन को प्रोत्साहित करने वाले इस आयोजन में अचानक कुछ लोग 'अलगाववादी आंदोलन' खालिस्तान के समर्थन में नारे लगाने लगे। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना ने विभिन्न मुद्दों पर दोनों देशों के बीच जारी वार्ता को नुकसान पहुंचाया है। भारत के लिए यह घटना संवेदनशील है क्योंकि वह खालिस्तान आंदोलन को अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए खतरा मानता है। भारतीय अधिकारी खासकर राष्ट्राध्यक्षों की उपस्थिति में 'खालिस्तान-समर्थन' के किसी प्रदर्शन को बहुत गंभीरता से लेते हैं। इसलिए भारत सरकार ने बिना कोई समय गंवाये कनाडाई अधिकारियों से अपने सरोकारों का साझा किया। कनाडाई राजनयिक को तलब करना भारत की अप्रसन्नता का स्पष्ट संकेत है और इससे मामले की गंभीरता का पता चलता है। इस बीच कनाडा में हुई इस घटना ने 'अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता' की सीमा तथा ऐसी घटनाओं के राजनयिक संबंधों पर प्रभावों के बारे में चर्चा छेड़ दी है।

भले ही कनाडा स्वतंत्र भाषण एवं समागम के सिद्धान्तों का सम्मान करता हो,

पर उसकी धरती पर उसके प्रधानमंत्री की उपस्थिति में खालिस्तान-समर्थक नारेबाजी खासकर राजनयिक संदर्भ में ऐसी कार्रवाइयों के औचित्य पर सवाल उठाती है। बहु-सांस्कृतिकता तथा विविधता के पैरोकार त्रूदो ने अब तक इस घटना पर कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं की है। लेकिन उम्मीद है कि वे राजनयिक प्रभावों तथा भारत के साथ रचनात्मक संबंध बनाए रखने के महत्व पर गौर करते हुए उचित समय पर इस मुद्दे को संबोधित करेंगे। कनाडा में खालिस्तानियों की जड़ों को देखते हुए ऐसी किसी घटना की संभावना का अनुमान पहले से ही था। ऐसे में कनाडा के प्रधानमंत्री को पहले से ही सुनिश्चित करना चाहिए था कि ऐसी घटना न हो जिससे सरकार की छवि खराब हो तथा भारत के साथ संबंधों में तनाव पैदा हो। वास्तव में अपनी धरती पर खालिस्तानियों का 'तुष्टीकरण' कनाडा के लिए भी समस्या पैदा कर सकता है क्योंकि इतिहास स्वयं को दुहराता है तथा ऐसे तत्वों को शरण देने वाली सरकारों को इसका भारी खामियाजा भुगतना पड़ा है। यह घटना खासकर संवेदनशील भू-राजनीतिक मुद्दों पर अनिवासी राजनीति के प्रबंधन की जटिलता भी रेखांकित करती है। कनाडा में सिखों की बड़ी संख्या है जिनमें से अनेक के भारत के साथ मजबूत संबंध हैं और 'खालिस्तान आंदोलन' के बारे में उनके विचार अलग-अलग हैं। कुल मिला कर टोरंटो घटना विश्व राजनीति के परस्पर जुड़ाव तथा संप्रभुता, एकता व विविध दृष्टिकोणों के बीच सम्मान के सिद्धान्तों की सुरक्षा में सतर्कता को प्रकट करती है। यह घटना इस बात की भी याद दिलाती है कि परस्पर निर्भर एवं आपस में पूरी तरह जुड़ी दुनिया के एक कोने में बोले गए शब्द या की गई कार्रवाइयों का पूरी दुनिया पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है और इससे वर्षो तक अंतरराष्ट्रीय संबंध भी प्रभावित होते हैं।

भारत में सेमीकंडक्टर क्रांति

भारत की प्रतिभा, उसके संसाधन तथा ढांचागत संरचना की स्थिति उसे सेमीकंडक्टर क्षेत्र में क्रांति का अवसर देती है। भारत इस क्षेत्र में दुनिया भर में अग्रणी बनने की ओर बढ़ रहा है।

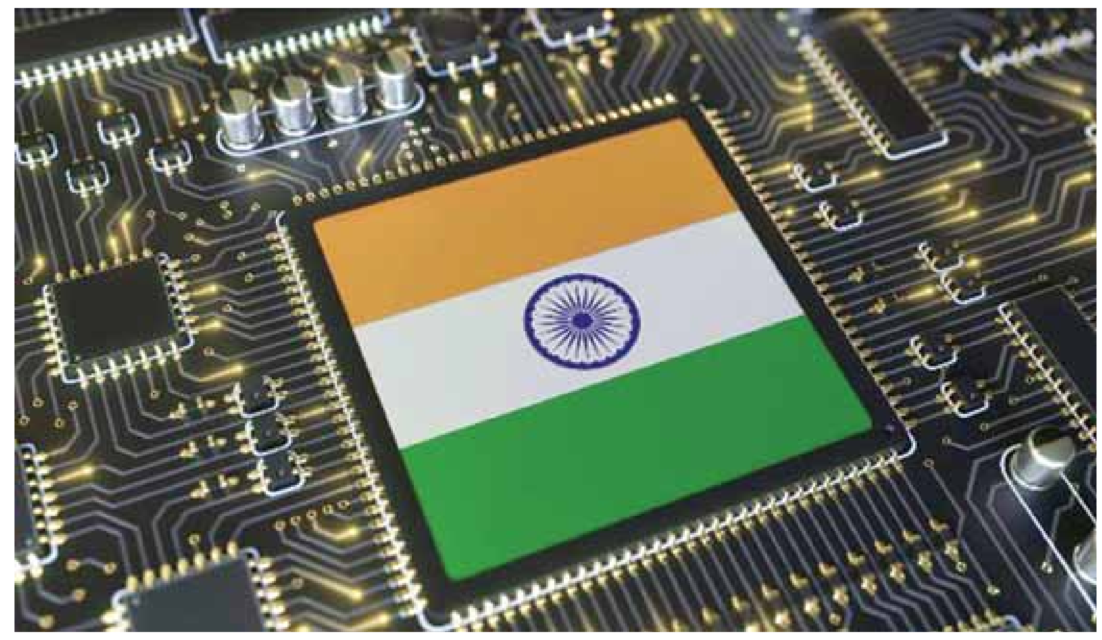

ए.एस. मित्तल
(लेखक, उद्योग जगत से संबद्ध हैं)

वर्तमान समय में हमारा जीवन लगातार तकनीक पर निर्भर होता जा रहा है। ऐसे में सेमीकंडक्टर समाज का आवश्यक आधार बन गए हैं। ये छोटी-छोटी चिपें हमारे एलेक्ट्रानिक उपकरणों, संचार व्यवस्थाओं तथा यहां तक कि कृषि उपकरणों, चिकित्सा उपकरणों व वाहनों के लिए जरूरी हो गई हैं। भारत ने तकनीक में इस 'मौन क्रांति' की सामाजिक-आर्थिक व रणनीतिक संभावनाओं को पहचाना है। वह जीवन्त सेमीकंडक्टर परिस्थितिकी तंत्र तथा इसके लिए प्रशिक्षित कार्यबल के विकास का निर्माण करने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।

भारत का लक्ष्य सेमीकंडक्टर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के साथ विश्व नेता बनने का है। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि सेमीकंडक्टर उद्योग एक मिलियन से अधिक रोजगार सृजित कर सकता है जिसमें सेमीकंडक्टर डिजाइन इंजीनियर, निर्माण इंजीनियर, आरएंडडी वैज्ञानिक, आपरेटर, तकनीकविद तथा चिप डिजाइन व सेमीकंडक्टर फैब्रीकेशन, पैकेजिंग तथा बिक्री सुविधाओं में अगले पांच साल में कुशल कामगार शामिल हैं। नेशनल असोसियेशन आफ साफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज़-नैस्काम तथा जिनोव की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, 'पिछले साल दिसंबर की तिमाही में भारत में स्थापित नए वैश्विक क्षमता केन्द्रों में से लगभग 30 प्रतिशत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में थे। इससे फ्रंट एंड डिजाइन, क्षमता परीक्षण तथा पोस्ट-सिलिकान वैलीडेशन में स्थानीय प्रतिभा के विकास में बढ़ती दिलचस्पी प्रकट होती है।' दुनिया की प्रमुख चिप डिजाइन कंपनियों ने भारत में अपने डिजाइन व आरएंडडी सेंटर स्थापित किए हैं। इनमें इंटेल, टेक्सास इन्स्ट्रूमेंट्स, एमडी, एनविडा और क्वालकाम शामिल हैं।

एएमडी ने हाल ही में बैंगलुरू में अपने सबसे बड़े वैश्विक डिजाइन सेंटर की स्थापना की है। मार्च में 'इंडियाज़ टेकएड: चिप्स फार विकसित भारत' आयोजन में तीन सेमीकंडक्टर परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया जिनमें 1.25 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा।

टाटा एलेक्ट्रानिक्स ने ताइवान की पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्यूफैक्चरिंग कार्पोरेशन-पीएसएमसी के सहयोग से गुजरात के ढोलेरा में देश का पहला सेमीकंडक्टर मैन्यूफैक्चरिंग प्लांट स्थापित किया है जिसमें 91,000 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है। इसके साथ ही उसने असम के मोनगांव में 27,000 करोड़ के निवेश से एक और प्लांट स्थापित किया है जिसमें 2026 में चिपों का उत्पादन शुरू हो जाएगा। अमेरिका के सेमीकंडक्टर निर्माता माइक्रान इंडिया का प्लांट 22,500 करोड़ के निवेश से गुजरात के सानंद में स्थापित किया गया है। उम्मीद है कि यह दिसंबर में पहली 'मेड इन इंडिया' मेमोरी चिप्स का उत्पादन शुरू कर देगा।

चंद्रयान-3 मिशन में योगदान करने वाले सेमीकंडक्टर कार्पोरेशन आफ इंडिया-एससीएल ने मोहाली प्लांट में अपनी चिप सुविधा को अद्यतन बनाने का प्रस्ताव किया है जिस पर 20,000 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। इसके साथ ही उसने इसरो तथा अन्य अंतरिक्ष शोध संगठनों के साथ वैश्विक स्तर पर सहयोग शुरू किया है। सेमीकंडक्टर क्षेत्र में फिलहाल 95 प्रतिशत आयात निर्भरता है। भारत के वर्तमान सेमीकंडक्टर चिप परिस्थितिकी तंत्र की तेज प्रगति के बावजूद भारत अभी अमेरिका, ताइवान, चीन, जापान, मलेशिया, सिंगापुर व दक्षिण कोरिया पर सेमीकंडक्टरों के लिए निर्भर है जहां से लगभग 95 प्रतिशत सेमीकंडक्टरों का आयात होता है। आयात पर यह निर्भरता घटाने के लिए भारत ने सेमीकंडक्टर उद्योग के जीवन्त स्वदेशी रणनीतिक महत्व को स्वीकार किया है। इसने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन-आईएसएम की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत क्षेत्र में नए प्रवेश करने वालों को 50 प्रतिशत पूंजीगत खर्च, उत्पादन आधारित प्रोत्साहन-पीएलआई तथा डिजाइन-आधारित प्रोत्साहन-डीएलआई का प्रस्ताव किया गया है। इसके लिए 76,000 करोड़ रुपये की धनराशि रखी गई है। इसके साथ ही राज्य सरकारों ने भी प्रोत्साहनों, अंतरराष्ट्रीय साझेदारी तथा क्षमता विकास पर ध्यान केन्द्रित किया है। कौशल में कमी को संबोधित करने के लिए एलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय ने अगले पांच वर्षों में चिप डिजाइन में 85,000 से अधिक इंजीनियरों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य बनाया है। इस प्रकार के केन्द्रित प्रयासों से उपयुक्त नीति निर्माण की सहायता से वह परिस्थितिकी तंत्र विकसित करने का इरादा है जो इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर तंत्र तैयार कर सके।

चीन-अमेरिका व्यापार युद्ध के कारण पैदा भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के कारण कंपनियों को चीन के बाहर अपने वैकल्पिक उत्पादन आधार तलाशने पर मजबूर किया है। उद्योग द्वारा स्थान बदलने के इन प्रयासों के कारण भारत और दक्षिणपूर्वी एशियाई देश, जैसे मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम और इंडोनेशिया को भविष्य में सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए पसंद किया जा रहा है। भारत ने इस परिस्थितिकी तंत्र में सही समय पर और रणनीतिक रूप से प्रवेश किया है। यह वैश्विक सप्लाई श्रृंखला में विविधता लाने तथा भारत को सेमीकंडक्टर डिजाइन तथा उत्पादन व तकनीकी विकास में अग्रणी बनाने के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इससे देश के नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर बड़े पैमाने पर विकसित होंगे। भारत में इस उद्योग के विकास की वर्तमान परिस्थितियां बहुत अच्छी हैं।

बैंगलुरू और हैदराबाद भारत में सेमीकंडक्टर वैश्विक क्षमता केन्द्रों-जीसीसी के दो तिहाई को स्थान देते हैं। यह देश में सेमीकंडक्टर जीसीसी का लगभग 55 प्रतिशत है। 95 अन्य जीसीसी इकाइयों तथा 50,000 के कुशल कार्यबल के साथ यह भारत में सेमीकंडक्टर उद्योग के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता का प्रतीक भी है। वर्तमान समय में भारत का सेमीकंडक्टर बाजार लगभग 15 बिलियन डालर है जिसके 2026 तक 55 बिलियन डालर पहुंचने की आशा है। वर्तमान समय में स्मार्टफोन व वियरेबल्स, आटोमोबाइल हिस्से, कंप्यूटर व डेटा स्टोरेज का इस बाजार के 60 प्रतिशत से अधिक हिस्से पर कब्जा है। वास्तव में विभिन्न प्रकार के सेमीकंडक्टरों का उत्पादन एक अत्यधिक जटिल प्रक्रिया है जिसमें सबसे छोटे स्तर पर भी पूर्ण सटीकता जरूरी है। चूंकि वैश्विक स्तर पर चिपों की दुनिया पूरी तरह एक दूसरे से जुड़ी है, इसलिए भारतीय कंपनियों को ताइवान व दक्षिण कोरिया की कंपनियों से सहयोग करने की आवश्यकता है ताकि वे अद्यतन तकनीक तक अपनी पहुंच बना सकें तथा इसका प्रयोग ज्यादा से ज्यादा चिपों में कर सकें। इन क्षेत्रों में आटोमोबाइल मशीनें, स्मार्ट चिकित्सा उपकरण, 6जी तथा उसके बाद के भावी संचार उपकरण तथा सभी प्रकार के एलेक्ट्रानिक्स में एआई शामिल हैं। भारत को इस क्षेत्र में, खासकर उत्कृष्ट चिप डिजाइन व फैब्रीकेशन में उपयुक्त कौशल तैयार करना होगा। वैश्विक सेमीकंडक्टर निर्माण उद्योग में लगभग 2.3 मिलियन अत्यन्त कुशल कामगार हैं जिनमें से लगभग 25 प्रतिशत वरिष्ठ इंजीनियर भारतीय हैं।

इस प्रतिभा को अपने पास बनाए रखने तथा नई प्रतिभा आकर्षित करने के लिए भारतीय कंपनियां ताइवान के चिप निर्माता केन्द्र शिंचू में रोडशो कर रही हैं। संचार एवं आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है, 'अमेरिका से अनेक युवा इंजीनियरों ने भारत लौटने का निर्णय किया है। इसके उलट ताइवान, सिंगापुर और मलेशिया में इस क्षेत्र में काम करने वाले इंजीनियरों की औसत आयु 45 वर्ष है और वे ज्यादा अनुभवी हैं। हमें उम्मीद है कि उनमें से अनेक भारत के हाईटेक निर्माण क्रांति में हिस्सा लेने के लिए भारत वापस आएंगे।' इस प्रकार भारत में सेमीकंडक्टर उद्योग का भविष्य असाधारण संभावनाओं वाला है। यह देश के परिष्कृत तकनीकी परिदृश्य में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, देश की आर्थिक प्रगति का संचालन करता है तथा देश को खोज के मामले में दुनिया भर में अग्रणी बनाता है।

सेमीकंडक्टर क्षेत्र इस क्षेत्र में प्रवेश करने तथा यहां काम करने वाली भारतीय प्रतिभाओं के लिए दुनिया भर में अवसर प्रदान करता है। भारत में सेमीकंडक्टर उद्योग की तेजी से होती प्रगति को देख कर विदेशों में कार्यरत भारतीय युवा इंजीनियर भारत लौटने की तैयारी कर रहे हैं। भारत स्पष्ट रूप से सेमीकंडक्टर उद्योग के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना चाहता है। अपनी प्रतिभा, संसाधनों व ढांचागत संरचनाओं को देखते हुए भारत ने सेमीकंडक्टर क्षेत्र में असाधारण प्रगति की है और वह आने वाले वर्षों में पूरी दुनिया में अग्रणी बनने की ओर बढ़ रहा है।

भारत में बौद्धिक संपदा की भूमिका

> भारत नवाचार का उपयोग करके, परिवर्तन को अपनाकर और जोखिम लेने वाली संस्कृति विकसित कर जापान के मेजी परिवर्तन के बाद का अनुकरण कर सकता है।

कृष्णा सरमा
(लेखक, कारपोरेट क्षेत्र से जुड़े हैं)

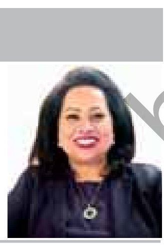

15 अगस्त, 2022 को 76वें स्वतंत्रता दिवस के भाषण में, प्रधानमंत्री ने जय अनुसंधान पर प्रकाश डालते हुए स्वदेशी नवाचारों पर ध्यान देने के साथ नवाचार का आह्वान किया। 2047 तक भारत को आत्मनिर्भर, प्रतिस्पर्धी और 30 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए नवाचार महत्वपूर्ण है। नवाचार में प्रमुख उत्पादकता लाभ हासिल करने की क्षमता है और यह राष्ट्र को सभी क्षेत्रों में उच्च मूल्य वर्धित उत्पादों और सेवाओं की ओर छलांग लगाने की अनुमति देगा।

पिछले कुछ वर्षों में, विश्व स्तर पर हमने ज्ञान अर्थव्यवस्था से कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और आभासीता के युग में एक मौलिक और तेजी से बदलाव देखा है। उसी समय के दौरान, महामारी की अभूतपूर्व प्रकृति और पैमाने ने नए इलाज – टीके, दवाएं और निदान खोजने के लिए एक नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के महत्व की पुष्टि की।

वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान आधार की विरासत वाले देश के लिए, भारत में निजी क्षेत्र ने पहले अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) में मामूली निवेश किया है। भारत ने अपनी अनूठी चुनौतियों से निपटने के लिए नवाचार के प्रति एक अलग दृष्टिकोण अपनाया है। आधार प्लेटफ़ॉर्म से शुरू होने वाला परिवर्तनकारी डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा इसका एक उदाहरण है। इसी तरह, सार्वजनिक स्वास्थ्य, दवाओं की पहुंच और सामर्थ्य और घरेलू उद्योग की सुरक्षा के संबंध में चिंताओं की पृष्ठभूमि में, बायोफार्मास्युटिकल क्षेत्र में नवाचार के लिए भारत का दृष्टिकोण मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के नेतृत्व वाले सहयोगी नवाचार पर आधारित है, जहां निजी क्षेत्र केवल प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। जबकि कई मामलों में, सार्वजनिक रूप से समर्थित अनुसंधान प्रारंभिक खोज का स्रोत प्रदान करता है, यह निजी क्षेत्र है जिसे नई प्रौद्योगिकियों को विकसित करना होगा और उन्हें बाजार में लाना होगा। सभी क्षेत्रों में तेजी से बदलते बाज़ार में अग्रणी बनने के लिए, निजी क्षेत्र का नवाचार महत्वपूर्ण है। कोई नवप्रवर्तन को कैसे मापता है? एक तरीका यह निर्धारित करना हो सकता है कि कोई कंपनी अपने राजस्व के प्रतिशत के रूप में अनुसंधान एवं विकास पर सालाना कितना खर्च करती है। चूंकि पेटेंट एक आविष्कार के लिए विशेष अधिकार सुरक्षित करते हैं, किसी कंपनी के नवोन्वेषी सूचकांक को अतिरिक्त रूप से ग्रेटेड पेटेंट की संख्या, दायर किए गए पेटेंट आवेदनों, चाहे फाइलिंग कई देशों में हो, पेटेंट की गुणवत्ता आदि से आंका जा सकता है।

भारत में आईपीआर व्यवस्था पर वाणिज्य पर संसदीय स्थायी समिति की 161वीं रिपोर्ट (जुलाई 2021) में चिंता व्यक्त की गई है कि पिछले चार वर्षों में भारत में पेटेंट की संख्या में वृद्धि की दर अमेरिका और चीन की तुलना में बहुत कम रही है। यह कहा जाता है कि यह आर और डी पर सूक्ष्म खर्च से सह-संबंधित है जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद का केवल 0.7 प्रतिशत है। विश्व स्तर पर, सबसे अधिक अनुसंधान और विकास व्यय वाली कंपनियां अमेज़ॅन, मेटा, अल्फाबेट, माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल कॉर्प जैसी बड़ी तकनीकी अमेरिकी कंपनियां और रोश, जे एंड जे, फाइजर, ब्रिस्टल-मायर्स स्क्विब और मर्क एंड कंपनी जैसी बायो-फार्मास्युटिकल कंपनियां हैं। यह सूची इसमें चीन की तीन कंपनियां भी शामिल हैं – हुआवेई, टेनसेंट होल्डिंग्स और अलीबाबा; दक्षिण कोरिया से सैमसंग; और वोक्सवैगन और मर्सिडीज-बेंज जैसे यूरोपीय ऑटोमोबाइल निर्माता।

बायोफार्मास्युटिकल क्षेत्र के संबंध में, 1970 में दवाओं के लिए उत्पाद पेटेंट संरक्षण को हटाने से रिवर्स इंजीनियरिंग की अनुमति मिली, जिससे घरेलू जेनेरिक उद्योग की तेजी से वृद्धि हुई और भारत को %दुनिया की फार्मेसी% बनने में मदद मिली। हालाँकि, उसी समय, प्रभावी पेटेंट संरक्षण की कमी ने अनुसंधान एवं विकास में कॉर्पोरेट निवेश और नए अणुओं की खोज पर गहरा प्रभाव डाला। 2013 में लॉन्च किया गया ज़ाइडस कैडिला का सारोग्लिटाज़र अब तक एकमात्र ऐसा यौगिक है जिसे पूरी तरह से स्वदेशी रूप से खोजा गया था।

भारत में अपनी शक्तियों का लाभ उठाकर, परिवर्तन को अपनाकर और जोखिम लेने वाली संस्कृति को बढ़ावा देकर अपनी नवोन्मेषी भावना को बढ़ावा देने की क्षमता है। मीजी रेस्टोरेशन के बाद विदेशी प्रौद्योगिकियों के आयातक और नकलकर्ता से लेकर नवाचार में एक वैश्विक पावरहाउस बनने तक जापान का परिवर्तन, जिसने दुनिया के तकनीकी परिदृश्य को परिभाषित किया है, इस बात का उदाहरण है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। नवप्रवर्तन के लिए एक सक्षम वातावरण बनाने के लिए कोई आशा की किरण नहीं है। ब्रायस हॉफमैन ने अपनी पुस्तक रेड टीमिंग में दिखाया है कि कैसे विघटनकारी नवाचार के लिए आलोचनात्मक और विरोधाभासी सोच की आवश्यकता होती है। इसलिए, वैज्ञानिक स्वभाव और जोखिम लेने और उद्यमशीलता की भावना को विकसित करने के लिए, हमारी शिक्षा प्रणाली को रटने और अनुरूपता पर जोर देने की सख्त जरूरत है। दूसरा, हमें नवाचार का व्यावसायीकरण करने के लिए शिक्षा जगत और उद्योग के बीच घनिष्ठ सहयोग को सख्ती से आगे बढ़ाना चाहिए। यह बहुत गर्व की बात है कि आईआईटी मुंबई के प्रोफेसर राहुल पुरवार ने कैंसर के इलाज के लिए पहली स्वदेशी रूप से विकसित सेल और जीन थेरेपी के लिए विपणन अनुमोदन प्राप्त किया।

अंतिम लेकिन कम से कम, एक मजबूत, सार्थक और पूर्वानुमानित बौद्धिक संपदा अधिकार प्रणाली आविष्कारकों और निवेशकों को आविष्कारशील गतिविधि में जोखिम पूंजी निवेश करने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान कर सकती है – एक बहुत ही उच्च जोखिम वाला उपक्रम है।

आप की बात

दलबदल की बीमारी

दलबदल की बीमारी से कोई भी राजनीतिक दल अछूता है। किन्तु चुनाव के मौसम में और मतदान के ऐन वक्त पर कांग्रेसी तथा निर्दलीय उम्मीदवारों द्वारा नामांकन वापस लेने, पार्टी छोड़ने और भाजपा में शामिल होने का जो सिलसिला इस चुनाव में तेजी से देखने को मिल रहा है, ऐसा पिछले किसी चुनाव में देखने को शायद ही मिला हो। आखिर कांग्रेस से इतने नाराज लोग भाजपा में शामिल होने को आतुर क्यों हो रहे हैं? सूरत से कांग्रेसी उम्मीदवार का पर्चा रद्द होने और निर्दलियों द्वारा नाम वापस लेने के बाद भाजपा उम्मीदवार मुकेश दलाल को निर्विरोध विजयी घोषित किया गया। इसके बाद इंदौर के कांग्रेसी उम्मीदवार अक्षय कांति बम ने नामांकन वापस लेकर भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। पहले भी अलग-अलग और समूह के समूह कांग्रेस से अलग हुए और भाजपा या अन्य पार्टियों में शामिल हो गए। शायद ऐसे लोगों को कांग्रेस नेतृत्व की नीतियां ठीक नहीं लग रही है या उन्हें वो डूबती नाव लग रही है। चुनावों से ज्यादा जनता में दलबदल की मौजूदा बीमारी की चर्चा हो रही है जो संक्रामक रूप धारण कर चुकी है। यह बीमारी जनता में राजनीतिक दलों व राजनेताओं के प्रति भारी अविश्वास का कारण बन सकती है। इस परिघटना पर गंभीरता से विचार होना चाहिए।

– **शकुंतला महेश नेनावा,** इंदौर

कनाडा में खालिस्तानी

जस्टिन त्रूदो की मौजूदगी में कनाडा के टोरंटो में हुए एक आयोजन में खालिस्तान समर्थक नारे लगाए जाते रहे। इस प्रकरण पर भारत का चिंतित होना स्वाभाविक है। कनाडा का प्रशासन तंत्र शासन के इशारे पर और वोटों की राजनीतिक के चलते पूरी तरह से खालिस्तानियों का समर्थक बन गया है और उसने अपने देश को खालिस्तानी आतंकवादियों व अलगाववादियों का सुरक्षित स्वर्ग बना दिया है। पूर्व में भी पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या पर हत्यारों का गुणगान करते हुए वहां झांकी निकाली गई थी तथा जमकर भारत-विरोधी नारेबाजी की गई थी। मगर कनाडा सरकार ने उस समय ऐसे तत्वों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की थी और अब भी उससे कठोर कार्रवाई की उम्मीद कम है। भारत सरकार को ही अब कनाडा से सखती के साथ पेश आना होगा। भारत सरकार को वहां पढ़ने गए छात्रों तथा काम कर रहे युवाओं को खालिस्तानियों के शिकंजे में आने से बचाना होगा। हालांकि, कनाडा में रहने वाला सिख समाज अधिकांशत: खालिस्तान-समर्थक नहीं है और वह भारत के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना चाहता है। कनाडा में रहने वाले सिखों को भी अब अपने भीतर के चरमपंथी तत्वों का विरोध करना होगा।

– **सुभाष बुडावन वाला,** रतलाम

बाल विवाह

हर साल आखातीज या अक्षय तृतीया पर कुछ समाजों में सामूहिक विवाहों का आयोजन किया जाता है। अक्सर ही इन सामूहिक विवाहों में कम उम्र के लड़के-लड़कियों के विवाह भी कर दिए जाते हैं। हालांकि, पहले की तुलना में इस बार अक्षय तृतीया पर बाल विवाह की घटनाओं को सुर्खियों में स्थान नहीं मिला, लेकिन इसका कारण संभवत: देश में आम चुनाव संबंधी खबरों की भरमार है। लेकिन इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि आज भी देश में बाल-विवाह की निंदनीय पृथा जारी है। कम उम्र में विवाह करना कानूनी तौर पर तो अपराध है, इससे बच्चों-बच्चियों के भावी विकास और पूरे जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हालांकि, सरकारी योजनाओं तथा स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा फैलाई जन-जागरूकता के कारण बाल-विवाह की घटनाओं में काफी कमी आई है। लेकिन इसके बावजूद समाज के बहुत गरीब लोग अथवा कट्टरपंथी धार्मिक सोच के कारण भी कुछ लोग बच्चियों व किशोरियों का बालिग होने के पहले ही विवाह कर देते हैं। पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू कर और जमीनी स्तर पर उसका क्रियान्वयन सुनिश्चित कर बाल विवाहों पर स्थाई रूप से रोक लगाने का काम किया जा सकता है।

–**एमएम राजावत,** शाजापुर

मजदूरों की पीड़ा

पहली मई या मजदूर दिवस पर विश्व के मजदूरों को एक संदेश दिया जाता है कि तमाम देशों की सरकारें आपके साथ हैं और आपके कल्याण के लिए काम कर रही हैं। लेकिन सवाल है कि क्या खासकर शारीरिक श्रम करने वाले मजदूरों की परेशानियों को हल निकाला गया है या इसके गंभीर प्रयास किए गए हैं। बाकी दुनिया की तरह भारत में भी मजदूरों की पीड़ा का कोई अंत नहीं है। पिछले काफी सालों से देश में विभिन्न पार्टियों की सरकारों ने शोषणकारी ठेकेदारी प्रथा को ही बढ़ावा दिया है। एक समय था कि देश में सरकारी कामकाज में स्थाई रूप से काम करने वाले मजदूरों के लिए ठेकेदारी प्रथा नहीं थी, लेकिन अब अधिकांश नियमित सरकारी काम भी ठेकेदारों के माध्यम से होते हैं। ऐसे कामों में मजदूरों का सरकारों द्वारा निर्धारित मिलने वाली न्यूनतम मजदूरी भी सुनिश्चित नहीं होती है। महंगाई तथा अन्य जरूरतें बढ़ने के बावजूद मजदूरों की मजदूरी में आवश्यक वृद्धि नहीं हुई है। इनको कोई सामाजिक सुरक्षा भी उपलब्ध नहीं है और ठेकेदार अपनी मर्जी से उनको काम पर रखते और हटा देते हैं। मजदूरों की पीड़ा दूर करने के प्रयास होने चाहिए।

– **वीरेंद्र कुमार जाटव,** दिल्ली

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से responsemail.hindipioneer@gmail.com पर भी भेज सकते हैं।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

जलवायु परिवर्तन और भारतीय चुनाव

कुलभूषण उपमन्यु

इस बार कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने ही इस मुद्दे पर कुछ लक्ष्य अपने चुनाव घोषणा पत्र में रखे हैं। किन्तु पिछले अनुभव के आधार पर ज्यादा आशा नहीं जगती है। शिमला में 2009 में जलवायु कॉन्क्लेव हुआ था, उसके साथ ही हिमालयी परिस्थिति तंत्र को बचाने के लिए कुछ लक्ष्य तय किए गए थे। किन्तु दोनों प्रमुख दलों को पर्याप्त समय मिलने के बावजूद विशेष प्रगति इस दिशा में नहीं हो सकी। वैश्विक स्तर और हिमालय के स्तर पर जलवायु परिवर्तन की चुनौती के कारण बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं के चलते अब समय आ गया है जब कि इस मुद्दे पर आम जनता और राजनीतिक दलों को चुनावी राजनीति के केंद्र में जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण के मुद्दे को लिया जाना चाहिए, ताकि सरकार गठन के बाद इस मुद्दे पर समुचित कार्य किया जा सके और सरकारों की जवाबदेही भी तय हो।

संयुक्त राष्ट्र संघ की विश्व मौसम विज्ञान संस्था ने एशिया में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों पर एक रिपोर्ट गत सप्ताह जारी की है, जिसमें यह बात सामने आई है कि वैश्विक तापमान वृद्धि का प्रभाव एशिया में विश्व औसत से ज्यादा पड़ रहा है। इस क्षेत्र में कई देशों में आज तक का अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है, जिसके कारण इस महाद्वीप में 2023 में 90 लाख लोग बाढ़ और तूफान से प्रभावित हुए। दो हजार लोग काल का ग्रास बन गए। जलवायु परिवर्तन ने बाढ़, सूखे और तूफानों की घटनाओं को न केवल बढ़ाया है बल्कि उनकी भयानकता को भी बढ़ाया है, जिसका दुष्प्रभाव वहां के समाज, अर्थ व्यवस्था, और मानव जीवन पर पड़ा है।

जलवायु परिवर्तन के मुख्य सूचकों जैसे कि जमीनी तापमान में वृद्धि, ग्लेशियरों का पिघलना, और समुद्र के जलस्तर के बढ़ने से बिगड़ती हुई स्थिति का पता चल रहा है। 1960-1990 के दौर के मुकाबले तापमान वृद्धि की दर लगभग दुगुनी हो गई है। 2023 में जहां एक ओर सूखा पड़ा वहीं दूसरी ओर भयानक बाढ़ आई। चीन की बाढ़ और भारत में सूखे से 65 बिलियन डॉलर का आर्थिक नुकसान होने का अनुमान लगाया गया है। चीन में 140 वर्षों का वर्षा का रिकार्ड टूट गया।

वहीं दक्षिण पश्चिमी चीन भारी सूखे की चपेट में रहा। भारत में लू के कारण 100 लोगों की मौत हो गई और सिक्किम का तीस्ता-3 बांध बाढ़ की चपेट में आकर ध्वस्त हो गया और 100 लोग अपनी जान गंवा बैठे। बढ़ते तापमान के कारण इस तरह की घटनाओं के बढ़ने की संभावना है। भारत और बांग्लादेश में लू की संभावनाओं में 30 गुणा वृद्धि की आशंका पैदा हो गई।

एशिया के तेज गति से बढ़ते तापमान के चलते इसके ग्लेशियर भी खतरे में पड़ गए हैं। मुख्य 22 ग्लेशियरों में से 20 में भारी नकारात्मक बदलाव पाए गए हैं। यानी ग्लेशियरों के पिघलने की गति तेज हुई है। तापमान वृद्धि से समुद्र का जल भी ज्यादा गर्म हो रहा है जिसके कारण भारी बारिश और समुद्री तूफानों का खतरा बढ़ा है। पिछले चार दशकों में अरब सागर में समुद्री तूफानों की संख्या में डेढ़ गुणा वृद्धि हुई है और तूफानों की घातकता भी बढ़ी है।

जुलाई और अगस्त 2023 में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण भूस्खलन के कारण हुई भारी तबाही का भी रिपोर्ट में जिक्र किया गया है ,जिसको भारत सरकार ने आपात स्थिति घोषित किया। इन स्थितियों से निपटने के लिए आपदा प्रबन्धन के विषय में भी काफी कुछ करने की जरूरत पर रिपोर्ट में प्रकाश डाला गया है। हालांकि भारत ने इस विषय में कुछ मानकों पर अच्छी प्रगति की है फिर भी काफी कुछ किए जाने की जरूरत है। पूर्व चेतावनी व्यवस्था में सुधार करके आपदाओं में होने वाली हानि को 30 प्रतिशत तक कम किया जा सकता है।

रिपोर्ट में आर्थिक असमानता के चलते जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के और ज्यादा चिंताजनक होने की बात कही गई है। जाहिर है कि बढ़ते तापमान का प्रत्यक्ष डंक उन गरीब लोगों को भुगतना पड़ता है जिनके पास आवास की व्यवस्था नहीं है, या जिन्हें दैनिक मजदूरी पर निर्भर रहना पड़ता है, या वह किसान जिनकी फसल खुले में में ईश्वर भरोसे रहती है। उनके लिए जलवायु अनुकूलन व्यवस्था खड़ी करना भी संभव नहीं होता। बढ़ते तापमान से फसलों की उत्पादकता पर भी विपरीत प्रभाव पड़ने के कारण खाद्य सुरक्षा पर भी खतरा पैदा होने की संभावना बन सकती है।

इस दिशा में जलवायु की विपरीत स्थितियों को झेलने में सक्षम फसलों और फसल किस्मों पर ज्यादा शोध और प्रचार-प्रसार की जरूरत है। इस दिशा में पुराने समय में प्रचलित श्री धान्य फसलों कोदा, रामदाना, स्वांक, बाजरा, आदि का प्रचार-प्रसार करके अच्छी पहल की जा रही है। किन्तु कार्बन उत्सर्जन करने वाली ऊर्जा उत्पादन तकनीकों और बड़े प्रोजेक्टों, खनन परियोजनाओं के कारण वनों के विनाश से कार्बन प्रदूषण क्षमता में आ रही कमी की चुनौतियां यथावत बनी हैं और बढ़ भी रही हैं।

पिछले 15 वर्ष में भारत में 3 लाख हेक्टेयर वन भूमि का उपयोग इस तरह की बृहदाकार योजनाओं के लिए बदला जा चुका है और यह क्रम सतत रूप से जारी है। इतनी चिंताजनक स्थिति के बावजूद वर्तमान आम चुनाव में यह मुद्दा जनता के बीच महत्वपूर्ण नहीं बन सका है। पर्यावरण से जुड़े दिवसों पर चेतना रैली निकालने, कुछ अच्छे नारे लगाने, भाषण प्रतियोगिता आयोजित करने, या ज्यादा से ज्यादा चुनाव मैनिफेस्टो में पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से जुड़े वादे उछालने तक हम सीमित होते जा रहे हैं। राजनीतिक दल भी जन चेतना जगाने के इस मौके का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं।

आम मतदाता निजी आर्थिक लाभ से ज्यादा सोचने को तैयार नहीं है। इस लिए राजनीतिक दल भी इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लेते हैं। हिमालय के नाजुक परिस्थिति संतुलन के दृष्टिगत यह मामला हिमालय में और भी ज्यादा संगीन हो जाता है। किन्तु हम प्राकृतिक आपदा का बहाना गढ़कर आत्मसंतुष्टि कर लेते हैं या खुद को धोखा देते रहते हैं। जबकि हम सब समझते हैं कि जलवायु परिवर्तन मानव निर्मित गलतियों का नतीजा है। फिर भी हम न तो आत्मसंयम से अनावश्यक वस्तुओं, पदार्थों के उपयोग से बचना चाहते हैं न ही सरकारों के सामने अपनी पर्यावरण विषयक चिंताओं को रख कर दबाव बना कर नीतिगत बदलाव की मांग रखना चाहते हैं। सरकारें अपने आप विकास को सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर से नाप कर आगे बढ़ती हैं उन्हें पर्यावरण जैसे मुद्दे उतने लुभावने नहीं लगते। दुनिया भर में सरकारें जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर टालमटोल करते हुए, शमार्ते हुए कुछ थोड़ा बहुत कार्य करती रहती हैं। कुछ गंभीरता जब आपदाएं आती हैं तब दिखाई देती है। धीरे-धीरे प्रकृति के ऊपर दोषारोपण करके समस्या भूल जाते हैं।

इस बार कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने ही इस मुद्दे पर कुछ लक्ष्य अपने चुनाव घोषणा पत्र में रखे हैं। किन्तु पिछले अनुभव के आधार पर ज्यादा आशा नहीं जगती है। शिमला में 2009 में जलवायु कॉन्क्लेव हुआ था, उसके साथ ही हिमालयी परिस्थिति तंत्र को बचाने के लिए कुछ लक्ष्य तय किए गए थे। किन्तु दोनों प्रमुख दलों को पर्याप्त समय मिलने के बावजूद विशेष प्रगति इस दिशा में नहीं हो सकी। वैश्विक स्तर और हिमालय के स्तर पर जलवायु परिवर्तन की चुनौती के कारण बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं के चलते अब समय आ गया है जब कि इस मुद्दे पर आम जनता और राजनीतिक दलों को चुनावी राजनीति के केंद्र में जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण के मुद्दे को लिया जाना चाहिए, ताकि सरकार गठन के बाद इस मुद्दे पर समुचित कार्य किया जा सके और सरकारों की जवाबदेही भी तय हो।

(लेखक, जल-जंगल-जमीन के मुद्दों के पैरोकार हैं।)

संपादकीय

कांग्रेस को झटका

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अरविंदर सिंह लवली ने दिल्ली इकाई के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। इसकी वजह उन्होंने आम आदमी पार्टी से गठबंधन बताई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को भेजे इस्तीफे में लिखा मैं खुद को लाचार महसूस कर रहा हूं। दिल्ली इकाई ऐसी पार्टी के साथ गठबंधन के खिलाफ थी, जो कांग्रेस के खिलाफ झूठे, मनगढंत और दुर्भावनापूर्ण भ्रष्टाचार के आरोपों पर बनी। हालांकि उन्होंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता नहीं छोड़ी है। आनन-फानन में उन्हें मनाने की कोशिशें चालू हो गई हैं। भाजपा में शामिल होने की अटकलों को विराम लगाते हुए लवली ने स्पष्ट किया कि वह लोक सभा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। शीला दीक्षित सरकार में मंत्री रहे लवली ने आप के आधे मंत्रियों के भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल में होने की बात भी उठाई। साथ ही कन्हैया कुमार व उदितराज को दिल्ली में उम्मीदवार बनाये जाने पर भी विरोध व्यक्त किया और इनको बाहरी बताया। लवली के इस्तीफे को कांग्रेस के लिए झटका माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि इससे पार्टी के भीतरी विवाद व मतभेद सामने आ रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संदीप दीक्षित ने लवली के दर्द को समझने और उन्हें पार्टी के लिए संपत्ति बताया। लवली का लंबा राजनीतिक अनुभव है। उन्होंने जो बातें कीं, उनमें से किसी को गलत नहीं ठहराया जा सकता। यह सच है कि कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी द्वारा विभिन्न क्षेत्रीय पार्टियों के आगे झुकना दल के वरिष्ठ नेताओं के गले नहीं उतरा, लेकिन उन्हें यह समझना चाहिए कि कांग्रेस आला कमान इन तथ्यों से कतई अनजान नहीं है। केजरीवाल ही नहीं, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी व शरद पवार के साथ गठबंधन करते हुए भी इसकी अनदेखी की गई कि उनकी पार्टियां भी लंबे समय तक कांग्रेस का विरोध ही करती रही हैं। यह समय कांग्रेस के लिए किसी भी लिहाज से अच्छा नहीं है। उसे इस हकीकत को समझने की जरूरत है। उसके पास अच्छे उम्मीदवारों का टोटा है। उस पर उन चेहरों को पीछे धकेलना, जो कांग्रेस का लंबे समय तक चेहरा रहे हैं, उसके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। चुनाव के दरम्यान कड़े निर्णय लेने का वक्त नहीं बचा है इसलिए कांग्रेस को पहले अपनी अंदरूनी कलह व मतभेदों से रातों-रात निपटना होगा, तभी उसकी स्वीकार्यता भी बढ़ेगी।

चिंतन-मनन

आत्मबल के लिए

एक गरीब बुढ़िया थी। अपनी झोपड़ी में अकेली रहती थी। उसके पास एक गाय थी। बस उसी के सहारे वह अपना जीवन निर्वाह करती थी। पर्युषण पर्व चल रहा था। वह अपनी झोपड़ी में बैठी-बैठी रोज देखती थी कि गांव के लोग बहुत ठाट-बाट से पूजा की थाल और प्रसाद आदि लेकर लिए मंदिर जा रहे हैं। उन्हें देख कर बुढ़िया सोचती थी, मैं इतनी ठाट से पूजा नहीं कर सकती, मेरे पास पर्याप्त साधन नहीं है। पूजा की इच्छा दब जाती। एक दिन उसने सोचा, यदि पूजा नहीं कर सकती तो आरती तो कर सकती हूं। बस, यह सोच कर वह उठी, अपनी गाय के दूध से निकाला हुआ घी लिया। पड़ोसी के एक कपास के खेत में से थोड़ी-सी रूई ले आई।

एक मिट्टी के दीपक में आरती संजोकर चल दी मंदिर की ओर। अत्यंत श्रद्धा भक्ति से उसने आरती की, जिसके परिणाम स्वरूप आगामी भव में उसे अत्यंत ज्ञानी मुनिराज की पर्याय प्राप्त हुई। न कोई उपवास, न कोई व्रत, केवल पवित्र भावना, श्रद्धा और भक्ति से उसे यह प्राप्त हुआ। किसी शक्तिहीन व्रती प्राणी का उपहास मत कीजिए। संभव है, उसमें शक्ति की अल्पता हो पर भक्ति की प्रबलता हो। कोई छोटा बच्चा पवित्र भावना लेकर व्रत करना चाहता है, तो उसे रोकिए मत, करने दीजिए। उसकी भावनाओं को खंडित मत कीजिए, ठेस मत पहुंचाइए। बल्कि उसे व्रत के वास्तविक उद्देश्य को समझा कर उसके इरादे को और दृढ़ बनाइए। तप के मार्ग को सामान्य मत समझिए।

कुछ लोग कहते हैं, तप में क्या रखा है? बेकार है? व्यर्थ है। ऐसा वे लोग कहते हैं जिनमें पुरुषार्थ का अभाव है। जो स्वयं पालन नहीं कर सके, उन्हें कहना चाहिए हम तो नहीं कर पाते, पर आप कर रहे हैं, यह अच्छी बात है। आपका कल्याण हो। उसके प्रति कम से कम अपनी भावनाएं पवित्र रखनी चाहिए। तप की सबसे बड़ी पूंजी आत्मशक्ति की उत्पत्ति है। इस आत्मशक्ति के माध्यम से हमारे में विरोध में भी जीने का साहस उत्पन्न होता है।

कोविशील्ड वैक्सीन और मोदी की विश्वसनीयता

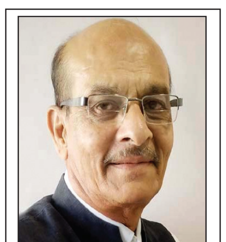

सनत जैन

ब्रिटेन की कंपनी एस्ट्राजेनिका ने ब्रिटेन की हाईकोर्ट में स्वीकार किया है कि उसकी कोरोना वैक्सीन से हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक का खतरा है। रक्त के थक्के जम जाने का भी साइड इफेक्ट हो सकता है। ब्रिटेन की कंपनी एस्ट्राजेनिका के फामूर्ले से ही भारत में सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा कोविशील्ड वैक्सीन को तैयार किया गया था। ब्रिटेन की कंपनी ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर इसे तैयार किया था। ब्रिटेन की दवा कंपनी द्वारा हाईकोर्ट में स्वीकार किया गया है कि वैक्सीन लगने के बाद इसके साइड इफेक्ट भी हैं। ब्रिटेन की कंपनी यह बताने से हमेशा बचती रही है। 2023 में इस कंपनी के खिलाफ वैक्सीन लगाने के बाद हुए साइड इफेक्ट से हजार्ने की मांग का मुकदमा ब्रिटेन की अदालत में चल रहा था। अब जाकर कंपनी ने स्वीकार किया है, ??जिन्हें वैक्सीन लगाई गई थी, उन्हें गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ा है। मरीजों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। ब्रिटेन की कंपनी ने यह भी स्वीकार किया है कि क्लिनिकल ट्रायल और अलग-अलग देशों के डेटा से यह साबित भी होता है कि जिन लोगों को वैक्सीन लगी है, उनके ऊपर अलग-अलग प्रभाव देखने को मिले हैं। इसके बाद भी कंपनी ने दावा किया, कि उसकी वैक्सीन सुरक्षा से जुड़े हुए मामलों को पूरा करती है।

भारत में इस वैक्सीन के ब्रांड एंबेसडर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने थे। भारत सरकार ने कहा था इस वैक्सीन की जांच इंडियन कौंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा की जा चुकी है। इसे अदार पूनेवाला ने सीरम इंस्टीट्यूट की खोज बताया था। यह दावा अब गलत साबित हुआ है। भारत सरकार ने कोविशील्ड वैक्सीन को सुरक्षित मानते हुए इसे सभी के ?लिये अनिवार्य किया था। भारत में लगभग 175 करोड़ वैक्सीन के डोज महिला पुरुष और बच्चों को लगाए गए हैं। इस वैक्सीन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चित्र छापकर इसे विश्वसनीय बनाया गया था। निशुल्क वैक्सीन सरकारी खर्चे पर नागरिकों को लगाई गई थी। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आमजनों के बीच लोकप्रियता और विश्वसनीयता का लाभ कंपनी को मिला। पिछले वर्षों में जिस तरह से साइलेंट हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक के मामले भारत में बड़ी तेजी के साथ बढे हैं। कोरोना के दूसरे फेस में लाखों लोगों की मौत हुई थी। उनमें किसी के पोस्टमार्टम नहीं कराए गए। अस्पतालों में जो कोरोना के मरीज भर्ती होते थे, उन्हें कोरोना के मरीज मानकर तथा जिन मरीजों की मौत अन्य बीमारियों के कारण चिकित्सा के दौरान हुई थी। उनको साधारण मौत मानकर उनका भी शव परीक्षण नहीं कराया गया, जिसके कारण यह कहना मुश्किल है कि वैक्सीन के साइड इफेक्ट के कारण मौत हुई है। भारत में साइलेंट हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक और रक्त संबंधी बीमारियों के कारण उन लोगों की मौत हुई है। भारत में दूसरे चरण का मतदान हो चुका है। पांच चरण का मतदान होना है। इसी बीच ब्रिटेन हाईकोर्ट में कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी ने साइड इफेक्ट की जो बात स्वीकार की है, उसको लेकर अब भारत में भी भय का वातावरण देखने को मिल रहा है। अकेले दिल्ली में 30000 लोगों की मौत हार्ट अटैक के कारण हुई है। विभिन्न राज्यों में बहुत कम उम्र के लोग नाचते-गाते, व्यायाम करते, अथवा बैठे-बैठे ही साइलेंट हार्ट अटैक से मौत हो जाने के मामले रोजाना देखने और सुनने को मिलते हैं। भारत सरकार ने अभी तक इस तरह के मामलों में कोई जांच नहीं कराई है। एम्स जैसे संस्थान ने कोरोना के कुछ मरीजों की मौत के बाद शव का परीक्षण किया गया था। उसकी रिपोर्ट भी अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है। हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक से कम उम्र के लोगों की जो मौत हो रही है उसके बारे में भी अभी तक कोई जांच शुरू नहीं की गई है। भारतीय नागरिक जिन्हें अनिवार्य रूप से वैक्सीन लगवाई गई थी, उन सबमें भय का वातावरण बन गया है। वैक्सीन बनाने वाली कंपनी और अन्य दवा कंपनियों ने जिस तरह से राजनीतिक दलों को चंदा दिया है। उसके बाद यह आशंका व्यक्त की जा रही है कि सरकार ने इस मामले में लापरवाही बरती है। कोरोना काल में ही सबसे ज्यादा चंदा दवा कंपनियों द्वारा राजनीतिक दलों को दिया जाना तथा अमानक दवाइयों के निर्माण और बिक्री पर रोक नहीं लगाए जाने से आम आदमियों को जान और माल का नुकसान हुआ है। इसका असर राजनीतिक दलों और राजनेताओं की साख पर भी पड़ेता हुआ दिख रहा है।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

लव जिहाद के बाद अब वोट जिहाद...

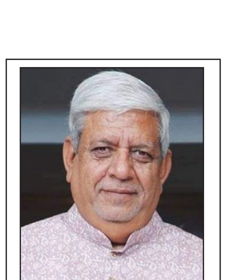

राकेश अचल

जिहाद वैसे कोई आतंकी शब्द नहीं है लेकिन इसका जन्म चूंकि अरबी भाषा से हुआ है इसलिए सनातनी इसे आतंक का पर्याय मानने लगे हैं। जिहाद का शुब्दिक अर्थ जाने बिना देश में वर्षों से राजनीति हो रही है। पहले लव जिहाद के नाम पर हुई और अब वोट -जिहाद के नाम पर हो रही है । लव जिहाद को लेकर भाजपा आक्रामक थी और वोट जिहाद कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद का जुमला है।

जिहाद का शब्दिक अर्थ होता है नैतिक मूल्यों के संरक्षण के लिए की जाने वाली जद्दोजहद या संघर्ष, किसी जायज माँग के लिए भरपूर कोशिश करना या आंदोलन। जिहाद का अर्थ मेहनत और मशक़्कत करना भी है किन्तु जिहाद का दुर्भाग्य कि उस जैसे पवित्र शब्द का चरमपंथियों ने गलत अर्थ दुनिया को समझा दिया और अब ये आम जिंदगी से निकालकर सियासत का अभिन्न अंग बनता जा रहा है। इसके लिए जितने चरमपंथी जिम्मेदार हैं उतनी ही भाजपा और कांग्रेस भी जिम्मेदार है । भाजपा ने जिहाद के बाद लव -जिहाद को औजार की तरह इस्तेमाल किया तो मौजूदा आम चुनावों में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने मुस्लिम मतदाताओं से सत्ता परिवर्तन के लिए वोट जिहाद करने की अपील कर दी और अब फंस गए। उनके खिलाफ बाकायदा आपराधिक मुकदद्मा दर्ज कर लिया गया है।

उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को लेकर सरकार अतिरिक्त रूप से संवेदनशील है ,शायद इसीलिए खुर्शीद की भतीजी मारिया आलम के वीडियो वायरल होने के तुरंत बाद फरुर्खाबाद पुलिस ने मारिया आलम और सलमान खुर्शीद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। दोनों नेताओं पर आईपीसी की धारा 188, 295 (ए) और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया। अब उत्तरप्रदेश की सरकार और पुलिस के ऊपर है की वो खुर्शीद साहब और उनकी भतीजी को गिरफ्तार करती है या नहीं ?

खुर्शीद साहब मुझसे उम्र में छह साल बड़े हैं ,वे मुझे अपनी शराफत,नजाकत और बुद्धिमत्ता की वजह से शुरू से प्रिय रहे हैं। उनका मुसलमान होना एक संयोग है । वे मुसलमान भी न होते तो एक मनुष्य के रूप में उतने ही चर्चित होते जितने की आज हैं। खुर्शीद भाई को पूरा देश जानता है। आज के विदेश मंत्री जयशंकर से ज्यादा जानता है। सलमान खुर्शीद एक भारतीय राजनीतिज्ञ,चर्चित वरिष्ठ अधिवक्ता, प्रख्यात लेखक और कानून शिक्षक हैं। वे विदेश मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री थे। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित हैं वह एक वकील और एक लेखक है [1] जो 2009 की आम चुनाव में फरुर्खाबाद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए। इससे पहले खुर्शीद 1991 में फरुर्खाबाद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से 10 वीं लोकसभा के लिए चुने गए थे। वह जून 1991 में वाणिज्य के केंद्रीय उप मंत्री बने, और बाद में विदेश मामलों के राज्य मंत्री बन गए। खुर्शीद साहब शुरू में नेता नहीं बल्कि 1981 में प्रधान मंत्री कार्यालय में एक विशेष अधिकारी के रूप में पदस्थ थे तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी उन्हें राजनीति में लेकर आयीं।

दरअसल जो लोग खुर्शीद को नहीं जानते उन्हें बता दूँ की सलमान खुर्शीद उस व्यक्ति का नाम है जो अपना घर फूंक क्र तमाशा देखने वाला है। एक लेखक है,एक अभिनेता है और बाद में जन नेता है। सलमान से असहमत लोगों ने सलमान खुर्शीद के नैनीताल स्थित आवास को आग तक लगा दी थी लेकिन न सलमान खुर्शीद बदले और न उनके स्वर । वे 1992 में जैसे थे वैसे ही 2024 में भी हैं। सलमान खुर्शीद और उनकी भतीजी को वोट के जरिये व्यवस्था बदलने के लिए जिहाद शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था,क्योंकि इस देश में आज भी कूढ़ मगज लोग जिहाद के नाम से भड़क जाते हैं ,जैसे जिहाद कोई संक्रामक रोग हो ! सलमान खुर्शीद की मजबूरी ये रही कि वे जिस इलाके में राजनीति करते हैं उस इलाके में उर्दू मातृभाषा के रूप में प्रचलित है। वे यदि परिवर्तन के लिए जिहाद शब्द का इस्तेमाल न करते तो मुमकिन था कि उनकी बात स्थानीय मतदाता समझ न पाता।

इस देश में मुसीबत ये है कि जो होता है उसे वो माना नहीं जाता । जैसे जो हेट स्पीच है उसे हेट स्पीच नहीं कहा जाता और जो हेट स्पीच नहीं है उसे आनन-फानन में हेट स्पीच मान लिया जाता है। घृणा की भाषा के बारे में जब हमारे नेता नहीं जानते तो हमारी पुलिस उसके बारे में कैसे जान सकती है ? पुलिस तो हुक्म की गुलाम है। उसके हाथ बंधे हैं। भारत में पुलिस के हाथ लम्बे जरूर होते हैं किन्तु उन्हें काम नहीं करने दिया जाता। हमारी पुलिस आज भी अंग्रेजों के जमाने कीपुलिस है। पुलिस तब बदलेगी जब देश का संविधान बदलेगा। संविधान तब बदलेगा जब मोदी जी तीसरी बार सत्ता में वापस आएंगे। तब तक हमें ,आपको ,सलमान खुर्शीद को इन्तजार करना होगा। अभी चुनाव के पांच चरण बाकी हैं ,देखिये आगे-आगे होता है क्या ? वैसे मै ईमानदारी से कहूँ कि आज आम चुनाव एक धर्मयुद्ध जैसा ही है। एकदम महाभारत के माफिक। लोकतंत्र में वोट जिहाद के बिना कोई तब्दीली आ ही नहीं सकती। इसलिए यदि आपके पास मताधिकार है तो आप वोट जिहाद यानि वोट से क्रांति कर सकते है।भाजपा भी यदि तीसरी बार सत्ता में वापस आएगी तो वोट कि जरिये ही ।

{ संपादकीय }

नई दिल्ली, गुरूवार 02 मई 2024

संस्थापक-सम्पादक : स्व. मायाराम सुरजन

घबराई भाजपा संविधान की शरण में

लोकसभा चुनाव के पहले दो चरणों में हुए मतदान को लेकर जो अनुमान लगाये जा रहे हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी और उसके राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबन्धन (एनडीए) की हालत पस्त बताई जा रही है। तीसरे चक्र का मतदान जो 7 मई को होने जा रहा है, उसके बारे में भी कहते हैं कि रूझान कुछ ऐसे ही होंगे। फिर, भाजपा की मुख्य विपक्षी कांग्रेस एवं उसके गठबन्धन इंडिया के सहयोगी दल लोकतंत्र और संविधान को लेकर जिस तरह से हमलावर हैं, उसके कारण भाजपा अब संविधान की दुहाई जोर-शोर से दे रही है। उसके सबसे प्रमुख बिन्दु आरक्षण के साथ कोई छेड़छाड़ न करने का वह बारम्बार वादा भी कर रही है। यह अलग बात है कि उसके कहे पर कोई भरोसा नहीं कर रहा है और लोग मानने लगे हैं कि यदि तीसरी बार भाजपा-एनडीए की सरकार आई तो संविधान निश्चित रूप से बदल दिया जायेगा और इसकी पहली मार आरक्षण व्यवस्था पर ही पड़ेगी।

कांग्रेस व इंडिया जिस जोरदार तरीके से जातिगत जनगणना कराये जाने का भरोसा जनता को दिला रहे हैं, उससे भाजपा की बेचैनी बढ़ चली है। इस बात को पहली बार उठाने तथा उस पर दमदारी से टिके रहने वाले राहुल गांधी की लोकप्रियता का राज इसी में छिपा है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल ने इस मामले को उठाया था। यह मुद्दा उनकी दूसरी यात्रा के दौरान और ताकतवर बन गया। कांग्रेस के घोषणापत्र का प्रस्थान बिन्दु, जिसे 'न्याय पत्र' नाम दिया गया है- यही जातिगत जनगणना है। सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित करने का जरिया जातिवार जनसंख्या तो है ही, आरक्षण को बनाये रखने को भी वही औचित्यपूर्ण व तर्कसंगत बनाता है। समतामूलक व न्यायपूर्ण समाज की सरंचना के लिये आरक्षण के महत्व से तो सभी अवगत थे लेकिन भाजपा तथा उसकी मातृसंस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को यह व्यवस्था कभी भी स्वीकार्य नहीं रही। 26 नवम्बर, 1950 को देश ने इस संविधान को लागू किया था। केवल 5 दिनों के बाद संघ ने अपने मुखपत्र 'ऑर्गेनाइज़र' में एक लेख लिखा था जिसमें संविधान को यह कहकर अस्वीकृत किया था कि इसमें देश की परम्परागत व्यवस्था के लिये स्थान नहीं है। उसका यह भी मानना रहा है कि भारत के पास मनुस्मृति जैसी संहिता पहले से मौजूद है जिसके आधार पर देश चलना चाहिये।

संविधान के लागू होने के वक्त से ही संघ एवं उसके अनुषांगिक संगठन इस संविधान में विश्वास या श्रद्धा दोनों ही नहीं रखते आये हैं। वैसे बाद के वर्षों में इसकी बहुत सी व्यवस्थाएं व प्रावधान अपना लिये जाने के बावजूद आरक्षण का विरोध संघ, पूर्ववर्ती जनसंघ व मौजूदा भाजपा करती रही है। उसके द्वारा एक तरह से यह धारणा फैलाई गयी है कि इसके चलते अयोग्य व प्रतिभाहीन लोगों को अवसर मिलते हैं तथा प्रतिभा व योग्यता उससे वंचित रह जाती है। इसका आशय साफ तौर पर आरक्षण के जरिये शिक्षा, नौकरियों तथा प्रतिनिधि सभाओं में बहुजनों, पिछड़ों, आदिवासियों, महिलाओं, अल्पसंख्यकों आदि को मिलने वाले अवसरों से होता है।

दो बार केन्द्र में सरकार बनाने के बाद तीसरी मर्तबा पूर्ण बहुमत हासिल करने हेतु अपने दम पर 370 तथा एनडीए के जरिये 400 सीटें पाने का लक्ष्य भाजपा की संविधान बदलने की मंशा से जुड़ा है। जब चुनाव प्रचार हुआ तब भाजपा एवं उसके नेता व उम्मीदवार इस नारे को जोर-शोर से उठाते थे, लेकिन जब उन्होंने पाया कि प्रतिकार स्वरूप कांग्रेस व इंडिया आरक्षण बचाने के लिये मजबूती से खड़े है; और जनता उनका साथ भी दे रही है तो भाजपा के हाथ-पांव ढीले पड़ गये। कांग्रेस-इंडिया ने एक कुशल रणनीति के तहत आरक्षण बचाने की लड़ाई को संविधान व लोकतंत्र बचाने की लड़ाई बना दिया है। इसके कारण लोकसभा चुनाव में उसे बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। अब भाजपा के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं रह गया है कि वह लोगों को सफाई देती फिरे कि संविधान नहीं बदला जाएगा। उसे कहना पड़ रहा है कि आरक्षण जारी रहेगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हों या गृह मंत्री अमित शाह या अन्य नेतागण- हर चुनावी सभा में कहते सुनाई पड़ रहे हैं कि यह कांग्रेस व इंडिया का फैलाया गया झूठ है।

वैसे भाजपा द्वारा तीसरी बार केन्द्र की सत्ता हासिल होने पर उसके द्वारा संविधान खत्म करने की आशंका को इसलिये बल मिला कि खुद उसके कई नेता कह चुके हैं कि मोदी को इसलिये 400 सीटें चाहिये क्योंकि उन्हें संविधान बदलना है। अनंत हेगड़े, मेरठ से उसके प्रत्याशी अरूण गोविल, लल्लू सिंह, ज्योति मिर्धा आदि इस आशय का बयान दे चुके हैं। लोग तो अब यह भी कहने लगे हैं कि अगर भाजपा का ऐसा कोई इरादा नहीं है तो उसने ऐसा बयान देने वाले उपरोक्त नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की।

भाजपा की पतली हालत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अब खुद संघ प्रमुख मोहन भागवत यह कहने के लिये उतर पड़े हैं कि 'समाज में जब तक भेदभाव है, तब तक आरक्षण जारी रहना चाहिये।' हैदराबाद में एक कार्यक्रम में तो उन्होंने यह भी मान लिया है कि 'देश में भेदभाव चाहे ऊपर से दिखलाई न दे परन्तु यह मौजूद है।' यदि कोई सोचे कि संघ में वैचारिक परिवर्तन आया है और वह उदार हो चला है, तो उसे यह गलतफहमी दूर कर लेनी चाहिये। संविधान विरोध के चक्कर में आरक्षण का लाभ पाने वाले वर्ग व उसकी महत्ता जानने वाले यदि भाजपा के खिलाफ गये तो चुनाव के सम्भावित परिणाम की कल्पना से दहशत में आने की यह घबराहट है।

देश के लिए शर्मिंदगी और अफसोस मुमकिन हुए

दुनियादारी

■ सर्वमित्रा सुरजन

> भाजपा अब भी जेडीएस के साथ गठबंधन में है, मानो प्रज्वल रेवन्ना पर लगे आरोपों का जेडीएस या भाजपा से कोई लेना-देना नहीं है। जेडीएस ने प्रज्वल को निलंबित करने की औपचारिकता निभा ली है। लेकिन यह काम पिछले साल ही क्यों नहीं किया गया, जब आरोप पहली बार लगे थे। प्रज्वल के खिलाफ कर्नाटक सरकार ने राज्य महिला आयोग की शिकायत के बाद विशेष जांच समिति गठित कर ली, लेकिन इससे पहले की जांच शुरु हो, 26 अप्रैल को हुए मतदान के अगले ही दिन सुबह प्रज्वल रेवन्ना जर्मनी भाग गया।

दस साल पहले जब नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद पर बैठने के लिए देश के लोगों से कई वादे किए थे। वो सारे वादे, जुमले साबित हो गए, एक भी पूरा नहीं हुआ। चलिए, कोई बात नहीं। अपनी बात पर खरा न उतरने के लिए वो देश के लोगों से माफी नहीं मांगेगे, यह भी स्वीकार्य है। लेकिन क्या वे इस बात के लिए कभी माफी मांगेंगे कि उनके पद पर रहते हुए इस देश में महिलाओं के साथ ऐसे भयावह कृत्य हुए, जिन्हें सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। या महिलाओं का सम्मान भी श्री मोदी के लिए राजनैतिक मुद्दे और नारे से अधिक की कीमत नहीं रखता है।

मणिपुर में दो महिलाओं को निर्वस्त्र करवाकर जातीय उन्माद में डूबी भीड़ ने उनका जुलूस निकाला था और इस शर्मनाक घटना की चर्चा पूरी दुनिया में हुई थी। अब इसमें सीबीआई ने एक और भयानक खुलासा किया है कि पीड़ित महिलाओं ने पुलिस से सहायता मांगी थी। पुलिस की गाड़ी तक वे महिलाएं पहुंच गई थीं, लेकिन गाड़ी में बैठे पुलिसकर्मी ने कह दिया कि उसके पास गाड़ी की चाबी नहीं है और फिर उन्हें भीड़ के हवाले कर दिया। अगर यह किस्सा-कहानी होता तो भी उसे पूरा पढ़ने में डर लगता। लेकिन मणिपुर में जो कुछ हुआ, वो वास्तविक घटना है और फिर भी प्रधानमंत्री इसके लिए शर्मिंदगी महसूस नहीं करते, तो फिर उनकी संवेदनशीलता और नारी शक्ति के लिए अंतिम सांस तक काम करने के दावे पर सवाल उठने लाजिमी हैं।

यहां फिलहाल प्रधानमंत्री से ही सवाल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मणिपुर में पिछले साल शुरु हुए जातीय दंगों के बाद वे आज तक मणिपुर नहीं गए। शायद इसलिए कि इसके बाद उन्हें और मणिपुर की भाजपा सरकार को कुछ कठिन सवालों का सामना करना पड़ता। मगर संदेशखाली प्रधानमंत्री मोदी गए, क्योंकि प.बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी की सरकार है और यहां श्री मोदी को पीड़ित महिलाओं के बहाने टीएमसी पर हमला बोलने और अपनी राजनीति गर्माने का मौका मिल गया।

मणिपुर और संदेशखाली से पहले बिल्किस बानो प्रकरण भी हुआ था, प्रधानमंत्री ने उस पर भी कुछ नहीं कहा, हाथरस, उन्नाव और कठुआ मामलों पर भी उनका रवैया न कुछ सुनना है, न देखना है, न बोलना है, वाला रहा। महिला पहलवानों के यौन शोषण के आरोपी भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को हटाने की हिम्मत भी श्री मोदी ने नहीं दिखाई। अब कर्नाटक से फिर एक डरावना मामला सामने आ गया है। यहां की हासन लोकसभा सीट से जेडीएस सांसद और एनडीए के मौजूदा उम्मीदवार प्रज्वल रेवन्ना पर एक-दो नहीं, हजारों महिलाओं के यौन शोषण और उनका वीडियो जारी करने का गंभीर आरोप लगा है। कम से कम 29 सौ वीडियो सामने आ चुके हैं, जिनमें महिलाओं के साथ जबरदस्ती की जा रही है और ये महिलाएं कमजोर तबके की हैं या जेडीएस की कार्यकर्ता हैं। प्रज्वल के ये वीडियो पिछले साल से ही सामने आने शुरु हो गए थे, लेकिन तब उसने इन्हें झूठा बताते हुए प्रेस और टीवी में इसकी जानकारी देने से रोका था। इस मामले को उजागर करने में भाजपा नेता देवराज गौड़ा की बड़ी भूमिका रही है। प्रज्वल पर लगे गंभीर आरोपों के बावजूद भाजपा और जेडीएस गठबंधन ने उसे उम्मीदवार बनाया, शायद इसकी वजह यह है कि प्रज्वल पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा का पोता, पूर्व मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी का भतीजा और विधायक एच डी रेवन्ना का बेटा है।

कर्नाटक की राजनीति में रसूख रखने वाले इस परिवार के साथ प्रधानमंत्री मोदी की कई तस्वीरें हैं। 26 अप्रैल को हासन में दूसरे चरण में मतदान हुआ और इसके पहले प्रज्वल के प्रचार के लिए पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से अपील की थी कि प्रज्वल को दिया हुआ हरेक वोट उन्हें मजबूती देगा।

सवाल ये है कि जब प्रज्वल पर यौन शोषण के आरोप पहले से लग रहे थे, तो प्रधानमंत्री मोदी उसका प्रचार करने क्यों पहुंचे। क्या उन्हें इस बारे में पता नहीं था। अगर ऐसा है तो क्या उन्हें प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए, क्योंकि उनकी अनभिज्ञता कमजोरी की निशानी है। क्या देश को कमजोर प्रधानमंत्री के हवाले किया जाना चाहिए। और अगर प्रधानमंत्री को प्रज्वल पर लगे आरोपों की जानकारी थी, तब भी उन्हें प्रधानमंत्री पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, क्योंकि एक यौन शोषण के आरोपी के लिए उन्होंने वोट मांगे। जबकि उनकी पहली जिम्मेदारी देश के लोगों की सुरक्षा और उनके आत्मसम्मान को बनाए और बचाए रखने की है।

हैरानी की बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी अपने पद से इस्तीफा देना तो दूर, इस मसले पर कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। एक बार भी उन्होंने इस बात के लिए अफसोस नहीं जताया कि उनकी तस्वीर एक बलात्कार के आरोपी के साथ है, जिसके साथ उन्होंने मंच साझा किया। भाजपा अब भी जेडीएस के साथ गठबंधन में है, मानो प्रज्वल रेवन्ना पर लगे आरोपों का जेडीएस या भाजपा से कोई लेना-देना नहीं है। जेडीएस ने प्रज्वल को निलंबित करने की औपचारिकता निभा ली है। लेकिन यह काम पिछले साल ही क्यों नहीं किया गया, जब आरोप पहली बार लगे थे। प्रज्वल के खिलाफ कर्नाटक सरकार ने राज्य महिला आयोग की शिकायत के बाद विशेष जांच समिति गठित कर ली, लेकिन इससे पहले की जांच शुरु हो, 26 अप्रैल को हुए मतदान के अगले ही दिन सुबह प्रज्वल रेवन्ना जर्मनी भाग गया। हालांकि उसके परिवार का कहना है कि उसका दौरा पहले से तय था। मान लिया दौरे का कार्यक्रम पहले से बना हुआ था, लेकिन जब हजारों महिलाओं के यौन शोषण का आरोप लगा है, और जांच शुरु हो गई है, तो एक जिम्मेदार नागरिक और सांसद होने के नाते प्रज्वल को दौरा रद्द करके देश वापस नहीं आ जाना चाहिए था। अगर हजारों महिलाओं की शिकायतें झूठी हैं, सारे वीडियो गलत हैं, तो फिर जांच-पड़ताल से दूरी क्यों बनाई जा रही है।

इस मामले में भाजपा का रवैया भी बेहद शर्मनाक है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा ने अब तक कुछ नहीं कहा, महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी भी खामोश हैं और गृहमंत्री अमित शाह कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि यह राज्य की कानून-व्यवस्था का मामला है। क्या श्री शाह यह नहीं जानते कि देश भर के विमानतल किसके अधीन आते हैं और वहां से किसी आरोपी या किसी अपराधी को भागने से रोकने की जिम्मेदारी किसकी है। विजय माल्या, नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चौकसी ये सारे लोग तो देश के लोगों का पैसा लूटकर भाजपा सरकार में भागने में कामयाब हो गए, अब मोदीजी ने इस बात को भी मुमकिन कर दिखाया है कि देश में सबसे भयानक और सबसे बड़े कहे जा रहे सेक्स स्कैंडल का आरोपी भी आराम से भाग गया।

कांग्रेस की यूपीए सरकार के वक्त जब निर्भया कांड हुआ था, उस पर भी कई सवाल उठे थे। लेकिन तब न देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री डा.मनमोहन सिंह या दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने सवालों और आलोचनाओं से बचने की कोशिश की। लोगों की नाराजगी को उन लोगों ने सुना और साथ ही निर्भया के इलाज से लेकर उसके दोषियों को सजा दिलवाने और उसके परिजनों की मदद तक सारी जिम्मेदारी निभाई।

नरेन्द्र मोदी हमेशा दावा करते हैं कि पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया और देश में सारे काम उन्होंने ही किए हैं। किस सरकार ने क्या किया और क्या नहीं, इसका लेखा-जोखा तो जनता की स्मृति में दर्ज है ही, और जनता उसका हिसाब वक्त आने पर कर लेगी। लेकिन पिछली सरकार और पिछले प्रधानमंत्री में जो नैतिक बल था, नरेन्द्र मोदी अपने कथित 56 इंची सीने से कभी उस बल का प्रदर्शन नहीं कर पाए। यहां मोदी है तो मुमकिन है, नहीं कह पाए। देश इसके लिए हमेशा अफसोस करेगा, हमेशा शर्मिंदा रहेगा।

बढ़ती असमानता पर बहस से बचाव के लिए कांग्रेस घोषणापत्र की विकृत आलोचना

■ नित्य चक्रवर्ती

> महत्वपूर्ण बात यह है कि विकासशील देश भी वंचितों के लिए अतिरिक्त धन उपलब्ध कराने के लिए अमीरों पर अधिक कर लगाने की संभावना पर चर्चा कर रहे हैं। जी-20 के अध्यक्ष के रूप में ब्राजील ने वैश्विक स्तर पर मौजूदा दौर में अमीरों और गरीबों के बीच असमानता के स्तर को कम करने के लिए अत्यधिक धनियों पर वैश्विक कर लगाने का प्रस्ताव रखा है।

इस पर आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी भी आम लोगों, विशेषकर हिंदुओं से उनके सोने, अचल संपत्ति और अन्य कड़ी मेहनत से कमाई गई संपत्ति को कांग्रेस पार्टी द्वारा लूटने और उसे पुनर्वितरण करने की योजना का आरोप लगाते हुए राहुल गांधी के खिलाफ अपना अभियान जारी रखे हुए हैं। प्रधानमंत्री उस बात के आधार पर आरोप लगा रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी के घोषणापत्र में नहीं है।

वह अठारह साल पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के एक भाषण को शरारतपूर्ण ढंग से तोड़-मरोड़कर मुसलमानों के पक्ष में धन के पुनर्वितरण के मुद्दे को लगातार ला रहे हैं। केवल वही नहीं, अमित शाह, राजनाथ सिंह और अनुराग ठाकुर जैसे अन्य वरिष्ठ नेता भी अधिक प्रतिशोध के साथ अपने नेता का अनुसरण कर रहे हैं। अब यह स्पष्ट है कि इस प्रकार का सांप्रदायिक प्रचार वर्तमान लोकसभा चुनाव के शेष पांच चरणों में भाजपा के चुनाव अभियान की मुख्य विशेषता होगी।

लेकिन क्यों? भाजपा एक बड़ी पार्टी है जिसमें कई सदस्य हैं जो उच्च शिक्षित हैं और कांग्रेस के घोषणापत्र में वास्तव में क्या लिखा है और राहुल गांधी अपने अभियान में क्या कह रहे हैं उसे भली-भाति जानते हैं। भाजपा का 2024 का चुनाव घोषणापत्र 14 अप्रैल को जारी किया गया था और आम तौर पर यह भाजपा के अभियान का मुख्य फोकस होना चाहिए था जिसका लक्ष्य इस बार - 400 पार है। लेकिन मजे की बात है कि दूसरे चरण के चुनाव के बाद पिछले कुछ दिनों में प्रधानमंत्री अपनी सभी चुनावी सभाओं में भाजपा के संकल्प पत्र की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि वह कांग्रेस के घोषणापत्र के अलिखित हिस्से की बात कर रहे हैं और मुसलमानों को भविष्य में इसके लाभार्थी के रूप में पेश कर रहे हैं।

प्रधानमंत्री द्वारा प्रचार अभियान की शैली में यह अचानक बदलाव इस तथ्य के कारण हो सकता है कि प्रधानमंत्री और उनके सलाहकार इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि संकल्प पत्र में दी गयी मोदी की गारंटी काम नहीं कर रही है, बल्कि कांग्रेस के घोषणापत्र में दी गयी राहुल की गारंटी अधिक आकर्षक है। इसके अलावा, भाजपा शासन के पिछले दस वर्षों में बढ़ती असमानता का मुद्दा हिंदू मतदाताओं के मन में है, और इसलिए कांग्रेस के घोषणापत्र के कार्यक्रम गैर-अमीर हिंदुओं के लिए अधिक अनुकूल हैं। इसलिए प्रधानमंत्री असमानता के मुद्दे पर बहस से बचने के लिए कांग्रेस या इडिया गुट पर सांप्रदायिक पुनर्वितरण के माध्यम से अल्पसंख्यकों के कथित तुष्टिकरण की ओर माहौल को मोड़ना चाहते हैं।

महत्वपूर्ण बात यह है कि विकासशील देश भी वंचितों के लिए अतिरिक्त धन उपलब्ध कराने के लिए अमीरों पर अधिक कर लगाने की संभावना पर चर्चा कर रहे हैं।

जी-20 के अध्यक्ष के रूप में ब्राजील ने वैश्विक स्तर पर मौजूदा दौर में अमीरों और गरीबों के बीच असमानता के स्तर को कम करने के लिए अत्यधिक धनियों पर वैश्विक कर लगाने का प्रस्ताव रखा है। भारत पिछले साल जी-20 का अध्यक्ष था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रैल/मई 2024 में होने वाले आम चुनावों की पूर्व संध्या पर भारतीयों को प्रभावित करने के लिए अपनी अध्यक्षता कार्यकाल का बड़ा प्रदर्शन किया, लेकिन उन्होंने ब्राजील की तरह कोई पहल नहीं की।

वकालत समूह टैक्स जस्टिस नेटवर्क के 2023 के एक अध्ययन के अनुसार, टैक्स हेवेन के कारण दुनिया भर के देशों को अगले दशक में कर राजस्व में 4.8 ट्रिलियन (3.8 ट्रिलियन) तक का नुकसान हो सकता है। इन पनाहगाहों को वैश्विक कंपनियों और उनमें से कई भारत के अमीरों द्वारा संरक्षण प्राप्त है। इस साल की शुरुआत में ईयू टैक्स ऑब्जर्वेटरी की एक रिपोर्ट में पाया गया कि दुनिया भर के अरबपतियों पर प्रभावी कर दरें उनकी संपत्ति के 0 प्रतिशत से 0.5 प्रतिशत के बीच हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि महामारी के वर्षों के दौरान, जबकि गरीबों और अन्य लोगों को नुकसान उठाना पड़ा और अनेकों की मृत्यु हो गयी, बड़ी कंपनियों और अमीर व्यक्तियों की कमाई काफी बढ़ गयी। वास्तव में महामारी के वर्षों में असमानता और अधिक बढ़ जाती है।

भारत के लिए, अति अमीरों पर विशेष कर लगाना समुचित है क्योंकि इस साल जनवरी में जारी नवीनतम ऑक्सफैम रिपोर्ट सहित सभी हालिया रिपोर्टों से पता चलता है कि असमानता लगातार बढ़ रही है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट के अनुसार, भारत केवल पांच हाथों में बढ़ती औद्योगिक एकाग्रता का सामना कर रहा है, और अरबपतियों, निजी इक्विटी फंडों और क्रोनी पूंजीपतियों को समृद्ध कर रहा है, जिससे लोगों के बीच अभूतपूर्व स्तर की असमानताएं और गरीबी बढ़ रही है। रिपोर्ट बताती है, कॉर्पोरेट शक्ति चार तरीकों से असमानता को बढ़ावा देती है- अमीरों को पुरस्कृत करना, श्रमिकों को उचित पारिश्रमिक नहीं देना; करों से बचना; सार्वजनिक सेवाओं का निजीकरण; और ड्राइविंग क्लाइमेट ब्रेकडाउन। निगम मज़दूरी को कम करके और अति-अमीर लोगों को सीधे मुनाफ़ा देकर असमानता को बढ़ावा देते हैं। ऑक्सफैम के विश्लेषण से पता चलता है कि वैश्विक स्तर पर 791 मिलियन श्रमिकों का वेतन मुद्रास्फीति के अनुरूप नहीं रह गया है और इसके परिणामस्वरूप पिछले दो वर्षों में प्रत्येक कर्मचारी को लगभग एक महीने (25 दिन) का वेतन खोना पड़ा है। इसके अलावा, निगमों ने अपने प्रभाव का उपयोग श्रम कानूनों और नीतियों का विरोध करने के लिए किया है जिनके माध्यम से श्रमिकों को लाभ पहुंचाया जा सकता है, जैसे कि न्यूनतम वेतन वृद्धि। उन्होंने उन सुधारों का समर्थन किया जो श्रमिकों के अधिकारों को कमजोर करते हैं, और ट्रेड यूनियन गतिविधियों पर राजनीतिक प्रतिबंध भी लगाते हैं।

निजीकरण महत्वपूर्ण सार्वजनिक सेवाओं में असमानताओं को और बढ़ा सकता है, जिससे अमीर और गरीब के बीच की खाई और बढ़ा सकती है। जो लोग भुगतान नहीं कर सकते उन्हें सेवा से बाहर कर दिया जायेगा और गरीब बना दिया जायेगा, जबकि जो लोग भुगतान कर सकते हैं वे अच्छी स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं। निजीकरण लिंग, नस्ल और जाति के आधार पर असमानताओं को भी बढ़ा सकता है।

भारत में, जहां निजी स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र अब 236 अरब अमेरिकी डॉलर का है और तेजी से बढ़ रहा है, विश्व बैंक की निजी क्षेत्र शाखा, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (आईएफसी) ने देश की कुछ सबसे बड़ी कॉर्पोरेट अस्पताल श्रृंखलाओं में सीधे तौर पर आधा अरब डॉलर से अधिक का निवेश किया है। इनमें कुछ सबसे अमीर अरबपतियों के स्वामित्व में हैं। फिर भी जून 2023 में, ऑक्सफैम ने पाया कि आईएफसी ने 25 साल पहले शुरू होने के बाद से भारत में अपनी स्वास्थ्य परियोजनाओं का एक भी मूल्यांकन प्रकाशित नहीं किया है। भारतीय स्वास्थ्य नियामकों ने कई शिकायतों को सही ठहराया है, जिनमें अस्पतालों द्वारा अधिक कीमत वसूलने, कीमतों में हेराफेरी और सरकारी जमीन मुफ्त में मिलने की शर्त होने के बावजूद गरीबी में रहने वाले मरीजों का मुफ्त में इलाज करने से इनकार करने के मामले शामिल हैं। इसके अलावा, वित्त पोषित 144 अस्पतालों में से केवल एक ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है।

चूंकि भारतीय जन 18वीं लोकसभा चुनाव में भाग ले रहे हैं, इसलिए वंचितों की जीवन स्थितियों का मुद्दा महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री की तमाम कोशिशों के बावजूद इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। राहुल गांधी सही हैं जब वह साठगांठ वाले पूंजीपतियों की बात करते हैं और कैसे नरेंद्र मोदी राज में कुछ परिवारों की रक्षा की जा रही है जो अपनी संपत्ति बेतहाशा खर्च बढ़ा रहे हैं जबकि सामान्य श्रमिकों की वास्तविक मजदूरी भी गिर रही है। इंडिया ब्लॉक के नेताओं के लिए अच्छा होगा कि वे रोजी-रोटी के मुद्दे को सांप्रदायिक रंग देने में प्रधानमंत्री और भाजपा के खेल का पर्दाफाश करें। प्रधानमंत्री को लोगों को झांसा देकर बच निकलने का मौका नहीं दिया जाना चाहिए।

गुरवाणी विचार

सतगुरु चरणी लगिआ, हरि नाम नित जपनी

बिन सतगुरु सेवे सांति न आवई दूजी नांही जाये
जे बहुतेरा लोचिये, बिन करमे न पाइआ जाये
जिना अंतर लोभ विकार है भाये खुआये
जनम मरण न चूकई हऊमे विच दुख जाये
जिना सतगुरु सिओ चित लाएआ सो खाली कोय नाहे
जिन जम की तलब न होवई न आये दुख सहाये
नानक गुरमुख उबरै सचै संबद समाहे।

इन शब्द की पंक्तियों द्वारा गुरदेव मानव मन को समझाइश देते हुए फरमा रहे हैं कि परमात्मा से मन को जोड़े बिना कभी आत्मिक शांति प्राप्त नहीं हो सकती और हम चाहे कहीं भी धक्के खाते रहें मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों, गिरजाघरों में घूमते रहें, भटकते रहें पीर फकीरों के इर्द-गिर्द चक्कर लगाते रहें हमें कहीं भी चैन नहीं मिल सकता जब तक हमारा मन प्रभु सिमरन बंदगी में रम न जाए। प्रभु बंदगी कर हमें हमारे घट में विराजमान प्रभु मूरत को खोज निकालता है। इसके लिए कहीं हमें वन, कंदराओं में जाने की जरूरत नहीं है। प्रभु तो हर घट में संसार के जर्रे जर्रे में विराजमान है ठीक उसी तरह जिस तरह फूल में सुगंध महसूस कर सकते हैं। दर्पण में अपनी छवि देख सकते हैं। वैसे ही हमारे घट में परमात्मा विराजमान हैं-

पुहुप मधजिओ वास बसत है मुकर मोह जैसे छाइ।
तैसे ही हरि बसै निरंतर घटि ही खोजो भाई।।

हम लाख जतन करते रहें। लोगों से ठगी बेईमानी कर अपने लाभ की पूर्ति हेतु धन इकट्ठा करते रहें, लोगों से ठगी-बेईमानी इत्यादि का सहारा लेते रहें पर हमें प्राप्ति उतनी ही होनी है जितनी हमारे भाग्य में है। हमारे भाग्य में जो कुछ परमात्मा ने लिख दिया है हमें उतना ही मिलने वाला है और इस तरह करने से परमात्मा की प्रसन्नता भी प्राप्त नहीं की जा सकती। हम हर वक्त सांसारिक मोह माया में विषय विकारों की अग्नि में जलते रहते हैं। माया के मोह में गलतान रहते हैं। धन-कमाने हेतु हर वक्त पागल हुए रहते हैं। लाख मिलने पर दस लाख पाने की तरफ दौड़ते हैं। माया चीज ही ऐसी है तृष्णा हमारी कभी खत्म नहीं हो पाती।

सहस्र खटे लखि को उठि धावै,
तृप्त न आवै माया पाछै पावै।

इन सबसे हमें सच्चा सुख मिलने वाला नहीं है। गलत तरीके से इकट्ठी की गई माया भी हमारे दुख का एक कारण बन जाती है। मानव मन की कृष्णा के कारण ही बार-बार जन्म लेता है। मृत्यु को प्राप्त होता है फिर जन्म लेता है। मगर जब तक उसके अंदर हृदय में शांति प्राप्त नहीं हो जाती। संतोष नहीं आ जाता तब तक उसका यह जनम-मरण के चक्कर से छुटकारा पाने हेतु प्रभु सिमरन बंदगी में मन रमाना चाहिए। सांसारिक दृष्टि से मनुष्य चाहे जितनी भी उन्नति कर ले उसे सच्चा सुख आनन्द की प्राप्ति नहीं हो सो सकती। मनुष्य को संसार के किसी भी उच्च से उच्च पद अथवा संसार के समस्त धन पदार्थों की प्राप्ति क्यों न हो जाए। उसकी भूख जब तक नहीं मिटती तब तक उसे चैन नहीं पड़ता। जब तक वह परम लक्ष्य की प्राप्ति न कर ले। वह परम लक्ष्य है प्रभु की सिमरन बंदगी कर उसकी प्राप्ति करना। इसलिए इंसान किसी क्षेत्र में उन्नति कर भी ले तो सुख आनंद प्राप्त कर ले तो भी वह चिरस्थियी नहीं रहता परन्तु यदि वह प्रभु बंदगी कर प्रभु की कृपा प्राप्त करने में सफल हो जाता है तो फिर वह संसार के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच जाता है और उसका लोक परलोक सुहेला हो जाता है फिर उसके आनंद की कोई सीमा नहीं रहती।

इसलिए गुरदेव हमें समझा रहे हैं कि इस संसार समुद्र से वही पार उतर सकता है जो साचे मन से प्रभु बंदगी करता रहे। हमारा मन इधर उधर भटकता रहता है इसलिए गुरवाणी हमें समझा रही है-

सतगुरु चरणी लगिआ, हरि नाम नित जपनी।
जो इच्छे सो फल पाऐसी सब घरे विच जचनी।।

इस बात की ताईद गुरुवाणी द्वारा कुछ इस तरह भी की गई है-

इच्छा पूरक सरब सुख दाता हरि जाके वस है कामधेना।
सो ऐसा हरि धिआइये मेरे जीअड़े, तां सरब सुख पावै मेरे मना।।

इसलिए हमें प्रभु सिमरन बंदगी में हर वक्त मन को रमाना चाहिए तभी हम इस संसार में सुखपूर्वक जीवन यापन कर पाएंगे और प्रभु के सांचे दरबार में भी हमें स्थान की प्राप्ति हो सकेगी। जहां फिर हमें सदा आनन्द ही आनंद की प्राप्ति होती रहेगी।

इंदर सिंह आहुजा

आपके पत्र

देश मे कई राज्यो में हिटवेव, बढ़ता पारा जनजीवन बेहाल

देश के कई राज्य हिटवेव की चपेट में है। गर्मी के तेवर तीखे है। बढ़ती गर्मी के कारण जनजीवन पर भारी असर देखने को मिल रहा है। गुजरात, राजस्थान, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार और उत्तरप्रदेश के कई जिले रेड अलर्ट पर है। घर से बाहर निकलना मुश्किल होता जा रहा है। 39 से 43 डिग्री तापमान में जनजीवन पर असर होता दिखाई दे रहा है। कई जिलों में गर्मी के कारण मौतें भी हुई है। कानपुर की बढ़ती गर्मी से हाल बेहाल है। वाराणसी का 43 डिग्री तापमान और कानपुर में 43.6 डिग्री तापमान से गले सूख रहे है। चमड़ी जल रही है, गर्मी में लोग घर से बाहर निकलना पसंद नहीं कर रहे है। शीतलता की आवश्यकता है। शीतल पेय और आइस डिश, आइस गोले, आइसक्रीम और गन्ने के जूस की दुकानें और हाथ लारियों पर लोगों की कतार दिखाई दे रही है। गर्मी में लू से बचने के लिए सूती कपड़े और दोपहरी में घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी जा रही है। बढ़ते तापमान से इस वर्ष बारिश जल्द आने के संकेत मौसम विभाग दे रहा है। कई जिलों में आंधी, बारिश के आसार है। गर्मी की वजह से जनजीवन प्रभावित हुआ है। दोपहर को मार्ग पर आवाजाही बन्द रहती है। गर्मी से और लू से बचने के जतन करना चाहिए। गर्मी के कारण अटैक की कई घटना अखबार में पढ़ने को मिल रही है। शीतलपेय, नारियल पानी और छाछ का इस्तेमाल भरपूर करना चाहिए। बासी भोजन से बचना चाहिए। खुराक का नियमित ध्यान रखा जाना चाहिए। बढ़ते तापमान और ग्लोबल वार्मिंग का असर जलवायु पर देखने को मिल रहा है। बिन मौसम बारिश और अचानक बारिश से फसलों को नुकसान हुआ है। बढ़ती गर्मी जानलेवा है। कई जगह अंधड़ और बारिश की बौछारों से वातावरण में ठंडक पसर गई है, लेकिन गर्मी से लोगों के स्वास्थ्य पर असर हो रहा है। अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। ओपीडी में भीड़ बढ़ रही है। तबियत का ध्यान रखा जाना चाहिए। अयोध्या में दो लोगो की मौत हो गई। 42 डिग्री गर्मी से मूक पशु पक्षियों पर प्रभाव पड़ रहा है। लोग घरों के बाहर पानी के परिंडे लगाकर पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। हाई राइजिंग बिल्डिंगों के कारण पंक्षियों के लिए पानी दूर-दूर तक कहीं नहीं मिलता। लुप्त होती प्रजाति से पक्षियों की कलरव कम सुनाई देती है। लोग गर्मियों में पानी के परिंडे लगाकर अबोल पक्षियों के लिए सेवा दे रहे हैं।

कांतिलाल मांडोत, सूरत

https://t.me/AllNewsPaperPaid

प्रकाशक, मुद्रक : राजीव रंजन श्रीवास्तव द्वारा पत्रकार प्रकाशन प्रा. लि. के लिए 506, आई.एन.एस. बिल्डिंग, 9, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित एवं बीएफएल इंफोटेक लि., सी 9, सेक्टर-3, नोएडा से मुद्रित। सम्पादक : राजीव रंजन श्रीवास्तव, (पी.आर.बी. एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार)। आर.एन.आई. नं. DELHIN/2008/24216. दिल्ली कार्यालय :फोन: 011-23718195,23357784, फैक्स: 011-43581404, नोएडा कार्यालय: फोन: 0120-4114404 फैक्स: 0120-4273770

ई-मेल: deshbandhudelhi@gmail.com वेब: www.deshbandhu.co.in

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 17 अंक 65

ब्रांड का बचाव

गोदरेज समूह ने अपने 127 वर्ष के इतिहास में एक मजबूत ब्रांड विकसित किया है। कुछ अनुमानों के मुताबिक यह देश के 10 सबसे प्रतिष्ठित और मूल्यवान ब्रांड में से एक है। बीते कई दशकों के दौरान उसके उत्पादों खासकर उपभोक्ताओं से जुड़े उत्पादों का मूल्यवर्द्धन हुआ है। परंतु इस दौरान समूह में आंतरिक समन्वय और पारिवारिक नियंत्रण के संस्थानीकरण के क्षेत्र में लगातार संघर्ष की स्थिति बनी रही। वास्तव में कोई 'गोदरेज समूह' है ही नहीं जो इसके सभी उपक्रमों को एकजुट करता हो, न ही टाटा संस की तरह कोई एक होल्डिंग कंपनी है। करीब एक दशक से भी अधिक पहले पारिवारिक कारोबार बोर्ड गठित करने की योजना भी फलीभूत नहीं हो सकी। भारत में परिवारों के स्वामित्व वाले कारोबारों के संस्थापकों की शुरुआती सख्ती के बाद आगे की पीढ़ियों में अलग-अलग दृष्टिकोण वाले कई हितधारक आ गए। यह भी समस्याओं की एक वजह रही।

बहरहाल, हाल ही में घोषित गोदरेज परिवार की हिस्सेदारी में विभाजन जिसे 'स्वामित्व पुनर्संयोजन' कहा जा रहा है, वह ऐसी असहमति के प्रबंधन वाला अपेक्षाकृत कम प्रभाव डालने वाला और सौहार्दपूर्ण तरीका प्रतीत होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि मोटे तौर पर गोदरेज समूह की सूचीबद्ध कंपनियों के अंशधारक शायद संपत्ति के उस नुकसान से बच जाएं जो आमतौर पर पारिवारिक विवादों के बाद होता है। विभिन्न सूचीबद्ध कंपनियां मसलन गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड और गोदरेज प्रॉपर्टीज लिमिटेड एक तरफ रहेंगी और इन्हें आदि और नादिर गोदरेज के परिवार चलाएंगे जबकि उनके भाई बहिन यानी जमशेद गोदरेज और स्मिता गोदरेज कृष्णा गोदरेज एंटरप्राइजेज समूह को चलाएंगे जिनमें गोदरेज ऐंड बॉयस की गैर सूचीबद्ध फर्म का दबदबा है। कई लोगों की रुचि इस बात में थी कि विक्रोली में भारी भरकम लैंड बैंक का प्रबंधन किस प्रकार होगा। इस पर गोदरेज ऐंड बॉयस का नियंत्रण है। करीब 3,000 एकड़ से अधिक की यह जमीन एक सदी से परिवार के पास है और इसमें मुंबई के निकट ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से लगी हुई काफी जमीन शामिल है।

परिवार ने अपनी मुख्य प्रेस विज्ञप्ति में इस जमीन के भविष्य को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी है। बहरहाल, एक अन्य प्रेस विज्ञप्ति में जोर देकर कहा गया कि जमीन मालिक और डेवलपर गोदरेज ऐंड बॉयस तथा उसकी अनुषंगी गोदरेज कंस्ट्रक्शंस तथा डेवलपमेंट मैनेजर और मार्केटर गोदरेज प्रॉपर्टीज मिलकर इस जमीन पर काम करना जारी रखेंगे। सारी जमीन विकास कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं है लेकिन मुंबई की 1,000 एकड़ जमीन पारिवारिक विवाद पैदा करने के लिए पर्याप्त है। खुशकिस्मती से ऐसा प्रतीत होता है कि परिवार इससे बचने में कामयाब रहा है। बहरहाल इस जमीन का विकास किस प्रकार होगा और क्या आदि गोदरेज का पक्ष इस पर नियंत्रण खो चुका है, यह आगे पता चलेगा। जमीन के आकार और पर्यावरण को लेकर उसकी संवेदनशीलता तथा मुंबई में जमीन की कमी को देखते हुए ट्रस्टीशिप और प्रबंधन को लेकर गहरे सवाल हैं। ये न केवल परिवार बल्कि शहर और सरकार को भी प्रभावित करते हैं।

जमीन के विकास में कोई भी मूल्यवर्द्धन आंशिक रूप से गोदरेज के ब्रांड नाम के साथ भी जुड़ा होगा। ऐसे में व्यापक प्रश्न यह है कि दोनों अलग-अलग समूह जो परिवार के गोदरेज ब्रांड और लोगो को साझा करते रहेंगे, वे इस एक सदी से भी अधिक पुराने ब्रांड की छवि को कैसे बरकरार रख पाएंगे। ठोस ढंग से बात करें तो दोनों में से कोई भी पक्ष उन हालात का प्रबंधन कैसे करेगा जहां उसे लगता है कि दूसरा पक्ष इस साझा ब्रांड के मूल्य को कम कर रहा है। स्पष्ट संस्थागत ढांचे के अभाव में यह सद्भावना पर निर्भर करेगा।

अजय मोहंती

कराधान की दृष्टि से सही विचार नहीं

संपत्ति और विरासत पर कर लगाने के प्रयास पहले भी किए जा चुके हैं। इससे जुड़े अनुभव अच्छे नहीं रहे हैं। इन पर नए सिरे से विचार करना उचित नहीं प्रतीत होता है। बता रहे हैं अजय शाह

देश में इस समय यह लोकलुभावन मांग जोरों पर हैं अमीरों से संपत्ति छीनकर उसे गरीबों में बांट दिया जाए। यह रास्ता निरंतर गरीबी और आर्थिक नाकामी की ओर ले जाता है। इन दिनों संपत्ति कर और विरासत कर के रूप में जिन दो विषयों पर चर्चा की जा रही है वे सार्वजनिक वित्त के क्षेत्र में सुपरिचित विषय हैं। पूरी दुनिया में इनी उपयोगिता कम होने को लेकर विश्लेषण हुए हैं। भारत में भी इन्हें लगाने की कोशिश की जा चुकी है। इन्हें दोबारा नहीं लगने देना चाहिए।

आमतौर पर एक दशक में एक बार भारत में संपत्ति और विरासत पर कर का मुद्दा बहस में आता है। ये मुद्दे 19वीं सदी से ही विचार में आते रहे हैं और कई देशों ने इन्हें अपनाने का प्रयास भी किया। अधिक आजादी हासिल करने के लिए इन करों को हटाए जाने के साथ ही अच्छी खासी समृद्धि हासिल हुई है।

भारत में 1953 से 1985 तक संपदा शुल्क लगता था। इसकी दरें 85 फीसदी तक थीं लेकिन व्यवहार में संग्रह की राशि बहुत कम होती थी। राजीव गांधी ने इसे समाप्त किया। संपदा या विरासत पर कर लगाने की व्यवस्था कई देशों में आज भी लागू है। औसतन 24 ओईसीडी देशों में यह कर राजस्व में 0.5 फीसदी का हिस्सेदार है। सार्वजनिक प्रशासन की दृष्टि से देखें तो इसमें मामूली राजस्व के लिए काफी जटिलताओं का सामना करना होता है।

संपत्ति कर के मामले में संभावनाएं और भी कमजोर हैं। भारत में इसकी शुरुआत 1957 में की गई थी। इससे 2012-13 में 800 करोड़ रुपये का राजस्व जुटाया गया। इसे 2015 में समाप्त कर दिया गया। चार ओईसीडी देशों में यह लागू है और इससे नाम मात्र का राजस्व आता है।

इन्हें हासिल करने की प्रक्रिया में कीमत चुकानी होती है: मसलन देश में समझदारी भरी कर व्यवस्था लागू करने के बुनियादी काम पर ध्यान नहीं दे पाना। भारत में कराधान काफी ऊंचे स्तर पर है। देश में व्यक्तिगत आय कर की उच्चतम दर 42 फीसदी है। कॉर्पोरेट आय कर 25 फीसदी और अधिकतम जीएसटी की दर 18 फीसदी है। आयात, गैर टैरिफ अवरोध आदि पर कर स्थिर गति से बढ़ रहा है। अगर 1991 के बाद के दौर से तुलना करें तो हमारे यहां आयात कर की दर काफी अधिक है। इससे अत्यधिक उच्च कर वाला माहौल तैयार होता है और कर अधिकारियों को मनमाना अधिकार प्रदान करता है। कर नीति में हमारी प्राथमिकता संपदा कर या विरासत की चुनौती से जूझने के बजाय कर नीति और कर प्रशासन के क्षेत्र में बेहतर काम की होनी चाहिए। एक अर्थशास्त्री ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी काम के व्यवहार में सफल होने पर यह देखता है कि क्या यह सिद्धांत में भी सफल है। क्या कोई अनुभव केवल चुनिंदा दुर्घटनाओं पर आधारित होता है या फिर कोई अवधारणात्मक आधार होता है जिनसे बचा न जा सके। ऐसे में तह तक जाकर यह सवाल पूछना सही होगा कि विरासत कर और संपदा कर का प्रदर्शन सही रहेगा या नहीं? लोग प्रोत्साहन पर प्रतिक्रिया देते हैं। अधिक कराधान को लेकर पहली प्रतिक्रिया कम काम के रूप में सामने आती है। अगर विरासत और संपदा कर से दंडित किया जाएगा तो लोग संपत्ति बनाने के लिए कम काम करेंगे। यह देश के लिए नुकसानदायक होगा।

दूसरी प्रतिक्रिया है कर किफायत ढांचे में नई जान फूंकना। अपने अंतिम समय में वसीयत बनाने के बजाय लोग अपनी परिसंपत्ति जिंदा रहते ही चुने हुए लोगों को हस्तांतरित कर देंगे। यह सरकार की राजस्व प्राप्ति की क्षमता को बाधित करते हुए उनके व्यवहार में विसंगति लाएगा। कई माता-पिता कर से बचने के लिए बच्चों को जल्दी संपत्ति देकर अधिकार खोने के बजाय अप्रत्याशित निधन के पहले के वर्षों में बार-बार वसीयत को बदलना पसंद कर सकते हैं। तीसरी प्रतिक्रिया है कारोबारी गतिविधियों को किसी मित्रतापूर्ण क्षेत्र मसलन दुबई, श्रीलंका, केमैन आइलैंड, सिंगापुर या आयरलैंड में स्थानांतरित करना। यह बात कर राजस्व को प्रभावित करती है।

अगर भारत की अर्थव्यवस्था एक खुली अर्थव्यवस्था होती तो कुछ भी गलत नहीं होता। एक व्यक्ति आयरलैंड में कर चुकाता और भारत में कारोबारी गतिविधियां संचालित करता। परंतु भारत खुली अर्थव्यवस्था वाला देश नहीं है। हमारे यहां सीमा पार गतिविधियों को लेकर कई दिक्कतें हैं। चालू खाते और पूंजी खाते में परिवर्तनीयता अनुपस्थित है। ऐसे में एक बार जब कोई व्यक्ति अपना कर आवास देश के बाहर कर लेता है तो एक तरह के अलगाव की भावना घर कर जाती है तथा देश में संगठन बनाने की भावना कमजोर पड़ती है। भारत का भविष्य करीब 10,000 कंपनियों के हाथ में है और यह बेहतर है कि भारतीय राज्य को इस प्रकार तैयार किया जाए कि वह इन नेतृत्वकारी टीम में से प्रत्येक की ऊर्जा और महत्त्वाकांक्षा का पोषण करे। संक्षेप में कहें तो संपत्ति कर और विरासत कर कमजोर प्रदर्शन करते हैं क्योंकि वे लोगों के व्यवहार को बाधित करते हैं जिससे जीडीपी को नुकसान पहुंचता है। लोगों के व्यवहार में आई विसंगति कर राजस्व को प्रभावित करती है। ऐसे में ये कर दुनिया के सबसे बुरे उदाहरण पेश करते हैं। व्यवहारगत विकृतियां जीडीपी को प्रभावित करती हैं, एक जटिल कर अफसरशाही तैयार होती है जो भारत जैसे देश में कर अधिकारियों को मनमाना अधिकार दे सकती है और कर राजस्व में कमी आती है।

यह बहस पुनर्वितरण बनाम वृद्धि की व्यापक पहेली में सटीक बैठती है। हमें ऐसी बहसों में अपना ध्यान नहीं भटकाना चाहिए कि एक पिज्जा किस प्रकार बांटा जाएगा। भारत एक निम्न मध्य आय वाला देश है। हमारे सामने एक बड़ी चुनौती है और वह है आगामी 100 वर्षों तक वृद्धि को बरकरार रखना तथा विकासशील राज्य की क्षमता बनाए रखना। सन 1947 में गरीब रहे देशों में से केवल चार आज उन्नत अर्थव्यवस्था वाले देश बन सके हैं। विकास की यात्रा एक कठिन यात्रा है जहां सफलता की कोई गारंटी नहीं। ऐसे में वर्ग को लेकर जंग छेड़ना निजी गतिशीलता पर बुरा असर डालेगा और राज्य की क्षमता को प्रभावित करेगा।

लैंट प्रिचिट कहते हैं कि दुनिया भर में गरीबी की दर में 99 फीसदी अंतर को केवल एक आंकड़े से समझा जा सकता है और वह है: औसत आय। अगर हम गरीबी दर में बदलाव करना चाहते हैं तो हमें औसत आय पर ध्यान देना होगा। कर, सामाजिक कार्यक्रम आदि के माध्यम से पुनर्वितरण के सरकार के सभी प्रयास शेष एक फीसदी में बैठते हैं और कम वृद्धि की कीमत पर आते हैं।

(लेखक एक्सकेडीआर फोरम में शोधकर्ता हैं)

कैसा रहने वाला है इलेक्ट्रिक कारों का भविष्य?

अनदेखी
सुवीन सिन्हा

द इकॉनमिस्ट पत्रिका जो स्वयं को एक समाचार पत्र कहती है, वह एक पुराना और प्रतिष्ठित संस्थान है। कहा जाता है कि उसे सफल लोग पढ़ते हैं जबकि कम सफल लोग, मिसाल के तौर पर आपके इस स्तंभकार जैसे लोग उसे कभी-कभार पढ़ते हैं। एक बार ऐसे ही उसे पढ़ते हुए द इकॉनमिस्ट वेबसाइट की एक खबर का शीर्षक जेहन में अटक गया। 14 अप्रैल, 2023 के अंक में शीर्षक था, 'भविष्य बिजली से चलने वाले वाहनों का है।' भारत में कुछ लोगों को द इकॉनमिस्ट का वह लहजा पसंद नहीं आता है जिसमें वह भारत की अर्थव्यवस्था और राजनीति को कवर करता है। खासतौर पर तब जबकि अर्थव्यवस्था और राजनीति, दोनों शब्द एक साथ आते हैं। परंतु पत्रिका ने वाहन क्षेत्र को लेकर जो कहा वह बात भारत में कई लोगों को पसंद आई होगी।

पेट्रोल-डीजल इंजन (आईसीई) से इलेक्ट्रिक व्हीकल को अपनाने की ओर बढ़ना भारत जैसे देश के लिए एक रूमानी संभावना है जिसने लैंडलाइन फोन की कमी की स्थिति से सीधी छलांग लगाई और स्मार्टफोन की प्रचुरता वाली स्थिति में आ गया। इसे अंग्रेजी के चार अक्षरों वाले शब्द से स्पष्ट किया जा सकता है जो 'एस' से आरंभ होता है। यही वह शब्द है जिसका भारतीय गेंदबाजी के लिए इस्तेमाल करने से राहुल द्रविड़ पिछले वर्ष हिचकिचा गए थे। कुछ समय पहले तक चर्चा थी कि भारत कुछ वर्षों में आईसीई कारों के पंजीयन पर रोक लगा देगा, शायद इस दशक के अंत तक वह ऐसा कर दे। बिजली से चलने वाले दोपहिया वाहन सड़कों पर बड़ी तादाद में नजर आ रहे हैं। इस वर्ष मार्च में 1,38,000 बिजली चालित दोपहिया वाहनों का पंजीयन हुआ। इससे पहले मई 2023 में 1,03,000 इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन पंजीकृत हुए थे। मार्च में हुआ पंजीयन फरवरी की तुलना में करीब दोगुना था। इस महीने दोपहिया वाहनों में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी नौ फीसदी रही। अकेले स्कूटर के क्षेत्र में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी मार्च में 28 फीसदी तक पहुंच गई।

यह सही है कि अप्रैल का महीना निराशाजनक रहा और ऐसा मुख्य तौर पर सरकारी सब्सिडी में कमी आने की वजह से हुआ परंतु बिजली चालित दोपहिया वाहन का उपयोग मजबूत बना हुआ है। उनकी कीमतों में कमी आ रही है। उन्हें चार्ज करना आसान है। बाजार में ऐसे कई मॉडल आ चुके हैं और कई आने वाले हैं। कम दूरी के आवागमन के लिए ये बहुत अच्छे विकल्प हैं।

उदाहरण के लिए ई-कॉमर्स डिलिवरी वगैरह। कारें अधिक लंबी दूरी का सफर तय करती हैं क्योंकि सड़क नेटवर्क में सुधार के कारण लोगों की सड़क यात्राएं बढ़ी हैं। उन्हें बड़ी बैटरी की आवश्यकता होती है जो महंगी आती है और चार्ज होने में अधिक समय लेती है। कई चर्चित इलेक्ट्रिक कारों की कीमत अभी भी बहुत अधिक है हालांकि टाटा और एमजी ने कुछ सस्ती इलेक्ट्रिक कारें बनाई हैं। लक्जरी कारों की श्रेणी में इनका प्रदर्शन बेहतर है क्योंकि वहां कीमत कार खरीदने में अहम भूमिका नहीं निभाती। वहां अक्सर लोगों के पास एक से अधिक कारें होती हैं और लंबी दूरी के लिए आईसीई कार होती है।

परंतु जब इलेक्ट्रिक कारों की बात आती है तो हमें इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि इलेक्ट्रिक कारों पर 5 फीसदी वस्तु एवं सेवा कर लगता है और कुल कारों में इनकी हिस्सेदारी दो फीसदी के करीब है। तुलनात्मक रूप से देखें तो हाइब्रिड कारों पर 28 फीसदी वस्तु एवं सेवा कर लगता है लेकिन उपकर सहित इस पर लगने वाला कर बढ़कर 43 फीसदी हो जाता है।

केवल छोटी कारों पर इससे कम कर दर लगती है। आईसीई कारों पर भी वस्तु एवं सेवा कर लगता है लेकिन उपकर सहित इन पर कुल कर 50 फीसदी हो जाता है। कार के आकार और इंजन क्षमता के अनुसार इनमें अंतर होता है। अभी भी कुछ अनुमान हैं जो कहते हैं कि देश में वित्त वर्ष 2023 से 2030 के बीच 4.2 करोड़ यात्री वाहन बिकेंगे जिनमें इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी करीब 60 लाख होगी। यानी बहुत बड़ी तादाद में दूसरी किस्म की कारें बिकेंगी। याद रखना होगा कि अनुमान लगाया गया था कि 2030 तक देश में आईसीई कारों का पंजीयन बंद हो जाएगा।

दूसरी किस्म की कारों में हाइब्रिड कारें शामिल होंगी जिनमें आईसीई के अलावा बैटरी भी होती हैं। ये कारें इलेक्ट्रिक कारों की तुलना में सस्ती होती हैं। इनके साथ ये चिंता भी नहीं जुड़ी होती है कि ये कितनी दूरी तय कर पाएंगी और ये बात इन्हें बहुत अधिक उपयोगी बनाती है। भारत में ऐसी कारों की तादाद बढ़ी है। टोयोटा ने भारत में अपनी हाइब्रिड तकनीक पेश की। यह तब चर्चा में आई थी जब हॉलीवुड के सितारों ने इस सदी के आरंभ में प्रियस कार चलानी शुरू की थी। कंपनी ने देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजूकी के साथ साझेदारी में भी कई कारें बेचना आरंभ किया है।

दिलचस्प है कि एचएसबीसी रिसर्च ने जनवरी में एक रिपोर्ट पेश करते हुए कहा, 'हाइब्रिड कारें ईवी की तुलना में काफी कम प्रदूषण उत्पन्न करती हैं।' रिपोर्ट में कहा गया है कि ढेर सारे आंकड़ों, प्रतिशत, उत्सर्जन इकाइयों और भारत में गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन की हिस्सेदारी के साथ इलेक्ट्रिक वाहनों और हाइब्रिड उत्सर्जन को एक स्तर पर आने में सात से 10 वर्ष का समय लगेगा। इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर उत्साहित कंपनियों के अंदरूनी सूत्र रिपोर्ट को खारिज करते हैं। उनका कहना है कि हाइब्रिड एक पुरानी तकनीक है जिस पर भारत में जोर दिया जा रहा है। परंतु यह बात तो किसी भी कार तकनीक के बारे में कहा जा सकता है।

हाइब्रिड को लेकर अन्य जगहों पर भी चर्चा हो रही है। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने जनवरी में अमेरिका में हाइब्रिड के दोबारा उभार के बारे में लिखा कि इसकी बिक्री मजबूत है। रिपोर्ट में कहा गया कि कई अमेरिकी विद्युतीकरण को लेकर खुला रुख रखते हैं लेकिन वे पूरी तरह इलेक्ट्रिक कार को अपनाने के लिए तैयार नहीं हैं। रॉयटर्स में डेट्रॉइट से प्रकाशित एक हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि वाहन निर्माता कंपनियां और आपूर्तिकर्ता उपभोक्ता मांग पर दांव लगा रहे हैं। इस बीच आईसीई और इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर एक समझौता टिकाऊ रुझान वाला है। फरवरी में अमेरिका में हाइब्रिड कारें इलेक्ट्रिक कारों की तुलना में पांच गुना तेजी से बढ़ीं।

यह सही है कि विश्व स्तर पर टोयोटा की स्थिति बेहतर हुई जबकि इलेक्ट्रिक कारों के लिए प्रसिद्ध टेस्ला को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।

आपका पक्ष

साझी समृद्धि में रोजगार आवश्यक

लेख 'रोजगार और साझी समृद्धि की दिशा में काम जरूरी' वर्तमान में रोजगार सृजन को सबसे बड़ी प्राथमिकता देता है। इस दिशा में राजनीतिक पटल पर विमर्श में कुछ भ्रांतियां हैं जिनका निवारण आवश्यक है। जनकल्याणकारी योजनाओं या मुफ्त के बिजली, पानी और राशन से रोजगार सृजन नहीं होता और न ही हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ता है, न ही लाभार्थियों की आर्थिक स्थिति सुधरती है और न ही उनकी रोजगार क्षमता का विकास होता है। कृषि में रोजगार सृजन पर भी अर्थशास्त्रियों के विरोधाभासी विचार हैं। आरक्षण के भरोसे न रोजगार सृजन हुआ, न पर्याप्त सरकारी नौकरियां सृजित हुईं और न ही वंचितों को उच्च शिक्षा और उनकी रोजगार क्षमता में कोई लाभ हुआ बल्कि आरक्षितों को सरकारी नौकरियों के सहारे छोड़ दिया गया। बड़े औद्योगिक घरानों पर भी अनेक विमर्श चल रहे हैं परंतु यही औद्योगिक घराने अपने देश के औद्योगिक ढांचे और बड़ी परियोजनाओं में भारत को आत्मनिर्भर बनाते हैं और विदेश में भी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रतिस्पर्धा देते हैं। सबसे अधिक रोजगार सृजन बड़ी औद्योगिक इकाइयों और उनकी सहायक कंपनियों में सृजित होता है। भारत जैसे विशाल, विकासशील और कृषि प्रधान देश में कृषि में रोजगार सृजन को महत्त्व दिया जाना चाहिए और कृषि श्रमिकों को कौशल प्रशिक्षण से अधिक उत्पादन के योग्य बनाकर अच्छे पारिश्रमिक के योग्य बनाया जा सकता है। रोजगार सृजन के माध्यम शिक्षा, कृषि, उद्योग व्यापार, स्वावलंबन, सेवा क्षेत्र और तकनीक (एडटैक, फिनटैक, एग्रीटेक, सूचना प्रौद्योगिकी, एआई) ही हैं और इनको ही आधार मान कर सभी राज्यों और सुदूरवर्ती क्षेत्रों में उद्योग व्यापार का बुनियादी ढांचा खड़ा किया जा सकता है। देश में 30 करोड़ लोग रोजगार के लिए अपने मूल स्थान से देश भर में विस्थापित हैं। सच्चाई यह है कि उद्योग-व्यापार और सेवा क्षेत्र के प्रमुख केंद्र दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, हिमाचल प्रदेश तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश ही बने हुए हैं जबकि बिहार, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, केरल, आंध्र प्रदेश, उत्तर पूर्व, जम्मू-कश्मीर, तेलंगाना में बड़े औद्योगिक बुनियादी ढांचे का अभाव है या मात्र एक दो स्थानों तक ही सीमित हैं। रोजगार सृजन इस देश की सबसे बड़ी प्राथमिकता है और इसी के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक असमानताएं दूर होंगी।

विनोद जौहरी, दिल्ली

रोजगार सृजन इस देश की सबसे बड़ी प्राथमिकता है और इसी के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक असमानताएं दूर होंगी

ज्यादा प्रभावित हो सकता है भारतीय कारोबार

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ईरान और इजरायल दोनों से भारत की मित्रता के साथ घनिष्ठ व्यावसायिक संबंध भी हैं। चूंकि दोनों देशों के बीच भीषण युद्ध जैसी स्थिति बन गई है तो इसका सीधा प्रभाव भारतीय आयात-निर्यात, भारतीय बाजार और किसी सीमा तक हमारी अर्थव्यवस्था पर होगा। किसी एक देश से अगर बेहतर संबंध बनाए रखते हैं तो दूसरे से शत्रुता होना स्वाभाविक है। 'आगे कुआं पीछे खाई' जैसी स्थिति भारतीय कारोबार को प्रभावित करेगी।

रमेशचंद्र कर्नावट, उज्जैन

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो - पीटीआई

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने बुधवार को ओडिशा के तट पर डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से मिसाइल-आधारित कम भार वाली एक आयुध प्रणाली 'सुपरसोनिक मिसाइल-असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉरपीडो' (स्मार्ट) का सफल परीक्षण किया। 'स्मार्ट' नई पीढ़ी की मिसाइल-आधारित कम भार वाली एक आयुध प्रणाली है, जिसमें एक हल्का टॉरपीडो लगाया जाता है और इस टॉरपीडो का इस्तेमाल पेलोड की तरह होता है।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

विचार
नवभारत टाइम्स
नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । गुरुवार, 2 मई 2024

रुख पर सवाल

ऐन चुनावों के बीच जिस तरह के संगीन आरोप लगे और विवाद खड़ा हुआ, उसके बाद हासन लोकसभा सीट से मौजूदा सांसद, इस चुनावों में प्रत्याशी और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ भी गई JDS की कार्रवाई स्वाभाविक ही कही जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि अगर अभी कर्नाटक में वोटिंग बाकी न होती और विपक्षी कांग्रेस के साथ ही सहयोगी BJP का भी दबाव न होता, तब भी क्या पार्टी नेतृत्व का यही रवैया होता?

JDS से प्रज्वल रेवन्ना निलंबित

देरी क्यों | मंशा पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि इस मामले की सुगबुगाहट पिछले साल जून से थी। तब प्रज्वल रेवन्ना ने अदालत का रुख किया था। उन्होंने कोर्ट से मांग की थी कि उनसे जुड़े कुछ फेक विडियो हैं, जिन्हें पब्लिश करने से मीडिया संस्थानों को रोका जाए। कर्नाटक में BJP का JDS के साथ गठबंधन है। हासन से एक स्थानीय BJP नेता ने आम चुनाव से पहले अपनी पार्टी को इस मामले की जानकारी देते हुए आगाह किया था कि प्रज्वल और उसके पिता एचडी रेवन्ना को टिकट नहीं मिलना चाहिए।

छवि की चिंता | विडियो सामने आने के बाद JDS के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी की प्रतिक्रिया भी निराश करने वाली रही। उन्हें इस मामले में बड़ी बात यही दिखी कि विडियो हासन में वोटिंग के पहले क्यों रिलीज किए गए। साथ ही, उनकी चिंता थी कि केस से देवेगौड़ा का नाम न जोड़ा जाए। आरोपी प्रज्वल ने जब विडियो पब्लिश होने से रोकने के लिए अदालत का रुख किया तो उनकी भी चिंता अपनी इमेज को लेकर थी। इन सबके बीच पीड़ित महिलाओं का दर्द कहीं खो जाता है। क्या उनकी इमेज के कोई मायने नहीं?

अफसोस की बात | सबसे दुखद पहलू यह है कि इस पूरे प्रकरण का घटनाक्रम चौंकाता नहीं है। यह आम बात लगने लगी है - ताकतवर नेता, मजबूर महिलाएं और कमजोरों की अनदेखी करने वाला सिस्टम। हाल के कितने सारे मामले ध्यान में आ जाते हैं। कुछ ही समय पहले ऐसे ही आरोपों के साथ देश के जाने-माने और ओलिंपिक मेडल विनर पहलवान सड़क पर उतरे थे। उन्हें भी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ केस दर्ज कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा था।

नजीर बने | इस तरह की घटनाओं का बार-बार होना बताता है कि कुछ ताकतवर लोग खुद को नियम-कानून से ऊपर समझते हैं और तंत्र अपने लुंज-पुंज व्यवहार से उनकी इस समझ को मजबूती देता है। दिक्कत सामाजिक परिवेश में भी है, जहां एक महिला के लिए अपनी लड़ाई लड़ना मुश्किल होता है। लड़ाई में साथ देना तो दूर, उसे भावनात्मक समर्थन भी नहीं मिल पाता। जरूरी है कि इस मामले की तह तक जाकर सचाई का पता लगाया जाए और दोषी के खिलाफ जल्द से जल्द उचित कार्रवाई करके इसे एक नजीर की तरह पेश किया जाए।

साड्डी दिल्ली
सभाओं के मैदान
विवेक शुक्ला

रामलीला मैदान से कनॉट प्लेस में सुपर बाजार की दूरी एक-सवा किलोमीटर से ज्यादा नहीं है। इन दोनों जगहों पर लोकसभा चुनावों के दौरान इंदिरा गांधी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी लाजिमी तौर पर दिल्ली वालों के सामने जोशीले भाषण दिया करते थे। वाजपेयी शंकर मार्केट या फायर ब्रिगेड स्टेशन पर अपनी कार खड़ी कर पैदल ही सुपर बाजार के सभास्थल पर लोगों से मिलते हुए पहुंचा करते थे। INA मार्केट के आगे रामलीला मैदान में भी दोनों की सभा होती थी। लेकिन बीते दो-तीन लोकसभा चुनावों से ना तो सुपर बाजार और ना ही INA के पास के मैदान में सभाएं होती हैं। INA का रामलीला मैदान तो फ्लाईओवर बनने के कारण खत्म हो गया। वहीं, चांदनी चौक सीट के लिए गांधी मैदान और हौज काजी में बड़ी सभाएं होती रही हैं, लेकिन अब गांधी मैदान भी नहीं रहा। ईस्ट दिल्ली सीट के लिए राजनीतिक पार्टियां गांधी नगर चौक, शाहदरा अनाज मंडी और भोलाथ नगर के रामलीला ग्राउंड में सभाएं अवश्य करती हैं। इधर, जयप्रकाश नारायण, इंदिरा गांधी, एच.के.एल भगत, किशोरी लाल जैसे दिग्गज नेताओं ने बड़ी सभाओं को संबोधित किया था। शाहदरा के सोशल वर्कर नरेश कौशिक बताते हैं कि 1991 के लोकसभा चुनाव के दौरान राजीव गांधी ने भी इसी मैदान में एक विशाल सभा में अपनी बात रखी थी। तब राजीव गांधी रात को करीब एक बजे अलीगढ़ से सभास्थल पर पहुंचे थे। उस रोज देर रात तक हजारों लोग उनका इंतजार कर रहे थे। उस सभा के दो दिनों के बाद ही राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। इस बीच, सोशल मीडिया के असर के बावजूद दिल्ली-6 में होने वाली सभाओं में अब भी जनभागीदारी काफी रहती है। जिसे दिल्ली 1952 के लोकसभा चुनाव से बाहरी दिल्ली सीट के रूप में जानती थी, वह 2009 लोकसभा चुनाव से कहलाने लगी नॉर्थ-वेस्ट दिल्ली सीट। तब लोकसभा सीटों का परिसीमन हुआ था। दिल्ली देहात का बड़ा हिस्सा नॉर्थ-वेस्ट दिल्ली सीट में ही रहा। इस सीट के मतदाताओं से मुखातिब होने के लिए नेता मंगोलपुरी के रामलीला मैदान, इंदिरा पार्क, सुल्तानपुरी, पशु मेला ग्राउंड, नांगलोई और नरेला में सभाएं करना पसंद करते हैं।

इस बीच, द्वारका का रामलीला मैदान भी बड़ी चुनावी सभाओं के लिए मशहूर होता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इधर साल 2015 में दिल्ली विधानसभा चुनाव के समय विशाल सभा को संबोधित किया था।

Shital Verma

एकदा
सत्य के आगे सज़ा क्या

वह भारत की आजादी के लिए संघर्ष का दौर था। डॉ. राममनोहर लोहिया ने किसी सभा में अंग्रेज शासकों के विरुद्ध ज्वलंत भाषण दिया। नतीजा यह कि उन्हें पुलिस ने कोर्ट में पेश किया और उनका भाषण जज के सामने पढ़ा गया। जज ने भाषण सुनने के बाद डॉ. लोहिया से पूछा 'आपको कुछ कहना है?' 'जी हां, कहना यह है कि यह भाषण गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है।' डॉ. लोहिया ने उत्तर दिया। 'ठीक है तो आप अपना भाषण स्वयं लिखकर प्रस्तुत कर सकते हैं।' न्यायालय ने अपनी बात कही। डॉ. लोहिया ने अपना भाषण स्वयं लिखा और न्यायाधीश महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया। उसे पढ़कर न्यायाधीश बोले 'मिस्टर लोहिया! आपका यह भाषण तो पुलिस की ओर से पेश किए गए भाषण से भी अधिक कठोर और आपत्तिजनक है। आपने ऐसा क्यों किया?' डॉ. लोहिया ने कहा, 'महोदय! सत्य के आगे सजा की क्या हैसियत है? पुलिस ने जो कुछ लिखकर दिया उससे तो दुनिया को लगेगा कि लोहिया का देशप्रेम निस्तेज है। मेरे भाषण का अंग्रेजी अनुवाद भ्रामक है। आप मेरे लिखे हुए भाषण पर ही विचार कर मेरी सजा निश्चित कीजिए। यह हमारे आत्मसम्मान का प्रश्न है। आत्मसम्मान के आगे किसी भी सच्चे भारतीय को सजा की परवाह नहीं है।' अंग्रेज न्यायाधीश उस स्वाभिमानी भारत के सपूत को आंखें फाड़कर देखता रह गया।

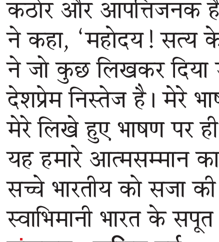
Subrata Dhar

संकलन : ललित गर्ग

दूसरे देश इस समय हिंदुस्तान का लोहा मान रहे हैं, लेकिन कई चुनौतियां भी बनी हुई हैं

बदलती दुनिया में कहां खड़ा है भारत

एस. जयशंकर

आज दुनिया में काफी उथल-पुथल मची है। कई देश कोविड महामारी से हुए सामाजिक-आर्थिक नुकसान से उबरने में लगे हैं। यूक्रेन में चल रहे संघर्ष से ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा पर गंभीर असर पड़ा है। अक्टूबर 2023 में इस्राइल पर हुए आतंकी हमले से पश्चिम एशिया में शुरू हुई लड़ाई गंभीर और व्यापक रूप ले सकती है। लाल सागर में ड्रोन और मिसाइल हमले वैश्विक शिपिंग को अस्त-व्यस्त कर रहे हैं। यहां तक कि अदन की खाड़ी में समुद्री डकैती की नई लहर और खतरनाक हो गई है। एशिया में क्षेत्रीय दावे और कानूनों और समझौतों की अवहेलना ने नए तनाव पैदा कर दिए हैं।

भारत के लिए ज्यादा अनिश्चितताएं चीन के साथ LAC (Line of Actual Control) पर दबाव, सीमा पार से आतंकवाद के खतरे और म्यांमार की सीमा पर अस्थिरता से बढ़ी हैं। हालांकि इनमें से प्रत्येक को उचित प्रतिक्रिया दी गई है। लेकिन कुल मिलाकर ये स्थितियां आने वाले दिनों में एक मजबूत, समझदार और सक्षम नेतृत्व की जरूरत को स्पष्ट करती हैं।

कोविड युग ने अति-केंद्रीकरण के खतरों को प्रदर्शित किया है, चाहे वो manufacturing sector हो या technology। महत्वपूर्ण और उभरती टेक्नॉलजी का दायरा इसे और गंभीर बना देता है। ऐसे में अच्छा यही होगा कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के साथ ही वैश्विक अर्थव्यवस्था भी जोखिम से मुक्त हो। ऐसा केवल विभिन्न क्षेत्रों में 'मेक इंडिया' को गति देने व लचीली और विश्वसनीय सप्लाई चेन से जुड़कर ही किया जा सकता है।

डिजिटल क्षेत्र में, भारत को एक विश्वसनीय और पारदर्शी देश के रूप में अपने रेकॉर्ड को और आगे ले जाना है। इसका मतलब हमें सेमीकंडक्टर क्षमताओं को बढ़ाना और सही डेटा पॉलिसी को अपनाना होगा। खुद को आर्टिफिशल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, ड्रोन, अंतरिक्ष और ग्रीन टेक्नॉलजी के युग के लिए भी तैयार करना होगा। साथ ही, देश की स्वास्थ्य, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना होगा। इसके लिए दूरदर्शी नेतृत्व की जरूरत है, जो टेक्नॉलजी की परिवर्तनकारी क्षमता को समझता हो और मजबूत विकास के लिए प्रतिबद्ध हो।

आज भारत अपने उम्दा बुनियादी ढांचे, बेहतर कारोबारी माहौल और अपेक्षित प्रतिभा की बदौलत आकर्षक निवेश गंतव्य है। लेकिन इसकी वजह हमारी राजनीतिक स्थिरता और नीतिगत पूर्वानुमान है। पिछले दशक में जमीनी स्तर पर सुधार और डिलिवरी ही विदेशों में हमारी विश्वसनीयता के स्रोत रहे हैं। कई मायनों में वैश्वीकरण ने एक अंतरराष्ट्रीय वर्कप्लेस भी बनाया है, जिसका उपयोग भारत अपनी बेहतरी के लिए कर सकता है। इसके लिए हमारे कौशल बेस को बढ़ाना, मोबिलिटी समझौते करना और विदेश में रह रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा अहम तत्व हैं।

भविष्य की तैयारी
- 'मेक इन इंडिया' को गति देने की जरूरत
- सेमीकंडक्टर क्षमताओं को बढ़ाना होगा
- अमृत काल में बने मौकों को पहचानें युवा

यह स्वाभाविक है कि दुनिया भारतीय लोकसभा चुनाव में गहरी दिलचस्पी ले। आखिरकार यह मानव इतिहास की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। यह चुनाव बाकी देशों के लिए एक बढ़ते प्रभाव वाले देश में आयोजित हो रहा है। इसके अलावा, हमारी चुनावी मशीनरी की क्वॉलिटी अन्य देशों के लिए उदाहरण है। महत्वपूर्ण है कि चुनाव में दिलचस्पी और हस्तक्षेप के बीच की रेखा को समझा जाए और उसका सम्मान किया जाए। जब अधिक जिम्मेदार लोग चुनिंदा मुद्दों पर टिप्पणी करते हैं, तो वे स्वयं के निहितार्थों को भी ध्यान में रखते हुए ऐसा कर सकते हैं। यह जीवन की सचाई है कि कई अन्य गतिविधियों की तरह ही राजनीति का भी वैश्वीकरण हो गया है। लेकिन, व्यवस्था की आलोचना करने वाले अपने घरेलू चुनाव के नतीजों को प्रभावित करने के लिए अगर बाहरी ताकतों को आमंत्रित करते हैं तो इससे हमें कोई लाभ नहीं होगा।

यह अमृत काल का पहला आम चुनाव है और युवाओं को इसके महत्व को पहचानना होगा। पिछले दशक ने हमें विकसित भारत के लिए गंभीरता से उम्मीद करने को एक आधार दिया है। हमारे विकास की नई गति को इसकी समावेशी प्रकृति और प्रौद्योगिकी की छलांग लगाने वाली क्षमता से बल मिला है। पहले के विपरीत, सुधार और आधुनिकीकरण को संकीर्ण रूप से परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन इसमें डोमेन की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। मानव संसाधनों का पोषण, entrepreneurship को बढ़ावा देना और जीवनयापन की आसानी को बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

औपचारिक और अनौपचारिक, अर्थव्यवस्था के दोनों ही क्षेत्रों में अवसर बढ़ रहे हैं। यहां तक कि नए फोकस क्षेत्र और वैल्यू एडिशन भी सामने आ रहे हैं। दुनिया ध्यान दे रही है कि हमारी डिजिटल रूप से सक्षम डिलिवरी ने बड़े पैमाने पर सोशल वेलफेयर सिस्टम (सामाजिक कल्याण प्रणाली) बनाया है, जिसकी पहले कल्पना नहीं की जा सकती थी। चाहे कोवैक्सीन हो या कोविन, 5G स्टैक या UPI, चंद्रयान या गगनयान मिशन, हम तेजी से वैश्विक मानकों से मेल बना रहे हैं।

जैसे-जैसे भारत अपने भविष्यों के बारे में निर्णय लेने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, यह जरूरी है कि हम सभी इसे पूरी तरह से समझें कि दांव पर क्या लगा है। भारत न केवल दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है बल्कि यह पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी है, जिसके जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की संभावना है। दुनिया चुनौतियां और अवसर दोनों प्रदान करती है और उन्हें व्यापक रूप से संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री के दृढ़ आत्मविश्वास और अनुभवी नेतृत्व की आवश्यकता है। जैसे ही हम अपनी राजनीतिक पसंद व्यक्त करते हैं, हम वैश्विक व्यवस्था की दिशा भी तय कर रहे होते हैं। दुनिया इंतजार कर रही है और उम्मीद कर रही है कि फैसला स्पष्ट और निर्णायक होगा।

(लेखक विदेश मंत्री हैं)

AI नेटवर्क से आएगी क्रांतिकारी टेक्नॉलजी

मुकुल व्यास

दुनिया में आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (AI) की प्रगति की वर्तमान रफ्तार को देखते हुए यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि भविष्य में AI का क्या रूप होगा? विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य के AI सिस्टम स्टार ट्रेक सीरियल में दिखाए गए बोर्ग के समान एक नेटवर्क के जरिए एक साथ काम करेंगे। MIT, येल और लफबरा विश्वविद्यालयों के रिसर्चरों ने नेचर मशीन इंटेलिजेंस पत्रिका में एक पेपर प्रकाशित किया है, जिसमें उन्होंने 'कलेक्टिव AI' पर रोशनी डाली है।

AI का समूह | रिसर्चरों का कहना है कि सामूहिक AI में विभिन्न इकाइयां होंगी। हर इकाई निरंतर सीखने और नई स्किल प्राप्त करने में सक्षम होगी। ये इकाइयां एक नेटवर्क बनाएंगी, जिसमें जानकारियां साझा की जाएंगी।

काम का तरीका | स्टैनफर्ड और गूगल के रिसर्चरों ने एक काल्पनिक दुनिया विकसित की, जिसका नाम उन्होंने स्मॉलविल रखा। इसमें 25 AI एजेंट बातचीत करते हैं और स्वायत्त रूप से काम करते हैं। MIT ने 'सोसाइटी ऑफ माइंड्स' प्रस्तुत की, जिसमें AI एजेंट यूजर की क्वेरी का समाधान खोजने के लिए एक-दूसरे से बहस करते दिखाई दिए। रिसर्चरों का कहना है कि कलेक्टिव AI के बारे में उनका विजन स्टार ट्रेक या रिप्लिकेटर जैसे साइंस फिक्शन के सीरियलों में वर्णित पात्रों से अलग है।

नेटवर्क में काम | स्टार ट्रेक में बोर्ग साइबरनेटिक (कृत्रिम अंगों से युक्त साइबोर्ग) जीवों की एक जाति है जो कलेक्टिव नामक हाइव माइंड (ग्रुप मस्तिष्क) के माध्यम से जुड़ी रहती है। इस सामूहिक चेतना ने बोर्ग ड्रोन को विचार साझा करने और नियमित रूप से परिस्थितियों के अनुकूल ढलने की अनुमति दी।

साइंटिफिक फैक्ट | रिसर्चरों के अनुसार बोर्ग की सूचना शेयर करने की क्षमता साइंस फिक्शन से बाहर निकलकर वैज्ञानिक तथ्य बन सकती है। उनका मानना है कि जानकारी शेयर करने का यह विचार कई AI इकाइयों को एक नेटवर्क के जरिए एक-दूसरे से नया ज्ञान और कौशल सीखने में सक्षम बनाएगा। ChatGPT जैसे वर्तमान सिस्टम का ज्ञान सीमित है, जबकि AI सिस्टम के ज्ञान को इंटरनेट एक्सेस के माध्यम से या रिट्रीवल-ऑगमेंटेड जेनरेशन (RAG) जैसी तकनीकों के माध्यम से बढ़ाया जा सकता है।

AI Image
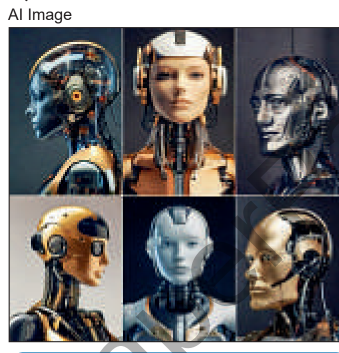

ज्ञान-विज्ञान

खुद से सीखना | AI मॉडल को समय के साथ नई जानकारी सीखने के लिए बार-बार प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है जिसमें ऊर्जा ज्यादा खर्च होती है। कलेक्टिव AI जैसी अवधारणा भविष्य के AI सिस्टम को दोबारा प्रशिक्षण के बगैर लगातार नई जानकारी सीखने में मदद कर सकती है।

तेज रिएक्शन | ब्रिटेन की लफबरा यूनिवर्सिटी के डॉ. एंड्रिया सोल्टोगियो का कहना है कि लगातार सीखने और नए डेटा को अपनाने में सक्षम AI इकाइयों के सामूहिक नेटवर्क में तत्काल ज्ञान साझा करने से नई स्थितियों, चुनौतियों या खतरों पर तेजी से प्रतिक्रिया करने में मदद मिलेगी।

सामूहिक प्रतिक्रिया | इसके बाद अनेक कौशल, विचार और अनुप्रयोग क्रमिक रूप से विकसित होंगे। इससे नेटवर्क तेजी से नए कार्यों को पूरा करना और परिवर्तनों पर प्रतिक्रिया देना सीख जाएगा, तब परिवर्तनकारी प्रौद्योगिकियां सामने आएंगी। उदाहरण के लिए, यदि एक AI इकाई किसी खतरे की पहचान करती है, तो यह तुरंत ज्ञान साझा कर सकती है।

खतरे भी हैं | रिसर्चर मानते हैं कि सामूहिक AI के जोखिम भी हैं। उन्होंने नापाक उद्देश्यों के लिए सामूहिक AI के दुरुपयोग की आशंका जताई है। सामूहिक AI परस्पर जुड़े AI सिस्टम को 'संभावित अनैतिक या अवैध ज्ञान' साझा करने में समर्थ बना सकती है। भविष्य के किसी भी सामूहिक AI सिस्टम की AI इकाइयों को अपने उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित करते हुए सामूहिकता से अपनी स्वतंत्रता बनाए रखनी होगी।

बुंदेलों के लिए मुगलों से भिड़े मराठा
सुविज्ञा जैन

भारतीय इतिहास में कई ऐसे युद्ध हुए, जिन्होंने राज्यों की नियति बदलकर रख दी। ऐसा ही एक युद्ध बुंदेलखंड के जैतपुर में लड़ा गया। उस युद्ध के दौरान राजा छत्रसाल का मराठा पेशवा बाजीराव को लिखा एक पत्र आज भी याद किया जाता है।

पत्र में गुहार | छत्रसाल ने बाजीराव को यह पत्र बुंदेली भाषा में लिखा था, 'जो गति ग्राह गजेन्द्र की, सो गति भई है आज, बाजी जात बुन्देल की, बाजी राखो लाज।' यानी, हमारी हालत उस हाथी जैसी हो गई है, जिसकी टांग ग्राह यानी मगरमच्छ ने पकड़ ली है। बुंदेलवंश की बाजी अब हाथ से निकल रही है। बाजीराव, आओ और हमारी लाज रखो। राजा छत्रसाल ने जब यह पत्र लिखा उनकी उम्र 79 साल थी।

AI Image

टाइम मशीन

शिवाजी से मुलाकात | छत्रसाल के पिता चंपत राय महोबा के राजा थे। जब छत्रसाल 12 साल के थे, तब चंपत राय के साथ उनके ही साथियों ने मुगल बादशाह औरंगजेब संग मिलकर विश्वासघात किया। इससे चंपत राय इतने आहत हुए कि पत्नी के साथ आत्महत्या कर ली। भाई के साथ अकेले रह गए छत्रसाल कुछ समय बाद अपने पिता के मित्र राजा जयसिंह की सेना में भर्ती हो गए। जयसिंह मुगलों के अधीन राज्य चला रहे थे। ऐसे में 1688 में छत्रसाल चले गए छत्रपति शिवाजी के पास। एक दिन शिवाजी ने उन्हें अपनी भवानी तलवार भेंट करते हुए कहा कि उनका असली मुकाम बुंदेलखंड में है।

प्रजा से सेना | छत्रसाल बुंदेलखंड वापस आ गए, लेकिन तब तक वहां की ज्यादातर रियासतें मुगलों के अधीन आ चुकी थीं। वह अपनी सेना तैयार करना चाहते थे। उन्होंने आसपास के कई राजाओं से मदद मांगी, लेकिन मुगलों के खिलाफ जाने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पाया। तब छत्रसाल ने बुंदेलखंड की प्रजा में से ही सैनिक चुनने का फैसला लिया। शुरू में 25 पैदल सैनिक और 5 घुड़सवारों की सेना तैयार की।

बुंदेला राज्य बनाया | छत्रसाल ने पहला हमला अपने पिता से विश्वासघात करने वाले सिहरा के धन्धेरों पर किया। जीत में मिली सारी धन संपदा छत्रसाल ने सैनिकों में बांट दी। इससे आसपास के इलाके से लोग छत्रसाल की सेना में शामिल होने लगे। 1671-80 के बीच छत्रसाल ने चित्रकूट से ग्वालियर तक और कालपी से गढ़ाकोटा तक सत्ता कायम कर ली।

आखिरी चुनौती | दो दशकों बाद 1728 में इलाहाबाद के नवाब और मुगल सेनापति मोहम्मद बंगश ने छत्रसाल के बेटे जगतराज पर आक्रमण किया। छत्रसाल वृद्ध हो चुके थे।

बाजीराव का हमला | एक-एक कर बड़े किले बुंदेलों के हाथ से निकलते जा रहे थे। पराजय निकट देख राजा छत्रसाल ने बंगश से समझौते को लेकर बातचीत शुरू की। बंगश को जीत का इतना भरोसा हो गया कि उसने सेना की एक बड़ी टुकड़ी वापस भेज दी। लेकिन, 12 मार्च 1729 को पता चला कि मराठा पेशवा बाजीराव जैतपुर की तरफ बढ़ रहे हैं।

मस्तानी से नाता | बाजीराव उस पत्र की वजह से आ रहे थे, जो छत्रसाल ने भेजा था। मई 1729 में बंगश ने आत्मसमर्पण कर दिया। इस जीत के बाद वृद्ध छत्रसाल ने युवा पेशवा बाजीराव को अपने बेटे की तरह स्नेह और सम्मान दिया। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि उन्होंने अपनी पुत्री मस्तानी की शादी भी बाजीराव से कर दी।

कुछ मिला कुछ बाकी
प्रणव प्रियदर्शी

यह बात अलग-अलग तरीकों से दर्ज होती रही है कि हाल के वर्षों में इंडस्ट्री में महिलाओं की भूमिका पर जोर बढ़ा है। लेकिन सवाल है कि इन पॉजिटिव बदलावों के बावजूद आज की तारीख में इंडस्ट्री में महिलाओं की वास्तविक स्थिति कैसी है? यह सचमुच बदली है तो पहले से कितनी और इन बदलावों की दिशा और रफ्तार कैसी है? पिछले हफ्ते आई AIMA-KPMG विमिन लीडरशिप रिपोर्ट, 2024 इन पहलुओं पर रोशनी डालती है। इसमें देश की अलग-अलग इंडस्ट्रीज में लीडरशिप रोल में महिलाओं के अनुपात और उनकी स्थिति का आकलन किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, सर्वे में शामिल कंपनियों में 9% ऐसी पाई गईं जिनमें लीडरशिप रोल में महिलाएं हैं ही नहीं। 56% कंपनियों में महिलाएं अग्रणी भूमिका में हैं जरूर लेकिन उनका अनुपात महज 10-30% के बीच है। मात्र 23% कंपनियां ऐसी मिलीं जिनमें लीडरशिप रोल में महिलाओं का अनुपात 30-50% के बीच है। लेकिन सबसे बड़ी बात, 77% कंपनियों में यह देखा गया कि एंट्री लेवल पोजिशन के लिए हायर की गई महिलाओं में 30% से भी कम ऐसी होती हैं जो वहां लीडरशिप रोल में शामिल हो पाती हैं।

AI Image

आधी दुनिया

जो महिलाएं लीडरशिप रोल हासिल कर लेती हैं, उनमें भी महज 50% ही खुद को अपने पुरुष समकक्षों के बराबर महसूस करती हैं। 25% से ज्यादा महिलाओं को लगता है कि उन्हें पुरुषों के मुकाबले कम पैकेज मिलता है। 15% महिलाओं को वेतन के मामले में पूर्वाग्रह का अहसास होता है। ज्यादातर महिलाएं (करीब 63%) इस बात पर संतोष जताती हैं कि लीडरशिप रोल में लड़कियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए कंपनी की तरफ से समय-समय पर कदम उठाए जाते हैं, लेकिन 58% महसूस करती हैं कि ये कदम उन चुनौतियों को सही ढंग से संबोधित नहीं कर पाते, जिनसे वास्तव में महिलाएं गुजर रही होती हैं। इस रिपोर्ट ने एक बार फिर इस तथ्य को रेखांकित किया है कि भले इंडस्ट्री में लड़कियों की स्थिति पहले से बेहतर हुई है, लेकिन अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है।

रीडर्स मेल
www.edit.nbt.in

■ कनाडा की दोहरी चाल
1 मई का संपादकीय 'ट्रूडो की गलती' पढ़ा। कनाडा में खालिस्तान समर्थकों को खुलेआम अलगाववादी गतिविधियों की अनुमति देना चिंताजनक है। कनाडाई प्रधानमंत्री ट्रूडो की उपस्थिति में खालिस्तान समर्थक नारे लगना और बैनर दिखाया जाना दरअसल कनाडा की वोट बैंक राजनीति की पराकाष्ठा है। यह न केवल भारत-कनाडा संबंधों के लिए नुकसानदेह है बल्कि कनाडा की आंतरिक सुरक्षा के लिए भी खतरा हो सकता है। अभिव्यक्ति की आज़ादी की आड़ में अलगाववाद, उग्रवाद और आतंकवाद को बढ़ावा देना हर हाल में गलत है। खासकर लोकतांत्रिक देशों को चाहिए कि वे एकजुट होकर अलगाववाद का विरोध करें।
दिनेश भार्गव, ईमेल से

■ चिकित्सा में नई उम्मीद
यह पत्र 1 मई को 'नजरिया' कॉलम में 'AI क्या करेगा' शीर्षक से प्रकाशित लेख के संबंध में है। लेख चिकित्सा क्षेत्र में लार्ज लैंग्वेज मॉडल (LLM) तकनीक की संभावनाओं और चुनौतियों पर प्रकाश डालता है। LLM रोगी के डेटा का विश्लेषण कर, निदान और उपचार में सहायता कर सकता है, शोध को गति दे सकता है और समय बचा सकता है। हालांकि, LLM की सीमाएं भी हैं। लेख में सुझाव दिया गया है कि LLM को चिकित्सा पेशेवरों के सहायक के रूप में उपयोग किया जाए, न कि उनके स्थान पर। लेकिन अंतिम निर्णय डॉक्टर को ही लेना चाहिए।
सोहनी रावत, ईमेल से

■ प्रतिभा को निखारें
नैशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने JEE Mains 2024 सेशन 2 का रिजल्ट जारी कर दिया है। IIT प्रवेश परीक्षा प्रतिभा की पहचान का एक महत्वपूर्ण मापदंड है, पर यह एकमात्र मापदंड नहीं हो सकता। कई प्रतिभावान छात्र संसाधनों की कमी और सामाजिक-आर्थिक विषमता के कारण इस दौड़ में पिछड़ जाते हैं। शिक्षा प्रणाली को समावेशी बनाना और सभी को समान अवसर प्रदान करना महत्वपूर्ण है।
मोहित सक्सेना, ईमेल से

nbtedit@timesgroup.com पर अपनी राय नाम-पते के साथ मेल करें।

अंतिम पत्र
ट्रेनों में लगेंगे बुलेट ट्रेन जैसे इंजन
– एक खबर
– जब ट्रेन भी वही है और पटरी भी वही, तो इंजन बुलेट कैसे?
गौरिका कपूर

THE SPEAKING TREE
और पढ़ने के लिए देखें
hindi.speakingtree.in

Motorbike हो या मन, रोकने की कला आनी चाहिए
सुरक्षित गोस्वामी

Silicon Valley में रहने वाले मेरे एक मित्र ने शौक के लिए BMW motorbike का highest version खरीदा। इसे harley davidson से भी बेहतर माना जाता है, और इसकी कीमत किसी बड़ी कार से कम नहीं होती। इसकी रफ्तार पकड़ने की गति और brake लगते ही रुकने की engineeering कमाल की है। यह bike पलक झपकते ही हवा से बात करने लगती है और दौड़ती कार के पास से फर्राटे के साथ निकल जाती है। Bike चलाने वाले के लिए उसका suit, goggle, helmet, shoe आदि सभी सुरक्षा को ध्यान में रख कर design किए जाते हैं। Bike खरीदने के बाद bike को समझाने के लिए बाकायदा class हुई। Class में coach ने बस brake के बारे में बताया कि brake कैसे लगाने हैं, तेज या धीमी रफ्तार पर brake का किस तरह प्रयोग करना है। brake लगाते वक्त कैसे अपना balance बनाए रखना है, brake के समय आपकी body language कैसी हो। आगे और पीछे वाले brake का सामंजस्य कैसे रखना है। brake लगाने का विज्ञान सिखाते-सिखाते class समाप्त हो गयी। एक बार भी यह नहीं बताया गया कि accelerator कैसे देना है। अक्सर car या motorbike में सही समय पर brake न लगाने के कारण ही accident होते हैं। Accelerator देना सीखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वह सब अपने आप सीख ही लेते हैं।

पतंजलि अपने योग सूत्र के दूसरे ही सूत्र में कहते हैं कि चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। हमारा चित्त लगातार भागता रहता है। जैसे एक मक्खी हर जगह घूमती रहती है, वैसे ही भागते चित्त को रोकने की कला 'योग' है। यहां पतंजलि भी चित्त को कैसे भगाना है यह नहीं सिखा रहे हैं। बल्कि उस पर brake कैसे लगाना है, उसको सिखाने के लिए पूरा शास्त्र लिख रहे हैं। गीता या अन्य सभी ग्रंथों में भी इंद्रियों, मन, बुद्धि, विकारों को रोकने की कला ही सिखाई गई है, न कि मन को कैसे दौड़ाया जाए। बाहर की तरफ चित्त का भागना सबसे आसान और उसे रोककर अपने काबू में कर लेना सबसे कठिन होता है। पूरा अध्यात्म और सभी आध्यात्मिक शास्त्र केवल चित्त को रोकने के अभ्यास सिखा रहे हैं। चित्त का स्वभाव अलग-अलग होता है, इसलिए अभ्यास के तरीके भी अनेक बताए गए हैं। 'विज्ञान भैरव तंत्र' में तो चित्त को काबू करने के लिए 112 प्रकार के ध्यान की विधियों का वर्णन किया गया है। जैसे motorbike coach ने मेरे मित्र को brake लगाना सिखाया, इसी तरह आध्यात्मिक गुरु भी शिष्य को चित्त पर brake लगाने के गुर सिखाते हैं।

हम अपने साथ भी देख सकते हैं कि मन का विचारों में भागना बड़ा सहज है। मन को दौड़ाना कोई कला नहीं, बल्कि दौड़ते मन पर लगाम लगाना कला है। अध्यात्म में सारी मेहनत, अभ्यास और तरकीब इसकी है कि मन को रोकें कैसे। जो मन को दौड़ाए, वह जगजीत बन सकता है। लेकिन जो मन को काबू में लाए, वह मनजीत बन जाता है। जगजीत अनेक हो सकते हैं लेकिन मनजीत कोई विरला ही बन पाता है। वैसे भी 'मनुष्य' शब्द का अर्थ यही है कि जो मन का मालिक हो गया है, वही मनुष्य है।

आर.एन.आई. नं. 510/57© सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति के बिना संपूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित। स्वत्वाधिकारी बैनेट, कोलमैन एण्ड कम्पनी लिमिटेड के लिए राजीव यादव द्वारा, 7 बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित तथा **टाइम्स ऑफ इंडिया प्रेस, साइट IV, औद्योगिक क्षेत्र साहिबाबाद** और प्लॉट नंबर 7-8, सेक्टर M-11, ट्रांसपोर्ट हब, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप, मानेसर, हरियाणा से मुद्रित। फोन : 23302000 फैक्सः 23492047, पंजीकृत कार्यालय : दादाभाई नौरोजी रोड, मुंबई-400001। विमान सेवा शुल्क : 1 रु. प्रति कॉपी। नेपाल में कुल मूल्य : सोमवार से शनिवार : नेपाली 5 रु. ; रविवार : नेपाली 6 रु.
संपादक (दिल्ली मार्केट) : आशीष पांडे (इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अन्तर्गत उत्तरदायी)

अनमोल वचन

विद्यार्थी को चाहिए कि अपने जीवन में साहस और दृढ़ संकल्प रखे। उसे कठिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए।

-आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी

जवाबदेह बनें संस्थाएं

सर्वोच्च अदालत ने लोक सभा चुनाव से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के समय को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से सवाल किया और जांच एजेंसी से इसका जवाब मांगा। अदालत ने पांच सवाल पूछे और उनके जवाब लेकर आने का निर्देश दिया। दो सदस्यीय बेंच ने कहा कि स्वतंत्रता बहुत महत्त्वपूर्ण है। आखिरी सवाल गिरफ्तारी के संबंध में है। न्यायिक कार्यवाही के बिना, जो कुछ हुआ उसके संदर्भ में कार्यवाही कर सकते हैं। अदालत ने पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के लिए कहा कि पक्ष और विपक्ष में निष्कर्ष हैं। हमें बताएं कि केजरीवाल का मामला कहां है। क्या हम सीमा को बहुत विस्तृत बनाते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि जो व्यक्ति दोषी है, उसका पता लगाने के लिए मानक समान हों। केजरीवाल 21 मार्च से शराब नीति घोटाले के मामले में न्यायिक हिरासत के तहत दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं।

केजरीवाल इस गिरफ्तारी से पहले ही सार्वजनिक तौर पर कई मर्तबा दोहरा चुके थे कि मोदी सरकार लोक सभा चुनाव के दौरान उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। दिल्ली सरकार के नेता पहले ही जेल में हैं। माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता विभिन्न राजनैतिक दलों के लिए चुनौती बनती जा रही है। सत्ताधारी दल की यह जिम्मेदारी है कि वह अन्य विपक्षी दलों के साथ पूर्वाग्रह भरा बर्ताव करने से बचे। दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 5 में स्पष्ट प्रावधान है, कोई भी गिरफ्तारी इसके अधीन ही होनी चाहिए। केजरीवाल अपनी गिरफ्तारी और हिरासत को अवैध बता रहे हैं। यह कहना गलत नहीं है कि चुनाव के दरम्यान लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं तथा नोटिस भी थमाए जा रहे हैं या छापे तक डाले जा रहे हैं। दरअसल, केजरीवाल की गिरफ्तारी की टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं, जिनके उत्तर मिलने चाहिए। यह स्थिति लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए उचित नहीं कही जा सकती। बेशक, न्यायिक व्यवस्था अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। सार्वजनिक जीवन में रहने वाला कोई भी राजनीतिज्ञ यदि किसी तरह के घोटाले में शामिल है तो उसे दंडित करने के लिए अदालतें हैं। अदालतों पर पहले ही लंबित मामलों का दबाव है। उस पर मोदी सरकार लगातार आरोपियों को भाजपा में शामिल कर उन्हें क्लीन चिट देने का काम कर स्पष्ट संकेत दे रही है। यह अपने आप में गलत संदेश दे रहा है। बावजूद इसके अंतिम फैसला तो जनता के हाथ में है, जो मूकदर्शक जरूर है, लेकिन अपना निर्णय समय आने पर देगी।

टीम चयन में यूटर्न

साल 2022 में ऑस्ट्रेलिया में हुए टी-20 विश्व कप में भी लंबे समय से चले आ रहे आईसीसी ट्रॉफी जीतने का सपना साकार नहीं होने पर टीम की बागडोर यंग ब्रिगेड के हाथों में सौंपने का फैसला किया गया था। क्रिकेट के इस सबसे छोटे प्रारूप की कमान हार्दिक पांड्या को सौंप कर यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, ईशान किशन, ऋतुराज गायकवाड़ और रिंकू सिंह जैसे युवाओं को मौका भी दिया गया। लेकिन धीरे-धीरे पुराने खिलाड़ियों पर ही भरोसा जताया जाने लगा। रोहित शर्मा को कप्तान बनाने के बाद विराट कोहली की वापसी हुई और आखिर में जब टीम का चयन किया गया तो टीम का कोर ग्रुप 2022 वाला ही है। इस विश्व कप में सेमीफाइनल तक चुनौती पेश करने वाली टीम के आठ खिलाड़ी इस टीम में भी हैं। पिछले विश्व कप में चोट की वजह से नहीं खेल सके जसप्रीत बुमराह को भी सीनियर खिलाड़ियों में गिना जा सकता है। इससे यह तो स्पष्ट है कि अंतिम एकादश में 2022 वाली टीम से ज्यादा अंतर नहीं होगा।

इसकी शायद वजह यह हो कि चयनकर्ताओं को आजमाए गई यंग ब्रिगेड पर भरोसा नहीं बन सका हो। वैसे देखा जाए तो टीम किसी हद तक संतुलित है। एक-आध चयन को लेकर ही उंगलियां उठ रही हैं। इनमें खास तौर से हार्दिक का चयन माना जा रहा है। हार्दिक की अगुआई में मुंबई इंडियंस तो खराब प्रदर्शन कर ही रही है, उनका बल्ला भी रूठा हुआ है। सही है कि हार्दिक प्रतिभाशाली हैं और लय पा लें तो मैच विनर की भूमिका निभा सकते हैं। रिंकू सिंह और रवि बिश्नोई को नहीं चुने जाने की भी आलोचना हो रही है। रिंकू ने जब भी मौका मिला है, फिनिशर की भूमिका अच्छे से निभाई है। वह शायद आईपीएल के इस सीजन में नहीं चल पाने से सुरक्षित खिलाड़ियों तक ही पहुंच सके हैं। बात बिश्नोई की तो जड़ेजा और अक्षर दोनों एक तरह के गेंदबाज हैं, इसलिए बिश्नोई को टीम में लेकर गेंदबाजी अटैक में विविधता लाई जा सकती थी। इस टीम की बल्लेबाजी सॉलिड तो स्पिन भी जानदार है। अलबत्ता, पेस अटैक में बुमराह का साथ देने वाले गेंदबाज की कमी महसूस की जा सकती है। वजह सिराज का रंगत में नहीं होना है पर अर्शदीप जरूर संतुलन बना सकते हैं। टीम के शिवम दुबे एक्स फेक्टर साबित हो सकते हैं। टीम में 2013 से आईसीसी ट्रॉफियों से चली आ रही दूरियों को खत्म करने की क्षमता है।

कटाक्ष/ सहीराम

हमका माफी दइ दो

वैसे माफी मांगने का टाइम तो जी कायदे से यह नेताओं का है। लेकिन आजकल नेता लोग कायदा कहां मानते हैं। सो वे माफी मांगने की बजाय धमका रहे हैं। कोई सवाल पूछ लो तो धमका रहे हैं, कोई वादा याद दिला तो धमका रहे हैं। कोई शिकायत कर दो तो धमका रहे हैं। यूपी में टेनी जी धमका रहे हैं तो हरियाणा में रणजीत चौटाला। कोई कह रहा है तुम कांग्रेसी हो। आजकल कांग्रेसी होने के कई मतलब हो गए हैं। जैसे कांग्रेसी हो तो देशद्रोही हो, भ्रष्टाचारी हो, जैसे कांग्रेसी हो तो तुम्हें धमकाया भी जा सकता है। धमकाने से कई कांग्रेसी भाजपाई हो जाते हैं। खैर जी, टाइम बेशक यह नेताओं के माफी मांगने का हो, पर माफी बाबा जी मांग रहे हैं। नहीं, भगवान से नहीं। हां, यह ठीक है कि बाबाओं का भगवान से माफी मांगना तो बनता है, पर वे भगवान से कहां मांग रहे हैं। नहीं, जनता से भी माफी नहीं मांग रहे। कायदे से तो जनता से भी उन्हें माफी मांगनी चाहिए कि हमसे भूल हो गई जो हमने आपसे कहा कि काला धन वापस आएगा और पेट्रोल तीस रुपये लीटर मिलेगा। लेकिन वे जनता से माफी नहीं मांग रहे।

वे तो अदालत से माफी मांग रहे हैं। जज साहेबान उन्हें डांट रहे हैं-तुमने हमें समझ क्या रक्खा है? जज साहेबान डांट रहे हैं और वे डांट खा रहे हैं। डांट कोई रिश्वत नहीं है। कोई चंदा नहीं है। कोई सरकारी संपत्ति नहीं है कि चुपचाप खाते चले जाओ। फिर भी वे चुपचाप डांट खा रहे हैं। वे हाथ बांधे खड़े हैं-खम्मा घणी हुजूर। हमसे भूल हो गई, हमका माफी दइ दो। जज साहेबान माफी भी नहीं दे रहे-माफी लायक तुम हो ही नहीं। तुमने कांड ही ऐसे कर रखे हैं कि उनकी कोई माफी नहीं है। वे यह भी नहीं कह पा रहे कि छिमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। उन्होंने यह कहते हुए खूब उत्पात मचाया कि लो, पाड़ लो मेरी पूंछ। उन्होंने टर्र-टर्र करते-कहते भी खूब उत्पात मचाया। डाक्टरों को, एलोपैथी चिकित्सा पद्धति को गाली दी। गाली देने में उन्हें उतनी ही महारत हासिल है जितनी अपना प्रोडक्ट बेचने में। दोनों महारतें अन्योनाश्रित हैं। उनका फंडा यही है कि गाली देंगे तभी तो प्रोडक्ट बिकेगा। इस माने में वे बाबा नहीं बिजनेसमैन हैं। लेकिन अब अदालत के समक्ष हाथ बांधे खड़े हैं और जज साहेबान उन्हें डांट रहे हैं। और वे माफी मांग रहे हैं-हमसे भूल हो गई...।

हमारे लिए व्यावहारिक नहीं

विरासत कर

प्रो. लल्लन प्रसाद

संसदीय चुनाव के द्वितीय चरण के दौरान भारतीय ओवरसीज कांग्रेस अध्यक्ष सैम पित्रोदा के उस बयान को लेकर देशव्यापी बहस छिड़ गई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका में जो उत्तराधिकार कानून है, उसकी तर्ज पर भारत में भी कानून बनाए जाने पर विचार होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इसे कांग्रेस पार्टी की शहरी नक्सलवादी विचारधारा एवं जनता को लूटने की योजना करार दिया है।

उन्होंने इसकी व्याख्या को आगे बढ़ाते हुए कहा है कि महिलाओं का मंगलसूत्र, उनकी जमा पूंजी, सोने-चांदी-गहने और लोगों की मेहनत की कमाई छीन कर कांग्रेस उन लोगों में बांटना चाहती है जो घुसपैठिये हैं, जिनके बहुत से बच्चे हैं। इशारा अल्प समुदाय की ओर है, जिसके लिए कहा जाता है कि कांग्रेस उन्हें अपने वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करती रही है। मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने वक्तव्य दिया था कि भारत की संपत्ति पर मुसलमानों का पहला अधिकार है। उस समय इस वक्तव्य पर तीखी प्रतिक्रिया हुई थी। संसदीय चुनाव में यह मुद्दा फिर से उठ गया है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि इस बयान को तोड़-मरोड़ कर रखा जा रहा है, मनमोहन सिंह का बयान पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यकों के सशक्तिकरण के रूप में देखा जाना चाहिए। पित्रोदा के बयान से भी कांग्रेस पार्टी अपने आप को अलग करने की कोशिश में है, इसे वह उनका निजी बयान मानती है न कि कांग्रेस का आधिकारिक बयान।

मनमोहन सिंह का बयान तो देश के बहुसंख्यक वर्ग के हितों पर सीधा प्रहार था जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। राममन्दिर के मसले पर भी कांग्रेस का जो रुख रहा उससे भी इस भावना को बल मिलता है। कांग्रेस के चुनाव घोषणापत्र में कहीं भी उत्तराधिकार कानून और उसके फलस्वरूप संपत्ति के पुनर्वितरण की बात खुले रूप से नहीं की गई है किंतु परोक्ष रूप में पार्टी की मंशा संदेह के घेरे में है। घोषणापत्र में एक पुस्तक 'भारत में आमदनी और संपत्ति की असमानता 1922-2023: अरबपतियों का बढ़ता राज' का जिक्र है जिसे थॉमस पिकेटी और उनके सहयोगियों ने लिखा है। इस पुस्तक में कहा गया है कि भारत में आर्थिक विषमता चरम सीमा पर है। 1991 के आर्थिक उदारीकरण के बाद इसमें तेजी से बढ़ोतरी हुई है। 1991 में मात्र एक अरबपति थे, 2011 में 52 और 2022 में 162 हो गए। जातिगत जनगणना पर कांग्रेस पार्टी का जोर और लोगों की संपत्ति के एक्सरे कराने के बयान इस संदेह की पुष्टि करते हैं कि यदि पार्टी शासन में आई तो संपत्ति के पुनर्वितरण की योजना बना सकती है।

कांग्रेस अध्यक्ष समाज में संपत्ति के वितरण में असमानता की बात बार-बार दोहराते

रहे हैं, और अमीरों का धन कमजोर वर्ग और अल्पसंख्यकों में वितरित करने की बात करते रहे हैं। आजादी के बाद लगभग 6 दशकों तक कांग्रेस का शासन रहा तब यह बात नहीं उठाई गई, समाज में असमानता दूर करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। पिछले 10 वर्षों के शासन में देश का आर्थिक विकास जितनी तेजी से हुआ उतना पहले कभी नहीं हुआ। इस बीच, संपत्ति का वितरण लोककल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से हुआ है, लोगों की आमदनी बढ़ी है, जीवन स्तर उठा है, भारत के गरीबी उन्मूलन के प्रयास की सफलता की विश्व बैंक ने भी सराहना की है। अर्थव्यवस्था के विकास का लाभ नीचे तक गया है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। यद्यपि यह सच है कि असमानता है और उसे कम करने के लिए संवैधानिक तरीकों से प्रयास करना चाहिए। भारत में 1953 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने संपत्ति कर विधेयक (इस्टेट ड्यूटी एक्ट) लागू किया था जिसमें बड़ी संपत्ति छोड़कर मरने वालों की संपत्ति में उनके उत्तराधिकारियों के अलावा सरकार का हिस्सा भी होता था जो 85% तक जा सकता था। इस कानून का अभिप्राय संपत्ति के केंद्रीयकरण को रोकना था किंतु यह कानून सफल नहीं हो सका। इसे लागू करने में जो प्रशासनिक खर्च आता था वह उस रकम से भी कम होता था जो इस कर से सरकार को मिलती थी। मार्च, 1985 में राजीव गांधी की सरकार में तत्कालीन वित्त मंत्री वीपी सिंह ने यह कानून निरस्त कर दिया। इसके निरस्तीकरण के कारण को लेकर भी विवाद उठ खड़ा हुआ है। कहा जा रहा है कि यह इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति को इस कर से बचाने के लिए ही निरस्त कर दिया गया था। इस विवाद पर कांग्रेस का कहना है कि इंदिरा गांधी ने 1970 में ही इलाहाबाद में अपनी पैतृक संपत्ति जवाहरलाल नेहरू स्मृति फंड को दे दी थी।

संपत्ति कर दुनिया के कई देशों में लगाया जाता है। अमेरिका के 6 राज्यों में संपत्ति कर लागू है, सामान्यतः यह उन लोगों को प्रभावित करता है जिनकी संपत्ति 10 लाख डॉलर से अधिक है। संपत्ति की मार्केट में जो कीमत होती है उसके ऊपर टैक्स लगता है जो 50- 55 प्रतिशत है। फ्रांस में संपत्ति कर दर 50-60 प्रतिशत है। इंग्लैंड में डोमिसाइल के आधार पर संपत्ति कर निर्धारित किया जाता है। जापान में 10-70 प्रतिशत तक संपत्ति कर की व्यवस्था है। बेल्जियम में यह 80% तक जा सकता है, साउथ कोरिया में 50% और स्पेन में 7.65-34 प्रतिशत तक संपत्ति कर लगाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और चीन में संपत्ति कर का कोई प्रावधान नहीं है।

भारत में संपत्ति कर दोबारा लगाया जाए या नहीं, यह विचार का विषय है। आर्थिक विषमता दुनिया के सभी देशों, चाहे वह पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत हों या किसी और व्यवस्था में हों, में मौजूद है। समाज में असमानता सदियों से चली आ रही सामाजिक, राजनीतिक प्रशासनिक और आर्थिक व्यवस्था के कारण होती है, उसे पूरी तरह समाप्त करना संभव नहीं है। मार्क्सवादी, माओवादी और नक्सलवादी व्यवस्थाओं में भी यह समाप्त नहीं की जा सकी। भारत जैसे विकासशील जनतांत्रिक देश में असमानता कम करने के लिए संवैधानिक तरीकों से ही आगे बढ़ा जा सकता है। तेजी से आर्थिक विकास और प्रशासनिक व्यवस्था, जिसमें संपत्ति का केंद्रीयकरण कम किया जा सके, लक्ष्य की प्राप्ति के साधक हो सकते हैं।

> जातिगत जनगणना पर कांग्रेस का जोर और लोगों की संपत्ति के एक्सरे कराने के बयान इस संदेह की पुष्टि करते हैं कि यदि पार्टी शासन में आई तो संपत्ति के पुनर्वितरण की योजना बना सकती है। कांग्रेस अध्यक्ष समाज में संपत्ति के वितरण में असमानता की बात बार-बार दोहराते रहे हैं, और अमीरों का धन कमजोर वर्ग और अल्पसंख्यकों में वितरित करने की बात करते रहे हैं। लेकिन समाज में असमानता दूर करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया

- भारत का सूती धागा, कपड़ा/'मेड अप' और हथकरघा उत्पादों का निर्यात वित्त वर्ष 2023-24 में सालाना आधार पर 6.71 प्रतिशत बढ़कर 11.7 अरब डॉलर का रहा। 'मेड अप' कपड़ा उत्पादों में चादर, कालीन, तकिये का कवर आदि आता है
- पिछले वित्त वर्ष के दौरान इस क्षेत्र के लिए शीर्ष पांच निर्यात बाजार अमेरिका, बांग्लादेश, चीन, श्रीलंका और संयुक्त अरब अमीरात रहे

(स्रोत : मीडिया इन्पुट्स)

तो चुनाव आयोग ने दूसरे चरण के तीन दिन बाद और पहले चरण का मतदान होने के 10 दिन बाद आंकड़ा जारी कर ही दिया। पहले चरण में 66.14 और दूसरे चरण में 66.71 प्रतिशत मतदान हुआ। इतना समय तो नहीं लगना चाहिए था। बहरहाल, मतदान प्रतिशत ही क्यों? वास्तविक संख्या क्यों नहीं? जैसे पहले होता था। वाकई चुनाव आयोग की विश्वसनीयता का इम्तिहान है।

राजदीप सरदेसाई, पत्रकार
@sardesairajdeep

संकट का क्या है समाधान

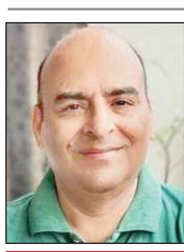

पेयजल | पंकज चतुर्वेदी

इस बार गर्मी जल्दी आई और साथ में प्यास भी गहराई। केंद्र सरकार की महत्त्वाकांक्षी 'हर घर जल योजना' ने बढ़ते ताप के सामने दम तोड़ दिया। आखिर, धरती का सीना चीर कर गहराई से पानी उलीचने से हर एक का कंठ तर होने से तो रहा। वैसे हकीकत तो यह है कि अब देश के 32 फीसद हिस्से को पानी की किल्लत के लिए गरमी के मौसम का इंतजार भी नहीं करना पड़ता-बारहों महीने, तीसों दिन जेठ ही रहता है।

कुछ दशक पहले पलट कर देखें तो आज पानी के लिए हाय-हाय कर रहे इलाके अपने स्थानीय स्रोतों की मदद से ही खेत और गले, दोनों के लिए अफरात पानी जुटाते थे। एक दौर आया कि अंधाधुंध नलकूप रोपे जाने लगे, जब तक संभलते जब तक भूगर्भ का कोटा साफ हो चुका था। समाज को एक बार फिर बीती बात बन चुके जल-स्रोतों की ओर जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है-तालाब, कुएं, बावड़ी। लेकिन एक बार फिर पीढ़ियों का अंतर सामने खड़ा है, पारंपरिक तालाबों की देखभाल करने वाले लोग किसी ओर काम में लग गए और अब तालाब सहेजने की तकनीक नदारद हो गई है। तभी बीते तीन दशक में केंद्र और राज्य की अनेक योजनाओं के तहत तालाबों से गाद निकालने, उन्हें सहेजने के नाम पर अफरात पैसा खर्च किया गया और नतीजा रहा वही 'ढाक के तीन पात!'

भारत के हर हिस्से में वैदिक काल से लेकर ब्रितानी हुकूमत के पहले तक सभी कालखंडों में समाज द्वारा अपनी देश-काल-परिस्थिति के मुताबिक बनाई गईं जल संरचनाओं और जल प्रणालियों के कई प्रमाण मिलते हैं, जिनमें तालाब हर जगह हैं। रेगिस्तान में तो उन तालाबों को सागर की उपमा दे दी गई तो कन्नड में कैरे और तमिल में ऐरी। यहां तक कि ऋग्वेद में भी सिंचित खेती, कुओं और गहराई से पानी खींचने वाली प्रणालियों का उल्लेख मिलता है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो (ईसा से 3000 से 1500 साल पूर्व) में जलापूर्ति और मल निकासी की बेहतरीन प्रणालियों के अवशेष मिले हैं। ईसा से 321-297 साल पहले, कौटिल्य का अर्थशास्त्र बानगी है जो बताता है कि तालाबों को राज्य की जमीन पर बनाया जाता था। समाज ही तालाब गढ़ने का सामान जुटाता था। जो लोग इस काम में असहयोग

करते या तालाब की पाल को नुकसान पहुंचाते उन्हें राज्य-दंड मिलता। आधुनिक तंत्र की कोई भी जल संरचना 50-60 साल में दम तोड़ रही है जबकि चंदेलकाल अर्थात 1200 साल से अधिक पुराने तालाब आज भी लोगों को जिंदगी का भरोसा दिए हुए हैं।

अंग्रेज शासक चकित थे, यहां के तालाबों की उत्तम व्यवस्था देख कर। उन दिनों कुओं के अलावा तालाब ही पेयजल और सिंचाई के साधन हुआ करते थे। फिर आधुनिकता की आंधी में सरकार और समाज, दोनों ने तालाबों को लगभग बिसरा दिया, जब आंख खुली तब बहुत देर हो चुकी थी। एक सदी पहले तक बुंदेलखंड के इन तालाबों की देखभाल का काम पारंपरिक रूप से ढीमर समाज के लोग करते थे। वे तालाब को साफ रखते, उसकी नहर, बांध, जल आवक को सहेजते-ऐवज में तालाब की मछली, सिंघाड़े और समाज से मिलने वाली दक्षिणा पर उनका हक होता। इसी तरह प्रत्येक इलाके में तालाबों को सहेजने का जिम्मा समाज के एक वर्ग ने उठा रखा था और उसकी रोजी-रोटी की व्यवस्था वही समाज करता था, जो तालाब के जल का इस्तेमाल करता था।

लेकिन आज गांव या शहर के रुतबेदार लोग जमीन पर कब्जा करने के लिए बाकायदा तालाबों को सुखाते हैं, पहले इनके बांध फोड़े जाते हैं, फिर इनमें पानी की आवक के रास्तों को रोका जाता है-न भरेगा पानी, न रह जाएगा तालाब। गांवों में तालाब से खाली हुई उपजाऊ जमीन लालच का कारण होती है तो शहरों में कालोनियां बनाने वाले भूमाफिया इसे सस्ता सौदा मानते हैं। राजस्थान में उदयपुर से ले कर जैसलमेर तक, हैदराबाद में हुसैनसागर, हरियाणा में दिल्ली से सटी सुल्तानपुर लेक या फिर उप्र के चरखारी और झांसी हों या फिर तमिलनाडु की पुलिकट झील; सभी जगह एक ही कहानी है। हां, पात्र अलग-अलग हो सकते हैं। सभी जगह पारंपरिक जल-प्रबंधन के नष्ट होने का खमियाजा भुगतने और अपने किए या फिर अपनी निष्क्रियता पर पछतावा करने वाले लोग एक समान ही हैं। समाज और सरकार पारंपरिक जल-स्रोतों कुओं, बावड़ियों और तालाबों में गाद होने की बात करते हैं, जबकि हकीकत में गाद तो उन्हीं के माथे पर है। सदा नीरा रहने वाली बावड़ी-कुओं को बोरवेल और कचरे ने पाट दिया तो तालाबों को कंक्रीट का जंगल निगल गया। एक तरफ प्यास से बेहाल होकर अपने घर-गांव छोड़ते लोगों की हकीकत है, तो दूसरी ओर पानी का अकूत भंडार! यदि जल संकटग्रस्त इलाकों के सभी तालाबों को मौजूदा हालात में भी बचा लिया जाए तो वहां के हर इंच खेत को तर सिंचाई, हर कंठ को पानी और हजारों हाथों को रोजगार मिल सकता है।

भय | डॉ. ज्ञानानंददास स्वामी

महाभारत के युद्ध से पूर्व दुर्योधन ने अपनी और पांडवों की सेना का बलाबल देखा। आगे वह आचार्य द्रोण को एक अजीब सी बात कहता है-'हे आचार्य! भीष्म द्वारा रक्षित हमारी सेना अपर्याप्त है जबकि भीम द्वारा रक्षित पांडव सेना पर्याप्त है।' यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि दुर्योधन के पास 11 क्षऔहिणी सेना थी, जबकि पांडवों के पास केवल 7 क्षऔहिणी सेना! फिर भी दुर्योधन को अपनी सेना अपर्याप्त लग रही है। यहां दुर्योधन को डर सता रहा है। क्योंकि सामने भीम और अर्जुन जैसे वीर और अजेय योद्धा हैं। साथ ही वे सक्रिय भी हैं। और इधर भीष्म और द्रोण महाशक्तिशाली होते हुए भी उतने सक्रिय नजर नहीं आते, जितना उन्हें होना चाहिए। इसीलिए दुर्योधन को लगता है कि उसकी सेना अपर्याप्त है जबकि पांडवों की सेना पर्याप्त है। इस प्रकार कौरव पक्ष के पास युद्ध कौशल, रणनीति और अनुभव था, फिर भी उसके नेता को समय-समय पर मानसिक भय क्यों सताता रहता है? विपुल और असीमित साधन भी कम क्यों लगते हैं? दुर्योधन कभी सोचता है कि भीष्म के अनुभव के आधार पर हम युद्ध जीतेंगे, कभी सोचता है कि द्रोण के दिव्य हथियार जीत दिलाएंगे। कभी उसे कर्ण कर्णधार लगता है तो कभी अश्वत्थामा! पहले से ही कभी वह अपनी शक्ति, सत्ता, कीर्ति और धन के आधार पर पांडवों को नीचा दिखाने के काम में लगा रहता था, तो कभी षड्यंत्र रच कर पांडवों को बदनाम करने पर तुला हुआ था। दुर्योधन की ये गतिविधियां पुकार-पुकार कर बता रही थीं कि अनेक मजबूत समर्थनों के बावजूद दुर्योधन भयभीत था। भीम को भोजन में जहर देकर नदी में डुबाने का प्रयास हो या लाक्षागृह में माता सहित पांडवों को जला देने का प्रयास हो, संधि करने आए भगवान कृष्ण को कैद करने का प्रसंग हो या पांडवों को कूटनीति में फंसाने का षडयंत्र। कपटपूर्ण जुआ हो या भरी सभा में द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का घृणित कार्य, दुर्योधन हर जगह अधर्म के साथ खड़ा है। और अधर्मी व्यक्ति के साथ एक ही तत्त्व खड़ा रहता है-भय! यह भय इंसान को भीतर ही भीतर कचोटता है। जी हां, महंतस्वामी महाराज कहते हैं-भयभीत और निराश व्यक्ति को अपने साधन हमेशा अल्प दिखाई देते हैं, जबकि दूसरों की अल्प संपत्ति भी प्रचुर प्रतीत होती है।

रीडर्स मेल

वैक्सीन को लेकर अफवाहबाजी

वैश्विक महामारी कोरोना के दहशत भरे माहौल में दुनिया कह रही थी कि जल्दी से जल्दी इससे निपटने के लिए कोई दवा तैयार होनी चाहिए। इसके लिए लगभग सभी देशों ने बहुत से एक्सपेरिमेंट्स भी किए और वैज्ञानिकों ने टीका तैयार कर लिया। एस्ट्राजेनेका कंपनी ने इसकी कोव वैक्सीन तैयार की और दूसरे देशों तक भी इसे पहुंचाया गया ताकि दुनिया वैश्विक महामारी को हरा सके। अब यह वैक्सीन फिर से सुर्खियों में है। वजह यह है कि एक ब्रिटिश नागरिक ने अपने यहां केस दर्ज कराते हुए कहा है कि उसे इससे साइड इफेक्ट्स हुए हैं। हमारे देश में लोकतंत्र का महापर्व आम चुनाव चल रहा है लेकिन इस बीच कोरोना वैक्सीन का जो मामला सामने आया उस पर राजनीति भी शुरू हो गई है और मोदी सरकार को इसके लिए विपक्ष घेर रहा है। सभी नागरिकों को चाहिए कि वो राजनीतिक दलों के बहकावे में न आएं, बल्कि इससे संबंधित जानकारी स्वास्थ्य विभाग, डॉक्टरों या संबंधित जानकारी रखने वाले लोगों से संपर्क करें। अफवाहों से बचना भी जरूरी है।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

लोकतंत्र की परिपक्वता दांव पर

सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज के मुताबिक वर्तमान में संपन्न हो रहे 18वीं लोक सभा के चुनाव दुनिया के सबसे मंहगे चुनाव साबित होने वाले हैं। इनमें अकेले सरकार का 1.20 लाख करोड़ खर्च हो रहा है। सात चरणों के मतदान में 97 करोड़ मतदाता मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं। इसके लिए देश भर में 10.5 करोड़ पोलिंग बूथ बनाने के साथ 55 लाख ईवीएम का उपयोग हो रहा है। चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराने में 1.5 करोड़ कर्मचारियों सहित सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की गई है लेकिन संपूर्ण आकलन में जनता द्वारा निष्क्रिय सदस्यों का चुनाव एवं चुने गए सदस्यों की जनता के प्रति जवाबदेही में अनदेखी और अनुशासनहीन आचरण विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की परिपक्तता को हास्यपद बनाता है।

विनोद शाह, विदिशा, मप्र

बाध्यता न रहे आरक्षण

आज के चुनावी माहौल में आरक्षण का मुद्दा चर्चा के केंद्र में है तो यह कांग्रेस और बीजेपी में मची इस होड़ का परिणाम है कि येन केन प्रकारेण दलित/आदिवासी समुदाय की वोट को अपने पाले में किया जाए। 150 करोड़ की आबादी वाले देश में दलित 38 करोड़ और ओबीसी 60 करोड़ है, जिनके बल पर कांग्रेस ओर बीजेपी चुनावी वैतरणी पार करना चाहते हैं। मेरा व्यक्तिगत मत है कि राहुल गांधी और भाजपा नेताओं की आरक्षण पर बहस बेमानी है। आजादी के 75 साल में कांग्रेस ने 55 वर्ष और बीजेपी ने करीब 16 वर्ष शासन किया है, बावजूद केंद्र सरकार की सेवाओं में आरक्षण का निर्धारित कोटा कभी भी पूरा नहीं हुआ है। अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग की हमेशा मांग रही है कि आरक्षण पर कानून बनाया जाए। यह कड़वा सच है कि आरक्षण एक बाध्यता है, जिसको सरकार को लागू करना पड़ता है। कांग्रेस और बीजेपी आरक्षण को प्रभावी ढंग से लागू करना चाहती हैं, तो कानून बनाकर इस बाध्यता को कानूनी जामा पहनाया जाए।

विरेंद्र कुमार जाटव, दिल्ली

letter.editorsahara@gmail.com

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

राष्ट्रीय सहारा • राष्ट्रीयता • कर्तव्य • समर्पण
वर्ष-33, अंक 258
सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक जिया कादरी द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन प्रेस, सी-2,3,4, सेक्टर-11, नोएडा में मुद्रित तथा 705-706, सातवां तल, नवरंग हाउस, 21 के.जी. मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित।
। समूह संपादक - डॉ. विजय राय। स्थानीय संपादक - रत्नेश मिश्र* ।
दूरभाष - दिल्ली कार्यालय - 23352368, 23352369, 23352371, 23352372, फैक्स - 23352370, दूरभाष - नोएडा प्रेस 0120-2444755, 2444756 फैक्स - 2550750
आर.एन.आई. सं. 53469/91, पंजीकरण संख्या UP/BR /GZB- 38/2024-2026
*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन तथा कानूनी मामलों के लिए उत्तरदायी

ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्

भगवान इस जग के कण-कण में विद्यमान हैं।

चुनावी विमर्श की सही पहचान

मई दिवस यानि मजदूर दिवस चुनावी शोर-शराबे में गुजर गया और भारत के लोग पहले श्रम मन्त्री बाबू जगजीवन राम को याद करना भी भूल गये। मगर बाबू जी के अलावा डा. अम्बेडकर ने गरीबों व मजदूरों के लिए बहुत काम किया और स्वतन्त्र भारत में उन्हें सम्मान के साथ जीने का हक भी दिलाया। इसके बावजूद आज भी 144 करोड़ लोगों में से 81 करोड़ लोग मुफ्त भोजन पर आश्रित हैं। असल में चुनाव इन्हीं लोगों के लिए होते हैं और सरकार भी इन्हीं के लिए बनती है। वरना भरे पेट आदमी को राजनैतिक अखाड़ेबाजी में रुचि नहीं होती। यह विडम्बना ही कही जायेगी क्योंकि शहरों का मतदान प्रतिशत गांवों की अपेक्षा शुरू से ही कम रहता आया है। खुद को संभ्रान्त समझने वाला यह वर्ग मत देने में क्यों कोताही बरतता है, यह कोई शोध का विषय नहीं है। उसकी रुचि सरकार की आलोचना करने में तो होती है मगर मतदान के दिन मतदान केन्द्र तक जाने की जहमत वह नहीं उठाता।

लोकसभा चुनावों में इस वर्ग की हिस्सेदारी कम होती है मगर सरकार से यह वर्ग बहुत कुछ अपेक्षा करता है। इसमें इस वर्ग की गलती नहीं है क्योंकि बाजार मूलक अर्थव्यवस्था में पूंजी का प्रभाव सर्वत्र रहता है। मगर भारत एक कल्याणकारी राज्य है और चुनावों में हर पांच साल बाद हम यही व्यवस्था करते हैं कि भारत की सरकार समाज के वंचितों, गरीबों, दलितों व पिछड़ों व अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए इस प्रकार काम करेगी कि सम्पन्न लोगों के अधिकार भी सुरक्षित रहें अर्थात उनके साथ भी हर क्षेत्र में बराबर का न्याय हो। मगर गरीब वर्ग के लोगों के साथ लोकतन्त्र में न्याय होना बहुत जरूरी होता है। सबसे पहला न्याय उनकी मजदूरी को लेकर होता है। जो लोग अपना श्रम बेचते हैं उसकी पूरी कीमत आंकने की जिम्मेदारी लोकतन्त्र में जनता द्वारा चुनी गई सरकार की होती है। सरकार यह काम श्रम व रोजगार मूल्य आंकने वाले विशेषज्ञों की मार्फत कराती है। संयुक्त राष्ट्र संघ में इसके लिए पृथक प्रकोष्ठ है। यह अजीब संयोग है कि भारत में लोकसभा के 18वें लोकसभा चुनाव हो रहे हैं मगर किसी एक भी चुनाव में मजदूरों की वाजिब मजदूरी कभी भी चुनावी मुद्दा नहीं बन सकी। इसकी क्या वजह हो सकती है? बेशक कम्युनिस्ट पार्टियां यह सवाल उठाती रही हैं मगर प्रमुख मध्यमार्गी राजनैतिक दलों का विमर्श कभी मजदूरों की मजदूरी के करीब नहीं रहता। इस बारे में समाजवादी चिन्तक डा. राम मनोहर लोहिया बड़े स्पष्ट विचार रखते थे। वह कहते थे कि किसी मकान चिनने वाले मजदूर की मजदूरी का तय होना मकान बनाने के सामान की कीमत से सीधे बांधा जाना चाहिए। किसी नाई की मजदूरी किसी भी तरह किसी जूनियर इंजीनियर के बराबर ही होनी चाहिए। रिक्शा वाले की मजदूरी दवाइयों की बढ़ती कीमत के अनुपात में होनी चाहिए। कुली की मजदूरी रेलवे के प्रथम दर्जे के टिकट के बढ़ते भाड़े के अनुपात में होनी चाहिए।

लोकसभा चुनावों में इस वर्ग की हिस्सेदारी कम होती है मगर सरकार से यह वर्ग बहुत कुछ अपेक्षा करता है। इसमें इस वर्ग की गलती नहीं है क्योंकि बाजार मूलक अर्थव्यवस्था में पूंजी का प्रभाव सर्वत्र रहता है। मगर भारत एक कल्याणकारी राज्य है और चुनावों में हर पांच साल बाद हम यही व्यवस्था करते हैं कि भारत की सरकार समाज के वंचितों, गरीबों, दलितों व पिछड़ों व अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए इस प्रकार काम करेगी कि सम्पन्न लोगों के अधिकार भी सुरक्षित रहें अर्थात उनके साथ भी हर क्षेत्र में बराबर का न्याय हो। मगर गरीब वर्ग के लोगों के साथ लोकतन्त्र में न्याय होना बहुत जरूरी होता है।

भारत में आज भी जब 81 करोड़ लोग मुफ्त राशन लेकर अपना पेट भर रहे हैं तो समझा जा सकता है कि गरीबी की सीमा रेखा से थोड़ा ऊपर रहने वाले लोग किस प्रकार अपना गुजारा चला रहे होंगे। मगर बाजार मूलक अर्थव्यवस्था में बहुराष्ट्रीय कम्पनियां अपना कारोबार इन गरीब लोगों के बीच भी किस जुगाड़ से चला रही हैं, यह भी समझने वाली बात है। बिस्कुट से लेकर अन्य खाद्य पदार्थ बानने वाली कम्पनियों ने अपने सामान की मिकदार कम कर दी है और कीमत पुरानी ही रहने दी है। भारत के कस्बों में आपको दस रुपये की बड़ी कम्पनी की डबल रोटी भी मिल जायेगी और पांच रुपए में बिस्कुट का पैकेट भी मिल जायेगा। ये सब चीजें गरीबों का मजाक उड़ाती दिखती हैं। मगर चुनाव में कभी इनका जिक्र नहीं होता जबकि यह मसला भारत के उन्हीं 81 करोड़ लोगों का है जिन्हें सरकार महीने का मुफ्त का राशन देती है। मजदूरों को ठेके पर रखने की जो नई प्रथा शुरू हुई है उसे खत्म करने की हुंकार राजनैतिक दल भरते हुए दिखाई नहीं देते हैं। केवल राहुल गांधी इस बारे में बात करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं।

सवाल यह है कि जब करोड़ों लोगों का भविष्य ठेके से बंध चुका है तो यह विमर्श चुनावों में सुर्खियां क्यों नहीं बटोर रहा है लेकिन मुझे डर है कि कहीं कुछ लोग मुझे ही कम्युनिस्ट न समझ बैठें! मैं जो भी बात कर रहा हूं वह गांधीवाद की कर रहा हूं। गांधीवाद कहता है कि लोकतन्त्र में सरकार जो भी फैसला करे वह यह सोच कर करे कि उसके फैसले का असर समाज के सबसे गरीब आदमी पर क्या पड़ेगा। अत: सरकार को जो भी फैसला और नीति निर्धारित करनी चाहिए वह यह सोच कर करनी चाहिए कि उसके कदमों का असर 81 करोड़ गरीब लोगों पर क्या पड़ेगा। चुनावी प्रचार में हमें देखना चाहिए कि बात किन लोगों की हो रही है और किनके लिए हो रही है। लोकतन्त्र में चुनाव आम जनता के लिए राजनीति की पाठशाला होते हैं जिनमें प्रत्येक राजनैतिक दल अपने सिद्धांतों व विचारधारा के बारे में बताता है। मगर भारत में चुनावों में इसके अलावा और सभी मुद्दों पर जमकर वाद-विवाद होता रहता है। परिपक्व लोकतन्त्र हमें राजनीति में परिपक्व बनाता है न कि एक-दूसरे का निन्दक। सभी राजनैतिक दल इस बारे में गंभीरता से विचार करें।

आदित्य नारायण चोपड़ा

Adityachopra@punjabkesari.com

कुर्सी का अभिमान नजर आ रहा है

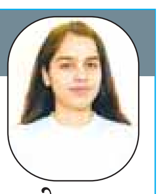

"कुछ नेताओं में कुर्सी का अभिमान नजर आ रहा है,
औरत को देवी का संबोधन बेईमान नजर आ रहा है,,
नारी की इज्जत का लगता हुआ यहां दाम नजर आ रहा है ,
बिकता हुआ देश की नारी का सम्मान नजर आ रहा है,,
राजनीति में मचता हुआ घमासान नजर आ रहा है,
आज का नेता मुझे आज का शैतान नजर आ रहा है...।"

गीता पाढा

मर्यादाएं

चन्द्रमोहन

संपादक : वीर प्रताप

chander_m@ hotmail.com
BLOG: chandermohan.net

देश की समस्या नम्बर-1, बेरोज़गारी

पहला समाचार महाराष्ट्र में मुम्बई से कुछ दूर पालघर से है जहां आदिवासी महिलाओं ने सरकार से मिले 5 किलो चावल और एक साड़ी यह कहते हुए लौटा दिए कि उन्हें ख़ैरात नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए। नरेन्द्र मोदी का चित्र लगे बैग में उन्हें राहत सामग्री भेजी गई थी, पर लौटा दी गई, क्योंकि उनका कहना था कि उन्हें मुफ्त कुछ नहीं चाहिए, उन्हें सशक्त बनाया जाए, वह इज्जत की रोटी खाना चाहती हैं। सरकार की तरफ़ से 80 करोड़ लोगों को 5 किलो मुफ्त चावल या आटा दिया जाता है। और यह महिलाओं अपने बच्चों के लिए वह शिक्षा चाहती हैं जिनसे उन्हें बाद में रोज़गार मिल सके। दूसरा समाचार हमारे प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स आईआईटी से है जहां पहली बार 30-35 प्रतिशत विद्यार्थी अभी भी सही नौकरी मिलने के इंतजार में हैं। पहली बार है कि कम्प्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग के छात्र जिनकी देश-विदेश में सबसे अधिक मांग रहती है, के साथ ऐसा हो रहा है कि शत-प्रतिशत को नौकरी नहीं मिली। कुछ अभी भी नौकरी के बुलावे के इंतज़ार में हैं।

वैश्विक मंदी इसका बड़ा कारण है। एआई, आरटीफिशल इंटेलिजेंस से भी इस सैक्टर की नौकरियों को ख़तरा है, पर अगर इतने पढ़े-लिखे लोग भी उचित रोजगार के लिए परेशान हैं तो यह देश की अर्थव्यवस्था की बहुत चिन्ताजनक तस्वीर पेश करती है। मैं डा. संदीप सिंह पीएचडी सब्जी वाला के बारे लिख चुकां हूं जो पीएचडी और चार एम.ए. करने के बाद भी रेहड़ी पर सब्जी बेचने पर मजबूर है। हमारे टैक्नालॉजी सैक्टर जिस पर हम गर्व करते हैं, में जनवरी, 2022 के बाद हजारों लोगों की नौकरी गई है। 25 साल के बाद पहली बार है कि आई.टी. सैक्टर भी सिंकुड़ रहा है। इस सबसे अलग एक और बुरा समाचार है। तेलंगाना से गए मोहम्मद अफ़सान की रूस की तरफ़ से लड़ते यूक्रेन सीमा पर मौत हो गई। उसे बताया गया कि मास्को में उसे काम मिलेगा, पर 15 दिन की ट्रेनिंग के बाद सीमा पर भेज दिया गया और भी हमारे लोग हैं जो धोखे में फंस गए और यूक्रेन सीमा पर पहुंच गए। युद्धरत इजराइल में भी हमारे लोग काम करने के लिए जा रहे हैं क्योंकि वेतन अच्छा है। मजबूरी है क्योंकि देश में नौकरी नहीं मिलती। विदेश में नौकरी की तलाश में हमारे नौजवान किस तरह भटक रहे हैं वह बहुत बार चर्चित हो चुका है। पिछले साल इंग्लिश चैनल को पार कर ब्रिटेन में अवैध तौर पर घुसने के प्रयास में भारतीयों में 60 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह सब अलग-अलग घटनाएं बता रही हैं कि दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ रही बड़ी अर्थव्यवस्था में रोज़गार का कितना बड़ा संकट पैदा हो चुका है। हम पंजाब में देख रहे हैं कि जो नौजवान बाहर जा सकता है वह बाहर भागने की कोशिश करता है और जो बाहर चले गए वह वापस आने के लिए तैयार नहीं। सीएसडीएस के राष्ट्रीय सर्वेक्षण में यह सामने आया है कि देश के सामने दो सबसे बड़े मुद्दे बेरोजगारी और महंगाई है, हिन्दुत्व या राम मंदिर नहीं है। सर्वेक्षण के अनुसार 27 प्रतिशत लोग बेरोजगारी और 23 प्रतिशत महंगाई को मुख्य मुद्दा मानते हैं। 62 प्रतिशत का कहना है कि पिछले पांच वर्षों में

नौकरी ढूंढना और मुश्किल हो गया है। नोटबंदी, कोविड और लॉकडाउन का रोजगार पर बहुत बुरा असर पड़ा है। विशेष तौर पर एमएसएमई अर्थात लघु, कुटीर और मध्यम उपक्रम को जो झटका मिला है उससे वह उभर नहीं सके जिसने रोजगार को बुरी तरह से प्रभावित किया है। अर्थव्यवस्था में मैनुफैक्चरिंग का हिस्सा 13 प्रतिशत गिरा है। इस तरफ बहुत ध्यान देने की जरूरत है। अमेरिका की टफ्टस यूनिवर्सिटी के डीन भास्कर चक्रवर्ती ने लिखा है कि भारत को, "आई-फोन, टैसला वाहन, सैमीकंडकटर ही नहीं बनाने चाहिए बल्कि छोटे और मध्यम उत्पादकों को सशक्त करना है...जो लेबर बेहतर खपा सकें"। बेरोजगार युवा किसी भी समाज को अस्थिर कर सकते हैं। इन्हें सम्भालने की बहुत जरूरत है। हम अमेरिका में देख रहे हैं कि किस तरह यूनिवर्सिटियों में फिलिस्तीन के पक्ष में प्रदर्शनों को लेकर छात्रों ने सरकार की नाक में दम कर रखा है। फ्रांस में ऐसे प्रदर्शन बार-बार होते हैं। हम बचे हुए हैं क्योंकि लोगों में धैर्य है, पर इस धैर्य की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। पिछले दशक से बहुत परिवर्तन आ गया है। लोगों के हाथ में मोबाइल है जो हर जानकारी घर-घर पहुंचा रहे हैं, जो जानकारी छिपाने की कोशिश की जाती है वह भी इंटरनेट के द्वारा घर-घर पहुंच रही है।

बढ़ती गैर-बराबरी चर्चा का विषय है। यह अच्छी बात है कि देश के धन को लेकर बहस हो रही है। हमें गरीबी नहीं बांटनी, पर बेहिसाब अरबपति पैदा करना भी सही दिशा नहीं है। अम्बानी, अडानी या टाटा जैसे उद्योगपतियों का योगदान है, यह स्वीकार किया जाना चाहिए। वह लाखों को रोजगार देते हैं। सरकार को भारी टैक्स मिलता है, अर्थव्यवस्था को गति मिलती है, पर दूसरा छोर भी तो है जहां 80 करोड़ को हम मुफ्त राशन देने के लिए मजबूर हैं। दुनिया के हर देश में गैर-बराबरी है, पर सबसे अधिक हमारे देश में हैं। 1 प्रतिशत रईसों के पास राष्ट्रीय सम्पत्ति का 40.1 प्रतिशत और आय का 22.6 प्रतिशत हिस्सा है। देश की बढ़ती जीडीपी का वितरण सही नहीं हो रहा। आर्थिक दिशा पर राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्रीय बहस की जरूरत है। दुनिया में तीसरी सबसे अधिक डालर-अरबपतियों की संख्या भारत में है जबकि दूसरी तरफ हमारे लगभग 1 अरब लोग रोजाना 250 रुपए से कम कमाते हैं। जनवरी 2023 में रोजगार का सबसे चिन्ताजनक आंकड़ा 37.4 प्रतिशत हरियाणा से था जबकि यह एक प्रगतिशील प्रांत समझा जाता है। हर सरकार ने रोजगार देने की कोशिश की है, पर हमारी आबादी ही इतनी है कि यह असंभव सा काम लगता है। अनुमान है कि अगले कुछ दशकों तक हर साल 1.2 करोड़ नए युवा वर्कर मार्केट में उतरेंगे। इनके लिए रोजगार का प्रबंध कैसे होगा? लेबर इकानिमिस्ट के.आर. श्याम सुंदर ने इंडिया टुडे को बताया है कि बढ़ती जनसंख्या के अनुपात में वेतनभोगी संख्या नहीं बढ़ रही।

उनके अनुसार, "जमीनी हकीकत बताती है कि निम्न स्तर के खुद काम करने वाले बढ़ रहे हैं..." इनमें घरों में काम करने वाले, रेहड़ी लगाने वाले या मजदूरी करने वाले हैं। कहने को तो कहा जा रहा है कि युवा हमारा खजाना हैं, पर यह तब ही है अगर हम इन्हें सही रोजगार दे सकें और इनके पास मौके का फायदा उठाने के लिए पर्याप्त कौशल हो। दोनों ही नहीं है।

सरकार की नई शिक्षा नीति में स्किल अर्थात कौशल पर जोर तो दिया जा रहा है, पर अभी भी हमारी शिक्षा प्रणाली अधिकतर पढ़े-लिखे अनपढ़ पैदा कर रही है। 2022-23 में 15-29 आयु के 16 प्रतिशत युवा अच्छी नौकरी के अभाव में या कौशल और सही शिक्षा की कमी के कारण बेरोजगार थे। लगभग 30 प्रतिशत ग्रैजुएट बेरोजगार हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ की 2024 की 'इंडिया एमप्लौयमैंट रिपोर्ट' के अनुसार भारत में रोजगार ढूंढना, विशेष तौर पर पढ़े-लिखे युवाओं के लिए बहुत मुश्किल है। काम की तलाश में भटकते युवाओं की संख्या डरावनी है। यह भी उल्लेखनीय है कि बेरोजगारी पढ़े-लिखों में अधिक है। इसी संकट का परिणाम है कि चार साल पहले की तुलना में आज कृषि सैक्टर में 6 करोड़ लोग अधिक काम कर रहे हैं। जो युवा नौकरी की तलाश में शहर की तरफ गए थे वह निराश वापस गांव लौट रहे हैं। इससे आर्थिक पीड़ा और बढ़ेगी। देश के अन्दर रोजगार की बहुत मंद तस्वीर है इसलिए जहां एक तरफ ध्यान हटाने का प्रयास (राजे-महाराजे बनाम नवाब, समाज का एक्स-रे आदि) हो रहा है तो दूसरी तरफ वादे किए जा रहे हैं। भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में 'रोजगार के पर्याप्त अवसर...गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा तक पहुंच' का वादा किया है, पर यह नहीं बताया कि रास्ता क्या है? कांग्रेस ने गारंटी दी है कि हर शिक्षित युवा को एक लाख रुपये वार्षिक का अप्रेंटिसशिप अधिकार दिया जाएगा और 30 लाख सरकारी नौकरियों को भरा जाएगा। कांग्रेस यह नहीं बता रही कि साधन कहां से आएंगे जबकि भाजपा नेतृत्व को उम्मीद है कि जैसे-जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होगा वैसै-वैसे रोजगार स्वयं ही बढ़ेगा लेकिन इस में समय लगेगा। युवा मिर्जा गालिब के साथ कह सकते हैं।

ख़ाक हो जाएंगे हम तुम को खबर होने तक !

कब तक पीएचडी और उच्च शिक्षा प्राप्त युवा चपरासी या क्लास फ़ोर की नौकरी के लिए भी धक्के खाते रहेंगे ? अगर हताशा फैल गई तो बहुत बड़ी समस्या होगी, जो राजनीतिक तू-तू मैं-मैं आजकल हो रही है क्या उससे आभास भी होता है कि राजनीतिक वर्ग को युवाओं की तकलीफ का अहसास भी है? न ही शिक्षा क्षेत्र में वह सुधार किया जा रहा है जिससे युवा बाद में अपने पैरों पर खड़े हो सके। राजनीति और विचारधारा से ऊपर उठ कर शिक्षा क्षेत्र की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। 2004 में वाजपेयी सरकार की हार के बाद प्रमोद महाजन ने कहा था कि गरीबों ने सरकार गिरा दी इसलिए सावधान रहना चाहिए। जब तक युवाओं को उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप रोजगार नहीं मिलता यह समस्या इस सरकार और आने वाली सरकारों को परेशान करती जाएगी।

खालसाई रंग में डूबी हुई है समूची दिल्ली

सिख सियासत

सुदीप सिंह

newsreporter.2008@gmail.com

इतिहास की जानकारी रखने वाले लोग भलीभांति इस बात को जानते हैं कि सिखों ने 19 बार दिल्ली को जीता और उसमें से 2 से 3 बार तो दिल्ली पर राज भी किया। 1783 में बाबा बघेल सिंह, जस्सा सिंह रामगढ़िया, जस्सा सिंह आहलुवालिया, महा सिंह शुक्रचकिया जैसे योद्धाओं के द्वारा दिल्ली को एक बार फिर से जीतकर सैकड़ों साल पुराने मुगल साम्राज्य का अंत किया। सिखों के द्वारा लालकिला पर

केसरिया निशान साहिब झुलाए गये और उसी की बदौलत आज वहां तिरंगा झूल रहा है मगर अफसोस कि सिखों की सूरवीरता के इतिहास की जानकारी दूसरों तक तो क्या पहुंचानी थी? ज्यादातर सिख अपने बच्चों को भी इसकी जानकारी नहीं दे पाए। पिछले कुछ साल पहले दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी पर जब मनजीत सिंह जीके, मनजिन्दर सिंह सिरसा की कमेटी बनी तो उनके द्वारा इस इतिहास को लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से दिल्ली फतेह दिवस का आगाज किया गया, हालांकि उस समय विपक्षी दलों के द्वारा इस पर कई तरह की टिप्पणियां करते हुए इसे फिजूल खर्च भी बताया गया था। उसके बाद से हर साल दिल्ली फतेह दिवस मनाकर लोगों को बताया जाता है कि सिख दिल्ली के असली वारिस हैं इसलिए उनकी देशभक्ति पर कभी शक नहीं किया जाना चाहिए। इस बार भी दिल्ली कमेटी अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका, महासचिव जगदीप सिंह काहलो, धर्म प्रचार चेयरमैन जसप्रीत सिंह करमसर के द्वारा दिल्ली फतेह दिवस को बढ़-चढ़ कर मनाया गया। इस बार माता गुजरी जी के 400 साला प्रकाश पर्व को समर्पित होकर इसे मनाया गया जिसमें महिलाओं को विशेष तौर पर कीर्तन करने और गतका प्रदर्शन की जिम्मेवारी सौंपी गई थी। साल में एक दिन ही सही पूरी दिल्ली खालसाई रंग में डूबी हुई दिखाई देती है। संगत में भी इस दिन को लेकर खासा उत्साह देखने को मिलता है।

सिखों के खिलाफ साजिश : सिख धर्म की अपनी मर्यादा है जो कि गुरु साहिब के समय से ही चलती आ रही है मगर कुछ दिन पहले जिस तरह से सिख मर्यादा के उलट जाकर गुरुद्वारा साहिब में नमाज अदा करवाई गई। उसे लेकर सिख चिन्ता में ही थे कि 2 सिख युवकों के द्वारा नमाजियों के साथ मिलकर नमाज अदा करने की एक और वीडीयो सोशल मीडीया पर वारयल हो गई जो कि पाकिस्तान के ननकाणा साहिब की बताई जा रही है और नमाज अदा करने वाले सिख भारत से पाकिस्तान दर्शनों के लिए गये थे। पंजाब के बरनाला से तो इससे भी दो कदम आगे जाकर गुरुद्वारा साहिब के अन्दर गुरुग्रन्थ साहिब की मौजूदगी में मुस्लिम धर्म में की जाने वाली पूजा, कलमें पढ़कर मुस्लिम लड़कियों का निकाह करवाया गया। इसके पीछे कौन लोग हैं और उनका मकसद क्या है यह समझना बहुत जरूरी है और अगर समय रहते इस पर रोक नहीं लगाई गई तो आने वाले समय में इसके गंभीर परिणाम भी देखे जा सकते हैं। सिख समाज सभी धर्मों का सम्मान करता है। हिन्दू भाईचारा को अपने धार्मिक कार्यक्रम मन्दिरों में इसी प्रकार मुस्लिम को मस्जिद और ईसाई को गिरजाघर में ही करने चाहिए हां अगर किसी कारणवश दूसरें धर्मों के लोगों को जगह की कोई खास आवश्यकता हो तो सिख समाज के लोगों को उनके लिए गुरुद्वारा साहिब के अन्दर किसी कमरे में जहां गुरु ग्रन्थ साहिब विराजमान न हों, इस तरह के आयोजन का प्रबन्ध किया जा सकता है मगर गुरु साहिब की हजूरी में किसी भी सूरत में इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। भाई बलदेव सिंह वडाला द्वारा इसका सख्त नोटिस लेते हुए दोषियों के खिलाफ बनती धार्मिक कार्यवाही की मांग की जा रही है। हालांकि तख्तों पर बैठे जत्थेदार यां अन्य धार्मिक लोगों को इस पर संज्ञान लेना चाहिए था मगर पता नहीं क्यों उनके द्वारा इस पर कोई प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आई है। यह भी हो सकता है कि हिन्दू सिख एकता में दरार डालने के लिए किसी के द्वारा इस तरह की घटनाओं को अन्जाम दिया जा रहा हो, सिख समाज के बुद्धिजीवियों को इसे गंभीरता से लेते हुए इसकी गहराई तक जांच करनी चाहिए और श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार साहिब को भी अपनी जिम्मेवारी समझते हुए दोषियों के खिलाफ सख्ती से कार्यवाही करनी चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हो सकें।

प्रो अजायब सिंह की याद हमेशा आएगी : इस दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनके संसार से जाने के बाद भी उन्हें दुनिया याद रखती है। उनके जाने का परिवार को उतना दु:ख नहीं होता जितना समाज को होता है। उन्हीं में से एक थे खालसा कालेज दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफैसर, स. अजायब सिंह। जिनका नाम दिल्ली के चुनिन्दा अकालियों में लिया जाता है। दिल्ली के एतिहासिक गुरुद्वारों को सरकारी कब्जे से मुक्ति दिलानी हो या फिर एमरजैंसी का मोर्चा हो प्रो. अजायब सिंह ने हमेशा आगे की कतार में खड़े होकर लड़ाई को लड़ा जिसके लिए उन्हें कई महीनों तक जेल में भी रखा गया।

देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपाई और इन्द्र कुमार गुजराल से भी उनकी काफी नजदीकियां रही हैं। प्रो. अजायब सिंह शिरोमणि अकाली दल के दिल्ली में प्रधान भी रहे और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी में भी उन्होंने अपनी सेवाएं दीं। अकाली नेता प्रकाश सिंह बादल, गुरचरण सिंह टोहड़ा, जत्थेदार अवतार सिंह हित, कुलदीप सिंह भोगल आदि सभी के साथ उन्होंने काम किया। पिछले लम्बे समय से वह बीमार चल रहे थे बावजूद इसके जब उनसे मिले तो उन्होंने सिख राजनीति में आ रही गिरावट पर चिन्ता व्यक्त करते हुए जत्थेदार अवतार सिंह हित को सभी सिखों को एकजुट करने का सुझाव दिया।

छत्तीसगढ़ : सुरक्षाबलों ने 60 किलोमीटर की दूरी पैदल चलकर 'माड़ बचाओ अभियान' को दिया अंजाम

नारायणपुर, (पंजाब केसरी): छत्तीसगढ़ के नारायणपुर-कांकेर जिले के घने जंगलों में सुरक्षाबलों के लगभग 900 जवानों ने चुनौतियों का सामना करते हुए 60 किलोमीटर की दूरी पैदल तय की और बड़े नक्सली नेताओं समेत 10 नक्सलियों को मार गिराया। एक सफल नक्सल विरोधी अभियान 'माड़ बचाओ अभियान' को अंजाम देने के बाद सुरक्षाबल के जवान मारे गए नक्सलियों के शवों को लेकर बुधवार को अपने आधार शिविर में लौट गए। मारे गए अधिकांश नक्सली गढ़चिरौली डिवीजन से हैं। बस्तर क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी. ने बताया कि महाराष्ट्र सीमा से लगे हुए जंगलों में नक्सली नेताओं की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद 28 अप्रैल की रात को 'माड़ बचाओ अभियान' शुरू किया गया। सुंदरराज ने बताया कि इस अभियान में जिला रिजर्व गार्ड (डीआरजी) के 240 और राज्य के विशिष्ट नक्सल विरोधी बल 'स्पेशल टास्क फोर्स' (एसटीएफ) के 590 जवानों को नारायणपुर और कांकेर जिलों के विभिन्न शिविरों से रवाना किया गया था। उन्होंने बताया कि सुरक्षा बलों ने दुर्गम इलाके और चुनौतियों का सामना करते हुए 60 किलोमीटर की दूरी को पैदल तय किया। सुंदरराज ने बताया कि मंगलवार सुबह लगभग चार बजे जब सुरक्षाबल टेकमेटा-काकुर गांव के जंगल की घेराबंदी कर रहे थे तब डेरा

डाले हुए नक्सलियों ने उन पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। जिसके बाद सुरक्षाबल के जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की। उन्होंने बताया कि रुक-रुक कर गोलीबारी रात आठ बजे तक करीब 16 घंटे तक चली। उन्होंने बताया कि तलाशी के दौरान मौके से तीन महिलाओं समेत 10 नक्सलियों के शव बरामद किए गए।

पुलिस अधिकारी ने बताया, 'मारे गए अधिकांश नक्सली माओवादियों के गढ़चिरौली डिवीजन से हैं, जो प्रेस टीम से जुड़े थे और तेलंगाना, महाराष्ट्र और बस्तर (छत्तीसगढ़) के रहने वाले थे।''

उन्होंने बताया कि डीआरजी, एसटीएफ और सीमा सुरक्षा बल अभी भी इलाके में अभियान पर हैं।

सुंदरराज ने बताया कि अब तक 10 में से आठ नक्सलियों की पहचान की जा चुकी है तथा उनके सिर पर कुल 63 लाख रुपये का इनाम है।

कोविशील्ड केस की हो उच्च स्तरीय न्यायिक जांच : अखिलेश यादव

लखनऊ, (पंजाब केसरी): कोविशील्ड वैक्सीन के 'साइड इफेक्ट्स' को लेकर उठे विवाद के बीच समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने लोगों की जान जोखिम में डालकर वैक्सीन निर्माता से राजनीतिक चंदा वसूला है और इसकी उच्च स्तरीय न्यायिक जांच की जानी चाहिए। यादव ने कहा कि ऐसी 'जानलेवा' दवाओं की अनुमति देना किसी की हत्या की साजिश के समान है और इसके लिए जिम्मेदार लोगों पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। यादव ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा,एक व्यक्ति को दो वैक्सीन के हिसाब से लगभग 80 करोड़ भारतीयों को कोविशील्ड वैक्सीन दी गयी है, जिसके बारे में

सरकार सौदागर नहीं होनी चाहिए

उसका मूल फ़ार्मूला बनानेवाली कंपनी ने कहा है कि इससे हृदयघात का ख़तरा हो सकता है। जिन लोगों ने वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट के कारण अपनों को खोया है या जिन्हें वैक्सीन के दुष्परिणामों की आशंका थी, अब उनका शक़ और डर सही साबित हुआ है। उन्होंने कहा, लोगों की ज़िंदगी से खिलवाड़ करने वालों को जनता कभी माफ़ नहीं करेगी। ऐसी जानलेवा दवाइयों को अनुमति देना किसी की हत्या के षड्यंत्र के बराबर है और इसके लिए ज़िम्मेदार लोगों पर आपराधिक मुक़दमा चलना चाहिए। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर निशाना साधते हुए कहा, ''सत्ताधारी दल ने वैक्सीन बनानेवाली कंपनी से राजनीतिक चंदा वसूलकर जनता की जान की बाज़ी लगायी है।

भाजपा के बुलावे पर चुनाव देखने भारत आए 10 देशों के प्रतिनिधि

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी) लोकसभा चुनाव का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करने के लिए सत्तारूढ़ पार्टी के निमंत्रण पर भारत की यात्रा पर आए 10 देशों के 18 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि यहां भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष जे पी नड्डा और विदेश मंत्री एस जयशंकर सहित पार्टी के कई नेताओं से बातचीत करेंगे। भाजपा ने कहा कि विदेशी नेताओं को पार्टी के चुनाव अभियान की जानकारी दी जाएगी और उन्हें उसकी रणनीतियों और समग्र चुनावी प्रक्रिया के बारे में बताया जाएगा। पार्टी की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि विदेशी प्रतिनिधि बुधवार को नड्डा से मुलाकात करेंगे और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ भी बातचीत करेंगे। बांग्लादेश की अवामी लीग, इजराइल की लिकुड पार्टी, युगांडा की नेशनल रेजिस्टेंस मूवमेंट, तंजानिया की चामा चा मापिनदुजी और रूस की यूनाइटेड रशिया पार्टी उन राजनीतिक दलों में शामिल हैं, जिनके प्रतिनिधि भारत की यात्रा पर हैं।

दिल्ली आर.एन.आई. नं. 40474/83

पंजाब केसरी

दिल्ली कार्यालय :
फोन आफिस: 011-30712200, 45212200,
प्रसार विभाग: 011-30712224
विज्ञापन विभाग: 011-30712229
सम्पादकीय विभाग: 011-30712292-93
मैगजीन विभाग: 011-30712330
फैक्स : 91-11-30712290, 30712384, 011-45212383, 84
Email: Editorial@punjabkesari.com

स्वत्वाधिकारी दैनिक समाचार लिमिटेड, 2-प्रिंटिंग प्रेस कॉम्पलैक्स, नजदीक वजीरपुर डीटीसी डिपो, दिल्ली-110035 के लिए मुद्रक, प्रकाशक तथा सम्पादक अनिल शारदा द्वारा पंजाब केसरी प्रिंटिंग प्रैस, 2-प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से मुद्रित तथा 2, प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से प्रकाशित।

हिन्दुस्तान
1936 सत्य • सार्थक • सदैव

विवाह की वैधता

देश की सर्वोच्च अदालत ने हिंदू विवाह पर एक नई व्यवस्था देते हुए कहा है कि अगर अपेक्षित विवाह समारोह नहीं हुआ है, तो हिंदू विवाह अमान्य है। अदालत ने हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत विवाह की कानूनी आवश्यकताओं और पवित्रता को स्पष्ट करने की जो कोशिश की है, उस पर पूरी गंभीरता से गौर करने की जरूरत है। इस फैसले को समग्रता में नहीं समझा गया, तो हिंदू विवाह की वैधता को लेकर अक्सर सवाल उठेंगे। न्यायालय ने जोर दिया है कि हिंदू विवाह की वैधता के लिए सप्तपदी (पवित्र अग्नि के चारों ओर सात फेरे) जैसे उचित संस्कार और समारोह जरूरी है। विवाद की स्थिति में समारोह के प्रमाण पेश करना जरूरी है। सात फेरों और समारोह का मूल्य समझाने की यह कोशिश ध्यान देने लायक है। इसमें कोई शक नहीं कि विवाह संस्कार का मूल महत्व पहले की तुलना में कम हुआ है, अब विवाह बहुतों के लिए एक दिखावा, मजबूरी या समझौता भर रह गया है। न्यायमूर्ति बी नागरत्ना ने अपने फैसले में बिल्कुल सही कहा है कि हिंदू विवाह एक संस्कार है, जिसे भारतीय समाज में एक महान मूल्य की संस्था के रूप में दर्जा दिया जाना चाहिए।

हालांकि, विवाह की पवित्रता का आभास समाज में समय के साथ घटा है और उसमें सुधार की जरूरत है। जो लोग विवाह को मात्र एक पंजीकरण मानते हैं, उन्हें चेत जाना चाहिए। उन्हें सात फेरों का अर्थ समझना होगा। सात फेरों का अर्थ समझे बिना हिंदू विवाह को नहीं समझा जा सकता और सर्वोच्च न्यायालय के ताजा फैसले में ऐसी ही समझाइश की कोशिश झलकती है। अदालत ने यह भी साफ किया है कि हिंदू विवाह एक संस्कार है और यह नाच-गाने, खाने-पीने का आयोजन नहीं है। अपेक्षित विवाह समारोह होना चाहिए, उसके बिना मात्र पंजीकरण से विवाह वैध नहीं हो जाता है। दहेज या उपहार का आदान-प्रदान भी विवाह नहीं है और इसे रोकने के लिए कानून भी लागू है। कुल मिलाकर, अगर न्यायालय का संदेश यह है कि फिजूल के तमाशे-दिखावे से बचते हुए विवाह के मूल अर्थ को समझना चाहिए, तो यह सुखद और स्वागतयोग्य है। फिर भी अदालतों को सचेत रहना होगा कि ताजा फैसले के बाद विवाह पंजीकरण का महत्व कहीं कम न हो जाए। असंख्य विवाह बहुत जरूरी होने पर या सुरक्षा की दृष्टि से ही सुनियोजित ढंग से पंजीकृत किए जाते हैं। विवाह पंजीकरण का यह रास्ता अगर बंद न हो, तो समाज में अपेक्षाकृत ज्यादा उदारता बहाल रहेगी।

कुछ खास हालात की वजह से विगत वर्षों में अनेक ऐसे अदालती फैसले आए हैं, जिनके बाद विवाह संबंधी नियम-कायदों को समग्रता में सुलझाने की जरूरत बढ़ गई है।

हिंदू विवाह को लेकर अब ज्यादा स्पष्टता की जरूरत है। पिछले वर्षों में कुछ खास हालात की वजह से अनेक ऐसे अदालती फैसले आए हैं, जिनके बाद विवाह संबंधी नियम-कायदों को सुलझाने की जरूरत बढ़ गई है। मिसाल के लिए, एक फैसला देखिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने पिछले दिनों यह माना कि हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार, हिंदू विवाह को संपन्न करने के लिए कन्यादान का समारोह जरूरी नहीं है। उस फैसले में भी सप्तपदी के महत्व को दर्शाया गया था। मध्य प्रदेश की एक परिवार अदालत के फैसले में महिला पक्ष को यह समझाया गया था कि सिंदूर लगाना एक विवाहित हिंदू महिला का धार्मिक कर्तव्य होता है। यह सवाल पूछा जा सकता है कि धार्मिक कर्तव्य बताने या तय करने का काम किसका है? वाकई, बदलते समय में विवाह के तमाम पुराने प्रतीकों और कर्मकांडों पर पुनर्विचार की जरूरत आन पड़ी है।

हिन्दुस्तान Hindustan | 75 साल पहले 02 मई, 1949

खाली लौटना पड़ेगा

नई दिल्ली, १ मई। संयुक्त राष्ट्र के काश्मीर कमीशन ने युद्ध-विराम संधि के लिए जो ''अन्तिम'' प्रस्ताव पेश किये हैं, उनके सम्बन्ध में आज पूछताछ करने से हमारे इस पूर्व विचार की पुष्टि हो गयी कि भारत-सरकार द्वारा उनका स्वीकार किया जाना असम्भव है। इन परिस्थितियों में यह महसूस किया जाता है कि एडमिरल निमिट्ज के लिए अपनी भारत-यात्रा स्थगित कर देना बुद्धिमत्तापूर्ण होगा।

अनुमान है कि काश्मीर कमीशन एडमिरल निमिट्ज को नवीनतम घटनाओं से निरन्तर अवगत करा रहा है, ताकि एडमिरल भारत आने और यहां आकर कुछ महीने बेकार बैठे रहने की परेशानी से बच जायें। ऐसा मालूम होता है कि काश्मीर कमीशन को, युद्ध-विराम संधि न करा सकने की अपनी असफलता की रिपोर्ट सुरक्षा-परिषद के सामने रखने के लिए लेक सक्सेस लौटना पड़ेगा और इसके उपरान्त जो कार्रवाई होगी उसमें कुछ समय लगाया जायेगा। जब तक युद्ध-विराम समझौता न होगा, तब तक जनमत-व्यवस्थापक का कार्य नहीं हो सकता। जो हो, वर्तमान स्थिति के लिए काश्मीर कमीशन को स्वयं अपना ही धन्यवाद करना है। अब वह अपने इरादों को एक अस्पष्ट प्रस्ताव के रूप में नहीं छिपा सकता।

उदाहरणतया, युद्ध-विराम काल में हमलावरों द्वारा अधिकृत प्रदेश का प्रबन्ध रियासती सरकार की तरफ से कमीशन को ''स्थानीय अधिकारियों'' की सहायता से करना है। इन शब्दों के निश्चित अर्थ मालूम होने चाहिए। चूंकि पाकिस्तान को इस मामले में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है और तथाकथित 'आजाद काश्मीर' सरकार को भारत, पाकिस्तान या कमीशन किसी ने स्वीकार नहीं किया है, इसलिए ''स्थानीय अधिकारियों'' शब्दों के अर्थ कुछ भी नहीं हो सकते। यदि कमीशन यह कहता है कि इसका अभिप्राय आजाद काश्मीर के अधिकारियों से है, तो भारत इसे कदापि स्वीकार नहीं कर सकता। क्योंकि इससे उन प्रदेश पर काश्मीर सरकार की सत्ता को ठेस पहुंचेगी, जिसे सुरक्षा-परिषद प्रस्ताव में स्पष्टरूपेण स्वीकार किया हुआ है। अतः ''स्थानीय अधिकारियों'' के शब्दों का निश्चय हुए बिना शांति व व्यवस्था के लिए आवश्यक सेना के प्रश्न पर विचार नहीं हो सकता।

स्कूलों में बम की सूचना से सबक

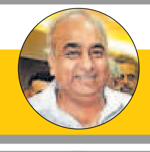
यहां स्कैन करें

दिलीप त्रिवेदी | पूर्व आईपीएस अधिकारी

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के स्कूलों में बम की धमकी में खास दम नहीं, इसका मतलब यह नहीं कि हम हाथ पर हाथ धरे बैठ जाएं। ऐसी धमकियों को पूरी गंभीरता से लेने की जरूरत है।

बुधवार सुबह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के करीब सौ स्कूलों में बम की सूचना ने सबको चिंता में डाल दिया। बड़े पैमाने पर स्कूलों के जरिये दहशत फैलाने की साजिश हुई है। हालांकि, ज्यादातर स्कूलों में सुरक्षा चाक-चौबंद है, बाहरी लोगों को स्कूलों में जाने नहीं दिया जाता है। फिर भी स्कूलों में सुरक्षा की ज्यादा चिंता होनी चाहिए और सभी को नए सिरे से सचेत हो जाना चाहिए।

वैसे, अगर हम गौर करें, तो शायद ही कभी ऐसा होता है, जब दहशतगर्द बताकर हमले करते हैं। 9/11 का हमला हो या 26/11 का हमला, दहशतगर्दों ने घातक हमले पहले बताकर या धमकाकर नहीं किए थे। आम तौर पर हमला होने के बाद ही कोई आतंकी संगठन उसकी जिम्मेदारी लेता है। फिलहाल, स्कूलों में बम की धमकी में कोई खास दम नहीं दिखता है, पर इसका मतलब यह नहीं कि हम हाथ पर हाथ धरे बैठ जाएं। ऐसी धमकियों को भी गंभीरता से लेने की जरूरत है, क्योंकि इसमें बच्चों की सुरक्षा का सवाल शामिल है। जांच पूरी होनी चाहिए, जहां-जहां बम की आशंका बताई गई है, वहां-वहां घेराबंदी करके पुलिस की स्थापित प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए।

दहशतगर्दों की मानसिकता को समझने की जरूरत है, वे अपनी किसी भी कारस्तानी का बड़ा प्रभाव देखना चाहते हैं। ऐसे तत्व भीड़ भरे बाजारों को चुनते हैं, ताकि छोटे धमाके का भी बड़ा असर हो सके। रेलवे स्टेशन, बाजार या बस अड्डे निशाने पर रहते थे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को नुकसान पहुंचाकर समाज में बड़े पैमाने पर दहशत फैला सकें। कभी दिल्ली में ट्रांजिस्टर की मदद से बसों में विस्फोट की साजिश होती थी, खिलौनों का भी इस्तेमाल होता था। अब भीड़ भरे इलाकों की संख्या बढ़ती जा रही है। जैसे ऊंची-ऊंची इमारतें बन गई हैं, अनेक मॉल्स खड़े हो गए हैं, उसी हिसाब से चिंता भी बढ़ गई है। अगर ऐसी जगहों पर विस्फोट हो और भगदड़ मचे, तो बड़े पैमाने पर क्षति पहुंच सकती है, अराजक स्थिति बन सकती है। मतलब, ऐसी तमाम भीड़ भरी जगहों की सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद बनाए रखना होगा, ताकि किसी भी तरह की हिंसक या गलत गतिविधियां ऐसी जगहों पर जाल न बिछा पाएं। भीड़ भरी जगहों की संख्या दिनों दिन बढ़ती चली जाएगी और इससे बचा नहीं जा सकता। मिसाल के लिए, पहले इतनी संख्या में स्कूल नहीं थे, पर अब जगह-जगह स्कूल हो गए हैं, तो चुनौतियां भी बढ़ गई हैं। छोटे शहरों में भी भीड़ बढ़ रही है, पर बड़े शहरों में ज्यादा खतरा है। बड़े शहरों में जब आतंकी घटना होती है, तो देश-दुनिया में ज्यादा चर्चा होती है। दहशतगर्दों का मकसद ही यही होता है कि ज्यादा से ज्यादा प्रचार हो सके। जब वर्ल्ड ट्रेड टावर पर हमला होता है या मुंबई जैसी व्यावसायिक राजधानी पर या दिल्ली में सीधे संसद पर, तब दहशत तेजी से फैलती है। इसमें कोई दोराय नहीं कि देश के सभी आर्थिक-राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण शहरों की चिंता हमें होनी चाहिए।

तमाम स्कूलों, भीड़ भरी जगहों, भवनों के लिए विशेष रूप से सोचना होगा। दुर्घटना होने की स्थिति में बचकर बच्चे या लोग कैसे निकलेंगे? हर भवन के पास भगदड़ से बचने की योजना होनी चाहिए। लोगों को भी जागरूक होना चाहिए। जैसे सिनेमा हॉल है, वहां जगह-जगह बाहर निकलने के आपात-रास्तों के बारे में सूचना दर्ज होती है, पर उस पर लोगों का ध्यान कम जाता है। ऐसी आपात योजनाओं के बारे में सभी लोगों को जानकारी होनी चाहिए, ताकि सुरक्षा और सावधानी के साथ लोग समय रहते अपनी जान बचाकर भवन से बाहर निकल जाएं।

इसी तरह स्कूलों की बात करें, तो स्कूलों में पहले रिहर्सल किया जाता था कि आपात स्थिति में किस कक्षा के छात्र किसी दिशा से होते हुए किस दरवाजे से बाहर निकलेंगे, सारे लोग आपात स्थिति में एक ही दरवाजे की ओर नहीं भागेंगे, कक्षाओं से निकल भागने के अधिक से अधिक या पर्याप्त रास्ते होंगे। छात्रों को बताना होगा कि आपात स्थिति होने पर किस रास्ते से भागकर कहां जाना है या कैसे स्कूल के मैदान में आना है। स्कूलों के पास बचाव की योजनाएं होनी चाहिए। आपातकालीन व्यवस्था का रिहर्सल समय-समय पर किया जाना चाहिए, इससे लोगों को सजग रहने में मदद मिलती है और समाज में लापरवाही भी घटती है।

बहरहाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के जिन स्कूलों को धमकी मिली है, वहां पुलिस को स्कूलों का पूरा मौका-मुआयना करना चाहिए और लगे हाथ स्कूलों की बचाव व्यवस्था की भी समीक्षा करनी चाहिए। ऐसा नहीं मानना चाहिए कि धमकी में कोई सार नहीं है, ऐसी धमकी भी एक सबक है कि हम पहले की तुलना में ज्यादा सचेत हों और बचाव संबंधी अपनी योजनाओं को पुनः परखकर चुस्त-दुरुस्त कर लें। पुलिस को स्कूल प्रबंधन के साथ बैठकर देखना चाहिए कि ऐसी स्थिति बनने पर स्कूल कैसे अपना या अपने बच्चों का बचाव करेगा। जिन स्कूलों के पास बचाव की योजना नहीं है, उनकी मदद पुलिस कर सकती है।

ऐसी ही तैयारी हर सोसायटी, हर ऊंची इमारत, कार्यालय, बाजार, मॉल में भी होनी चाहिए। हवाई अड्डों और बस अड्डों की सुरक्षा भी समीक्षा के दायरे में आनी चाहिए। बचाव की स्थिति में पानी, बिजली की व्यवस्था, आपात चिकित्सा सुविधा को मुकम्मल करना चाहिए। आसपास कौन से अस्पताल हैं? बचाव के लिए किधर जाना है, इसकी पूरी योजना लोगों के ध्यान में रहनी चाहिए।

आज देश में चुनाव का समय है, तो इस धमकी का एक सियासी कोण भी हो सकता है, पर इसका मतलब यह नहीं कि पुलिस या सुरक्षा एजेंसियां धमकी को हल्के से लेते हुए नजरंदाज कर दें। राजनीति की कोई चिंता न करते हुए पुलिस को अपना रवैया पेशेवर रखना चाहिए और अपनी तैयारी में ढील नहीं देनी चाहिए। पुलिस को देखना चाहिए कि वह क्या सीख सकती है और क्या सुधार कर सकती है।

गौरतलब है, दुनिया में तकनीक का तेजी से विस्तार हो रहा है। देशद्रोही या दहशतगर्द भी इसका दुरुपयोग कर सकते हैं। पहले आतंकी गतिविधि सामान्य किस्म की होती थी कि कहीं बम लगा दिया और नुकसान पहुंचा दिया। फिर आरडीएक्स का इस्तेमाल होने लगा। अब तो दूर बैठकर भी विस्फोट को अंजाम दिया जा सकता है। ऐसे में, पुलिस को भी तकनीकी स्तर पर बहुत कुशल होना पड़ेगा, ताकि किसी भी प्रकार के आधुनिक विस्फोट या हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। स्कूलों को मिली धमकी को समझने में कोई चूक नहीं होनी चाहिए।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

आतंकियों के खिलाफ क्या भारत ने बदल ली रणनीति

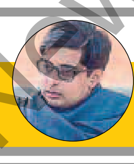
यहां स्कैन करें

प्रशांत झा | हिन्दुस्तान टाइम्स संवाददाता, अमेरिका

अमेरिकी अखबार *द वाशिंगटन पोस्ट* की एक रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि गुरपतवंत सिह पन्नू की हत्या की कथित साजिश एक भारतीय खुफिया अधिकारी ने रची थी। पन्नू वही आतंकी है, जिसे अमेरिका और कनाडा ने अपनी नागरिकता दे रखी है। यह रिपोर्ट पश्चिम के नजरिये से इस मामले के कई अन्य पहलुओं पर भी रोशनी डालती है। मसलन, उनका आकलन है कि भारत सरकार ने यह माना कि इन चरमपंथियों ने भारत की सुरक्षा के सामने सीधा खतरा पैदा किया है। अपनी राजनीतिक प्रवृत्ति या खालिस्तानी गतिविधियों में वृद्धि के कारण; या 2020-21 के किसान आंदोलन के बाद सुरक्षा के मद्देनजर बचाव के लिए उसने कदम उठाने का फैसला किया। शायद सरकार विरोधी-प्रदर्शन के बाद विदेशी सरजमीं पर रहने वाले खालिस्तानियों ने घरेलू राजनीतिक घटनाओं को आकार देने की क्षमता हासिल कर ली थी या पश्चिमी एजेंसियों की उदासीनता से निराश होकर या इस पूर्व धारणा के तहत कदम उठाया कि पश्चिमी एजेंसियां कोई कार्रवाई नहीं करेंगी। एक अनुमान है कि भारत के खुफिया विभाग के एक गुट ने अन्य कूटनीतिक विकल्पों पर गौर किए बिना अलगाववादी खतरे का जवाब देने का फैसला किया।

हालांकि, इन आरोपों में अतिरेक है। अमेरिका-भारत की बहुमूल्य रणनीतिक साझेदारी की कीमत पर एक खालिस्तानी आतंकी को मारने की साजिश को कोई उचित नहीं ठहरा सकता। सेवारत और सेवानिवृत्त खुफिया अधिकारियों ने निजी बातचीत में बताया है कि योजना व क्रियान्वयन, दोनों स्तरों पर यह ऑपरेशन उनके गले नहीं उतर रहा है।

अनेक देश दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए आक्रामक कदम उठाते रहे हैं, पर ऐसे मामलों में दुराव-छिपाव वैश्विक व्यवस्था की बुनियादी विशेषता है।

हां, यह सही है कि पश्चिम के अनेक देश ऐसा ही आक्रामक कदम अपने कथित दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए उठाते रहे हैं, पर ऐसे मामलों में दुराव-छिपाव अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की एक बुनियादी विशेषता रहा है। यदि आपके पास ताकत है, तो नियमों के पालन के मद्देनजर आपकी कथनी और करनी अलग हो सकती है। हालांकि, बहुत से लोग यह मानते हैं कि विश्व स्तर पर भारत अभी इतना मजबूत नहीं बन सका है कि वह विदेश में ऐसा कुछ कर सके। इसी आधार पर कुछ विशेषज्ञ भारत की कथित कार्रवाई का आकलन करते हैं। इस प्रकरण के तीन पहलू उल्लेखनीय हैं।

पहला, न तो वाशिंगटन और न नई दिल्ली ने इस मुद्दे के बहाने द्विपक्षीय संबंधों को बेपटरी करने की कोशिश की है। यह भारत-अमेरिकी रिश्ते की ताकत, शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व के आपसी विश्वास, खुलेपन के साथ वार्ता और दोनों सरकारों की चीन के रूप में मौजूदा वक्त की सबसे बड़ी कूटनीतिक चुनौती पर एकमत रहने की मंशा का उल्लेखनीय प्रमाण है। इस घटनाक्रम की खास बात यह नहीं है कि अमेरिका नाराज है, उसने इसे बाकी मसलों से अलग रखने का फैसला किया। यह कहने में कोई हर्ज नहीं कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन और उनकी टीम ने भारत की कूटनीतिक योजनाओं पर अभी भी पूरा भरोसा बनाए रखा है।

दूसरा, इससे यह भी आशंका होती है कि शायद अमेरिका इससे वाकिफ है कि भारत में इस ऑपरेशन के बारे में कौन-कौन जानता था। बहरहाल, चंद अमेरिकी अधिकारियों की मानें, तो यह योजना जून में उस वक्त बनाई गई थी, जब भारतीय सुरक्षा सलाहकार अपने अमेरिकी समकक्ष जेक सुलिवन के साथ द्विपक्षीय कूटनीतिक रिश्तों को मजबूत बनाने में जुटे थे। जाहिर है, अमेरिका और भारत के बीच आपसी भरोसा बना हुआ है। खास यह भी कि अमेरिका ने भारत में बनी एक जांच समिति को भी मान लिया है।

तीसरा, इस मामले में फिलहाल कानूनी जवाबदेही तय करने की अमेरिका की मांग घरेलू कार्रवाई करने संबंधी भारत की स्वेच्छा से टकरा रही है, पर बात शायद इससे आगे नहीं बढ़ेगी। मौटे तौर पर, पश्चिम के सार्वजनिक विमर्शों में भारत की प्रतिष्ठा बनी रहेगी, लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है, वह यह है कि भारत आगे के लिए कोई बदलाव करता है या नहीं? खासकर ऐसे समय में, जब नई दिल्ली पर दुनिया भर की नजर है। यह देखना प्रासंगिक होगा कि भारत खुफिया सुधारों की तरफ कितना बढ़ता है? सीमा पार के खतरों से निपटने में कितनी अधिक समझदारी का परिचय देता है?

मनसा वाचा कर्मणा

मुक्ति सोना, भक्ति पारसमणि

भक्ति की महिमा और मुक्ति के संबंध में एक साधक ने प्रश्न किया है। भक्ति एक अमूल्य रत्न के समान है, जिसके माध्यम से मुक्ति की प्राप्ति सहज और सुगम हो जाती है। जैसे पारसमणि पत्थर लोहे को सोने में बदल देता है, वैसे ही भक्ति हमारे हृदय को शुद्ध कर हमें सांसारिक बंधनों से मुक्त करती है। यहीं से परमात्मा से मिलन का मार्ग प्रशस्त होता है।

एक सच्चा भक्त अपने हृदय में अटूट विश्वास संजोए रहता है। उसे यह पूर्ण भरोसा होता है कि मुक्ति प्राप्त करना उसके लिए सहज है। वह जब भी चाहे, सांसारिक बंधनों से मुक्त हो सकता है और परम आनंद की प्राप्ति कर सकता है। इस संदर्भ में राम और नाविक की कथा को समझने की जरूरत है। जब राम और लक्ष्मण गंगा पार कर रहे थे, तो केवट ने देखा कि उसकी नाव सोने में परिवर्तित हो गई है। यह चमत्कार राम के चरण-स्पर्श से हुआ था। केवट की पत्नी अपने घर से लकड़ी का सारा सामान लेकर आई और राम के चरणों से स्पर्श कराकर उनको सोने में बदल लिया। केवट ने पत्नी को समझाया- इन चरणों को ही अपने घर ले चलो, सामान को ढोने से क्या लाभ? पत्नी ने ऐसा ही किया। श्रीराम ने उन्हें चार फल दिए- काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष! ये चारों फल जीवन के महत्वपूर्ण लक्ष्यों को दर्शाते हैं।

लक्ष्मण ने उस दंपति को भक्ति का फल प्रदान किया। उन्होंने समझाया कि राम द्वारा दिए गए चारों फल तब तक सुपाच्य नहीं होंगे, जब तक उनके पास भक्ति का फल न होगा। भक्ति ही वह चीज है, जो जीवन के चारों लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होती है और उन्हें सार्थक बनाती है। मुक्ति का अर्थ है बंधनों से मुक्ति। ये बंधन शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक हो सकते हैं। काल, देश और व्यक्तिगत सीमाएं भी बंधन का कारण बनती हैं। इन सभी बंधनों से मुक्त होकर ही मनुष्य सच्चे आनंद की प्राप्ति कर सकता है।

स्थायी मोक्ष की प्राप्ति केवल आध्यात्मिक जगत में संभव है। जब व्यक्ति आध्यात्मिक बंधनों से मुक्त होता है, तो उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं और वह परमानंद की अवस्था को प्राप्त करता है। आखिर मोक्ष साधना क्या है? यह एक ऐसा आध्यात्मिक अभ्यास है, जिसके द्वारा व्यक्ति आध्यात्मिक बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। ये बंधन मुख्यतः हमारे मन के विचारों और वासनाओं के होते हैं। कर्म और बंधन को समझे बिना न तो भक्ति हो पाती है और मुक्ति की राह निकलती है। हम जो कर्म करते हैं, उसकी प्रतिक्रिया का प्रभाव हमारी आत्मा पर पड़ता है। अच्छे कर्मों के बंधन सोने की जंजीरों जैसे होते हैं, और बुरे कर्मों के बंधन लोहे की जंजीरों की तरह। दोनों ही बंधन हमें मुक्त होने से रोकते हैं। भक्ति इन्हीं बंधनों से मुक्त करती है।

सच्चा भक्त अपने हृदय में अटूट विश्वास संजोए रहता है। उसे पूर्ण भरोसा होता है कि मुक्ति पाना उसके लिए सहज है। वह जब चाहे, सांसारिक बंधनों से मुक्त हो परमानंद को पा सकता है।

श्री श्री आनन्दमूर्ति

शेखर कपूर | फिल्म निर्देशक

बड़े व्यवसाय हमेशा बर्बर युद्धों से लाभ कमाने के इंतजार में रहते हैं। इंसानियत इनकी कितनी बड़ी कीमत चुकाती है, इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। गाजा की घेराबंदी के बावजूद कुछ लोग इसके पुनर्निर्माण के कारोबार की कल्पना में जुटे हैं।

धर्म के आधार पर आरक्षण बिल्कुल गलत

आम चुनाव के गति पकड़ने के साथ ही हर तरह के मुद्दे चुनावी फिजां में तैरने लगे हैं। कुछ मुद्दे तो नए हैं, लेकिन कुछ बहुत पुराने हैं। आरक्षण भी एक ऐसा ही पुराना मुद्दा है, जो फिर से सुर्खियों में है। एक जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कहा कि जब तक वह जिंदा हैं, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होने देंगे। उनकी यह बात सही है। आखिर धर्म के आधार पर आरक्षण क्यों मिले, जबकि देश भारतीय संविधान से चलता है? सांविधानिक प्रक्रिया के अनुसार, हर व्यक्ति, समूह, संप्रदाय और समाज को सुविधाएं देने के लिए भारत की सरकारें बाध्य हैं। इसमें धर्म शामिल नहीं है, इसलिए धर्म विशेष के आधार पर किसी को विशेष सुविधा देने के किसी भी प्रयास का पुरजोर विरोध लाजिमी है। मगर हमने देखा है कि कैसे पूर्व की सरकारें एक खास धर्म को तुष्ट करने के लिए तमाम तरह के उपाय किए जा रही थीं। विडंबना यह है कि ऐसे दल अभी जोर-शोर से यही कह रहे हैं कि वे देश का संविधान बचा रहे हैं, क्योंकि सत्तारूढ़ दल संविधान बदलने की जुगत में है, लेकिन दूसरी तरह जहां उनकी राज्य सरकार है, वहां संविधान को ताक पर रखकर धर्म विशेष के लोगों को विशेष रियायतें दी जा रही हैं।

जब सत्ताधारी दल मौजूदा परिस्थितियों के अनुसार संविधान में संशोधन करके सबको बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने के लिए प्रयासरत है, तब विरोधी दल क्यों महज विरोध के लिए इस काम का विरोध कर रहे हैं? ऐसे दल दावा कर रहे हैं कि कोई भी सत्ता भारत का संविधान नहीं बदल सकती, जो कि बिल्कुल हास्यास्पद है। यह दावा तब किया जा रहा है, जब हमारे देश ने आपातकाल जैसा वक्त भी देखा है, जिसमें संविधान को ताक पर रखकर लोकतंत्र का दमन किया गया था। यही कारण है कि यह कहा जा रहा है, विरोधी दल अपनी कथनी और करनी को एक करें। वे अनुचित विरोध न करें और आरक्षण को धर्म के आधार पर नहीं, बल्कि आर्थिक आधार पर देना सुनिश्चित करें। यही देश के व्यापक हित में है। यह समझना होगा कि धर्म को तवज्जो देकर हम अपने समाज को विकास की दौड़ में आगे नहीं ले जा सकते। हमें समग्रता की ओर बढ़ना चाहिए और उन लोगों के हाथ मजबूत करने चाहिए, जो आर्थिक रूप से विपन्न हैं। साधन-संपन्न लोगों के लिए, चाहे जिस किसी धर्म में हों, आरक्षण के दरवाजे बंद होने चाहिए। निर्धन और साधनहीन लोगों को ही विशेष रियायत मिलनी चाहिए। आरक्षण के भी उचित हकदार ऐसे ही लोग हैं।

शकुंतला महेश नेनावा, टिप्पणीकार

अनुलोम-विलोम
आरक्षण

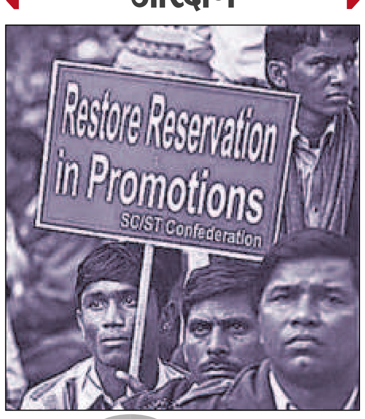

सभी नियुक्तियों में इसे बाध्य बनाया जाए

आज के चुनावी माहौल में आरक्षण का मुद्दा चर्चा के केंद्र में है, तो यह कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, दोनों में मची इस होड़ का परिणाम है कि किसी भी तरह से आरक्षण की सुविधा पाने वाले वर्गों का वोट अपने पाले में किया जाए। करीब 140 करोड़ की आबादी वाले भारत में 25 फीसदी दलित, यानी करीब 38 करोड़ और 40 फीसदी ओबीसी, यानी लगभग 60 करोड़ आबादी की कीमत पर कांग्रेस और बीजेपी चुनावी वैतरणी पार करना चाहती हैं। दोनों पार्टी के अंदर ऐसे कई बड़े नेता रहे हैं, जो आरक्षण को खुलेआम चुनौती देते रहे हैं और इसके विरोध में ही अपना बयान देते रहे हैं। हालांकि, बाद में पार्टी ने उन बयानों को व्यक्तिगत बताकर खुद को उनसे अलग कर लिया या अपना पल्ला झाड़ लिया। मगर सच तो यही है कि इस देश के दबे-कुचले समाज का मसीहा हर राजनीतिक दल बनना चाहता है, ताकि वह केंद्र की सत्ता में आ जाए या राज्य की बागडोर उसे मिल जाए, जबकि वास्तविक धरातल पर जांच पड़ताल करें, तो अधिकांश राजनीतिक दल आरक्षण के विरोधी ही नजर आते हैं। यदि वे वाकई पक्षधर होते, तो देश में ठेके पर होने वाली भर्तियों में भी आरक्षण की व्यवस्था की जाती, ताकि उपेक्षित वर्ग के नौजवानों को भी नौकरी मिल सके। यह सर्वविदित है कि आज ठेके पर चतुर्थ श्रेणी के उम्मीदवारों की ही नहीं, बल्कि डॉक्टर, इंजीनियर या अन्य बड़े अधिकारियों की भी नियुक्तियां हो रही हैं। स्पष्ट है, यह सब आरक्षण पर एक बड़ा कुठाराघात है।

इन सबको देखकर यही लगता है कि कांग्रेस और भाजपा नेताओं की आरक्षण पर बहस बेमानी है। आजादी के बाद केंद्र की सत्ता पर कांग्रेस ने करीब पांच दशकों तक, तो भाजपा ने भी डेढ़ दशक तक शासन कर लिया है, फिर भी सरकारी सेवाओं में आरक्षण का निर्धारित कोटा अधूरा रह जा रहा है। अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग की हमेशा मांग रही है कि नियुक्तियों में आरक्षण संबंधी प्रावधानों का कानूनन पालन किया जाए। आरक्षण नियमों को बाध्यकारी बनाना होगा, ताकि किसी भी कीमत पर लागू करना सरकारों के लिए अनिवार्य हो। यदि कांग्रेस और भाजपा वास्तव में आरक्षण को प्रभावी ढंग से लागू करना चाहती हैं, तो उनको तमाम सरकारी पदों पर आरक्षण के प्रावधानों के तहत तत्काल नियुक्तियां करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त उनको यदि अतिरिक्त प्रयास करना पड़े, तो जरूर करना चाहिए। यह नहीं हो सकता कि आप आरक्षण का स्वरूप ही बदल दें। आरक्षण की सुविधा उन तमाम वर्गों को मिलती रहनी चाहिए, जो इसके हकदार हैं।

वीरेंद्र कुमार जाटव, टिप्पणीकार

https://t.me/AllNewsPaperPaid

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
गुरुवार 2 मई, 2024

दैनिक जागरण

आत्मप्रेरित व्यक्ति सदैव पुरुषार्थ में संलग्न रहता है

नेताओं के अपराध

आम चुनाव के बीच कर्नाटक में जनता दल-एस सांसद एवं लोकसभा प्रत्याशी प्रज्वल रेवन्ना की ओर से तमाम महिलाओं के यौन उत्पीड़न के वीडियो सार्वजनिक होने के बाद पक्ष-विपक्ष में आरोप-प्रत्यारोप के सिलसिला छिड़ जाने पर हैरानी नहीं। चूंकि प्रज्वल रेवन्ना पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते हैं और इस बार जनता दल-एस भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहा है, इसलिए कांग्रेस और भाजपा एक-दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। ऐसा हमेशा होता है, लेकिन जो मुश्किल से होता है, वह यह कि ऐसे मामलों में आरोपित नेताओं के खिलाफ गहन जांच नहीं हो पाती और होती भी है तो धीमी गति से और कई बार तो जांच के नाम पर लीपापोती भी हो जाती है। आरोपित नेता खुद को राजनीतिक बदले की भावना से निशाना बनाने का आरोप लगाता है और विपक्षी उसे संरक्षण देने की तोहमत मढ़ते हैं। यह ठीक है कि कर्नाटक सरकार ने प्रज्वल रेवन्ना के बेहद गंभीर मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल का गठन कर दिया, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि यह मामला कई वर्ष पुराना है और उसे लेकर पहले भी आरोप-प्रत्यारोप सामने आ चुके हैं। तथ्य यह भी है कि पिछले वर्ष जून में प्रज्वल रेवन्ना स्थानीय अदालत से अपने पक्ष में यह आदेश पाने में सफल रहे थे कि उन्हें बदनाम करने के लिए कथित तौर पर उनके कुछ फर्जी वीडियो सार्वजनिक करने की जो तैयारी हो रही है, उस पर रोक लगाई जाए। क्या यह विचित्र नहीं कि तब कर्नाटक सरकार ने इस पर गौर नहीं किया कि किन वीडियो का उल्लेख हो रहा है और जिन्हें प्रज्वल रेवन्ना फर्जी बता रहे हैं, वे सही भी हो सकते हैं? क्या कर्नाटक सरकार इसलिए मौन रही कि तब देवेगौड़ा की पार्टी एवं भाजपा में गठबंधन नहीं हुआ था और कांग्रेस को उसके अपने साथ आने की उम्मीद रही हो?

प्रश्न यह भी है कि यदि भाजपा को प्रज्वल रेवन्ना के इतने गंभीर मामले की जानकारी हो गई थी तो उसने इस पर जोर क्यों नहीं दिया कि सच्चाई जाने बिना वह उनकी उम्मीदवारी का समर्थन नहीं कर सकती? इस मामले में पीड़ित वीडियो सार्वजनिक होते ही जर्मनी खिसक गए प्रज्वल रेवन्ना नहीं, महिलाएं हैं और उन्हें न्याय देना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। यह दलगत राजनीति नहीं, महिलाओं के मान-सम्मान का गंभीर मुद्दा है। अपने देश में नेताओं और अन्य रसूख वालों के अपराधों के खिलाफ प्राथमिकता के आधार सही जांच न हो पाना एक ऐसी समस्या है, जो बढ़ती ही दिखती है। एक ऐसे समय यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोपों की भी समय रहते सही तरह जांच न हो पाना शर्मनाक है, जब हर दल नारी सम्मान की रक्षा के प्रति खुद को समर्पित बताता है। यदि यह समर्पण वास्तव में होता तो क्या प्रज्वल रेवन्ना का मामला इतने दिन तक दबा रहता?

जल संरक्षण आवश्यक

झारखंड सघन वन से घिरा है। नदियां, झरने, झील, तालाब और कई बड़े-बड़े डैम भी यहां हैं। इसके बावजूद गर्मी आते ही भूगर्भ जलस्तर पाताल छूने लगता है। मौजूदा परिदृश्य की बात करें तो प्रायः नदियां सूख चुकी हैं, तालाबों और जलाशयों का जलस्तर काफी गिर चुका है। यह स्थिति राज्य के लगभग हर क्षेत्र की है। ऐसे में यह कहना कि कुछ क्षेत्रों, खासकर शहरी इलाकों में लोगों को पानी के लिए माथापच्ची और नगर निकाय प्रशासन को इसकी राशनिंग करनी पड़े तो गलत नहीं होगा। और तो और जल संकट से अब ग्रामीण क्षेत्र भी अछूते नहीं रहे। पानी के लिए कुओं और चापानलों पर आश्रित बड़ी ग्रामीण आबादी को भी भाग दौड़ करते देखा जा सकता है। तेजी से गिरते जलस्तर के विभिन्न कारणों में पहाड़ों को छलनी किया जाना, वन क्षेत्रों का अतिक्रमण, विकास के नाम पर पेड़-पौधों को काटा जाना और मानकों के अनुरूप पौधारोपण न होना भी है, जो कहीं न कहीं पर्यावरण को असंतुलित कर रहा है। इसका असर वर्षा चक्र पर तो पड़ता ही है, दूसरी ओर पठारी क्षेत्र होने के कारण वर्षा जल का बड़ा हिस्सा बह जाता है। हम भू-गर्भ जल का जितना दोहन कर रहे हैं, धरती को उतना दे नहीं पा रहे। पर्यावरण संरक्षण के लिए बड़ी-बड़ी बातें होती हैं, योजनाएं बनती हैं, अभियान चलाए जाते हैं, परंतु अधिकतर मामलों में यह कागजी साबित होता है। चेकडैम, गार्डवाल, कंटूर आदि का निर्माण, कुओं, जलाशयों आदि की बरसात पूर्व साफ-सफाई, वाटर हार्वेस्टिंग के पारंपरिक तथा आधुनिक तकनीक अपनाकर हम बहुत हद तक भावी जल संकट से बच सकते हैं। आवश्यकता है तो बस दृढ़ इच्छा शक्ति की।

लोगों को पानी के लिए माथापच्ची और नगर निकाय प्रशासन को इसकी राशनिंग करनी पड़े तो गलत नहीं होगा

हार-जीत का मनोवैज्ञानिक खेल

संदीप घोष

यदि चुनाव के बीच यह संकेत जाए कि कोई पक्ष हारने की कगार पर है तो एक वर्ग अपना पाला बदल लेता है। कांग्रेस इसी दांव के भरोसे लगती है

लोकसभा चुनाव के दो चरण संपन्न हो चुके हैं। इन्हें लेकर अलग-अलग दावे किए जा रहे हैं, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि उनमें कोई सच्चाई है। अभी तक 191 सीटों के लिए मतदान हो चुका है। इन सीटों के लिए किसी रुझान के बारे में पक्के तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इन निर्वाचन क्षेत्रों की प्रकृति एक जैसी नहीं। इन 191 में से करीब 40 प्रतिशत सीटें दक्षिण भारत की हैं। दक्षिण में मतदान का रुझान उत्तर से काफी अलग रहता है। इसलिए कोई भी सामान्यीकरण उचित नहीं। पिछले चुनाव में इनमें आधी सीटें भाजपा ने जीती थीं, लिहाजा इनके नतीजों में 10-20 प्रतिशत का विचलन अंतिम परिणाम को शायद निर्णायक रूप से प्रभावित नहीं करेगा। दो चरणों के आधार पर हार-जीत का माहौल जल्दबाजी कहा जाएगा। अभी जो हो रहा है, वह केवल मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल करने का खेल है।

एक समय इंटरनेट मीडिया पर पिछड़ी रहने वाली कांग्रेस अपने संचार प्रमुख जयराम रमेश के नेतृत्व में अब खासी मुखर है। 2004 में कांग्रेस को मिली जीत में जयराम के प्रभावी संचार को श्रेय दिया गया था। अब वह फिर से सक्रिय हैं। इसका असर भी दिख रहा है, क्योंकि पार्टी भाजपा और प्रधानमंत्री के खिलाफ पूरी तरह आक्रामक तेवर अपनाए हुए है। मोदी के प्रति टिप्पणियां कुछ हद तक अपमानजनक भी हैं। यह हैरान करता है, क्योंकि 2019 में मिली हार पर कांग्रेस की समीक्षा में यह सामने आया था कि मोदी पर निजी हमले भी पार्टी की पराजय का एक प्रमुख कारण रहे। पार्टी अपनी उसी असफल रणनीति को दोहरा रही है। इसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो यही कि कांग्रेस के आकलन में मोदी की छवि अब अपराजेय नेता की नहीं रही। दूसरे, कांग्रेस की नजर में भारत जोड़ो यात्रा के दो चरणों के साथ राहुल गांधी का कद इतना बढ़ गया कि वह उन्हें प्रधानमंत्री पद के गंभीर दावेदार के रूप में देख रही हो। कांग्रेस की प्रचार मशीनरी राहुल को 'पीएम इन वेटिंग' के रूप में पेश कर रही है। एक हालिया वीडियो में राहुल शपथ ग्रहण के लिए जाते दिखाए जा रहे तो एक अन्य में उन्हें लाल किले से राष्ट्र के नाम संबोधन की तैयारी करते हुए भी दिखाया गया है। आखिर आइएनडीआइए के घटक इसे किस रूप में लेंगे? वे यह तो पसंद नहीं करेंगे कि उनके नेतृत्व को हल्के में लिया जा रहा है। यह सब मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाकर मतदाता के मन को प्रभावित करने के लिए की जा रही कवायद है। चुनावी रणनीति में इस प्रकार का दांव तभी कारगर होता है, जब अनमने मतदाताओं का एक बड़ा वर्ग हो, जो संभावित विजेता के पक्ष में लामबंद होना पसंद करते हैं। अगर यह संकेत जाए कि कोई पक्ष हारने की कगार पर है तो यह वर्ग अपना पाला बदल लेता है। कांग्रेस इसी दांव के भरोसे लगती है। इसीलिए, उसने भाजपा के लिए नारा गढ़ा है, 'दक्षिण में साफ, उत्तर में हाफ!'

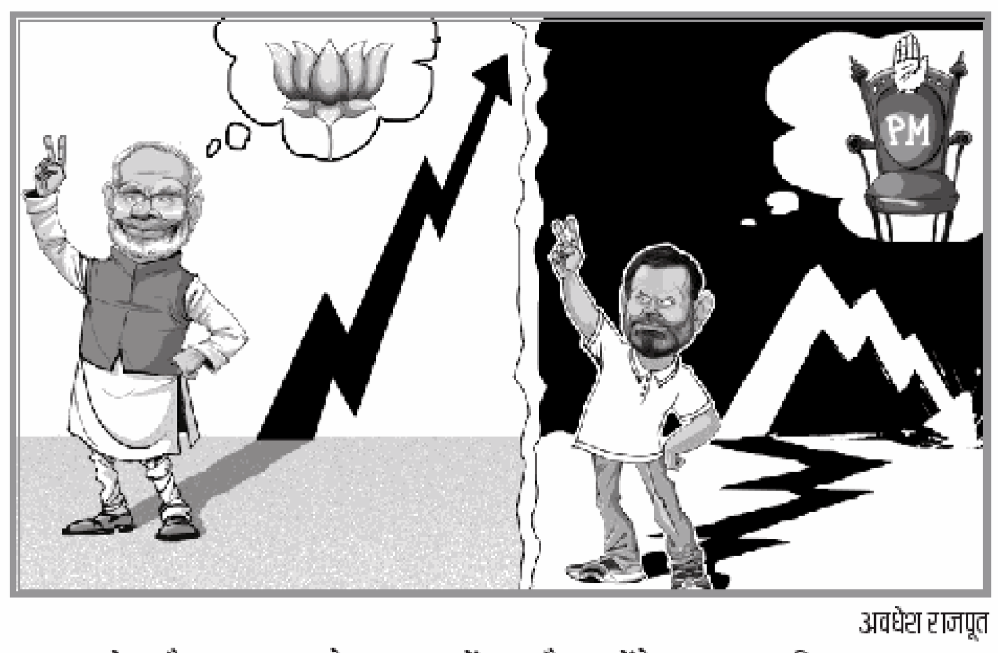

अवधेश राजपूत

मोदी मंजे हुए नेता हैं और ऐसा नहीं है कि वह इस खेल से अनभिज्ञ हों। वह खुद पर निजी हमले को ही अपना हथियार बना लेते हैं। इससे उन्हें कांग्रेस और राहुल पर सीधा हमला करने का मौका मिलता है। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर मोदी के निशाने से यह स्पष्ट भी हुआ। मोदी ने इसमें धन-संपदा के पुनर्वितरण और इस बारे में राहुल गांधी के बयान को मजहबी कोण से जोड़ दिया। यह नहीं भूलना चाहिए कि मोदी और भाजपा की ओर से यह जवाबी हमला है। कहा जा रहा है कि 'अबकी पार चार सौ पार' का मोदी का नारा अति-आत्मविश्वास पर आधारित है और उन्होंने यह समझा कि चुनाव एकदम आसान हैं। ऐसा मानने वाले नहीं जानते कि मोदी और अमित शाह तीसरे कार्यकाल की चुनौतियों से अवगत हैं। इसी कारण उन्होंने योजना बनाकर पहले ही अपनी तैयारी शुरू कर दी थी। इसके लिए उन्होंने क्षेत्रीय दलों के साथ गलबहियां शुरू कीं। मोदी और शाह को दक्षिण में भाजपा की संभावनाओं को लेकर कोई मुगालता नहीं था, जहां उसके मत प्रतिशत में वृद्धि सीटों की संख्या में रूपांतरित नहीं होती। इसलिए भाजपा को न केवल साझेदार चाहिए थे, बल्कि दूसरों को आइएनडीआइए का रुख करने से भी रोकना था।

उत्तर भारत में भी रणनीति बदली गई। मोदी-शाह को पता था कि पार्टी का पिछले चुनाव में प्रदर्शन चरम पर पहुंच गया था और ऐसे में कुछ सत्ता-विरोधी रुझान स्वाभाविक है। इसलिए अपने पारंपरिक वोट बैंक को साधे रखने की आवश्यकता थी। इस कड़ी में राम मंदिर के इर्दगिर्द बने माहौल का लाभ उठाने के लिए हिंदुत्व की राह अपरिहार्य थी। कांग्रेस जाति जनगणना, आरक्षण और संपदा के सर्वे का राग छेड़कर जाने-अनजाने भाजपा की पिच पर उतर आई। रही-सही कसर राहुल के मार्गदर्शक सैम पित्रोदा ने ऐसी कमजोर गेंद डालकर पूरी कर दी, जिसे मोदी ने स्टेडियम के बाहर भेज दिया। इसके बावजूद यही कहना उचित होगा कि कोई भी रणनीति अचूक नहीं और कोई भी मुकाबला अंतिम गेंद फेंके जाने तक अनिर्णित रहता है। अंतर्विरोधों से ग्रस्त कांग्रेस नेतृत्व वाले आइएनडीआइए के बजाय भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती उसके भीतर से है। भले ही मोदी ने कई मौजूदा सांसदों के टिकट काटे हों, लेकिन जिन्हें चुनावी रण में उतारा गया, उन सभी का रिकार्ड बेदाग नहीं। तमाम अहंकार और अनावश्यक आक्रामकता के शिकार हैं और केवल मोदी नाम के सहारे नैया पार लगाने की उम्मीद लगाए हैं। टिकट वितरण में कुछ गलतियां भी हुई हैं और खेमेबाजी की कुछ न कुछ आशंका हमेशा रहती है। इसकी कीमत भाजपा को अपने पारंपरिक गढ़ों में कुछ सीटें गंवाने के रूप में अदा करनी पड़ सकती है।

हालांकि भाजपा को कमजोर बताकर कांग्रेस जो माहौल बनाने का प्रयास कर रही है, वह भाजपा के लिए एक प्रकार का अहसान साबित हो सकता है। वह विकट गर्मी के बावजूद अपने मतदाताओं को बूथ तक लाने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए यह बहुत जरूरी होगा, जो निर्विवाद रूप से पीएम पद के लिए सबसे लोकप्रिय पसंद बने हुए हैं।

(लेखक राजनीतिक विश्लेषक एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं)

response@jagran.com

अलग-अलग विचारों वाला गठबंधन

प्रो. रसाल सिंह

आम चुनाव के लिए आइएनडीआइए के घटक दलों के घोषणा पत्र उनमें आपसी मतभेद को ही बयान कर रहे हैं

आम चुनावों में राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दल अपने वादों और घोषणा पत्रों के माध्यम से जनता को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। भाजपा ने अपने घोषणा पत्र को 'संकल्प पत्र' नाम दिया है, वहीं कांग्रेस ने इसे 'न्याय पत्र' कहा है। इसके अलावा भी कई राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दलों के घोषणा पत्र आए हैं। विपक्षी मोर्चे आइएनडीआइए के घटक दलों में कांग्रेस, द्रमुक, सपा, आप, राजद, माकपा और भाकपा के घोषणा पत्रों में कई समानताएं तो हैं, लेकिन उनमें वैचारिक या राजनीतिक स्तर पर अनेक असमानताएं भी हैं। प्रश्न है कि यदि आइएनडीआइए सत्ता में आता है तो क्या उसके घटक दल उन विषयों पर कोई कानून ला पाएंगे, जिन पर उनमें आपसी मतभेद, अंतर्विरोध और असहमति है? यदि आइएनडीआइए सत्ता में आता है, तो क्या उसकी सरकार पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को पुनर्जीवित करेगी? क्या नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) और गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) को रद करेगी? क्या निजी क्षेत्र में नौकरियों के लिए आरक्षण लाएगी? क्या राज्यपाल का पद समाप्त करेगी या उसकी नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव करेगी? क्या अनुच्छेद-356 को खत्म करेगी? क्या जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा बहाल करेगी? इन सवालों का जवाब इस पर निर्भर करेगा कि आप किस पार्टी का घोषणा पत्र पढ़ रहे हैं।

कांग्रेस ने अपने 'न्याय पत्र' में जम्मू-कश्मीर और पुडुचेरी को पूर्ण राज्य एवं आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने का वादा तो किया है, लेकिन दिल्ली को लेकर चुप्पी साध रखी है। वहीं आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को तो पूर्ण राज्य बनाने की बात की है, लेकिन अन्य राज्यों को लेकर मौन है। कांग्रेस और द्रमुक ओपीएस की बहाली पर चुप हैं, जबकि सपा, राजद, माकपा और भाकपा ने उसकी बहाली का वादा किया है। कांग्रेस, सपा और राजद जहां सीएए पर चुप हैं, वहीं द्रमुक, माकपा और भाकपा ने इसे खत्म करने का वादा किया है।

आइएनडीआइए के घटक दलों के घोषणा पत्र कई मुद्दों पर एकमत भी हैं, जिनमें राष्ट्रीय स्तर पर जातिगत जनगणना कराना, अग्निपथ योजना को खत्म करना, फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों को अपनाना शामिल है। कांग्रेस, सपा और माकपा ने एमएसपी को कानूनी गारंटी देने, शहरी रोजगार गारंटी कानून बनाने और मनरेगा के तहत मजदूरी बढ़ाने का वादा किया है।

असमान वादों वाला गठबंधन। फाइल

कांग्रेस ने जहां केंद्र सरकार में विभिन्न स्तरों पर 30 लाख पदों पर भर्तियों का वादा किया है, वहीं राजद ने एक करोड़ सरकारी नौकरियों का वादा किया है। बिना कोई आंकड़ा दिए सपा के घोषणा पत्र में खाली पदों को भरने और राष्ट्रीय रोजगार नीति बनाने की बात कही गई है, लेकिन किसी ने यह स्पष्ट नहीं किया कि वे इतनी सरकारी नौकरियां कहां से देंगे तथा इसके लिए धन कहां से लाएंगे? घोषणा पत्रों में रोजगार का मतलब केवल सरकारी नौकरियां प्रतीत होता है। यह तो सरकार पर लोगों की निर्भरता बढ़ाने के साथ-साथ देश पर आर्थिक बोझ में बढ़ोतरी का सौदा होगा। निजी क्षेत्र में आरक्षण पर भी आइएनडीआइए के दल एकमत हैं। कांग्रेस ने कहा है कि वह एससी, एसटी और ओबीसी को निजी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण देने के लिए एक कानून बनाएगी। सपा ने निजी क्षेत्र में सभी वर्गों के लिए प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का वादा किया है। द्रमुक ने कहा है कि निजी क्षेत्र में सकारात्मक नीतियों को लागू करने के लिए निर्णायक कार्रवाई की जाएगी। वामपंथी दलों ने एससी, एसटी, ओबीसी और दिव्यांगों के लिए निजी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण का वादा किया है।

वामपंथी दलों माकपा और भाकपा ने 'परमाणु, रासायनिक और जैविक आदि हथियारों का पूर्ण रूप से उन्मूलन करने की बात कही है। माकपा भारत-अमेरिका रक्षा फ्रेमवर्क समझौते, क्वाड और आइटूयूटू से बाहर निकलने की पक्षधर है। इस विषय पर अन्य घटक चुप हैं। राज्यपाल को लेकर भी आइएनडीआइए के घटक दलों ने कई वादे किए हैं, जिसमें राज्यपाल की नियुक्ति प्रक्रिया में संशोधन करने तथा उसकी शक्तियों को कम करना भी शामिल है। द्रमुक ने वादा किया है कि नई सरकार राज्य के मुख्यमंत्रियों के परामर्श से राज्यपालों की नियुक्ति के लिए कार्रवाई करेगी। राज्यपाल भी कानूनी कार्रवाई के अधीन हों। भाकपा ने कहा है कि वह सुनिश्चित करेगी कि राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा मुख्यमंत्री द्वारा सुझाए गए तीन प्रतिष्ठित व्यक्तियों के पैनल से की जाए। भाकपा, माकपा और द्रमुक अनुच्छेद-356 को हटाने के पक्ष में हैं, वहीं अन्य सहयोगी दल इस पर चुप हैं।

स्पष्ट है कि आइएनडीआइए के घटक दलों के पास न तो कोई एकसमान नजरिया है और न ही एक जैसी रणनीति। उनके घोषणा पत्रों में मौलिक सोच का अभाव दिखता है, जिसमें न तो रोजगार बढ़ाने, बेरोजगारी, महंगाई और गरीबी कम करने को लेकर कोई ठोस योजना है और न ही राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति को मजबूत करने का कोई विजन है। आखिर ऐसे विरोधाभास के बीच यदि आइएनडीआइए सत्ता में आ भी जाता है तो वह सत्ता में देर तक कैसे टिक सकेगा? इसका भी वही हश्र हो सकता है, जो जनता पार्टी के मोरारजी देसाई और राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के वीपी सिंह और राष्ट्रीय मोर्चा-वाम मोर्चा की देवेगौड़ा और गुजराल सरकार का हुआ था। इस पर हैरानी नहीं कि मतदान के दो चरण बीत जाने के बाद भी आइएनडीआइए अपनी एकजुटता का प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है। इसका कारण यही है कि विपक्षी गठबंधन में एकजुटता कायम करने के लिए अपेक्षित प्रयास नहीं हुए।

(लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोड़ीमल कालेज में प्रोफेसर हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

वास्तविक सत्संग

सत्संग में ईश्वरीय चर्चा के दौरान सत्य बोलने, सदाचार अपनाने, काम-क्रोध और मोह-लोभ जैसे विकारों से मुक्त जीवन जीने का उपदेश दिया जाता है। इन उपदेशों को सुनने वाले व्यक्ति का जीवन यदि बदलने लगे और सत्संग में जाने के बाद व्यक्ति के स्वभाव में जो क्रोध आदि विकार थे, वे खत्म होने लगे तब यह माना जा सकता है कि सत्संग में दिए उपदेशों का असर पड़ा।

यह तो बाहरी जगत के सत्संग की कहानी है। सत्संग शब्द पर गहराई से दृष्टि डाली जाए तो इसमें 'सत् और संग' दो शब्द जुड़े हैं। यानी 'सत्य का संग'। इससे स्पष्ट होता है कि सत्य के साथ जीवन जीना सबसे बड़ा सत्संग है। इस संबंध में 'सत्य और संग' शब्दों पर मनन करना जरूरी है। सत्य यह है कि पहले स्तर पर 'तन' होता है। यह तन ईश्वरीय शक्तियों का एक तरह से निवास स्थल (अतिथि-गृह) है। जिस तरह विशिष्ट जनों के ठहरने के लिए साफ-सुथरे अतिथि-गृह होते हैं। उसी तरह भगवान के रहने का तन ही अतिथि-गृह है। इसमें जब ऊर्जा के रूप में चेतना शक्ति आ जाती है तब पंचभौतिक शरीर महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी चेतना शक्ति के निकल जाने के बाद शरीर मृत हो जाता है और अंतिम संस्कार कर दिया जाता है।

इस चेतना शक्ति का प्रतिनिधि 'मन' होता है। 'मन' सर्वोच्च न्यायाधीश भी होता है। जरा-सा सत्य आचरण से हटते 'मन' की अदालत से आवाज आती है कि 'कुछ गलत हो रहा है।' इस आवाज को दबाकर बाहरी आकर्षणों के पीछे भागने का मतलब 'सत्य' से 'संग' का विच्छेद हो जाना है। अब यह भी कैसे तय किया जाए कि क्या असत्य है और क्या सत्य? तब इस आंतरिक सत्संग के अनुसार जिस काम के लिए लुकाछिपी की नौबत आए, वह असत्य और जिस काम में इसकी नौबत न आए वही सत्य है। इस तरह आंतरिक सत्संग जीवन को रूपांतरित कर देता है।

सलिल पांडेय

सुखमय जीवन का आधार सही निर्णय

डा. महेश परिमल

लोगों को निर्णय लेते रहना चाहिए। एक गलत निर्णय भी जाते-जाते एक सबक तो दे ही जाता है। जो जितना अधिक निर्णय लेता है, उसे उतना ही अधिक सफल माना जाता है। निर्णय लेते रहने से छोटी-मोटी बाधाएं ऐसे ही पार हो जाती हैं। कोई भी निर्णय कितना जल्दी लें अथवा निर्णय लेने में कितना समय लगाएं यह सबसे महत्वपूर्ण है। सोचने के लिए भी समय अपेक्षित होता है। हड़बड़ी अथवा उत्तेजना की अवस्था में हम कभी सही निर्णय नहीं ले सकते। किसी के दबाव में लिया गया फैसला गलत हो सकता है। हमें शांत-स्थिर एवं दबावमुक्त होकर और समस्या के हर पक्ष पर अच्छी तरह से विचार करके ही किसी निर्णय पर पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। कई ऐसे लोग भी मिल जाएंगे, जो किसी भी विषय में कोई भी निर्णय नहीं ले पाते और समय के हिसाब से जो भी घटित होता है, उसे चुपचाप स्वीकार कर लेते हैं। कुछ लोग यही तय नहीं कर पाते कि कोई फैसला लें या न लें। इसी उलझन में उनका कीमती समय अनिर्णय की स्थिति में ही गुजरता चला जाता है। यह स्थिति ठीक नहीं है। निर्णय लेने में समस्या की प्रकृति के अनुसार कम या ज्यादा समय लग सकता है, लेकिन किसी निर्णय को लगातार टालते रहना ठीक नहीं।

जीवन में सही निर्णय लेने का बड़ा महत्व है, लेकिन उससे भी अधिक महत्व है सही समय पर निर्णय लेने का

कई निर्णय लेने के बाद यह साफ हो जाता है कि किस तरह के निर्णय कभी नहीं लिए जाएं। सही निर्णय जीवन को संवारने का काम करते हैं और गलत निर्णय से सबक लेते हुए आगे बढ़ना मनुष्य की प्रवृत्ति है। जीवन में सही निर्णय लेने का बड़ा महत्व है, लेकिन उससे भी अधिक महत्व है सही समय पर निर्णय लेने का। यदि हम उचित समय पर निर्णय नहीं ले पाते हैं तो समय बीत जाने पर बाद में लिया गया निर्णय कितना भी सही क्यों न हो, उसका कोई लाभ हमें नहीं मिल पाता है।

हमें समस्या का सही विश्लेषण करके मस्तिष्क और अंतर्मन, दोनों का ही सही उपयोग करके कोई निर्णय लेना चाहिए। हमारा अंतर्मन हमारे जीवन के अनुभवों का संग्रह होता है। बुद्धि हमें व्यावहारिकता प्रदान करती है। जो निर्णय समग्रता अर्थात जीवन के अनुभवों और विचारों के उचित तालमेल से लिया जाता है वही अधिक उचित होता है। ऐसा हर निर्णय चाहे ठीक हो अथवा गलत हमारे लिए उपयोगी अवश्य होता है। कई बार हमें किसी ऐसी स्थिति पर भी निर्णय लेना पड़ सकता है, जिससे किसी का अहित होने की संभावना हो। ऐसे निर्णयों को टालते रहना ही श्रेयस्कर होता है। यदि हमें किसी सकारात्मक स्थिति पर निर्णय लेना हो तो उसे यथासंभव शीघ्र लेकर उसके क्रियान्वयन में देर नहीं करनी चाहिए। क्या पता जीवन में फिर कभी ऐसा कोई अच्छा कार्य करने का अवसर मिले या न मिले।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

मेलबाक्स

फर्जी खबरों पर लगे लगाम

'फर्जी वीडियो' शीर्षक से प्रकाशित संपादकीय में पढ़ा कि फर्जी खबरों का चलन जोर पकड़ता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि चुनावों के कारण ऐसा हो रहा है, बल्कि फर्जी खबरों का ये बाजार काफी गहरी और सोची-समझी साजिश की ओर भी इशारा करता है। फर्जी वीडियो, फोटो आदि का प्रचार-प्रसार करके कुछ राजनीतिक पार्टियां जनता को बरगलाने का भरसक प्रयास कर रही हैं। उन्हें पता है कि उनका वोट बैंक तथ्यों पर विचार-विमर्श कर पाने में सक्षम नहीं है, मीडिया द्वारा जो भी दिखाया जाएगा वह उसे ही सच मानकर अपनी मानसिकता बना लेगा। साथ ही ऐसे मामलों पर लगाम लगाने के लिए न ही कोई अच्छी तकनीक विकसित की गई है और न ही कठोर सजा का प्रविधान है। ये सब बातें फर्जी खबरों को प्रसारित करने वाले लोगों को बेलगाम करती जा रही हैं। अक्सर ऐसा होता है कि कोई भी कार्रवाई होने पर जिस भी पार्टी को ऐसी भ्रामक सामग्री से लाभ होता है वह इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जोड़कर देखने लगती है, पर सच तो यह है कि भारत के संविधान में सिर्फ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद-19 का ही नहीं, बल्कि उस पर उचित प्रतिबंध अनु-19 (2) का उल्लेख भी किया गया है जिसे हर किसी को समझना आवश्यक है। फेक न्यूज से बचाने के लिए सरकार को ऐसे साफ्टवेयर विकसित करने पर जोर देना चाहिए, जो गलत तरीके से संपादित की गई फर्जी सामग्री की जल्द से जल्द पहचान कर सके। साथ ही जनता को समझना होगा कि इंटरनेट मीडिया पर फेक न्यूज का जंजाल बिछाया जा रहा है, इसलिए वह उन्हीं स्रोतों से सूचनाएं प्राप्त करे, जो विश्वसनीय हों। एक मजबूत लोकतंत्र और प्रभावशाली राजनीति के लिए तकनीकी का दुरुपयोग रोकने के लिए उचित कदम उठाना ही होगा।

सोनल वर्मा, प्रयागराज

लोकतंत्र को न करें लांछित

भारत लोकतंत्र की लौ को जलाए हुए है, जिसे मलिन करने के लिए वैश्विक स्तर से लेकर देश के भीतर तक कसरत जारी है। नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री काल की अपनी दस वर्षों की अल्पावधि में भारत को वैश्विक स्तर पर जिस मुकाम पर पहुंचा दिया है, उससे विदेशी समीक्षकों में गहरी हलचल है। इस वर्ष केवल भारत में ही आम चुनाव नहीं हो रहे हैं, बल्कि अमेरिका सहित दुनिया के 64 देशों में भी चुनाव हैं। दुनिया की कुल आबादी का लगभग 49 प्रतिशत इस बार वोट देगा। माना जा रहा है कि इस साल देशों से आपसी रिश्तों से लेकर काफी कुछ बदल सकता है। भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका में भी चुनाव है, जो बहुत खास माना जा रहा है। असल में साल 2022 में गंभीर आर्थिक संकट झेलने के बाद वहां राष्ट्रपति पद के लिए यह पहला चुनाव होगा। भारत और चीन दोनों की इस पर नजरें रहेंगी, क्योंकि दोनों ही देशों ने श्रीलंका को भारी कर्ज दिया है। भारत इस देश का सबसे करीबी सहयोगी भी माना जाता है। बहुत से ताकतवर देश, अपने पड़ोसियों, दुश्मन देशों से लेकर लगभग सभी के चुनावों पर खास नजर रखते हैं। हमारे यहां कौन पीएम बन रहा है, इसका अमेरिका के लिए भी मोल है और चीन के लिए भी। जिन तरीकों से चुनाव में सेंध लगती है, उसमें सबसे ऊपर सूचना प्रवाह है। सूचनाओं से छेड़छाड़ करके किसी एक पार्टी के पक्ष और दूसरे के खिलाफ माहौल बनाया जाता है। टूलकिट जैसे टर्म इसी का हिस्सा हैं। इसके तहत किसी एक सरकार को निकम्मा या घूसखोर बताया जाता है। वोटर अगर कम जानकार है तो उसे गलत बातों से तुरंत प्रभावित किया जा सकता है। कुल मिलाकर भ्रम पैदा करके अपने पक्ष में माहौल बनाया जाता है। बहुत से फेक अकाउंट बन जाते हैं, जो ट्रोलिंग करते या फेक न्यूज को फैलाते रहते हैं, जो आजकल भारत में चुनाव के दौरान देखा जा रहा है। देश के गृह मंत्री अमित शाह के फेक वीडियो बनाकर मतदाताओं को बेवकूफ बनाया जा रहा है। इस डीपफेक मामले में कई प्राथमिकियां दर्ज कर कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री पर भी इस मामले में कार्रवाई की जा रही है।

युगल किशोर राही, ग्रेटर नोएडा

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: mailbox@jagran.com

https://t.me/AllNewsPaperPaid

संस्थापक- स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक- स्व.नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन- महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक- संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।
****

संपादकीय जागरण

गुरुवार, 2 मई, 2024 : वैशाख कृष्ण-9 वि. 2081

आत्मप्रेरित व्यक्ति सदैव पुरुषार्थ में संलग्न रहता है

नेताओं के अपराध

आम चुनाव के बीच कर्नाटक में जनता दल-एस सांसद एवं लोकसभा प्रत्याशी प्रज्वल रेवन्ना की ओर से तमाम महिलाओं के यौन उत्पीड़न के वीडियो सार्वजनिक होने के बाद पक्ष-विपक्ष में आरोप-प्रत्यारोप के सिलसिला छिड़ जाने पर हैरानी नहीं। चूंकि प्रज्वल रेवन्ना पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते हैं और इस बार जनता दल-एस भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहा है, इसलिए कांग्रेस और भाजपा एक-दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। ऐसा हमेशा होता है, लेकिन जो मुश्किल से होता है, वह यह कि ऐसे मामलों में आरोपित नेताओं के खिलाफ गहन जांच नहीं हो पाती और होती भी है तो धीमी गति से और कई बार तो जांच के नाम पर लीपापोती भी हो जाती है। आरोपित नेता खुद को राजनीतिक बदले की भावना से निशाना बनाने का आरोप लगाता है और विपक्षी उसे संरक्षण देने की तोहमत मढ़ते हैं। यह ठीक है कि कर्नाटक सरकार ने प्रज्वल रेवन्ना के बेहद गंभीर मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल का गठन कर दिया, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि यह मामला कई वर्ष पुराना है और उसे लेकर पहले भी आरोप-प्रत्यारोप सामने आ चुके हैं। तथ्य यह भी है कि पिछले वर्ष जून में प्रज्वल रेवन्ना स्थानीय अदालत से अपने पक्ष में यह आदेश पाने में सफल रहे थे कि उन्हें बदनाम करने के लिए कथित तौर पर उनके कुछ फर्जी वीडियो सार्वजनिक करने की जो तैयारी हो रही है, उस पर रोक लगाई जाए। क्या यह विचित्र नहीं कि तब कर्नाटक सरकार ने इस पर गौर नहीं किया कि किन वीडियो का उल्लेख हो रहा है और जिन्हें प्रज्वल रेवन्ना फर्जी बता रहे हैं, वे सही भी हो सकते हैं? क्या कर्नाटक सरकार इसलिए मौन रही कि तब देवेगौड़ा की पार्टी एवं भाजपा में गठबंधन नहीं हुआ था और कांग्रेस को उसके अपने साथ आने की उम्मीद रही हो?

प्रश्न यह भी है कि यदि भाजपा को प्रज्वल रेवन्ना के इतने गंभीर मामले की जानकारी हो गई थी तो उसने इस पर जोर क्यों नहीं दिया कि सच्चाई जाने बिना वह उनकी उम्मीदवारी का समर्थन नहीं कर सकती? इस मामले में पीड़ित वीडियो सार्वजनिक होते ही जर्मनी खिसक गए प्रज्वल रेवन्ना नहीं, महिलाएं हैं और उन्हें न्याय देना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। यह दलगत राजनीति नहीं, महिलाओं के मान-सम्मान का गंभीर मुद्दा है। अपने देश में नेताओं और अन्य रसूख वालों के अपराधों के खिलाफ प्राथमिकता के आधार सही जांच न हो पाना एक ऐसी समस्या है, जो बढ़ती ही दिखती है। एक ऐसे समय यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोपों की भी समय रहते सही तरह जांच न हो पाना शर्मनाक है, जब हर दल नारी सम्मान की रक्षा के प्रति खुद को समर्पित बताता है। यदि यह समर्पण वास्तव में होता तो क्या प्रज्वल रेवन्ना का मामला इतने दिन तक दबा रहता?

चिंता की बात

दिल्ली के 165 नामी स्कूलों को ई-मेल से बम से उड़ाने की धमकी दिए जाने की घटना अत्यंत चिंताजनक है। बुधवार सुबह स्कूल खुलते ही राजधानी के स्कूलों में अफरातफरी मच गई थी। स्कूलों के प्रबंधन के पास एक ही ई-मेल आइडी से एक जैसा लिखा मेल पहुंचा था। स्कूलों में जैसे-जैसे मेल देखा गया, वैसे-वैसे स्कूल प्रबंधन पुलिस को सूचना देने के साथ ही अभिभावकों को स्कूल आकर बच्चों को घर ले जाने के लिए कहने लगे। सूचना मिलने पर पुलिस और बम निरोधक दस्ता इन स्कूलों में पहुंचा और खाली कराकर गहन तलाशी ली। तलाशी में किसी भी स्कूल में कोई विस्फोटक नहीं मिला, तब जाकर स्कूल प्रबंधन और पुलिस ने राहत की सांस ली।

> घटना को सबक की तरह लेते हुए प्रबंधन को पुलिस की सलाह लेकर अपने स्कूलों में पुख्ता सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने चाहिए

दिल्ली के तीन नामी स्कूलों को कुछ माह पहले भी अलग-अलग दिनों में धमकी दी जा चुकी है, लेकिन बुधवार को एक साथ इतनी बड़ी संख्या में स्कूलों से धमकी से दहशत और अफरातफरी होना असामान्य था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और केंद्रीय जांच एजेंसियां भी जांच में सहयोग कर रही हैं। ऐसे में आशा की जा सकती है कि गुनहगार के चेहरे से जल्द पर्दा हटेगा और उसे उसके किए की उचित सजा दी जाएगी। वहीं, इस घटना को एक सबक की तरह लेते हुए स्कूलों के प्रबंधन को पुलिस की सलाह लेकर अपने स्कूलों में पुख्ता सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करना चाहिए। साथ ही आपात स्थिति में बिना समय गंवाए छात्रों व शिक्षकों को बाहर निकालने और स्कूल को खाली करने की उचित व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि ऐसे विषम हालात से आसानी से निपटा जा सके।

कह के रहेंगे — माधव जोशी

जागरण जनमत — कल का परिणाम

क्या टी-20 विश्व कप के लिए चयनित टीम संतुलित है?

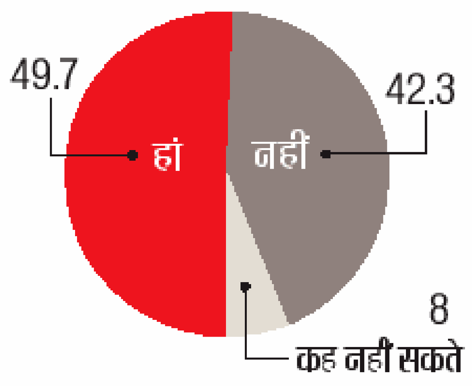

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल
क्या जेल में बंद लोगों को चुनाव लड़ने की सुविधा मिलनी चाहिए?

हार-जीत का मनोवैज्ञानिक खेल

संदीप घोष

यदि चुनाव के बीच यह संकेत जाए कि कोई पक्ष हारने की कगार पर है तो एक वर्ग अपना पाला बदल लेता है। कांग्रेस इसी दांव के भरोसे लगती है

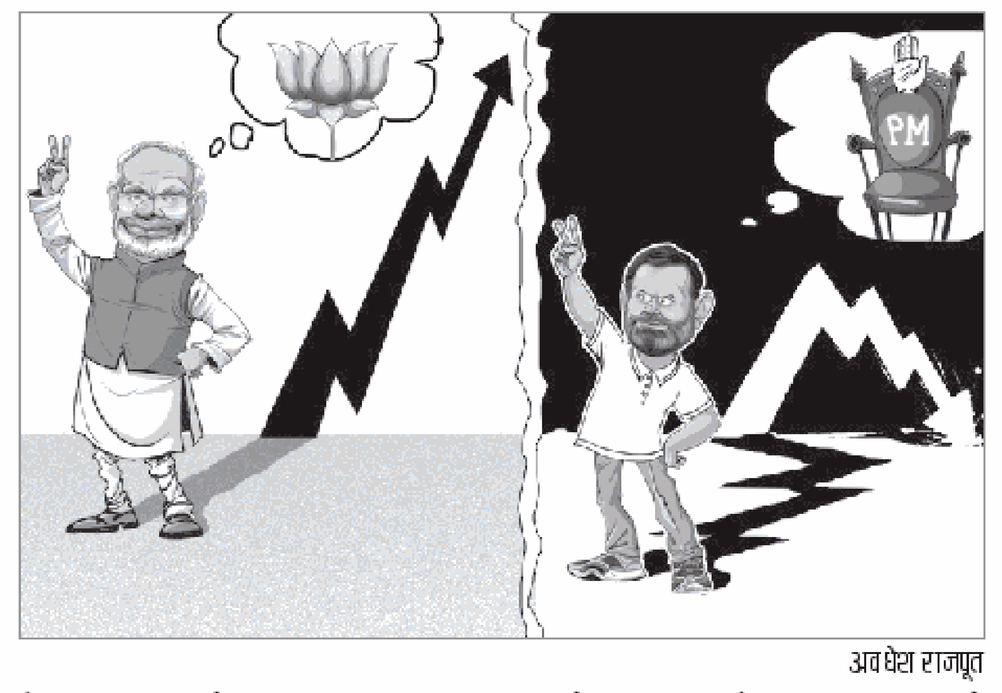

अवधेश राजपूत

लोकसभा चुनाव के दो चरण संपन्न हो चुके हैं। इन्हें लेकर अलग-अलग दावे किए जा रहे हैं, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि उनमें कोई सच्चाई है। अभी तक 191 सीटों के लिए मतदान हो चुका है। इन सीटों के लिए किसी रुझान के बारे में पक्के तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इन निर्वाचन क्षेत्रों की प्रकृति एक जैसी नहीं। इन 191 में से करीब 40 प्रतिशत सीटें दक्षिण भारत की हैं। दक्षिण में मतदान का रुझान उत्तर से काफी अलग रहता है। इसलिए कोई भी सामान्यीकरण उचित नहीं। पिछले चुनाव में इनमें आधी सीटें भाजपा ने जीती थीं, लिहाजा इनके नतीजों में 10-20 प्रतिशत का विचलन अंतिम परिणाम को शायद निर्णायक रूप से प्रभावित नहीं करेगा। दो चरणों के आधार पर हार-जीत का माहौल जल्दबाजी कहा जाएगा। अभी जो हो रहा है, वह केवल मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल करने का खेल है।

एक समय इंटरनेट मीडिया पर पिछड़ी रहने वाली कांग्रेस अपने संचार प्रमुख जयराम रमेश के नेतृत्व में अब खासी मुखर है। 2004 में कांग्रेस को मिली जीत में जयराम के प्रभावी संचार को श्रेय दिया गया था। अब वह फिर से सक्रिय हैं। इसका असर भी दिख रहा है, क्योंकि पार्टी भाजपा और प्रधानमंत्री के खिलाफ पूरी तरह आक्रामक तेवर अपनाए हुए है। मोदी के प्रति टिप्पणियां कुछ हद तक अपमानजनक भी हैं। यह हैरान करता है, क्योंकि 2019 में मिली हार पर कांग्रेस की समीक्षा में यह सामने आया था कि मोदी पर निजी हमले भी पार्टी की पराजय का एक प्रमुख कारण रहे। पार्टी अपनी उसी असफल रणनीति को दोहरा रही है। इसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो यही कि कांग्रेस के आकलन में मोदी की छवि अब अपराजेय नेता की नहीं रही। दूसरे, कांग्रेस की नजर में भारत जोड़ो यात्रा के दो चरणों के साथ राहुल गांधी का कद इतना बढ़ गया कि वह उन्हें प्रधानमंत्री पद के गंभीर दावेदार के रूप में देख रही हो। कांग्रेस की प्रचार मशीनरी राहुल को 'पीएम इन वेटिंग' के रूप में पेश कर रही है। एक हालिया वीडियो में राहुल शपथ ग्रहण के लिए जाते दिखाए जा रहे तो एक अन्य में उन्हें लाल किले से राष्ट्र के नाम संबोधन की तैयारी करते हुए भी दिखाया गया है। आखिर आइएनडीआइए के घटक इसे किस रूप में लेंगे? वे यह तो पसंद नहीं करेंगे कि उनके नेतृत्व को हल्के में लिया जा रहा है। यह सब मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाकर मतदाता के मन को प्रभावित करने के लिए की जा रही कवायद है। चुनावी रणनीति में इस प्रकार का दांव तभी कारगर होता है, जब अनमने मतदाताओं का एक बड़ा वर्ग हो, जो संभावित विजेता के पक्ष में लामबंद होना पसंद करते हैं। अगर यह संकेत जाए कि कोई पक्ष हारने की कगार पर है तो यह वर्ग अपना पाला बदल लेता है। कांग्रेस इसी दांव के भरोसे लगती है। इसीलिए, उसने भाजपा के लिए नारा गढ़ा है, 'दक्षिण में साफ, उत्तर में हाफ!'

मोदी मंजे हुए नेता हैं और ऐसा नहीं है कि वह इस खेल से अनभिज्ञ हों। वह खुद पर निजी हमले को ही अपना हथियार बना लेते हैं। इससे उन्हें कांग्रेस और राहुल पर सीधा हमला करने का मौका मिलता है। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर मोदी के निशाने से यह स्पष्ट भी हुआ। मोदी ने इसमें धन-संपदा के पुनर्वितरण और इस बारे में राहुल गांधी के बयान को मजहबी कोण से जोड़ दिया। यह नहीं भूलना चाहिए कि मोदी और भाजपा की ओर से यह जवाबी हमला है। कहा जा रहा है कि 'अबकी पार चार सौ पार' का मोदी का नारा अति-आत्मविश्वास पर आधारित है और उन्होंने यह समझा कि चुनाव एकदम आसान हैं। ऐसा मानने वाले नहीं जानते कि मोदी और अमित शाह तीसरे कार्यकाल की चुनौतियों से भलीभांति अवगत हैं और इसी कारण उन्होंने योजना बनाकर पहले ही अपनी तैयारी शुरू कर दी थी। इसके लिए उन्होंने क्षेत्रीय दलों के साथ गलबहियां शुरू कीं। मोदी और शाह को दक्षिण में भाजपा की संभावनाओं को लेकर कोई मुगालता नहीं था, जहां उसके मत प्रतिशत में वृद्धि सीटों की संख्या में रूपांतरित नहीं होती। इसलिए भाजपा को न केवल साझेदार चाहिए थे, बल्कि दूसरों को आइएनडीआइए का रुख करने से भी रोकना था।

उत्तर भारत में भी रणनीति बदली गई। मोदी-शाह को पता था कि पार्टी का पिछले चुनाव में प्रदर्शन चरम पर पहुंच गया था और ऐसे में कुछ सत्ता-विरोधी रुझान स्वाभाविक है। इसलिए अपने पारंपरिक वोट बैंक को साधे रखने की आवश्यकता थी। इस कड़ी में राम मंदिर के इर्दगिर्द बने माहौल का लाभ उठाने के लिए हिंदुत्व की राह अपरिहार्य थी। कांग्रेस जाति जनगणना, आरक्षण और संपदा के सर्वे का राग छेड़कर जाने-अनजाने भाजपा की पिच पर उतर आई। रही-सही कसर राहुल के मार्गदर्शक सैम पित्रोदा ने ऐसी कमजोर गेंद डालकर पूरी कर दी, जिसे मोदी ने स्टेडियम के बाहर भेज दिया। इसके बावजूद यही कहना उचित होगा कि कोई भी रणनीति अचूक नहीं और कोई भी मुकाबला अंतिम गेंद फेंके जाने तक अनिर्णित रहता है। अंतर्विरोधों से ग्रस्त कांग्रेस नेतृत्व वाले आइएनडीआइए के बजाय भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती उसके भीतर से है। भले ही मोदी ने कई मौजूदा सांसदों के टिकट काटे हों, लेकिन जिन्हें चुनावी रण में उतारा गया, उन सभी का रिकार्ड बेदाग नहीं। तमाम अहंकार और अनावश्यक आक्रामकता के शिकार हैं और केवल मोदी नाम के सहारे नैया पार लगाने की उम्मीद लगाए हैं। टिकट वितरण में कुछ गलतियां भी हुई हैं और खेमेबाजी की कुछ न कुछ आशंका हमेशा रहती है। इसकी कीमत भाजपा को अपने पारंपरिक गढ़ों में कुछ सीटें गंवाने के रूप में अदा करनी पड़ सकती है।

हालांकि भाजपा को कमजोर बताकर कांग्रेस जो माहौल बनाने का प्रयास कर रही है, वह भाजपा के लिए एक प्रकार का अहसान साबित हो सकता है। वह विकट गर्मी के बावजूद अपने मतदाताओं को बूथ तक लाने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए यह बहुत जरूरी होगा, जो निर्विवाद रूप से पीएम पद के लिए सबसे लोकप्रिय पसंद बने हुए हैं।

(लेखक राजनीतिक विश्लेषक एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं)
response@jagran.com

अलग-अलग विचारों वाला गठबंधन

प्रो. रसाल सिंह

आम चुनाव के लिए आइएनडीआइए के घटक दलों के घोषणा पत्र उनमें आपसी मतभेद को ही बयान कर रहे हैं

आम चुनावों में राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दल अपने वादों और घोषणा पत्रों के माध्यम से जनता को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। भाजपा ने अपने घोषणा पत्र को 'संकल्प पत्र' नाम दिया है, वहीं कांग्रेस ने इसे 'न्याय पत्र' कहा है। इसके अलावा भी कई राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दलों के घोषणा पत्र आए हैं। विपक्षी मोर्चे आइएनडीआइए के घटक दलों में कांग्रेस, द्रमुक, सपा, आप, राजद, माकपा और भाकपा के घोषणा पत्रों में कई समानताएं तो हैं, लेकिन उनमें वैचारिक या राजनीतिक स्तर पर अनेक असमानताएं भी हैं। प्रश्न है कि यदि आइएनडीआइए सत्ता में आता है तो क्या उसके घटक दल उन विषयों पर कोई कानून ला पाएंगे, जिन पर उनमें आपसी मतभेद, अंतर्विरोध और असहमति है? यदि आइएनडीआइए सत्ता में आता है, तो क्या उसकी सरकार पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को पुनर्जीवित करेगी? क्या नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) और गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) को रद करेगी? क्या निजी क्षेत्र में नौकरियों के लिए आरक्षण लाएगी? क्या राज्यपाल का पद समाप्त करेगी या उसकी नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव करेगी? क्या अनुच्छेद-356 को खत्म करेगी? क्या जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा बहाल करेगी? इन सवालों का जवाब इस पर निर्भर करेगा कि आप किस पार्टी का घोषणा पत्र पढ़ रहे हैं।

कांग्रेस ने अपने 'न्याय पत्र' में जम्मू-कश्मीर और पुडुचेरी को पूर्ण राज्य एवं आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने का वादा तो किया है, लेकिन दिल्ली को लेकर चुप्पी साध रखी है। वहीं आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को तो पूर्ण राज्य बनाने की बात की है, लेकिन अन्य राज्यों को लेकर मौन है। कांग्रेस और द्रमुक ओपीएस की बहाली पर चुप हैं, जबकि सपा, राजद, माकपा और भाकपा ने उसकी बहाली का वादा किया है। कांग्रेस, सपा और राजद जहां सीएए पर चुप हैं, वहीं द्रमुक, माकपा और भाकपा ने इसे खत्म करने का वादा किया है।

आइएनडीआइए के घटक दलों के घोषणा पत्र कई मुद्दों पर एकमत भी हैं, जिनमें राष्ट्रीय स्तर पर जातिगत जनगणना कराना, अग्निपथ योजना को खत्म करना, फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों को अपनाना शामिल है। कांग्रेस, सपा और माकपा ने एमएसपी को कानूनी गारंटी देने, शहरी रोजगार गारंटी कानून बनाने और मनरेगा के तहत मजदूरी बढ़ाने का वादा किया है।

असमान वादों वाला गठबंधन • फाइल

कांग्रेस ने जहां केंद्र सरकार में विभिन्न स्तरों पर 30 लाख पदों पर भर्तियों का वादा किया है, वहीं राजद ने एक करोड़ सरकारी नौकरियों का वादा किया है। बिना कोई आंकड़ा दिए सपा के घोषणा पत्र में खाली पदों को भरने और राष्ट्रीय रोजगार नीति बनाने की बात कही गई है, लेकिन किसी ने यह स्पष्ट नहीं किया कि वे इतनी सरकारी नौकरियां कहां से देंगे तथा इसके लिए धन कहां से लाएंगे? घोषणा पत्रों में रोजगार का मतलब केवल सरकारी नौकरियां प्रतीत होता है। यह तो सरकार पर लोगों की निर्भरता बढ़ाने के साथ-साथ देश पर आर्थिक बोझ में बढ़ोतरी का सौदा होगा। निजी क्षेत्र में आरक्षण पर भी आइएनडीआइए के दल एकमत हैं। कांग्रेस ने कहा है कि वह एससी, एसटी और ओबीसी को निजी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण देने के लिए एक कानून बनाएगी। सपा ने निजी क्षेत्र में सभी वर्गों के लिए प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का वादा किया है। द्रमुक ने कहा है कि निजी क्षेत्र में सकारात्मक नीतियों को लागू करने के लिए निर्णायक कार्रवाई की जाएगी। वामपंथी दलों ने एससी, एसटी, ओबीसी और दिव्यांगों के लिए निजी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण का वादा किया है।

वामपंथी दलों माकपा और भाकपा ने 'परमाणु, रासायनिक और जैविक आदि हथियारों का पूर्ण रूप से उन्मूलन करने की बात कही है। माकपा भारत-अमेरिका रक्षा फ्रेमवर्क समझौते, क्वाड और आइटूयूटू से बाहर निकलने की पक्षधर है। इस विषय पर अन्य घटक चुप हैं। राज्यपाल को लेकर भी आइएनडीआइए के घटक दलों ने कई वादे किए हैं, जिसमें राज्यपाल की नियुक्ति प्रक्रिया में संशोधन करने तथा उसकी शक्तियों को कम करना भी शामिल है। द्रमुक ने वादा किया है कि नई सरकार राज्य के मुख्यमंत्रियों के परामर्श से राज्यपालों की नियुक्ति के लिए कार्रवाई करेगी। संविधान की धारा 361 को हटाएगी, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि राज्यपाल भी कानूनी कार्रवाई के अधीन हो। भाकपा ने कहा है कि वह सुनिश्चित करेगी कि राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा मुख्यमंत्री द्वारा सुझाए गए तीन प्रतिष्ठित व्यक्तियों के पैनल से की जाए। भाकपा, माकपा और द्रमुक अनुच्छेद-356 को हटाने के पक्ष में हैं, वहीं अन्य सहयोगी दल इस पर चुप हैं।

स्पष्ट है कि आइएनडीआइए के घटक दलों के पास न तो कोई एकसमान नजरिया है और न ही एक जैसी रणनीति। उनके घोषणा पत्रों में मौलिक सोच का अभाव दिखता है, जिसमें न तो रोजगार बढ़ाने, बेरोजगारी, महंगाई और गरीबी कम करने को लेकर कोई ठोस योजना है और न ही राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति को मजबूत करने का कोई विजन है। आखिर ऐसे विरोधाभास के बीच यदि आइएनडीआइए सत्ता में आ भी जाता है तो वह सत्ता में देर तक कैसे टिक सकेगा? इसका भी वही हश्र हो सकता है, जो जनता पार्टी के मोरारजी देसाई और राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के वीपी सिंह और राष्ट्रीय मोर्चा-वाम मोर्चा की देवेगौड़ा और गुजराल सरकार का हुआ था। इस पर हैरानी नहीं कि मतदान के दो चरण बीत जाने के बाद भी आइएनडीआइए अपनी एकजुटता का प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है। इसका कारण यही है कि विपक्षी गठबंधन में एकजुटता कायम करने के लिए अपेक्षित प्रयास नहीं हुए।

(लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोड़ीमल कालेज में प्रोफेसर हैं)
response@jagran.com

ऊर्जा

वास्तविक सत्संग

सत्संग में ईश्वरीय चर्चा के दौरान सत्य बोलने, सदाचार अपनाने, काम-क्रोध और मोह-लोभ जैसे विकारों से मुक्त जीवन जीने का उपदेश दिया जाता है। इन उपदेशों को सुनने वाले व्यक्ति का जीवन यदि बदलने लगे और सत्संग में जाने के बाद व्यक्ति के स्वभाव में जो क्रोध आदि विकार थे, वे खत्म होने लगे तब यह माना जा सकता है कि सत्संग में दिए उपदेशों का असर पड़ा।

यह तो बाहरी जगत के सत्संग की कहानी है। सत्संग शब्द पर गहराई से दृष्टि डाली जाए तो इसमें 'सत् और संग' दो शब्द जुड़े हैं। यानी 'सत्य का संग'। इससे स्पष्ट होता है कि सत्य के साथ जीवन जीना सबसे बड़ा सत्संग है। इस संबंध में 'सत्य और संग' शब्दों पर मनन करना जरूरी है। सत्य यह है कि पहले स्तर पर 'तन' होता है। यह तन ईश्वरीय शक्तियों का एक तरह से निवास स्थल (अतिथि-गृह) है। जिस तरह विशिष्ट जनों के ठहरने के लिए साफ-सुथरे अतिथि-गृह होते हैं। उसी तरह भगवान के रहने का तन ही अतिथि-गृह है। इसमें जब ऊर्जा के रूप में चेतना शक्ति आ जाती है तब पंचभौतिक शरीर महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी चेतना शक्ति के निकल जाने के बाद शरीर मृत हो जाता है और अंतिम संस्कार कर दिया जाता है।

इस चेतना शक्ति का प्रतिनिधि 'मन' होता है। 'मन' सर्वोच्च न्यायाधीश भी होता है। जरा-सा सत्य आचरण से हटते 'मन' की अदालत से आवाज आती है कि 'कुछ गलत हो रहा है।' इस आवाज को दबाकर बाहरी आकर्षणों के पीछे भागने का मतलब 'सत्य' से 'संग' का विच्छेद हो जाना है। अब यह भी कैसे तय किया जाए कि क्या असत्य है और क्या सत्य? तब इस आंतरिक सत्संग के संविधान के अनुसार जिस काम के लिए लुकाछिपी की नौबत आए, वह असत्य और जिस काम में इसकी नौबत न आए वही सत्य है। इस तरह आंतरिक सत्संग जीवन को रूपांतरित कर देता है।

सलिल पांडेय

पाठकनामा

pathaknama@nda .jagran.com

फर्जी खबरों पर लगे लगाम

'फर्जी वीडियो' शीर्षक से प्रकाशित संपादकीय में पढ़ा कि फर्जी खबरों का चलन जोर पकड़ता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि चुनावों के कारण ऐसा हो रहा है, बल्कि फर्जी खबरों का ये बाजार काफी गहरी ओर सोची-समझी साजिश की ओर भी इशारा करता है। फर्जी वीडियो, फोटो आदि का प्रचार-प्रसार करके कुछ राजनीतिक पार्टियां जनता को बरगलाने का भरसक प्रयास कर रही हैं। उन्हें पता है कि उनका वोट बैंक तथ्यों पर विचार-विमर्श कर पाने में सक्षम नहीं है, मीडिया द्वारा जो भी दिखाया जाएगा वह उसे ही सच मानकर अपनी मानसिकता बना लेगा। साथ ही ऐसे मामलों पर लगाम लगाने के लिए न ही कोई अच्छी तकनीक विकसित की गई है और न ही कठोर सजा का प्रविधान है। ये सब बातें फर्जी खबरों को प्रसारित करने वाले लोगों को बेलगाम करती जा रही हैं। अक्सर ऐसा होता है कि कोई भी कार्रवाई होने पर जिस भी पार्टी को ऐसी भ्रामक सामग्री से लाभ होता है वह इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जोड़कर देखने लगती है, पर सच तो यह है कि भारत के संविधान में सिर्फ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद-19 का ही नहीं, बल्कि उस पर उचित प्रतिबंध अनु-19 (2) का उल्लेख भी किया गया है जिसे हर किसी को समझना आवश्यक है। फेक न्यूज से बचाने के लिए सरकार को ऐसे साफ्टवेयर विकसित करने पर जोर देना चाहिए, जो गलत तरीके से संपादित की गई फर्जी सामग्री की जल्द से जल्द पहचान कर सके। साथ ही जनता को समझना होगा कि इंटरनेट मीडिया पर फेक न्यूज का जंजाल बिछाया जा रहा है, इसलिए वह उन्हीं स्रोतों से सूचनाएं प्राप्त करे, जो विश्वसनीय हों। एक मजबूत लोकतंत्र और प्रभावशाली राजनीति के लिए तकनीकी का दुरुपयोग रोकने के लिए उचित कदम उठाना ही होगा।

सोनल वर्मा, प्रयागराज

लोकतंत्र को लांछित कर रहे विपक्षी दल

भारतीय लोकतंत्र को लांछित करने का अभियान शीर्षक आलेख में श्रीराम चौलिया ने उचित लिखा है कि भारत लोकतंत्र की लौ को जलाए हुए हैं, जिसे मलिन करने के लिए वैश्विक स्तर से लेकर देश के भीतर तक कसरत जारी है। भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री काल की अपनी दस वर्षों की अल्पावधि में भारत को वैश्विक स्तर पर जिस मुकाम पर पहुंचा दिया है, उससे विदेशी समीक्षकों में गहरी हलचल है। इस वर्ष 2024 में केवल भारत में ही आम चुनाव नहीं हो रहें है। बल्कि अमेरिका सहित दुनिया के 64 देशों के साथ-साथ यूरोपियन यूनियन में भी चुनाव हैं। दुनिया की कुल आबादी का लगभग 49 प्रतिशत इस बार वोट देगा। जिन तरीकों से चुनाव में सेंध लगती है, उसमें सबसे ऊपर इंफार्मेशन मैनिपुलेशन है। इसके तहत सूचनाओं से छेड़छाड़ करके किसी एक पार्टी के पक्ष, और दूसरे के खिलाफ माहौल बनाया जाता है। टूलकिट जैसे टर्म इसी का हिस्सा हैं। इसके तहत किसी एक सरकार को निकम्मा या घूसखोर बताया जाता है। देश के गृह मंत्री अमित शाह के फेंक विडियो बनाकर मतदाताओं को बेवकूफ बनाया जा रहा है। इस मामले में कई प्राथमिकियां दर्ज कर कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री पर भी इस मामले में कार्रवाई की जा रही है।

युगल किशोर राही, ग्रेटर नोएडा

राजनीति और धर्म के उद्देश्य अलग

देश की सर्वोच्च अदालत लोगों को आगाह करते हुए कहा कि सभी जनप्रतिनिधियों, राजनीतिज्ञों और धर्माचार्यों को चाहिए कि दुष्प्रभाव, अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करें। राजनीति और धर्म दोनों के उद्देश्यों को अलग रखने की चेष्टा करें वरना देश की लोकतांत्रिक प्रणाली और समाज का शांतिपूर्ण ढांचा चरमरा जाएगा। निःसंदेह सभी देशवासियों को अपने धर्म प्रचार की अनुमति है परंतु देश की न्याय व्यवस्था को किसी प्रकार की क्षति पहुंचाने या दुष्प्रभाव से घृणात्मक, जहरीले भाषणों तथा आपत्तिजनक शब्दों के प्रयोग की इजाजत हरगिज नहीं है। हम देशवासियों का समाज के प्रति दायित्व है कि नफरत फैलाने से परहेज करें। यह मत भूलिए कि धर्म और राजनीति दो अलग-थलग रास्ते हैं। धर्म पथप्रदर्शक एवं जीवन की सार्थकता का प्रतीक है। धर्म प्रचार से न केवल जीवन सार्थक होता है बल्कि एक अच्छे इंसान बनने का सुनहरी मौका भी मिलता है। महानुभवी लोग जानते हैं कि नफरत की जड़ राजनेताओं द्वारा अपशब्दों का प्रयोग और नफरत के भाषण ही हैं। पिछले दिनो माननीय सर्वोच्च न्यायाधीशों की शीर्ष पीठ में से चार ने बोलने की आजादी पर अंकुश नहीं लगाने का निर्णय लिया और एक न्यायाधीश का अंकुश प्रस्ताव अस्वीकार्य हुआ। ऐसा क्यों हो रहा है। यह कहना कठिन है। संभव है न्यायाधीशों में आपसी मतभेद हो या कोई फिर बाह्य दबाव। हालात कहते हैं धर्म और राजनीति का मिश्रण देश के लिए खतरनाक साबित होगा।

कृष्ण खन्ना, दिल्ली

पोस्ट

राजनीति में दुश्मनी कुछ नहीं होती और सब कुछ परिस्थितियां ही होती हैं। राज बब्बर और आनंद शर्मा कांग्रेस के उस जी-23 समूह के सदस्य रहे, जिन्होंने आलाकमान के विरुद्ध आवाज उठाई थी। अब कांग्रेस ने इन दोनों नेताओं को लोकसभा का उम्मीदवार बनाया है।

आदेश रावल@AadeshRawal

जब आपने हार्दिक पांड्या को उपकप्तान बना दिया तो फिर अंतिम एकादश में शिवम दुबे की जगह बननी ही मुश्किल हो जाएगी। फिर एक जैसे खिलाड़ियों को चुनने का क्या तुक?

जोय भट्टाचार्य@joybhattacharj

किसी भी लिहाज से हार्दिक पांड्या की जगह रिंकू सिंह को चुना जाना चाहिए था। हार्दिक को न केवल चुना गया, बल्कि उपकप्तान भी बना दिया गया। जबकि कायदे से बुमराह को यह जिम्मेदारी दी जानी चाहिए थी।

गुरमीत चड्ढा@connectgurmeet

आप पिज्जा खाने की बात करते हैं और आपको पिज्जा के आफर वाला मैसेज आ जाता है। कुछ खरीदने की सोचते हैं और मोबाइल दिन भर वही दिखाता है। क्या आपका फोन आपको बेच रहा है?

प्रमिला दीक्षित@pramiladixit

जनपथ

फंडा देखो अब नया आया 'वोट जिहाद',
पढ़े-लिखे खुर्शीद का बोलो जिंदाबाद।
बोलो जिंदाबाद अगर अब होय रिएक्शन,
रोएगा तब बैठ देश का सेक्युलर सेक्शन!
स्वयं उठाकर लोग देश में कम्युनल झंडा,
रहे हमें समझाय आज तक सेक्युलर फंडा!!
– ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व. नरेन्द्र मोहन, चेयरमैन एवं एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा जागरण प्रकाशन लि. के लिए डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित एवं 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित, संपादक (दिल्ली एनसीआर)-विष्णु प्रकाश त्रिपाठी, स्थानीय संपादक-प्रदीप कुमार शुक्ल* दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No 50755/90 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त। वर्ष 34 अंक 288

****

प्रवाह

महोत्सव विश्वास का 75
निर्भीक पत्रकारिता का आठवां दशक
स्थापना वर्ष : 1948

आप जो कर रहे हैं, यदि वह सही है, तो उसके बारे में कभी भी भयभीत नहीं होना चाहिए। -रोजा पार्क्स

एस्ट्राजेनेका ने भले यह स्वीकारा हो कि उसकी वैक्सीन से दुर्लभ मामलों में कुछ दुष्प्रभाव हो सकते हैं, पर ध्यान रहे कि महामारी के मुश्किल दौर में व्यापक परीक्षणों के बाद उसे मंजूरी दी गई थी, जिसमें जोखिम का अनुपात भी दस लाख पर एक का है। ऐसे में, पूरे मामले को तर्कशीलता के साथ देखने की जरूरत है।

घबराने की बात नहीं

एस्ट्राजेनेका कंपनी, जिसके वैक्सीन को भारत में कोविशील्ड के रूप में उत्पादित किया गया, की ब्रिटेन की अदालत में इस स्वीकारोक्ति के बाद कि उनकी वैक्सीन से दुर्लभ मामलों में रक्त के थक्के जमने जैसे दुष्प्रभाव हो सकते हैं, दुनिया भर में एक बार फिर आशंकाएं और सवाल उठने लगे हैं, हालांकि इनमें से ज्यादातर निर्मूल ही हैं। मामला यह है कि 2021 में कोविशील्ड की डोज लेने के बाद इंग्लैंड के जेमी स्कॉट के दिमाग में खून का थक्का जमा और उनका दिमाग स्थायी तौर पर क्षतिग्रस्त हो गया। तब एस्ट्राजेनेका ने वैक्सीन के इस्तेमाल से ऐसे किसी नुकसान को सख्ती से नकार दिया था। विवाद यह है कि जब 2021 के अंत तक चिकित्सा जगत ने भी बेहद दुर्लभ मामलों (दस लाख मामलों में एक) में ही सही, लेकिन वैक्सीन के दुष्प्रभाव को स्वीकार लिया था, तब एस्ट्राजेनेका को इसे स्वीकारने में तीन साल क्यों लगे। यह चौंकाने वाली बात है कि पश्चिमी देशों, खासकर इंग्लैंड में वैक्सीन के दुष्प्रभावों को झेलने वाले हर पांच में से एक व्यक्ति की मौत हुई है और इसलिए इस वैक्सीन का इस्तेमाल वहां नहीं हो रहा है। फिर भी दुनिया भर के विशेषज्ञों व नीति नियंताओं ने माना है कि इसके दुष्प्रभावों की तुलना में फायदे कहीं ज्यादा हैं। नहीं भूलना चाहिए कि इसने पहले ही साल में साठ लाख से ज्यादा लोगों की जानें तो बचाई ही, ऐसे दौर में जब प्रति दस लाख आबादी में करीब 15 हजार लोगों की जान खतरे में बताई जा रही थी, तब यही वैक्सीन थी, जिसने महामारी के जोखिम को 90 फीसदी तक घटा दिया था। भारत की स्थिति इंग्लैंड से अलग है। भारत में वैक्सीन की 200 करोड़ से ज्यादा खुराकें दी गईं, जिनमें से करीब 175 करोड़ कोविशील्ड की थीं। इसके बावजूद अब तक खून के थक्के जमने के मामले आधा फीसदी से भी कम मिले हैं। दरअसल, कोविड के वक्त भी वैक्सीन को लेकर कई अफवाहें सुनने में आई थीं, जिनकी जड़ में गलत जानकारियां थीं। यह समझना चाहिए कि कोरोना हो या फिर कोई

दूसरी बीमारी, पिछली दो सदियों में टीकाकरण ने मानवता की जो सेवा की है, उसे देखते हुए इनके महत्व को नकारा नहीं जा सकता। जहां तक सवाल दुष्प्रभावों का है, तो कोई भी टीका या दवा पूरी तरह से जोखिम मुक्त नहीं होता। मगर यह ध्यान रखना चाहिए कि महामारी के मुश्किल दौर में व्यापक परीक्षणों के बाद वैक्सीन को मंजूरी दी गई थी, जिसमें जोखिम का अनुपात भी दस लाख पर एक का है। ऐसे में, पूरे मामले को बगैर किसी पूर्वाग्रह के तर्कशीलता के साथ देखने की जरूरत है।

औरत क्या चाहती है

स्त्री क्या चाहती है, इस बारे में न पुरुष जानने की कोशिश करता है, न ही समाज को इसकी परवाह है। स्त्री किस तरह अपना जीवनयापन करना चाहती है? मुझे लगता है कि ज्यादातर स्त्रियों में अभी तक यह सोच विकसित नहीं हो पाई है कि अपनी तरह से जीवन जीने का क्या अर्थ है।

वर्ष 1991 में मैंने *निमंत्रण* नाम से एक उपन्यासिका लिखी थी, जिसमें स्त्री शोषण और पुरुषतंत्र की भयावहता के बारे में बताया गया था। *निमंत्रण* लिखने के कारण मुझे अनेक लोगों की निंदा-आलोचना सुननी पड़ी थी। कुछ लोगों के मुताबिक, वह पोर्नोग्राफी थी, जिसमें यौन संबंधों का खुला चित्रण था। बस, फिर क्या था, चारों ओर मेरी बदनामी कर दी गई। मेरी बदनामी फैलने लगी। कहा गया कि मैं पोर्नोग्राफी लिखती हूं। मेरी उस उपन्यासिका में आखिर था क्या?

कहानी यह थी कि अट्ठारह साल की किशोरी एक सुदर्शन युवक के प्रेम में पड़ जाती है। जबकि वह युवक उस तरुणी के दायरे से बहुत दूर है। तरुणी उस युवक को रोज चिट्ठी लिखती है, जिसमें वह अपना प्रेम निवेदन करती है। लेकिन युवक के पास वे चिट्ठियां पहुंचती ही नहीं। आखिरकार जब युवक को किशोरी के उससे एकतरफा प्रेम का पता चलता है, तब दो दिन प्रेम का अभिनय कर एक दोपहर को वह उसे अपने घर लंच के लिए आमंत्रित करता है। किशोरी सज-धजकर अपने प्रेमी के लिए कीमती उपहार खरीदकर उसके यहां पहुंचती है। वहां युवक और उसके सात दोस्त थे। वे सब उससे बलात्कार करते हैं।

तसलीमा नसरीन
चर्चित लेखिका

सामूहिक बलात्कार के बाद अंदर और बाहर से गंभीर रूप से घायल वह किशोरी घर लौटते हुए मन ही मन सोचती है कि पिता जब उससे पूछेंगे कि कहां गई थी, तब वह झूठ नहीं बोलेगी। उन्हें बता देगी कि वह किसी के निमंत्रण पर उसके घर गई थी। उपन्यासिका यहीं खत्म हो जाती है। उसमें बलात्कार के जो ब्योरे दिए गए थे, स्त्री-विरोधियों ने उसे पोर्नोग्राफी कहा था। समाज में जब स्त्री विरोधियों की संख्या बढ़ जाती है, तब औरतों के शोषण को स्वाभाविक समझ लिया जाता है। ऐसे तत्वों के लिए बलात्कार भी स्वाभाविक घटना है।

निमंत्रण की कहानी काल्पनिक नहीं थी। हालांकि समाज का एक वर्ग मानता है कि इस तरह की घटनाएं नहीं होतीं। दूसरा वर्ग यह तो मानता

है कि इस तरह की घटनाएं होती हैं, लेकिन उसका कहना है कि इसके लिए महिलाएं ही दोषी हैं। वे क्यों दोषी हैं, इसकी वजह भी बताई जाती है। दोष यह है कि वे प्रेम में पड़ती ही क्यों हैं? वे पुरुषों के पास जाती ही क्यों हैं? जाने पर तो उनके साथ गलत होगा ही। जो लोग बलात्कार का शिकार होने वाली महिलाओं पर ही बलात्कार की जिम्मेदारी डाल देते हैं, वे चाहते हैं कि लड़कियां घर से बाहर न निकलें, किसी के प्रेम में न पड़ें, किसी पर भरोसा न करें और किसी के निमंत्रण पर उसके यहां या उसके साथ न जाएं। वे महिलाओं को तो जिम्मेदार ठहरा देते हैं, लेकिन पुरुष की आंखों में उंगली डालकर नहीं कहते कि महिलाओं के साथ अत्याचार करने का पुरुषों को कोई अधिकार नहीं है। यह अजीब है कि घर से बाहर तक लड़कियों-महिलाओं के साथ गलत बर्ताव और यौन हिंसा को अंजाम तो पुरुष देते हैं, लेकिन इन सबके लिए जिम्मेदार महिलाओं को ठहराया जाता है। पुरुषवर्चस्ववादी समाज में पुरुषों की बर्बरता को कमतर करके दिखाने या उन्हें निर्दोष बताने की प्रवृत्ति पुरानी है।

जिन लोगों ने *निमंत्रण* की कहानी को मनगढंत बताया था, उन्हें छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की एक खबर से अवगत कराना चाहती हूं, जहां सोलह वर्षीय एक किशोरी के साथ उसके प्रेमी और उसके दो साथियों ने मिलकर बलात्कार किया। तीन युवाओं ने किशोरी को पूरी रात एक परित्यक्त घर में बंधक बनाकर रखा था। सुबह घर लौटी किशोरी ने पिता को सारी बातें बताईं, तो घरवालों ने थाने में रिपोर्ट लिखवाई। *निमंत्रण* नाम की उपन्यासिका मैंने लड़कियों-महिलाओं को सजग करने के लिए लिखी थी। मैं महिलाओं को यह बताना चाह रही थी कि उन्हें पुरुषों के जाल में नहीं फंसना चाहिए। इसमें संदेह नहीं कि शिक्षा ने आज की बहुत-सी स्त्रियों को जिस तरह आत्मनिर्भर बनाया है, उसी तरह उन्हें सजग भी किया है। लेकिन सभी स्त्रियां शिक्षित और सजग नहीं हैं, इसलिए वे पुरुषों के जाल में आसानी से फंस जाती हैं। हालांकि अनेक शिक्षित और आत्मनिर्भर स्त्रियां भी पुरुषों के धोखे और यौन अत्याचार का शिकार होती हैं। मौजूदा 21वीं सदी में भी स्त्रियों की यह दुर्दशा है, तो इसके लिए पुरुषवादी सोच जिम्मेदार है।

लेकिन मैं यहां यह भी बताना चाहती हूं कि शिक्षा ने स्त्रियों के प्रति अनेक पुरुषों की भी सोच बदली है। *निमंत्रण* उपन्यासिका में भी पुरुषों के लिए संदेश था, और मेरा मानना है कि उसे पढ़कर अनेक पुरुषों ने भी स्त्रियों के प्रति संवेदनशील व्यवहार करने के बारे में सीखा या सोचा होगा। लेकिन पुरुषों की बड़ी आबादी की सोच नहीं बदली है, इसी कारण महिलाओं के साथ होने वाली यौन हिंसा की घटनाएं कम होने का नाम ही नहीं ले रहीं। इस उपमहाद्वीप में धर्म या मजहब का महत्व सामाजिक-राजनीतिक जीवन में बहुत बढ़ा है। देखने वाली बात यह है कि इसके बावजूद स्त्रियों के साथ होने वाली यौन हिंसा की घटनाओं में कमी नहीं आई है।

पुरुष चाहता है, स्त्री उसके हिसाब से चले। समाज चाहता है कि स्त्री उसके मुताबिक चले। स्त्री क्या चाहती है, इस बारे में न पुरुष जानने की कोशिश करता है, न ही समाज को इसकी परवाह है। स्त्री क्या चाहती है? मुझे लगता है कि स्त्री की चाह अब भी स्पष्ट नहीं हो पाई है। स्त्री किस तरह अपना जीवनयापन करना चाहती है? मुझे लगता है कि ज्यादातर स्त्रियों में अभी तक यह सोच विकसित नहीं हो पाई है कि अपनी तरह से जीवन जीने का क्या अर्थ है। यह स्वाभाविक भी है। पुरुष रचित धर्म, पुरुष रचित समाज और पुरुष रचित पुरुष तंत्र जिस तरह स्त्रियों को चलाते रहे हैं, स्त्रियां उसी तरह संचालित होती रही हैं। स्त्रियों की खुशी, उसके सपने और उसके सुख वही हैं, जो पुरुष उसे बताता है। यह आकस्मिक नहीं है कि ज्यादातर स्त्रियों की खुशी उनके पुरुषों की खुशियों में है। ज्यादातर स्त्रियों के सपने उनके पुरुषों से जुड़े हैं। ठीक इसी तरह स्त्रियों का सुख उनके पुरुषों के साथ होने और उन्हें सुखी रखने में है।

कहीं भी स्त्रियों को स्वतंत्रता नहीं है। पुरुष, परिवार और समाज यह कल्पना तक नहीं कर सकते कि स्त्रियों का जीवन पुरुषों के जीवन से अलग या स्वतंत्र भी हो सकता है। जब तक इस तरह की सोच नहीं बदलेगी, तब तक इस बारे में सोचा भी नहीं जाएगा कि आखिर औरत चाहती क्या है?

edit@amarujala.com

https://t.me/AllNewsPaperPaid

जीवन धारा

संत तुकाराम

मनुष्य जीवित परमात्मा का मंदिर होता है, जिसमें हमें परमात्मा को खोजना और पाना है। देवता भी मनुष्य शरीर पाने के लिए तरसते हैं, क्योंकि प्रभु भक्ति केवल मनुष्य जीवन में ही हो सकती है।

ईश्वर को पा लेना ही असली सुख है

***मन** को हमेशा खुश रखना चाहिए। यही सब सिद्धियों का मूल है। यही बंधन और मोक्ष का भी कारण है। इसलिए मन को वश में रखकर ही असली सुख प्राप्त हो सकता है। असली सुख यानी प्रभु की भक्ति, ईश्वर को पाना। हालांकि यह बात कहने में जितनी सहज है, व्यवहार में उतनी ही कठिन भी है। पर असंभव नहीं। ईश्वर से बार-बार यही प्रार्थना करनी चाहिए कि वह मन को वश में रखने की शक्ति दे, वरना मन की निरंकुशता जीवन को कठिन और अशांत बनाती है। ऐसे में मन हानि पहुंचाता है। इसका कारण यह है कि मन के भीतर ही सांसारिक प्रपंच भरा है, भक्ति तो केवल बाहर ही दिखती है। यह मन ही है, जिसने ईश्वर की भक्ति के मार्ग में काम, क्रोध, लोभ जैसे अवरोध खड़े कर दिए हैं। ये अवरोध पर्वतों से भी बड़े हैं। ऐसे में ईश्वर इनके दूसरी तरफ रह जाते हैं। इसी का नतीजा है कि हम ईश्वर तक पहुंच नहीं पाते, क्योंकि इन अवरोधों को लांघने का कोई रास्ता हमें नजर नहीं आता। और ऐसा मन की चंचलता के कारण होता है। मन की चंचलता अज्ञानता का परिणाम होती है। ज्ञान के अभाव में मन की चंचलता बढ़ती जाती है और वह विषयों की तरफ ही भागता रहता है।*

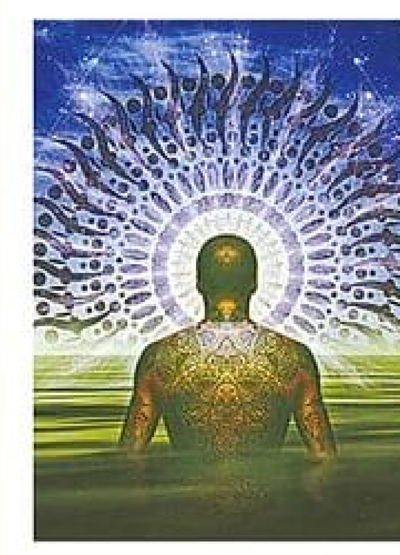

धन, काम, यश और अहंकार अध्यात्म-मार्ग में बड़ी बाधा होते हैं। पहली बात तो यह कि इस मार्ग पर चलने वाले यात्री ही थोड़े होते हैं। और फिर जो होते भी हैं, उनमें से ज्यादातर धन की लिप्सा में ही गायब हो जाते हैं। इसके बाद बचे लोग कामवासना की खाई में गिर जाते हैं और इससे भी बच कर जो निकल जाते हैं, वे यश और अहंकार का शिकार हो जाते हैं। और जो लोग इन तीनों खाइयों से बच जाते हैं, उन्हीं के लिए अध्यात्म का रास्ता खुला होता है।

कई जन्मों और पुण्य कर्मों के बाद आत्मा को मनुष्य जन्म मिलता है। इसलिए जन्म-मरण के चक्र से छुटकारा पाने के लिए मन को ईश्वर की भक्ति में लगाना चाहिए। एक बार मनुष्य जीवन का अंत हो जाए तो यह फिर नहीं मिलता। इसलिए इसे सार्थक बनाने का एक ही मार्ग है और वह है ईश्वर की भक्ति, जो मन को वश में रखने से ही मिल सकती है।

मनुष्य जीवित परमात्मा का मंदिर होता है, जिसमें हमें परमात्मा को खोजना और पाना है। देवता भी मनुष्य शरीर पाने के लिए तरसते हैं, क्योंकि प्रभु भक्ति केवल मनुष्य जीवन में ही हो सकती है। इसलिए जब मनुष्य जन्म मिल ही गया है, तो प्रभु का नाम जपो और परम सुख प्राप्त करो। परमात्मा की खोज में लोग तीर्थयात्रा करते हैं या फिर पहाड़ों पर या जंगलों में चले जाते हैं। लेकिन तीर्थयात्रा भर से मन के भीतर शांति, दया या भक्ति का भाव तो उत्पन्न नहीं होता। तीर्थों में तो केवल पानी होता है और पत्थर की नदियां। जबकि संतों में ईश्वर वास करते हैं। इसलिए प्रभु के दर्शन के लिए किसी तीर्थ पर जाने की जरूरत नहीं है, उसके दर्शन तो संतों के भीतर ही हो जाते हैं।

परमात्मा की खोज...

सूत्र

साधारणतया लोग ईश्वर को पाने की विधि से अनजान होते हैं। परमात्मा की खोज में वे तीर्थ यात्रा करते हैं या फिर पहाड़ों पर या जंगलों में चले जाते हैं। और ऐसे में लोगों को लगने लगता है कि तीर्थ कर लेने भर से उन्होंने ईश्वर को पा लिया। लेकिन तीर्थयात्रा भर से मन के भीतर शांति, दया या भक्ति का भाव तो उत्पन्न नहीं होता।

दूसरा पहलू

वैक्सीन इसलिए दी जाती है, ताकि वह रोगजनक के एंटीजन से जुड़कर उसे बेअसर कर दे।

लाखों जिंदगियां बचाने वाले टीके पर संदेह ठीक नहीं

मुझे नहीं लगता कि कोविशील्ड टीका लगवाने वाले को डरने या चिंतित होने की जरूरत है। असल में, किसी भी वैक्सीन के अंदर एंटीजन होता है, जिसकी प्रकृति प्रोटीन की हो सकती है। जैसे कोविशील्ड में सार्स कोव-2 का एंटीजन, स्पाइक प्रोटीन था। वैक्सीन जब शरीर में लगाई जाती है, तो वह बी कोशिका से एंटीबॉडीज का निर्माण करती है। यह एंटीबॉडी वायरस के एंटीजन से जुड़कर या तो उसके प्रभाव को कम करता है या उसे खत्म कर देता है। वैक्सीन इसलिए दी जाती है, ताकि वह रोगजनक के एंटीजन से जुड़कर उसे बेअसर कर दे। शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली पैथोजन के खिलाफ टी कोशिका का निर्माण करती है, जो संक्रमित कोशिका को नष्ट करती है और वायरस के हमले से हमें बचाती है। शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को रोगजनक को खत्म करने के लिए पर्याप्त एंटीबॉडी बनाने में कुछ समय लगता है। ऐसे में वैक्सीन रोगजनक का पता लगाने और उसे तुरंत बेअसर करने के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रेरित करके एंटीबॉडी के निर्माण के समय को कम करती है।

डॉ. सुनीत कुमार सिंह
डॉ. बीआर आंबेडकर सेंटर फॉर बायोमेडिकल रिसर्च, नई दिल्ली के निदेशक एवं वायरोलॉजिस्ट

जब किसी दवा या वैक्सीन का दुष्प्रभाव कम होता है और लाभ ज्यादा होते हैं, खासकर जब कोई विषाणुजनित महामारी के नियंत्रण के लिए कोई दवा न हो, तो उसका उपयोग करने में परेशानी नहीं है।

साइड इफेक्ट सिर्फ वैक्सीन के ही नहीं, दवाओं के भी होते हैं, जो हल्के से लेकर गंभीर स्तर तक के हो सकते हैं। जैसे कि, जब टीका लगाया जाता है, तो अक्सर हल्का बुखार होता है और टीका लगाए जाने वाली जगह पर सूजन या लाल चकत्ते हो जाते हैं। ये हल्के दुष्प्रभाव के लक्षण हैं, जो जल्दी खत्म हो जाते हैं।

जब किसी दवा या वैक्सीन का दुष्प्रभाव कम होता है और लाभ ज्यादा होते हैं, वह भी तब, जब कोई विषाणुजनित महामारी फैली हो और नियंत्रण के लिए कोई दवा न हो, तो उसका उपयोग करने में परेशानी नहीं है। हालांकि, कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी ने कुछ लोगों में रक्त का थक्का जमने (थ्रोम्बोसिस विथ थ्रोम्बोसिटोपेनिआ सिंड्रोम-टीटीएस) जैसी जानकारी को साझा किया है, क्योंकि यह वैक्सीन एडीनोविरास पर आधारित थी। इसलिए इसमें अभी और अध्ययन की जरूरत है। पर इस तरह का दुष्प्रभाव टीका लगने के चार से छह हफ्तों के भीतर होता है। अब, जबकि लोगों को कोविशील्ड टीका लगाए महीनों हो गए हैं, तो उसके दुष्प्रभावों को लेकर डरने की जरूरत नहीं है। फिर भी अध्ययन की आवश्यकता है। सहरुग्णता वाले व्यक्तियों में साइड इफेक्ट का प्रभाव ज्यादा हो सकता है। पर लाखों जिंदगियां बचाने वाले संपूर्ण टीकाकरण अभियान पर संदेह करना ठीक नहीं है।

आंकड़े

सेवाओं का निर्यात

भारत सिर्फ वस्तुओं का ही नहीं, बल्कि सेवाओं का भी निर्यात करता है, जिनमें सबसे ज्यादा निर्यात आईटी सेवाओं का किया जाता है।

आईटी	72%
परिवहन	11%
यात्रा	8%
वित्त. बीमा	3%
निर्माण	1%

स्रोत : DBIE, RBI

संत ने कहा, जब तू मुझे नहीं धकेल सकता, तो बता मेरा मालिक (भगवान) भला कैसे मुझे खाई में गिरने देगा! वह तो गिरे हुए लोगों को उबारता है।

ईश्वर पर विश्वास

अंतर्यात्रा
संकलित

ऋषिकेश में गंगा के किनारे एक संत रहते थे। वह जन्मांध थे, पर वह हर शाम के समय पहाड़ों पर भ्रमण करने के लिए निकल जाते थे। एक दिन एक शिष्य ने उनसे पूछा, आप हर रोज इतने ऊंचे पहाड़ों पर भ्रमण हेतु जाते हैं। वहां खाइयां भी हैं। आपको दिखाई नहीं देता। क्या आपको डर नहीं लगता? कभी पांव लड़खड़ा गए तो?

संत ने उस समय कुछ नहीं कहा और शाम को शिष्य को भी अपने साथ ले गए। संत ने शिष्य से कहा, जैसे ही कोई गहरी खाई आए, तो बताना। दोनों चलते रहे और जैसे ही गहरी खाई आई, शिष्य ने बताया कि गहरी खाई आ चुकी है। संत ने कहा, मुझे इसमें धक्का दे दे। इतना सुनते ही शिष्य सकपका गया। उसने कहा, मैं आपको धक्का कैसे दे सकता हूं? आप तो मेरे गुरुदेव हैं, मैं तो किसी शत्रु को भी नहीं धकेल सकता। संत ने फिर कहा, मैं कहता हूं कि मुझे इस खाई में धक्का दे दो। यह मेरी आज्ञा है और मेरी आज्ञा की अवहेलना करोगे, तो नर्क में जाओगे।

शिष्य ने कहा, मैं नर्क भोग लूंगा, मगर आपको खाई में नहीं धकेल सकता।

तब संत ने कहा, जब तू मुझे नहीं धकेल सकता, तो बता मेरा मालिक भला कैसे मुझे खाई में गिरने देगा! वह तो गिरे हुए लोगों को उबारता है। वह पल-पल हमारे साथ है।

(अमर उजाला आर्काइव से)

अमर उजाला
पुराने पन्नों से — 31 मई, 1991

भूमि एवं भवन कर एक साथ जमा करने की सुविधा

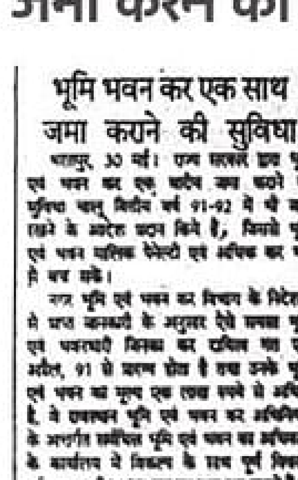

भूमि भवन कर एक साथ जमा कराने की सुविधा

उत्तर प्रदेश सरकार ने भूमि एवं भवन कर एक साथ जमा करने की सुविधा को चालू वित्तीय वर्ष में भी जारी रखने के आदेश दिए हैं, ताकि भवन मालिक दंड एवं अधिक कर भार से बच सकें।

ई-कचरे से खतरे में धरती

अगर दुनिया भर के ई-कचरे को ट्रकों में भरकर, उन्हें कतार में खड़ा किया जाए, तो ये भूमध्यरेखा के चारों ओर एक लाइन बना सकते हैं।

ऋषभ मिश्रा
पर्यावरण

वर्तमान तकनीकी और डिजिटल युग में इलेक्ट्रॉनिक कचरा (ई-वेस्ट) पूरी दुनिया में एक चुनौती के रूप में उभर कर सामने आया है। हम सबके पास मोबाइल फोन, टीवी, लैपटॉप जैसे बहुत से इलेक्ट्रॉनिक सामान हैं, जिन्हें खराब हो जाने पर हम कचरे में डाल देते हैं। पर इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की बढ़ती चाहत हमारे वातावरण का गला घोंट रही है।

ई-कचरे पर संयुक्त राष्ट्र की 'द ग्लोबल ई-वेस्ट मॉनीटर- 2024' रिपोर्ट के मुताबिक, वैश्विक स्तर पर सालाना 6.2 करोड़ टन इलेक्ट्रॉनिक कचरा पैदा हो रहा है। वर्ष 2010 के बाद से इसमें 82 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। अगर ई-कचरा ऐसे ही बढ़ता रहा, तो वर्ष 2030 तक 32 फीसदी की वृद्धि के साथ बढ़कर यह 8.2 करोड़ टन पर पहुंच सकता है। ई-कचरा प्रति वर्ष 23 लाख टन की दर से बढ़ रहा है। जिन इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों ने हमारी जिंदगी को आसान बनाया, अब वे ही हमारी जिंदगी में जहर घोल रहे हैं।

ई-कचरे की असली समस्या तब शुरू होती है, जब इसका सही तरीके से संग्रहण (कलेक्शन) और पुनर्चक्रण (रीसाइक्लिंग) नहीं होता है, जिससे मिट्टी, पानी और हवा जहरीली हो रही है। बहुत से ऐसे देश हैं, जहां ई-कचरा बड़ी मात्रा में निकलता है, लेकिन उसके संग्रहण एवं पुनर्चक्रण का उचित प्रबंधन नहीं किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक, 2022 में उत्पन्न हुए ई-कचरे का सिर्फ 22.3 प्रतिशत हिस्सा ही एकत्रित और पुनर्चक्रित हो पाया था। वर्ष 2030 तक इसके संग्रहण और पुनर्चक्रण की दर घटकर सिर्फ 20 फीसदी रह जाएगी। दुनिया का करीब एक तिहाई यानी 2,000 करोड़ किलोग्राम ई-कचरा खिलौनों, माइक्रोवेव ओवन, वैक्यूम-क्लीनर और ई-सिगरेट जैसे छोटे उपकरणों से पैदा हो रहा है। जिस तरह से जलवायु परिवर्तन पूरी दुनिया की समस्या है, ठीक उसी तरह से ई-कचरा भी पूरे विश्व की समस्या है।

दुनिया में ई-कचरे की मात्रा कितनी ज्यादा है, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि अगर इस ई-कचरे को 40 मीट्रिक टन क्षमता के ट्रकों में भरा जाए, तो इसके लिए करीब 15.5 लाख से ज्यादा ट्रकों की जरूरत पड़ेगी। इन ट्रकों को कतार में खड़ा किया जाए, तो ये भूमध्यरेखा के चारों ओर एक लाइन बना सकते हैं। वैश्विक स्तर पर ई-कचरे की रीसाइक्लिंग की दर मात्र 12 फीसदी है। बड़ी मात्रा में ई-कचरे को नदियों, समुद्रों में बहा दिया जाता है, जिससे पर्यावरण के साथ-साथ जीव-जंतुओं को भी नुकसान हो रहा है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट 'चिल्ड्रन ऐंड डिजिटली कनेक्टेड साइट' के मुताबिक, 1.29 करोड़ महिलाएं ई-कचरे से जुड़े क्षेत्र में काम करती हैं। ये महिलाएं या तो ई-कचरा जमा करती हैं या पुनर्चक्रण के काम में लगी हुई हैं। ई-कचरे के संपर्क में आने पर इन महिलाओं की सेहत पर तो असर पड़ता ही है, उनके गर्भ में पलते अजन्मे बच्चे पर भी असर पड़ता है। इसी तरह करीब 1.8 करोड़ बच्चे और किशोर, जिनमें से कई पांच वर्ष से भी कम उम्र के हैं, भी इस काम में जुटे हुए हैं। ई-कचरे में मौजूद सीसा और पारा इन बच्चों की दिमागी क्षमता को नुकसान पहुंचा सकता है। ई-कचरे के पुनर्चक्रण से न केवल पर्यावरण बचेगा, बल्कि इससे कीमती धातुओं को भी बचाया जा सकता है। जैसे, वर्ष 2022 में जो ई-कचरा इकट्ठा हुआ, उसमें 7.50 लाख करोड़ रुपये की बहुमूल्य धातुएं थीं।

भारत पूरी दुनिया में ई-कचरा पैदा करने के मामले में तीसरे नंबर पर है। वर्ष 2021 से 2022 तक भारत में 16 लाख टन ई-कचरा पैदा हुआ था। वर्ष 2030 तक भारत में 1.4 करोड़ टन ई-कचरा होने का अनुमान है। हालांकि भारत ने इससे निपटने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। देश में नई स्क्रैप पॉलिसी के तहत सरकार ने वर्ष 2022 में मोबाइल फोन, लैपटॉप, फ्रिज, टीवी, एसी समेत 134 इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उपयोग की अंतिम तिथि (एक्सपायरी डेट) तय कर दी। इसके बाद इनका उपयोग बंद करना होगा। जिस तरह से पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग का काम 'रीसाइक्लिंग एजेंसी' करती है, उसी तरह इलेक्ट्रॉनिक सामान के कलेक्शन और स्क्रैपिंग का काम भी 'प्राइवेट एजेंसियां' कर रही हैं।

ई-कचरे की बढ़ती मात्रा पृथ्वी के लिए खतरनाक है। इसलिए इन पर अंकुश लगाने के साथ इनके बेहतर रीसाइक्लिंग का भी ठोस इंतजाम करना होगा, ताकि हम पृथ्वी के अनमोल संसाधनों का न सिर्फ सावधानीपूर्वक इस्तेमाल कर सकें, बल्कि उसकी सेहत का भी ध्यान रख सकें।

कल्पमेधा

मैं उनसे प्रेम करता हूं जो मुसीबत में मुस्कुरा सकें, जो संकट में शक्ति एकत्रित कर सकें, और जो आत्मचिंतन से साहसी बन सकें।
– लिओनार्दो दा विंची

शक की सुई

इस आम चुनाव के पहले और दूसरे चरण में कम मतदान के आंकड़े आए, तो निर्वाचन आयोग पर सवाल उठने शुरू हो गए थे कि उसका मतदाता जागरूकता अभियान कारगर साबित क्यों नहीं हो पा रहा। अब उसने अंतिम आंकड़े जारी किए हैं, जो पिछले आंकड़ों से पांच से छह फीसद तक अधिक हैं। यानी दोनों चरण में छियासठ फीसद से अधिक मतदान हुए। यह एक संतोषजनक आंकड़ा कहा जा सकता है। मगर विपक्षी दलों ने सवाल उठाया है कि निर्वाचन आयोग ने अंतिम आंकड़े जारी करने में इतना वक्त क्यों लगाया। ये आंकड़े पहले चरण के ग्यारह दिन और दूसरे चरण के चार दिन बाद आए हैं। अभी तक मतदान के चौबीस घंटों में अंतिम आंकड़े जारी कर दिए जाते थे। फिर, विपक्षी दलों ने यह भी पूछा है कि आयोग ने मतदाताओं की संख्या क्यों नहीं बताई है। इस तरह चुनाव नतीजों में गड़बड़ी की शंका भी जाहिर की जाने लगी है। पहले ही विपक्षी दल और कई सामाजिक संगठन मतदान मशीनों में गड़बड़ी की आशंका जताते रहे हैं। निर्वाचन आयोग के चुनाव प्रक्रिया और परंपराओं का उचित निर्वाह न करने से उनका संदेह स्वाभाविक रूप से और गहरा होगा। यह समझना मुश्किल है कि निर्वाचन आयोग ने मतदान के अंतिम आंकड़े जारी करने में इतना वक्त क्यों लगाया।

मशीनों के जरिए मतदान कराने के पीछे मकसद यही था कि इससे मतगणना में आसानी होगी, मतदान से संबंधित आंकड़ों को अधिक पारदर्शी और विश्वसनीय बनाया जा सकेगा। मतदान मशीनों की केंद्रीय इकाई में हर मतदान केंद्र पर पड़े मतों की संख्या दर्ज होती है। इस तरह हर घंटे मतदान के आंकड़े जारी किए जाते हैं। हालांकि अंतिम आंकड़ा मतदान अधिकारियों के रजिस्टर में दर्ज संख्या से मिलान करने के बाद ही तय होते हैं। इसलिए मान कर चला जाता है कि मतदान मशीनों की केंद्रीय इकाई से मिले आंकड़ों में कुछ फीसद की बढ़ोतरी हो सकती है। मगर मतदान अधिकारियों के रजिस्टर में दर्ज संख्या की गणना करने में भी इतना वक्त नहीं लगता। जब इससे पहले मतदान समाप्त होने के अगले दिन अंतिम आंकड़े जारी कर दिए जाते थे, तो इस बार ऐसी क्या अड़चन आ गई कि ग्यारह दिन लग गए। फिर मतदाताओं की संख्या वेबसाइट पर बताने में क्या दिक्कत है। वह तो मतदाता सूची में दर्ज ही होती है। आज के डिजिटल युग में ऐसी सूचनाएं जारी करने में ज्यादा समय नहीं लगता।

निर्वाचन आयोग का दायित्व है कि वह न केवल स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराए, बल्कि चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता भी बनाए रखे। अगर किसी विषय या बिंदु पर आम लोगों या राजनीतिक दलों को किसी प्रकार का संदेह या प्रश्न है, तो उसका निराकरण भी करे। पहले ही आम मतदाता के मन में यह धारणा बैठी हुई है कि मशीनों में गड़बड़ी करके मतों को इधर से उधर किया जा सकता है। फिर राजनेताओं के आपत्तिजनक बयानों और आचार संहिता के उल्लंघन संबंधी शिकायतों पर पक्षपातपूर्ण रवैए के आरोप भी निर्वाचन आयोग पर लगते रहे हैं। ऐसे में उससे अतिरिक्त रूप से सावधान रहने की अपेक्षा की जाती है। चुनाव की तारीखों का ऐलान करते हुए आयोग ने बढ़-चढ़ कर दावा किया था कि वह नियम-कायदों की किसी भी प्रकार की अनदेखी बर्दाश्त नहीं करेगा। मगर उसके इस दावे पर भरोसा इस बात से बनेगा कि वह खुद नियम-कायदों की कितनी परवाह करता है।

अपवाह का असर

अफवाह फैलाने वालों का मूल मकसद लोगों में दहशत फैलाना और प्रशासन को परेशान करना होता है। वे इस बात से अच्छी तरह वाकिफ होते हैं कि ऐसा करने पर उन्हें कड़ी सजा हो सकती है। फिर भी अफवाहों के सिलसिले पर रोक नहीं लग पा रही। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के करीब सौ स्कूलों में बम रखे होने की सूचना मेल के जरिए देना इसकी ताजा कड़ी है। यह मेल बुधवार को तड़के भेजा गया था। उसके बाद स्वाभाविक ही अफरातफरी का माहौल बन गया। स्कूल खाली करा लिए गए। पुलिस और बम निरोधक दस्ते स्कूलों की छानबीन करने में जुट गए। दोपहर तक पूरे प्रशासन का ध्यान इसी तरफ लगा रहा। आखिरकार पता चला कि सूचना झूठी थी। पुलिस ने पता कर लिया है कि मेल कहां से भेजा गया था। इससे पहले भी कुछ स्कूलों में इसी तरह बम रखे जाने की झूठी सूचनाएं दी गई थीं, जिससे प्रशासन को नाहक परेशान होना पड़ा था। इस समय चुनाव की सरगर्मी है, इसलिए भी ऐसी सूचना से प्रशासन के माथे पर बल पड़ गए थे।

इस तरह बम रखे होने की सूचनाएं देने के मामले पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़े हैं। हवाई जहाजों में बम रखने की अफवाहें तो जैसे आम बात हो चली है। ऐसी गलत सूचनाएं देने वाले पकड़े भी जाते हैं। उनमें से कइयों को लंबी अवधि की सजाएं भी सुनाई जा चुकी हैं। फिर भी अफवाह फैलाने वाले कोई सबक नहीं ले रहे, तो इसकी एक वजह तो युवाओं में पुलिस को परेशान कर क्षणिक सुख पाने की प्रवृत्ति है। दूसरे, बहुत सारे लोग किसी झुंझलाहट में या किसी को सबक सिखाने के इरादे से ऐसा करते हैं। संचार संसाधनों के प्रसार और उन्हें उपयोग करने की चोर विधियों ने गलत सूचना देकर सुख पाने की प्रवृत्ति को और बढ़ाया है। ऐसे लोग अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं कर पाते कि ऐसी सूचनाओं से कितने लोगों को परेशानी उठानी पड़ती और कई बार बड़े हादसे भी जाते हैं। अच्छी बात है कि पुलिस ने ऐसी सूचनाओं पर त्वरित कार्रवाई का व्यवस्थित तंत्र विकसित कर लिया है।

मुसीबत बनता आबादी का असंतुलन

भारत में आबादी का असंतुलन लगातार बढ़ रहा है। लड़कियों की जन्मदर घटने के कारण सामाजिक ताने-बाने पर बुरा असर पड़ रहा है।

अखिलेश आर्येंदु

आज तमाम विकासशील देश बढ़ती आबादी और संसाधनों की कमी की वजह से परेशान हैं। दूसरी तरफ, विकसित देशों में घटती जन्मदर, खासकर नौजवानों की घटती आबादी से आर्थिक और सामाजिक ताने-बाने पर पड़ रहे असर से कई तरह की समस्याएं पैदा हो गई हैं। 2022 के संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के मुताबिक पिछले दस वर्षों में एक करोड़ से ज्यादा आबादी वाले आठ देशों की आबादी कम हो गई, जिनमें ज्यादातर देश यूरोप के हैं। जापान में पिछले कई वर्षों से जनसंख्या में कमी और बुजुर्गों की बढ़ती आबादी की वजह से सामाजिक और आर्थिक हालात पर असर पड़ा है। इससे कई तरह के असंतुलन पैदा हो गए हैं।

'द लैंसेट' में 20 मार्च, 2024 को प्रकाशित अध्ययन के मुताबिक भारत में आबादी का असंतुलन लगातार बढ़ रहा है। लड़कियों की जन्मदर घटने के कारण सामाजिक ताने-बाने पर बुरा असर पड़ रहा है। भारत में जीवन शैली में बदलाव की वजह से युवा शादियां विलंब से करने लगे हैं, जिससे संतान होने में देर हो रही है, जिसका असर बच्चों के पालन-पोषण, उनकी शिक्षा और सेहत पर पड़ता है। इससे सामाजिक ताना-बाना बिगड़ रहा है। रपट के मुताबिक 1950 यानी चौहत्तर वर्ष पहले तक भारत की प्रजनन दर 6.2 फीसद थी, जो 2021 आते-आते घट कर दो फीसद से भी कम रह गई। अनुमान के मुताबिक 2050 तक प्रजनन दर घट कर 1.29 फीसद और 2100 में घटते-घटते 1.04 तक पहुंच सकती है। इसे भारत के लिए किसी भी नजरिए से अच्छा नहीं कहा जा सकता है।

गौरतलब है कि प्रजनन दर 2.1 को 'रिप्लेसमेंट लेवल' कहा जाता है। यानी इस दर पर आबादी स्थिर रहती है और इससे कम होने पर घटने लगती है। युवाओं की आबादी घटने का मतलब है, वृद्धों की आबादी में वृद्धि। वृद्धों की आबादी बढ़ने का मतलब है, श्रमशक्ति में कमी आना। यह किसी भी देश के लिए जोखिम की स्थिति हो सकती है। भारत को भी एक या दो दशक बाद श्रमशक्ति में कमी से कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।

विकसित देशों में प्रजनन दर लगातार कम हो रही है, जिससे युवाओं की तादाद कम और बुजुर्गों की बढ़ रही है। यानी जन्म और मृत्यु दर में असंतुलन पैदा हो गया है। अध्ययन के मुताबिक 2030 तक स्पेन, दक्षिण कोरिया, रूस, सिंगापुर और जर्मनी की आबादी घटनी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा, भारत, नेपाल, श्रीलंका और म्यांमा की आबादी की रफ्तार भी थम सकती है। अभी कई विकसित देशों में बच्चों की जन्मदर बहुत तेजी से घट रही है। इसमें सिंगापुर और जापान प्रमुख हैं। सिंगापुर में जन्मदर 0.97 फीसद है, जापान में 0.6 फीसद और कोरिया में 0.72 फीसद है।

गौरतलब है कि जापान ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए युवाओं को इनाम दे रहा है। इसके बावजूद, शादी करने वाले युवाओं की संख्या लगातार कम हो रही है। आंकड़े बताते हैं कि जापान में शादी न करने

वाले युवाओं की संख्या लगातार घट रही है। वर्ष 2023 में महज चार लाख युवाओं ने शादियां कीं। इसी तरह सिंगापुर में 2023 में 26,500 युवाओं ने ही शादियां कीं। इसलिए जापान और सिंगापुर में जन्मदर में लगातार गिरावट आ रही है। सिंगापुर इस समय दोहरे संकट से जूझ रहा है। एक तरफ जन्मदर में बेतहाशा कमी आ रही है, तो दूसरी तरफ देश की बहुत बड़ी आबादी बूढ़ी हो गई है। जन्मदर में यह कमी जापान और सिंगापुर की अर्थव्यवस्था पर सीधे असर डाल रही है।

विकसित देशों में प्रजनन दर लगातार कम हो रही है, जिससे युवाओं की तादाद कम और बुजुर्गों की बढ़ रही है। यानी जन्म और मृत्यु दर में असंतुलन पैदा हो गया है। अध्ययन के मुताबिक 2030 तक स्पेन, दक्षिण कोरिया, रूस, सिंगापुर और जर्मनी की आबादी घटनी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा, भारत, नेपाल, श्रीलंका और म्यांमा की आबादी की रफ्तार भी थम सकती है। अभी कई विकसित देशों में बच्चों की जन्मदर बहुत तेजी से घट रही है। इसमें सिंगापुर और जापान प्रमुख हैं। सिंगापुर में जन्मदर 0.97 फीसद है, जापान में 0.6 फीसद और कोरिया में 0.72 फीसद है।

आबादी के मामले में चीन दुनिया का सबसे बड़ा देश है, उसकी आबादी 2100 तक आज के स्तर से आधी यानी 1.4 अरब से घट कर 77.1 करोड़ रह सकती है। मगर दुनिया के तमाम अविकसित देशों में आबादी घटने के बजाय लगातार बढ़ रही है। इनमें अफ्रीकी देशों के अलावा मुसलिम देश भी शामिल हैं। दुनिया के जिन देशों में जन्मदर बहुत अधिक है, उनको संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ रहा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि जनसंख्या का घनत्व लगातार बढ़ने के कारण कई तरह की समस्याएं पैदा होती हैं। उन समस्याओं में पीने के पानी, पोषण युक्त खाद्यान्न के अलावा दवाओं और रोजगार की कमी जैसी समस्याएं शामिल हैं। भारत भी ऐसी समस्याओं का सामना वर्षों से कर रहा है, लेकिन पिछले दस वर्षों में पानी, खाद्यान्न और रोजगार पर गौर करने के कारण इनमें कमी देखी जा रही है। फिर भी जनसंख्या घनत्व अधिक होने और जीवन-शैली में बदलाव की वजह से बच्चों के जन्मदर में कमी देखी जा रही है। मगर बूढ़े हो रहे लोगों की संख्या जापान की तरह भारत में भी बढ़ रही है, इस पर तुरंत गौर करने की जरूरत है। वहीं, भारत के पड़ोसी देशों, खासकर बांग्लादेश, म्यांमा से पलायन कर भारत में चोरी-छिपे रह रहे लाखों लोगों की वजह से भी जनसंख्या घनत्व पर असर पड़ा है।

भारत में स्थिर जनसंख्या वृद्धि का लक्ष्य हासिल करना बहुत बड़ी चुनौती है। इसलिए प्रजनन दर में कमी लाने के लिए व्यावहारिक कदम उठाने की जरूरत है। बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ में बच्चों की जन्मदर काफी अधिक है। इसलिए इन राज्यों को परिवार नियोजन पर अधिक ध्यान देना होगा। इसी के साथ भारत में युवाओं की बहुत बड़ी आबादी बेरोजगार है। इससे जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा देश के विकास में बाधा बना रहता है। इसलिए रोजगार की समस्या को प्राथमिकता के स्तर पर हल करने की जरूरत है।

यों तो बढ़ती आबादी पर रोक लगाने और बेरोजगारी की समस्या हल करने के मद्देनजर केंद्र और राज्य सरकारों ने कई कदम उठाए हैं, लेकिन आज भी करोड़ों की तादाद में भारत के युवा बेरोजगार हैं। इसलिए गैरबराबरी की समस्या भारतीय समाज में तेजी से बढ़ी है। भारत एक विकसित देश बने, इसके लिए जरूरी है कि बढ़ती आबादी पर रोक लगाई जाए और सबको शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं समान रूप से हासिल हों। गांवों से शहरों की तरफ पलायन को रोकना भी जरूरी है। क्योंकि पलायन से कई तरह की समस्याएं पैदा होती हैं और जनसंख्या असंतुलन लगातार बढ़ता है।

अर्थशास्त्रियों के अनुसार जनसंख्या समस्या का सबसे बेहतर समाधान है कि सेहत और शिक्षा संबंधी सुविधाओं का लगातार प्रसार किया जाए और गुणवत्ता में तेजी लाई जाए। आज जरूरत है स्त्री-पुरुष जनसंख्या संतुलन को बनाए रखने में आ रही बाधाओं को खत्म करने की। इसके लिए सरकार की नीतियों और योजनाओं को आम आदमी का भरपूर समर्थन मिले, ताकि जनसंख्या का असंतुलन न हो और बढ़ती गैरबराबरी की समस्या में कमी लाई जा सके। उम्मीद की जानी चाहिए कि भारत अपनी बेहतर नीतियों और योजनाओं से इस समस्या से कुछ वर्षों में पार पा लेगा।

सकारात्मक खालीपन

लोकेंद्रसिंह कोट

दुनिया मेरे आगे

अपने किसी प्रियजन को खोने या उनके बिछड़ने के बाद एक ऐसा खालीपन उभर कर सामने आता है, जिसे भरना नामुमकिन-सा रहता है। यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि उन दो व्यक्तियों में आपसी लगाव किस हद तक रहा और दोनों एक दूसरे के प्रति कितने संवेदनशील रहे या हैं। कई बार यह आपसी लगाव इतना गहरा होता जाता है कि कभी कल्पना में भी बिछड़ने की वे सोच नहीं सकते। किसी ऐसे ही पल में ये पंक्तियां फूटी होंगी कि 'मैं घर में एक कमरा रखूंगा... दूंगा नाम तेरा और उसे तन्हा रखूंगा!'

जीवन और मृत्यु का खेल सभी को पता होता है। सभी को किसी न किसी से बिछड़ना है, यह भी पता होता है। मगर फिर भी मन के किसी कोने से इसका भान ही नहीं होता। कुछ समय पहले एक खबर आई कि लंदन में एक महिला है, जो हर दिन सबवे (मेट्रो) स्टेशन में जाकर बैठती है, केवल 1950 में अपने पति द्वारा रिकार्ड की गई घोषणा को सुनने के लिए। 2003 में मार्गरेट के दिल में एक खाली स्थान छोड़कर ओसवाल्ड की मृत्यु हो गई। इसलिए मार्गरेट ने पति की उपस्थिति के अहसास को करीब से महसूस करने का एक तरीका खोजा। और वे उनकी रिकार्ड की हुई सूचना सुनने मेट्रो स्टेशन आने लगीं। आधी सदी से भी अधिक समय के बाद इस आवाज की जगह एक इलेक्ट्रानिक रिकार्डिंग ने ले ली। मार्गरेट ने लंदन ट्रांसपोर्ट कंपनी से यह कैसेट टेप मांगा, ताकि वह घर पर अपने पति की आवाज सुन सके। इस मसले के इतिहास के बारे में जानकारी होने के बाद कंपनी ने उत्तरी लाइन के तटबंध ठहराव पर मार्गरेट के घर के पास वाले स्टेशन पर घोषणा को बहाल करने का फैसला किया, जहां सभी यात्री आज ओसवाल्ड लारेंस की आवाज सुन सकते हैं और यह सोचने के लिए कि शाश्वत प्रेम वास्तव में मौजूद है।

खालीपन, अकेलेपन से नितांत अलग है। खालीपन मन के किसी कोने का अहसास है जो सिर्फ वही व्यक्ति भर सकता है जो अब नहीं रहा। जाहिर है, अगर वह व्यक्ति किसी रूप में हमेशा के लिए बिछड़ गया है तो उसकी यादें, तस्वीरें, आवाज, बातें सब सहारा होती हैं उस खालीपन को भरने का। समय की गूंज इतनी तेज होती है कि उस खालीपन के अव्यक्त मौन को भी चीर देती है। जब जेहन में किसी व्यक्ति की यादें भरी होती है तो हर कहीं वही दिखाई देता है। हर परिस्थिति में लगता है उसका साथ होता तो वह अभी क्या-क्या कर रहा होता। खालीपन उस श्मशान वैराग्य को भी छीन लेता है जो अक्सर कहता है कि कुछ नहीं रखा इस दुनिया में।

ऐसे अनचाहे दुख से निपटने के लिए हमें कमर कस कर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि यह खत्म भी तभी होगा, जब हम चाहेंगे। यह इसलिए भी जरूरी है कि जीवन जब तक नदी की तरह बह रहा है, तब तक जीवन है। जिस दिन ठहर गया, उस दिन वह दुनिया से बिछड़ गया। इसलिए हम स्मृतियों के समांतर जीने के विकल्प की खोज कर सकते हैं। बाहर दूसरे लोगों की निस्वार्थ सेवा एक ऐसा मार्ग है, जहां हमें सुकून मिल सकता है। अनाथाश्रम, वृद्धाश्रम, महिला सुधार गृह, बाल सुधार गृह, जेल, अस्पताल, गरीब बस्ती आदि ऐसी जगहें हैं, जहां अपने दुख कम ही लगेंगे। यों भी सेवा करने से बहुत सारे आंतरिक सीमाएं टूटती हैं। जब हमारे दुख छोटे होने लगते हैं तो फिर अपनों की याद में हम दूसरों का भला कर सकते हैं। हमारी सारी शिकायतें धुल जाती हैं। सेवा का मार्ग हमें और विस्तृत करता है। मैं, मेरा से निकालकर हमें एक विशाल दुनिया का परिचय करवाता है। सेवा करते हुए हम पाते हैं कि जिनको हमने खोया है, उन्हीं की याद दिलाते चेहरे हमें हमारी यादें खुशगवार बना देंगे।

जीवन जब तक नदी की तरह बह रहा है, तब तक जीवन है। जिस दिन ठहर गया, उस दिन वह दुनिया से बिछड़ गया। इसलिए हम स्मृतियों के समांतर जीने के विकल्प की खोज कर सकते हैं। बाहर दूसरे लोगों की निस्वार्थ सेवा एक ऐसा मार्ग है, जहां हमें सुकून मिल सकता है।

दूसरा रास्ता है प्रार्थना का, समर्पण का। जिस किसी को भी हम मानते हैं, चाहे वह ईश्वर हो, गुरु हो या फिर कोई और सम्माननीय हों, उन्हें समर्पण कर देना चाहिए और प्रार्थना करना चाहिए कि इस परिस्थिति से निकलने में हमारी मदद करें। कहते हैं, सच्चे मन से की गई प्रार्थना सुनी जाती है। ध्यान, प्राणायाम ऐसे माध्यम हैं, जो किसी की भी प्रार्थना को श्रेष्ठ बना सकते हैं, उसके समर्पण को मजबूती दे सकते हैं।

तीसरा रास्ता है अपनी शक्ति की पहचान। हमारे अंदर एक शक्ति है जो हमें अपने बिछड़े साथी, मित्र, बंधु के अधूरे सपने को पूरा करने के लिए प्रेरित कर सकता है। हमें उनके अधूरे कार्यों को पूरा करने में उनके साथ होने का आनंद मिल सकता है। उनकी याद में गोष्ठी, संगीत, सत्संग, पुरस्कार रख कर हम उन्हें बेहतर ढंग से याद कर पाएंगे।

कुल मिलाकर जो बिछड़ गया है, वह हमारी यादों में सकारात्मक रूप से रहे, यही उसके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। स्वयं दुखी होकर या नकारात्मक होकर हम दूसरों के और अपने साथ अन्याय कर रहे होते हैं। इसलिए आवश्यक है कि हम सकारात्मक रहें। कुछ नुकसान की भरपाई कुछ ठोस काम करके या इसके अलावा सेवा, प्रार्थना, सपने पूरे करके की जा सकती है। विरह की नकारात्मकता को प्रेम में बदलना ही खाली जगह को भरना है और यह भी सत्य है कि केवल हममें से कोई खास ही इसके पीड़ित नहीं हैं, संसार में और भी लोग हैं जो इस स्थिति से गुजर रहे हैं, उसका सामना कर रहे हैं।

चौपाल

धरती के लिए

हमारे सौरमंडल में पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन संभव है, लेकिन आज इस ग्रह का अपना जीवन संकट नजर आ रहा है। जिस तरीके से मानव जीवन शैली में भौतिकवाद और उपभोक्तावादी और लालच बढ़ता जा रहा है। आज इन सबका परिणाम यह है कि यह ग्रह संकट खाई में गिरता नजर आ रहा है। मनुष्य को लगता है कि वह प्रकृति के विनाश की शर्त पर अपना विकास कर लेगा तो यह उसकी सबसे बड़ी भूल साबित होगी। हमें इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए कि पृथ्वी जैसा आदर्श वायुमंडल किसी अन्य ग्रह पर मौजूद नहीं है, इसीलिए इस ग्रह को बचाना सबकी जिम्मेदारी है। पानी का संकट लगातार बढ़ रहा, वन लगातार सिकुड़ते जा रहे हैं। मानव और अन्य जीव-जंतुओं में संघर्ष बढ़ रहा है। हमारे जीवन में प्लास्टिक का बढ़ता उपयोग भी पृथ्वी के लिए घातक सिद्ध होने वाला है। पूरी दुनिया के महानगरों में कचरे के पहाड़ के पहाड़ देखे जा सकते हैं। सवाल यह है कि क्या हम सच में पर्यावरणीय कागजी बातों को वास्तविक रूप से धरातलीय स्तर पर लागू कर रहे हैं या सिर्फ खोखले दावों के भरोसे धरती मां को बचाने का ख्वाब पाल रहे हैं।

– सौरभ बुंदेला, भोपाल, मप्र

स्त्री का हक

देश की चुनावी प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी को भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था की परिपक्वता और प्रभावकारिता का एक महत्त्वपूर्ण संकेतक माना जा रहा है। राज्य चुनावों में महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि देखी गई है और कुछ जगहों पर महिलाओं का मतदान पुरुषों से अधिक हो रहा है। महिलाओं का योगदान भारतीय राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था में दिनोंदिन बढ़ रहा है। यह समावेशी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए एक सफल प्रयास है। सरकार द्वारा महिलाओं के उत्थान के लिए अनेक कार्यक्रम एवं योजनाओं का संचालन किया जाता रहा है। लंबे समय में इसका काफी सकारात्मक प्रभाव पड़ा और महिलाओं के सोच से लेकर जीवन-शैली में बड़ा बदलाव आया है। आज जिस पार्टी को भी चुनाव में जीत मिले, मगर उसमें महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका होगी।

– युगल किशोर राही, छपरा, बिहार

भूख के बरक्स

'भूख की त्रासदी' (संपादकीय, 26 अप्रैल) पढ़ा। विडंबना है कि एक तरफ अरबों टन खाना बर्बाद हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ अस्सी करोड़ लोग भूखे सोते हैं। ताज्जुब तो तब होता है जब भोजन बर्बादी में केवल अमीर देश ही नहीं है, बल्कि गरीब देश भी शामिल पाए जाते हैं। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि भोजन की बर्बादी के मामले में गांव-देहात अभी पीछे हैं, जबकि शहरी इलाके बहुत ज्यादा आगे हैं। एक तरफ कई देश भुखमरी और कुपोषण की पीड़ा झेल रहे हैं, वहीं सक्षम देश मानवता का ढिंढोरा पीटते हुए भोजन की बर्बादी में अव्वल पाए जा रहे हैं। हर हाल में भोजन की बर्बादी रोकना चाहिए, क्योंकि भूखा व्यक्ति ही जानता कि एक-एक निवाला कितना अमूल्य होता है। अगर भोजन बर्बाद करने वाले भूख की त्रासदी को समझ जाएं तो कई लोगों को भूखे पेट सोने पर मजबूर होने से बचाया जा सकता है।

– हुकुम सिंह पंवार, टोड़ी, इंदौर

निराश मतदाता

चुनाव में मतदान का गिरता अनुपात इंगित करता है कि आम मतदाता मत डालने को लेकर उदासीन है। वह इधर कुआं, उधर खाई वाली मनोदशा से गुजर रहा है। पक्ष-विपक्ष के अनर्गल आरोपों-प्रत्यारोपों वाला प्रचार उसे लुभा नहीं पा रहा। महंगाई, बेरोजगारी जैसे उससे जुड़े मूलभूत मुद्दों की चर्चा न होना शायद उसे रास नहीं आ रहा। धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण, जातियों के आधार पर तुष्टीकरण उसे हतोत्साहित कर रहा है। चुनाव पूर्व सिर्फ टिकट के लिए किए गए दलबदल से जनादेश को तोड़-मरोड़ कर सरकारें बनाने-गिराने से मतदाता खुद को ठगा महसूस कर रहा है। उसे शायद यह भी लग रहा है कि सरकार चाहे किसी भी पार्टी की बने, उसके हालात ऐसे ही रहेंगे। राजनीति और नेताओं से निराशा वाले इस माहौल में चुनाव आयोग की मतदान बढ़ाने की कोशिशें फलीभूत होना मुश्किल लगता है।

– बृजेश माथुर, गाजियाबाद

हमें लिखें, हमारा पता : edit.jansatta@expressindia.com | chaupal.jansatta@expressindia.com

www.readwhere.com

हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत न हो पाऊं फिर भी विचार प्रकट करने के आपके अधिकारों की रक्षा करूंगा। –वाल्तेयर

राजस्थान पत्रिका
संस्थापक
कर्पूर चन्द्र कुलिश

राजनीतिक दल नेताओं के लिए बनाएं आचरण संहिता

महिलाओं के यौन उत्पीड़न के आरोपों से घिरे प्रज्वल रेवन्ना को जनता दल-एस से निलम्बित कर दिया गया है। यह फैसला करना पार्टी के लिए जरूरी भी हो गया था। रेवन्ना पर लगे आरोप इतने गंभीर हैं कि पार्टी से रेवन्ना के निलम्बन की यह कार्रवाई नाकाफी लगती है। हैरानी इस बात पर है कि चरित्र पर उठ रहे सवालों से अवगत होने के बावजूद पार्टी ने इस बार भी सांसद रेवन्ना को लोकसभा चुनाव के लिए टिकट दे दिया। जाहिर है, पार्टी के स्तर पर इस प्रकरण को इसलिए भी दबाने के प्रयास हुए होंगे, क्योंकि प्रकरण हाई प्रोफाइल राजनीतिक परिवार से जुड़ा हुआ है।

रेवन्ना पर लगे आरोपों की जांच के लिए राज्य सरकार ने विशेष जांच दल (एसआइटी) का गठन कर दिया है। प्रज्वल के चाचा और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एच.डी. कुमार स्वामी ने भी जांच का स्वागत करते हुए इस प्रकरण में किसी के बचाव के प्रयासों से इनकार किया है। उनका कहना है कि कानून अपना काम करेगा। सवाल यह है कि यदि पार्टी में किसी भी स्तर पर प्रज्वल पर लगे आरोपों की जानकारी थी तो फिर देश की सबसे बड़ी पंचायत के लिए पार्टी प्रत्याशी बनाने पर किसी ने सवाल क्यों नहीं खड़े गए। यह बात सही है कि ऐसे मामलों में किसी का बचाव करना राजनीतिक दलों के लिए काफी मुश्किल है। खास तौर से चुनावों के मौके पर बचाव करने वाले दल व नेताओं के खिलाफ मामला उलटा पड़ सकता है। इसीलिए सभी तरफ से नेताओं के बयान सधे हुए ही सामने आ रहे हैं। चुनावों में मौके पर राजनेताओं के चरित्र पर अंगुलि उठने के उदाहरण यों तो पहले भी आते रहे हैं, लेकिन प्रकरण जगजाहिर होने के बाद खुद रेवन्ना का देश से बाहर चले जाना भी संदेह को जन्म देता है। हमारे देश में सुखद पहलू यह है कि कानून के सामने हर कोई समान है, लेकिन कई बार दबाव के कारण जांच प्रक्रिया को दूसरी दिशा में पहुंचाने का काम भी होने लगता है। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौडा के पोते प्रज्वल को भी स्वदेश आने के लिए बाध्य करना होगा ताकि जांच तत्परता से हो सके। यह महिला सुरक्षा से जुड़ा मामला है। इसलिए मामले की जांच में किसी तरह की ढिलाई नहीं होनी चाहिए।

सार्वजनिक जीवन में रहने वालों के लिए यह जरूरी हो जाता है कि वे अपना दामन पाक-साफ रखें। यह इसलिए भी कि लोग उनसे आदर्श आचरण की उम्मीद करते हैं। लेकिन, चिंता इस बात की है कि सार्वजनिक मंचों पर महिलाओं के सम्मान की रक्षा का दावा करने के साथ-साथ महिला उत्पीड़न के मामलों में दूसरे नेताओं को घेरने वाले नेता भी नारी उत्पीड़न के आरोपों से घिरते रहे हैं। राजनीतिक दलों को नेताओं के लिए भी आचरण संहिता बनानी होगी और गलत आचरण वाले नेताओं से दूरी बनानी होगी।

लोकसभा चुनाव 2024

103 निर्दलीय प्रत्याशी दागी

लोकसभा चुनाव के तीसरे में चरण में चुनाव लड़ रहे 650 निर्दलीय प्रत्याशियों में से 103 ने आपराधिक मामले घोषित किए हैं। वहीं 74 प्रत्याशियों ने गंभीर आपराधिक मामले घोषित किए हैं।

पत्रिका लोकतंत्र का उत्सव

बिहार में 54 प्रत्याशी मैदान में

लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में बिहार में 54 प्रत्याशी मैदान में हैं। इनमें 13 प्रतिशत प्रत्याशी दागी हैं और 20 प्रतिशत प्रत्याशी करोड़पति हैं। प्रत्याशियों की औसत संपत्ति 2.79 करोड़ रुपए है।

चुनावी चटकारा

सवालों से कठिन हुआ परिणाम का इंतजार...

जिन लोकसभा क्षेत्रों में मतदान हो गया है, वहां के कई प्रत्याशियों को रोज किसी न किसी कार्यकर्ता को यह बताना पड़ रहा है कि वे कितने वोटों से जीत रहे हैं। इससे प्रत्याशी अपने आपको असहज महसूस कर रहे हैं। जिन प्रत्याशियों को हारने का डर है, वे यह भी नहीं कह पा रहे कि जीतना मुश्किल है। दावा तो जीतने का ही करना पड़ेगा। ऐसे में उन्होंने एक रास्ता अपनाया है। अब वे जहां चुनाव नहीं हुए हैं, वहां के पार्टी प्रत्याशियों के प्रचार में समय गुजार रहे हैं, ताकि रोज-रोज के सवालों के झंझट से निजात मिले। वहां कोई पूछता है तो यही कह देते हैं, कितने वोटों से जीतेंगे यह तो एक माह बाद ही पता चलेगा। इसके बाद भी कई कार्यकर्ता फोन पर प्रत्याशी का आकलन पूछने से बाज नहीं आ रहे। वह इसलिए कि कार्यकर्ताओं में हार-जीत की शर्त लगाने की होड़ मची है। हार-जीत के दावे सोशल मीडिया पर भी किए जा रहे हैं।

राग सियासी

फरजी फोटो वीडियो,
रहे सियासत तैर।
जिसकी जिससे ना बनत,
तनिक ना देखत खैर।।
तनिक ना देखत खैर,
बैर काढ़त नेता पर।।
करत जेल की सैर,
फेर मुंह लेता हर दर।।
समझो चलत चुनाव,
पोस्ट ना कर मनमरजी।।
दिन दिन बढ़त दुराव,
देख कर फोटो फरजी।।

-राम नरेश गौतम

पश्चिम बंगाल हॉट सीट बहरमपुर का चुनाव हुआ रोचक, अधीर रंजन चौधरी के समक्ष अपना गढ़ बचाने की चुनौती

पठान के जरिए कांग्रेसी वोट बैंक में सेंध की कोशिश

बहरमपुर शहर मुर्शिदाबाद जिले का मुख्यालय है। जिले में बहरमपुर व मुर्शिदाबाद नाम से दो लोकसभा सीट हैं। चौथे चरण में बहरमपुर सीट पर 13 मई को चुनाव है। बहरमपुर सीट पर कांग्रेस से पांच बार के सांसद अधीर रंजन चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं तो टीएमसी ने टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर युसूफ पठान को उतार कर चुनाव के खेल को रोचक बना दिया है। इस सीट पर टीएमसी की लड़ाई भाजपा की बजाय कांग्रेस से दिख रही है। भाजपा ने डॉ. निर्मल कुमार साहा पर दांव लगाया है। वोटबैंक के विभाजन की संभावना के लिहाज से चुनाव के समीकरण त्रिकोणीय बने दिखाई दे रहे हैं।

बहरमपुर से
कानाराम मुण्डियार

लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल राज्य की हॉट सीट बहरमपुर की सियासत पर पूरे देश की नजर है। हॉट इसलिए हैं, क्योंकि यह संसदीय क्षेत्र कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी का गढ़ माना जाता रहा है और चौधरी यहां से पांच बार लगातार सांसद चुनाव जीतते आए हैं। आखिर ऐसी कौनसी रणनीति या करिश्मा है, जिसके चलते चौधरी लगातार बेताज बादशाह बने हुए हैं। चौधरी के गढ़ के मिजाज को जानने की उत्सुकता लिए मैं आसनसोल से वाया कोलकाता बहरमपुर पहुंचा।

रेलवे स्टेशन पर उतर कर बहरमपुर शहर की ओर से रुख किया तो कांग्रेस प्रत्याशी अधीर रंजन चौधरी का पोस्टर लगा दिखा। पास में ही टीएमसी का झंडा लगा है। स्टेशन के बाहर थड़ी पर 70 वर्षीय बासुराय से चुनाव का माहौल पूछा तो बोले, यहां हर चुनाव में माहौल तो हाथ का ही रहता है। हम भी हाथ के साथ है, लेकिन इस बार क्रिकेट खिलाड़ी युसूफ पठान को उतार देने से कांग्रेस के मूल वोट बंटेंगे। फायदा भाजपा को मिल सकता है। गणेश रॉय बोले, बाकि सब बातें बेकार हैं, इतना जान लीजिए, कि बहरमपुर में इस बार पठान की जीत होगी। स्टेशन पार्किंग एरिया से शहर के बस स्टेण्ड रोड चौराहे की तरफ गौतम बुद्ध की प्रतिमा लगी है। चौराहे पर एक दुकान पर बिश्वजीत बोस से चर्चा हुई। बोस ने कहा कि हमने बचपन से कांग्रेस व सीपीएम को ही देखा और पढ़ा। कुछ साल से तीसरे दल टीएमसी के आने से माहौल खराब हुआ है। चौधरी की वजह से बहरमपुर-मुर्शिदाबाद सुरक्षित हैं। छोटे से छोटे मामलों में चौधरी ही मुर्शिदाबाद की जनता के साथ खड़े रहे हैं। राष्ट्र की मजबूती के लिए केन्द्र में सरकार तो मोदीजी की ही होनी चाहिए। लेकिन लोकल क्षेत्र के हितों की रक्षा के लिए हम चौधरी को ही पसंद करते हैं। बस स्टैंण्ड पर एक फल विक्रेता सीने पर हाथ रखते हुए बोले, इस बार किसे चुनना है, यह मन में ठान रखा है। मधुपुर बाजार में अमित कुमार विश्वास, कॉसिम बाजार स्थित हनुमान मंदिर में सुजीत कुमार शर्मा ने बरहमपुर में इस बार खेला होने संभावना जताई।

बहरमपुर सीट पर पिछले पांच लोकसभा चुनाव कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी जीतते रहे हैं। मुस्लिम मतदाताओं की बहुलता का फायदा कांग्रेस को मिलता रहा है। इस बार टीएमसी कांग्रेस के मुस्लिम वोट बैंक को तोड़ने में लगी हैं। गत विधानसभा चुनाव में भी टीएमसी ने चार विधानसभा सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी उतार कर कांग्रेस को पछाड़ा था। इस लोकसभा के चुनाव टीएमसी ने टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर युसूफ पठान को चुनाव में उतारा है। युसूफ चुनाव से ठीक पहले टीएमसी में शामिल हुए। अधीर रंजन के लिए टीएमसी उनके क्षेत्र में चुनौती बन गई है। हालांकि इस बार कांग्रेस का सीपीआइ (एम) के साथ गंठबंधन है। वामदल के जरिए कांग्रेस प्रत्याशी की झोली में कितने वोट आएंगे, इस पर अभी संशय ही है। टीएमसी व कांग्रेस के बीच घमासान को देखते हुए भाजपा की कोर टीम पनडुब्बी की तरह काम कर रही है। भाजपा ने यहां डॉ. निर्मल कुमार साहा को उतारा है। भाजपा को उम्मीद है कि टीएमसी प्रत्याशी युसूफ पठान कांग्रेस के कोर वोट को तोड़ेंगे, जिससे उनकी बाजी आसान हो सकती है।

भाजपा से समझौते के आरोप

लोकसभा चुनाव को लेकर टीएमसी व कांग्रेस दोनों ही दल एक दूसरे पर भाजपा से समझौता करने और भाजपा की बी टीम के रूप में कार्य करने के आरोप लगा रहे हैं। भाजपा इस तरह के आरोपों को सिरे से खारिज करती है। भाजपा का कहना है कि किसी से कोई पैक्ट नहीं है। ज्ञात है कि यहां टीएमसी ने इंडिया गंठबंधन से नाता तोड़ दिया है और अकेले चुनाव लड़ रही है। चुनावी कैम्पेन में ममता बनर्जी कांग्रेस को भाजपा की बी. टीम बताते हुए निशाने साध चुकी है। वहीं अधीर रंजन भी पूरा जोर लगा रहे हैं। हाल ही चुनावी सभा में चौधरी यह भी कह चुके हैं कि यदि यह चुनाव हार गया तो वह राजनीति से संन्यास ले लेंगे।

मुद्दों को भुना रहे दल: भाजपा राम मंदिर निर्माण, जम्मू व धारा-370 को हटाने, संदेशखाली प्रकरण, प. शिक्षक भर्ती घोटाला एवं देश में सीएए लागू करने जैसे मुद्दों को जोर-शोर से उठा रही है। टीएमसी सीएए व एनआरसी का विरोध कर रही है। कांग्रेस मुस्लिम वर्ग के वोट बैंक पर पकड़ बनाए रखने की कोशिश कर रही है एवं टीएमसी इसको छीनने की कोशिश कर रही है।

मैदान में प्रत्याशी

कांग्रेस: अधीर रंजन चौधरी

मजबूत पक्ष	कमजोर पक्ष
वाम मोर्चा के साथ कांग्रेस का सीट समझौते से फायदा।	कांग्रेस व वामदल के वोटबैंक बंटने की संभावना।
हिन्दू-मुस्लिम मतदाताओं पर अच्छी पकड़	कांग्रेस की संगठनात्मक कमजोरी।
पांच बार से सांसद होने से अनुभव	सीपीआइ (एम) के वोटों को लेकर संशय

टीएमसी: युसूफ पठान

मजबूत पक्ष	कमजोर पक्ष
पूर्व क्रिकेटर होने के कारण युवाओं में लोकप्रिय	बाहरी उम्मीदवार होने से व्यक्तिगत संपर्क का अभाव
टीएमसी से प्रत्याशी होने और मुस्लिम होने से फायदा।	सिर्फ मुस्लिम वोट पाने का भरोसा।
कांग्रेस की कमजोरी का फायदा।	हिन्दू वोट के लिए सीएम ममता बनर्जी पर निर्भर

भाजपा: डॉ. निर्मल कुमार साहा

मजबूत पक्ष	कमजोर पक्ष
अच्छे डॉक्टर हैं। सभी समुदायों पर पकड़।	राजनीति में नए हैं। दांव पेंच की कम समझ।
कांग्रेस का वोटबैंक बंटने की उम्मीद।	भाजपा के वोटर को शत-प्रतिशत बूथ तक लाना चुनौती है।
स्थानीय होने और आसान उपलब्धता और लोगों से जुड़ाव।	मुस्लिम मतदाताओं से दूरी।

बिहार अतिपिछड़ा और पिछड़े वर्ग की गोलबंदी ही पार्टियों को परिणाम तक पहुंचाएगी

राज्य की पांच लोकसभा सीटों पर 'पंचफोरन' का प्रभाव

प्रियरंजन भारती

जाति आधारित गणना किस तरह गेम चेंजर होगी या नहीं होगी, इसका आकलन इन पांच लोकसभा सीटों के परिणाम से ही होगा।

लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में बिहार की जिन पांच लोकसभा सीटों पर सात मई को मतदान होना है, उनमें अतिपिछड़ा और पिछड़े वर्ग की गोलबंदी ही पार्टियों को परिणाम तक पहुंचाएगी। इस बीच अब आरजेडी नेता लालूप्रसाद यादव और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भाजपा के चार सौ पार के नारे की जगह हिंदू कार्ड और जातिवाद ने ले ली है।

दो चरणों के मतदान पूरे हो जाने के बाद यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के लहजे पर सीधा हमला है। इसकी वजह सामाजिक और जातीय समीकरणों को अपने हित में साधने का लक्ष्य है। जाति आधारित गणना किस तरह गेम चेंजर होगी या नहीं होगी, उसका आकलन इन पांच लोकसभा सीटों के परिणाम से ही होगा। अगले दौर में सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया, अररिया और मिथिलांचल के झंझारपुर में चुनाव है। तीसरे दौर के चुनाव वाले जिन तीन क्षेत्रों झंझारपुर, सुपौल और मधेपुरा में जहां जदयू के सांसद हैं वहां पिछड़ा और अतिपिछड़ा वर्ग के वोटों की गोलबंदी ही जीत हार का फैसला करती आई है। झंझारपुर में जदयू सांसद रामप्रीत मंडल फिर से मैदान में हैं। मैथिल ब्राम्हणों और यादव समेत मल्लाह वोटरों के प्रभाव वाले इस क्षेत्र में 'इंडिया' गठबंधन से मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी के सुमन महासेठ को मुकाबले में उतारा गया है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. जगन्नाथ मिश्र के गृहक्षेत्र वाली इस संसदीय सीट पर अतिपिछड़ा और ब्राह्मण वोट ही निर्णायक होते हैं। इन इलाकों में पिछड़ा और अतिपिछड़ा मतदाताओं को 'पंचफोरन' कहा जाता है। इनमें पांच जातियों के लोग हैं। ये जीत-हार के कारण बनते आ रहे हैं। झंझारपुर से पांच बार सांसद रह चुके देवेंद्र प्रसाद यादव ने उम्मीदवारी की लालसा पूरी नहीं होने पर आरजेडी से रिश्ता तोड़ लिया और पप्पू यादव की राह पर चलते हुए महागठबंधन को धूल चटाने की ठान ली है। पूर्व विधायक गुलाब यादव ने आरजेडी से टिकट नहीं मिलने के बाद निर्दलीय ताल ठोकी दी है।

सुपौल संसदीय सीट भी पिछड़ा और अतिपिछड़ा वोट बैंक के लिटमस टेस्ट की धरती बनी है। इस क्षेत्र में भी यादव और अतिपिछड़ा पंचफोरन वोट बैंक प्रभावकारी है। यह सीट गठबंधन में नहीं मिलने से कांग्रेसी आहत हैं। रोम पोप का, मधेपुरा गोप का..। इस प्रचलित कहावत वाली बीपी मंडल (मंडल कमीशन के नायक) की धरती मधेपुरा में इस बार फिर दो यादव प्रत्याशी मैदान में हैं। दो बार से संसद में यहां का प्रतिनिधित्व करते आ रहे जदयू के दिनेशचंद्र यादव के मुकाबले लालू यादव ने 1971 में कांग्रेस के सांसद रह चुके डॉ रवींद्र कुमार यादव 'रवि' के पुत्र प्रो.कुमार चंद्रदीप को आरजेडी उम्मीदवार बनाया है। सीमांचल की अररिया और कोसी क्षेत्र की खगड़िया संसदीय सीट एक जैसे समीकरणों के लिए जानी जाती हैं। अररिया में अतिपिछड़ा, पिछड़ा वर्ग और मुस्लिम आबादी निर्णायक होती है। जबकि खगड़िया में यादव, कुशवाहा और मुस्लिम वोट असरदार हैं।

'नेताजी के तारे-सितारे'

मीठी बोली से श्रोताओं के दिल में बनाएं जगह

लोकसभा चुनाव के रण में नेता तन-मन-धन से जुटे हैं। चुनाव जीतने के लिए वे एड़ी-चोटी का जोर लगा रहे हैं। प्रचार में उनके परिवार वाले व हजारों शुभचिंतक साथ हैं। साथ ही राजनेता ज्योतिष का भी सहारा ले रहे हैं। तो जानिए आज नेताजी के तारे-सितारे क्या कह रहे हैं। **-अज़हर हाशमी**

मेष- आज आपकी राशि में चंद्रमा गोचर में दसवां है, जो शुभ है। आज आप प्रतिद्वंद्वी की पोल खोल देंगे।

वृषभ- आज गोचर में नौवां चंद्रमा आपके लिए रक्षा कवच बनेगा। आप प्रचार में प्रतिद्वंद्वी के प्रभाव का तिलिस्म तोड़कर श्रोताओं के दिल में जगह बनाएंगे।

मिथुन- आज आठवां चंद्रमा अशुभ है। अशुभता दूर करने के लिए प्रतिद्वंद्वी को 'पालक के भजिए' खिलाएं। प्रतिद्वंद्वी आपका भजन करेगा।

कर्क- आज गोचर में सातवां चंद्रमा बहुत अनुकूल है। आज प्रचार में आप प्रतिद्वंद्वी को पानी- पानी कर देंगे, लेकिन घमंड मत करना।

सिंह- आज आपकी राशि में गोचर में छठा चंद्रमा आपके अनुकूल नहीं है। छह गायों को चारा खिलाएं, लाभ होगा।

कन्या- आज गोचर में पांचवां चंद्रमा आपके लिए शुभ है। मुंशी प्रेमचंद की कहानी 'पंच परमेश्वर' पढ़ें। चंद्रमा अधिक शुभ हो जाएगा।

तुला- आज गोचर में चौथा चंद्रमा अशुभ है। प्रतिद्वंद्वी अपने तर्कों के मांझे से आपके प्रचार की पतंग काट सकता है। ज्यादा ऊंचे मत उड़िए। *सावधान!*

वृश्चिक- आज तीसरा चंद्रमा शुभ है। प्रचार में निकलने से पूर्व 'तीसरी कसम' फिल्म देखें। प्रतिद्वंद्वी तीन बार आपको प्रणाम करेगा

धनु- आज दूसरा चंद्रमा आपको प्रचार में दूज के चांद की तरह खुशियां देगा यानी आज प्रचार में आपकी चांदी ही चांदी है। क्या बात है!

मकर- आज चंद्रमा आपकी ही राशि में है। यह शुभ है। प्रतिद्वंद्वी आपकी टांग खींचने के चक्कर में खुद ही औंधे मुंह गिर जाएगा।

कुंभ- आज आपकी राशि में गोचर में बारे में चंद्रमा आपके लिए अशुभ है। प्रतिद्वंद्वी आज आपके 'बारह' बजा सकता है। होशियार!

मीन- आज आपकी राशि में 11वां चंद्रमा बहुत शुभ है। आज तो प्रतिद्वंद्वी खुद आपके 'चंवर' डुलाएगा। यानी आपकी हां में हां मिलाएगा।

अगला राशिफल सोमवार के अंक में

पोलीटून

सामयिक इजरायल को सैन्य सहायता नहीं देनी चाहिए

शांति के लिए नागरिकों के हितों को प्राथमिकता मिले

ऐनी-मैरी स्लॉटर
स्तंभकार और लेखिका
द वाशिंगटन पोस्ट से विशेष अनुबंध के तहत

गाजा और वेस्ट बैंक में बसे फिलिस्तीनियों के संरक्षण के लिए वह सब किया जाना चाहिए, जो किया जा सकता है। साथ ही इजरायलियों की सुरक्षा के लिए पूरे प्रयास करने चाहिए। जब तक गाजा में फिलिस्तीनी नागरिकों को युद्ध से बचने के लिए पर्याप्त भोजन, पानी, दवा और आश्रय सुलभ नहीं हो जाता, तब तक अमरीका को इजरायली सरकार की सैन्य सहायता पर विराम लगाना चाहिए। साथ ही इजरायली लोगों को गारंटी दी जाए कि अमरीका और उसके सहयोगी अगले किसी भी हमले से उन्हें बचाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे।

दोनों पक्षों के लोगों के जीवन पर ध्यान केंद्रित करना है न कि किसी देश को समर्थन देने या वापस लेने पर। क्या इजरायल एक यहूदी राज्य के रूप में जीवित रहेगा? क्या फिलिस्तीनी लोगों को अपना राज्य मिलेगा? ये सवाल ऐसे हैं जिन्हें लेकर सरकारी अधिकारी और विदेश नीति के विशेषज्ञ चर्चा करते हैं। यानी लोगों के बजाय सरकारों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।

अभी कुछ समय के लिए दोनों तरफ के लोगों को ऐसे सवालों को अनदेखा करना होगा। इजरायल ने हमास को खत्म करने की अपनी कोशिशों में हजारों फिलिस्तीनी पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को मार डाला है। हमास और उसके समर्थक इजरायल में रहने वाले यहूदियों को मार डालना या निष्कासित करना चाहते हैं। राष्ट्रपति जो बाइडन और अन्य देशों के नेता जो परम्परागत रूप से इजरायल का समर्थन करते रहे हैं, उनको सीधे तौर पर इजरायल और फिलिस्तीन दोनों से सीधे बात करनी चाहिए। फिलिस्तीन के लोगों के लिए उनका संदेश होना चाहिए कि वह सब कुछ करेंगे कि जो उनके लिए जरूरी होगा। साथ ही अमरीकी सेना इजरायल को हमलों से सीधे ही बचा सकती है। जैसाकि उसने अभी हाल में ब्रिटिश, फ्रांसीसी और जॉर्डन सरकार के साथ मिलकर ईरान के ड्रोन और मिसाइल से हमले से इजरायल को बचाया। अमरीकी सरकार, इजरायली सरकार की अनुमति से, अपने सैनिकों को इजरायल की सीमाओं पर भी तैनात कर सकती है।

आज का सवाल

कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर सवाल क्यों उठ रहे हैं?

ईमेल करें: edit@epatrika.com

भ्रष्ट तंत्र जिम्मेदार

राज्यों की ड्रग लाइसेंसिंग अथॉरिटी की निष्क्रियता के लिए भ्रष्ट तंत्र और अधिकारियों की उदासीनता जिम्मेदार है। इसके कारण नकली दवाओं का कारोबार चलता है।
-प्रकाश भगत, नागौर

राज्य सरकारों की जिम्मेदारी

राज्यों की ड्रग लाइसेंसिंग अथॉरिटी की निष्क्रियता के लिए राज्य सरकारें जिम्मेदार हैं। यह अथॉरिटी ड्रग्स विनिर्माण, बिक्री, वितरण और उपयोग को नियंत्रित करती है।
-संजय माकोड़े, बैतूल, मप्र

बनी रहे विश्वसनीयता

दस्तावेजों की सही तरीके से जांच नहीं होती। लोग रिश्वत देकर दवा निर्माण के लाइसेंस प्राप्त कर लेते हैं। ड्रग लाइसेंसिंग अथॉरिटी की विश्वसनीयता बनी रहनी चाहिए।
-मीना सनाढ्य, उदयपुर

हो रहा है फर्जीवाड़ा

जो भी व्यक्ति दवाओं का व्यवसाय करता है, उसके लिए लाइसेंस जरूरी है। इस काम में फर्जीवाड़ा हो रहा है। इसके लिए संबंधित विभागों के अधिकारी ही जिम्मेदार हैं।
-निर्मला देवी वशिष्ठ, राजगढ़, अलवर

patrika.com पर पढ़ें

पाठकों की प्रतिक्रियाएं

पत्रिकायन का सवाल था, 'राज्यों की ड्रग लाइसेंसिंग अथॉरिटी की निष्क्रियता के लिए कौन जिम्मेदार हैं?' पाठकों की प्रतिक्रियाएं ऑनलाइन भी देखें।
इसे स्कैन करें
https://rb.gy/07tc24

चिंतन

सामान्य सी खबर नहीं है बहुत ज्यादा गर्मी पड़ना

इस साल बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगी, पढ़ने और सुनने को यह सामान्य खबर ही लगती है, लेकिन अगर इसके मायनों को देखेंगे तो भविष्य में आने वाले गंभीर खतरे नजर आते हैं। जो न केवल मानव जाति बल्कि पूरी धरा के लिए बहुत बुरे होंगे। इसका असर न केवल धरती के समूचे मौसम चक्र और कालांतर में मनुष्य के जीवन चक्र पर पड़ेगा और सब कुछ उलट-पलट कर रख देगा। इसके चलते कहीं बेमौसम बारिश और कहीं भयानक गर्मी पड़ने की आशंका है। दुनिया विकास के नाम पर संसाधनों का दोहन करते हुए जिस तरह आगे बढ़ रही है, वैज्ञानिकों का मानना है कि 2050 तक दुनिया का तापमान डेढ़ डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। इसके बाद अगले पचास सालों में दुनिया का तापमान दो से चार डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है। आप भविष्य की तरफ न जाकर भूतकाल को ही देखेंगे तो औद्योगिकीकरण से पहले के काल की तुलना में 2023 में धरती का औसत तापमान 1.45 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है और बुरे परिणाम में आने शुरू हो गए हैं। गलेशियर लगातार पिघल रहे हैं और धरती पर पानी में मात्रा में लगातार इजाफा हो रहा है। जिससे दुनिया के अनेक शहरों का पानी के गर्त में समा जाने का खतरा पैदा हो गया है। सबसे ज्यादा चिंता की बात तो यह है कि मौसम खुद को जितनी तेजी से बदल रहा है, हम मानव उतनी तेजी से अपना व्यवहार नहीं बदल पा रहे। शायद हम मनुष्य इस बात को नहीं समझ पा रहे कि मौसम हमारे द्वारा बनाई गई सीमाओं को नहीं मानता। मौसम की चेतावनी पूरी धरती के लिए, अर्थात इस धरती पर रहने वाले, पलने वाले, फलने-फूलने वाले, हर चल-अचल के लिए है। इसलिए पर्यावरण के बारे में वर्ल्ड लीडरों की भाषणबाजी से ज्यादा प्रत्यक्ष रूप से अपने आचरण में ठोस बदलाव की जरूरत है। इस बात को गंभीरतापूर्वक समझना होगा कि अगर मौसम के बदलने की रफ्तार तेज है तो हमें भी अपने कार्बन उत्सर्जन के मानकों और उद्देश्यों को तेजी से नए सिरे से निर्धारित करना होगा। न सिर्फ कार्बन उत्सर्जन, बल्कि मीथेन और नाइट्रेड ऑक्साइड भी नई चुनौती है। चीन के बाद भारत ही सबसे ज्यादा मीथेन का उत्सर्जन करता है। इसकी बड़ी वजह हमारा पशुधन है। पशुधन को बचाते हुए मीथेन को नियंत्रित करना होगा। विकास और पर्यावरण में संतुलन जैसी बाज़ारवादी संकल्पनाओं को कुछ समय के लिए विराम देना होगा। लेकिन दुर्भाग्य से इस दिशा में मानव समाज की कोई ठोस तैयारी दिखाई नहीं देती। यही वजह है कि इन दिनों धरती को आहत करने वाले चक्रवाती तूफानों की संख्या में कुछ वर्षों से तेजी से इजाफा हुआ है। कौन उत्तराखंड में तबाही के मंजर को कौन याद करना चाहेगा या फिर भूकंप की त्रासदी को भूल पाएगा। हर साल कोई न कोई चक्रवाती तूफान धरती के किसी न किसी हिस्से को तहस-नहस कर दे रहा है, लेकिन हम आपनी जीवन शैली में कोई सुधार करने को तैयार नहीं हैं। अब फिर आईएमडी का कहना है कि राष्ट्रीय राजधानी समेत उत्तर भारत के ज्यादातर हिस्सों में मई के महीने में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से ज्यादा रह सकता है। इस दौरान दो से चार दिन लू चल सकती है। बेहाल करने वाली गर्मी होगी। इशारा साफ है कि हम अंधिकार की ओर बढ़ रहे हैं। अगर अब भी सुधरे तो बहुत देर हो जाएगी।

वैक्सीनेशन
डॉ. रमेश ठाकुर

कोविशील्ड के भय को दूर करे सरकार

कोरोना वैक्सीन निर्माता कंपनी एस्ट्राजेनेका द्वारा साइड इफेक्ट को लेकर कोर्ट में सरेआम कबूल कर लेने के बाद बीते एकाध दिनों से पूरे संसार में इसी को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। भारत में ही नहीं, बल्कि विश्व में कोरोना के बाद कुछ ऐसा हुआ है कि कम उम्र और बिल्कुल तंदुरुस्त और चंगे भले इंसानों को अचानक हार्ट अटैक होना आरंभ हुआ। हालांकि भारत के वैज्ञानिक और चिकित्सक इस पर सहमत नहीं हैं कि इन मौतों का संबंध कोरोना के टीके से है, पर ब्रिटिश कोर्ट ने विशेषज्ञों को नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया है। अब जिम्मेदारी हुकूमत की बनती है कि लोगों के मन में कोविशील्ड को लेकर पनप चुके डर को कैसे भी दूर करें?

कोरोना वैक्सीन निर्माता कंपनी एस्ट्राजेनेका द्वारा साइड इफेक्ट को लेकर कोर्ट में सरेआम कबूल कर लेने के बाद बीते एकाध दिनों से पूरे संसार में इसी को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। भारत में ही नहीं, बल्कि विश्व में कोरोना के बाद कुछ ऐसा हुआ है कि कम उम्र और बिल्कुल तंदुरुस्त और चंगे भले इंसानों को अचानक हार्ट अटैक होना आरंभ हुआ। सांस्कृतिक मंचन हो, या शादी-ब्याह, पार्टी फंक्शनों में लोगों के नाचने के दौरान गश खाकर गिरना और उसके तुरंत बाद मौत हो जाना? करीब दो-तीन सालों ऐसी मौतें सभी के लिए पहेली बनी हुई हैं। एस्ट्राजेनेका की स्वीकरोक्ति के बाद अब संदेह और गहरा गया है। ऐसा दावा है कि ये सब कोविशील्ड टीके के साइड इफेक्ट के चलते हो रहा है। भ्रम है या हकीकत? ये तो कोई नहीं जानता, पर कोविशील्ड कंपनी के खुलासे ने ये दर्शा दिया है कि भविष्य में टीकाधारकों को साइड इफेक्ट हो सकता है। जबकि, इस वैक्सीन के इस्तेमाल के आंकड़े देखें तो सिर्फ भारत में ही एक अरब 17 करोड़ का है जिसे कोरोना के बाद लोगों ने बचाओ को ध्यान में रखकर लगवाया था। पूरे संसार की बात करें, तो ये आंकड़ा ढाई से तीन अरब तक पहुंचता है।

गौरतलब है कि कोविशील्ड कंपनी एस्ट्राजेनेका ने जब से ब्रिटिश कोर्ट में जज के समक्ष यह स्वीकारा है कि उनके टीके के इस्तेमाल से 'ब्लड क्लॉटिंग' यानी खून के थक्कों के जमने की प्रबल संभावनाएं हैं। जब से चारों तरफ हंगामा मचा हुआ है। उनकी इस स्वीकारोक्ति से संसार भर में दहशत का माहौल है, जिन्होंने कोरोना से बचने के लिए कोरोनाकाल में कोविशील्ड का टीका लगवाया था, वे सब अब बुरी तरह से डरे हुए हैं। लोग चिकित्सकों से परामर्श करने में लगे हुए हैं। हालांकि, तसल्ली इस बात की है कि भारत के लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। भारतीय चिकित्सा तंत्र ने इसे मात्र भ्रम ही बताया है। उन्होंने फिलहाल वैक्सीन को सुरक्षित बताते हुए, भरोसा दिया है कि अगर साइड इफेक्ट देखें भी तो उस पर काबू पाने में हमारा हेल्थ सिस्टम सक्षम है। सरकार की ओर से भी यही बताया गया है, पर लोगों के भीतर बैठ चुका डर निकलने का नाम नहीं ले रहा, इसलिए इसे लेकर तरह तरह की बातें हो रही हैं।

इसे लेकर जब इतना हंगामा मचा हुआ है तो ये जानना भी आवश्यक हो जाता है कि आखिर एस्ट्राजेनेका का मामला कोर्ट तक पहुंचा कैसे? दरअसल, ब्रिटिश नागरिक 'जैमी स्कॉट' ने एस्ट्राजेनेका कंपनी के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दर्ज करवाया था। उन्होंने अप्रैल-2021 में कोविशील्ड के टीके लगवाए थे जिसके बाद वह स्थायी तौर पर मस्तिष्क से क्षतिग्रस्त हो गए। जैमी स्कॉट समेत कई अन्य कई लोग भी थ्रोम्बोसिस नामक दुर्लभ बीमारी से ग्रस्त हो गए। तभी इन सभी ने मिलकर कंपनी के खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज करवा दिया। उसके बाद इस दिग्गज दवा कंपनी ने कोर्ट में वैक्सीन के कारण गंभीर स्वास्थ्य जटिलताएं पैदा होने की बात स्वीकार ली। कोर्ट ने कंपनी को प्रभावित लोगों को 10 करोड़ पाउंड हर्जाने देने का आदेश भी दिया है।

इस खुलासे के बाद कोविड-19 की अन्य वैक्सीन जैसे फाइजर, मॉडर्ना भी सवालों के घेरे में हैं। ऐ कंपनियां भारत में उस वक्त खूब एक्टिव थी। इन्हें भी अपने टीकों के संबंध में अब जवाब देना होगा, क्योंकि मसला वैश्विक स्तर पर जो गर्मा चुका है।

गौरतलब है कि, जब कोरोना दुनियाभर में कहर बरपा रहा था, पूरी दुनिया इसके चपेट में थी। तब, कोविशील्ड को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा ईजाद किया गया। वैसे भी कम ही लोग जानते होंगे कि वैक्सीन को कोविशील्ड नाम भारत ने ही दिया था। एस्ट्राजेनेका वैक्स जोब्रिया टीके का निर्माण भारतीय फार्मा कंपनी 'सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया' यानी एसआईआई ने भी अपने स्तर से किया था। टीका बनने के बाद बाकायदा उसका ट्रायल हुआ था। सबसे पहले चूहों पर प्रयोग किया गया। उसके बाद एकाध गंभीर मरीजों को टीके चढ़ाए गए, जिसका रिजल्ट बेहतरीन पाया गया। फिर, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की स्वीकृति मिली, उसके बाद भारतीय वैज्ञानिकों और चिकित्सकों के संयुक्त पैनल की देखरेख में मुकम्मल जांच पड़ताल की गई, उसके बाद कहीं जाकर टीकों को मरीजों में लगवाना आरंभ हुआ।

हां, इतना जरूर है कोविशील्ड को ब्रिटिश में आनन-फानन में नियमों के विरुद्ध जल्दबाजी में बिना ट्रायल के लोगों को टीका देना शुरू कर दिया गया था। ये बात वहां की हुकूमत ने भी अदालत में स्वीकारी है, इसलिए एस्ट्राजेनेका का ये कहना सच साबित होता है कि वैक्सीन बहुत दुर्लभ मामलों में टीटीएस का कारण बन सकती है। चिकित्सकों के मुताबिक इसे लंबे ट्रायल की आवश्यकता थी। जो उस वक्त नहीं किया गया। इसकी जवाबदेही फार्मा कंपनी की ही बनती है। जब उन्हें ये पता था कि इसके दुष्परिणाम भविष्य में अच्छे नहीं होंगे? तो क्यों लोगों के जीवन से खिलवाड़ करने की इजाजत उन्होंने दी। कई ऐसे अहम सवाल हैं जिनके जवाब बिंदुवार तरीके से अब एस्ट्राजेनेका कंपनी को ही देने होंगे। ऐसे में भारतीय चिकित्सकों को चाहिए कि अगर इस टीके से साइड इफेक्ट की उन्हें जरा भी संभावनाएं नजर आती हैं तो उसका तोड़ बिना देर किए अभी से खोजने शुरू कर देने चाहिए, ताकि मानव समाज के जीवन को सुरक्षित बनाया जा सके।

कोरोना से जब संसार तकरीबन-तकरीबन हार चुका था। सभी को अपने जीवन को बचाने के लिए जूझना पड़ रहा था। तब, एस्ट्राज़ेनेका ने वैश्विक साझेदारों के साथ वैश्विक स्तर पर वैक्सीन की तीन बिलियन खुराक बनाई। सरकारों ने उन्हें बाकायदा लक्ष्य दिया हुआ था। जल्दबाजियां हुई थी, जिसे स्वीकारा जा चुका है। उन्हीं की भांति भारत में भी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ़ इंडिया ने कोविशील्ड टीके का उत्पादन युद्ध स्तर पर किया था और उन्हें भारत सरकार को सौप दिया। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए एस्ट्राजेनेका ने ऑक्सफोर्ड के साथ मिलकर कोविड वैक्सीन बनाई थी। वहीं, भारत में वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टिट्यूट ने एस्ट्राजेनेका के साथ समझौता करके कोविशील्ड वैक्सीन बनाई। इसके बाद देश में आधे से अधिक लोगों को कोविशील्ड वैक्सीन लगाई गई। कुछ अन्य कंपनियों की वैक्सीन को भी लोगों ने लगवाया था, लेकिन असर सबका एक जैसा ही दिखाई पड़ता है। हालांकि भारत के वैज्ञानिक और चिकित्सक इस मत में कतई नहीं हैं कि अचानक होती मौतों का संबंध कोरोना के टीकों से है, पर ब्रिटिश कोर्ट के मामले ने विशेषज्ञों को नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया है। भारतीय चिकित्सक भी इसकी खोज में लग गए हैं। यहां जिम्मेदारी अब हुकूमत की बनती है कि लोगों के मन में कोविशील्ड को लेकर पनप चुके डर को कैसे भी दूर करे?

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं बाल अधिकार कार्यकर्ता हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

लेख पर अपनी प्रतिक्रिया **edit@haribhoomi.com** पर दे सकते हैं।

विश्लेषण
आर.के. सिन्हा

भारत से कारोबारी संबंधों की बहाली क्यों चाहता है पाक

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ने अपने देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति पर विचार करने के लिए बीती 26 अप्रैल को अपने मुल्क के उद्योगपतियों से कराची में मुलाकात की। इस दौरान पाकिस्तान के चोटी के उद्योगपति और आरिफ़ हबीब ग्रुप के चेयरमेन आरिफ हबीब ने शाहबाज शरीफ से पुरजोर गुजारिश की कि पाकिस्तान भारत के साथ अपने व्यापारिक संबंध तुरंत बहाल करे। पाकिस्तान के अखबार द डॉन ने 25 अप्रैल, 2024 को इस खबर को प्रमुखता के साथ छापा भी है। उस वक्त वहां पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और देश के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के समधी इशाक डार भी मौजूद थे। डार ने पिछले महीने ही कहा था कि उनका मुल्क भारत से व्यापारिक संबंध बहाल करना चाहता है। उधर, भारत का मानना है कि व्यापार को द्विपक्षीय संबंधों के सामान्यीकरण के एक हिस्से के रूप में देखा जाना चाहिए। इसके लिए, पाकिस्तान को आतंकवाद पर लगाम लगानी होगी। भारत का यह भी मानना है कि आतंकवाद के मुद्दे पर ठोस कदम उठाए बिना व्यापार शुरू करना संभव नहीं है। दरअसल पाकिस्तान के नेताओं की भारत के साथ व्यापार शुरू करने की इच्छा कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था गंभीर संकट से जूझ रही है। यह सब जानते हैं। भारत के साथ व्यापार, विशेष रूप से चीनी और कपास जैसे उत्पादों का आयात बंद होना, पाकिस्तान के लिए महंगा पड़ रहा है, क्योंकि उसे ये उत्पाद दुबई जैसे देशों से मंगवाने पड़ते हैं। पाकिस्तान के व्यापारिक समुदाय का मानना है कि भारत के साथ सीधा व्यापार आर्थिक विकास को गति दे सकता है।

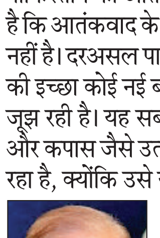

अफ़ग़ानिस्तान और ईरान के साथ तनावपूर्ण संबंधों ने भी पाकिस्तान की आर्थिक समस्याओं को और बढ़ा दिया है। यह भी देखना होगा कि ईरान के नेता की हालिया इस्लामाबाद यात्रा से दोनों देश कितने करीब आते हैं। भारत और पाक के बीच व्यापार दोनों देशों के सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। व्यापार, राजनीतिक मुद्दों पर व्यापक और सार्थक चर्चा के लिए भी एक प्रारंभिक कदम हो सकता है। हालांकि दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों में जल्द सुधार की संभावना भी नहीं है, क्योंकि अभी तो भारत में लोकसभा चुनाव का दौर चल रहा है। इस बीच, भारत को पाकिस्तान के साथ व्यापारिक संबंधों की बहाली करने से कोई बहुत लाभ नहीं होगा। अगर दोनों पड़ोसियों में व्यापारिक संबंध स्थापित होते हैं, तो इससे पाकिस्तान को ही बड़ा लाभ होगा। भारत की चिंता वाजिब है। भारत सरहद पार से होने वाले आतंकवाद का भुक्तभोगी रहा है, इसलिए वह कोई भी कदम बहुत सोच-समझकर ही उठाएगा। अब पाक लाख चाहे पर, पर भारत उससे व्यापारिक संबंधों को लेकर कतई उत्साहित नहीं है। पाक ने ही भारत के साथ अपने आर्थिक संबंधों को खत्म कर लिया था जब नरेंद्र मोदी सरकार ने 2019 में जम्मू-कश्मीर से धारा 370 को खत्म किया था। तब से पाक के कुछ नेता कहते रहते हैं कि जब तक धारा 370 की बहाली नहीं होगी तब तक वह भारत से संबंध बहाल नहीं करेगा। पिछले दिनों पाकिस्तान में शाहबाज शरीफ की प्रधानमंत्री के रूप में ताजपोशी के बाद यह तय ही था कि वहां भारत से व्यापारिक संबंध शुरू करने की पहल चालू होगी। खराब आर्थिक नीतियों और सेना के भारी बजट के कारण पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था तार- तार हो चुकी है। वह विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ), सऊदी अरब, चीन वगैरह के आगे मदद की आस में रहता है। विश्व बैंक ने 2018 में अनुमान लगाया था कि अगर पाकिस्तान का भारत के साथ व्यापार अपनी क्षमता तक पहुंच जाता है तो उसका निर्यात लगभग 25 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है। पाकिस्तान में पूर्व भारतीय उच्चायुक्त और प्रसिद्ध पुस्तक 'एंगर मैनेजमेंटः द ट्रबल्ड डिप्लोमैटिक रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान' के लेखक अजय बिसारिया कहते हैंः 'अगर भारत-पाकिस्तान में तिजारती संबंध शुरू होते हैं तो पाकिस्तान के कपड़ा और फार्मास्युटिकल क्षेत्रों को तगड़ा लाभ होगा।' सोशल मीडिया के इस दौर में पाकिस्तानी अवाम पड़ोसी भारत के विकास की रफ्तार को बारीकी से देख रहा है। शरीफ जानते हैं कि अब दुनिया युद्ध के रास्ते पर नहीं चल सकती है, क्योंकि; युद्ध विनाश का पर्यायवाची है। पाकिस्तान की भारत के साथ तिजारत की चाहत पूरी हो सकती है, अगर वह आतंकियों की गोद से मुक्त होकर भारत की चिंताओं का समाधान करे।

(लेखक पूर्व भाजपा सांसद हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

ईश्वर की प्राप्ति

संकलित
दर्शन

जड़ जगत की रचना के लिए ईश्वर की जो शक्ति काम करती है, उसे प्रकृति कहते हैं और चैतन्य जगत की रचना करने वाली शक्ति को जीव कहते हैं। जिस प्रकार दोनों हाथ एक ही शरीर के दो भाग हैं, उसी प्रकार जीव और प्रकृति दोनों ही ईश्वरतत्व के दो अंश हैं। अध्यात्म तत्व के जिज्ञासु जिस ईश्वर की उपासना करते हैं, असल में वह अखिल आद्यशक्ति का सतोगुणी अंश है। मानवीय उन्नति तो सत्व गुणों को प्राप्त करने से ही हो सकती है। इसलिए उन उच्च गुणों की एक मानसिक प्रतिमा बनाकर उपासना करने का विधान किया गया है। ईश्वर का सत्व गुण अदृश्य रूप से हमारे निकट ही वर्तमान है। उसे अधिक मात्र में खींचकर अपने अंदर भर लेने के लिए प्रेम, श्रद्धा, विश्वास और ध्यान अभ्यास की आवश्यकता होती है। इन्हीं चारों के समन्वय को 'उपासना' कहा जाता है। उपासना जितनी ही प्रबल होगी, आकर्षण भी वैसा ही सशक्त होगा और उसी के अनुसार उपास्य देवतत्व की प्राप्ति होगी। प्रेम, दया, करुणा, सहानुभूति, उदारता, त्याग, समता और न्याय आदि सद्गुणों का निष्ठापूर्वक जितना अधिक चिंतन किया जाता है, उतनी अधिक उनकी प्राप्ति होती है। उन्नति का क्रम तम से सत की ओर चलना है। जिसने जितना ही सत्गुण अपने में धारण कर लिया, आध्यात्मिक दृष्टि से वह उतना ही उन्नतिशील कहा जाएगा। यदि एक भक्त सत्तत्व की उपासना करता है तो कोई कारण नहीं कि उसे वह प्राप्त न हो। ईश्वर की उपासना का तात्पर्य उसके दिव्य सत तत्व की आराधना है।

योजना बनाकर किए काम में मिलती है सफलता

संकलित
प्रेरणा

रामायण में देवी सीता का हरण हो गया था। श्रीराम और लक्ष्मण सीता को खोज रहे थे। राम-लक्ष्मण उस जंगल में पहुंच गए, जहां सुग्रीव बाली की डर से छिपे हुए थे। सुग्रीव के साथ ही हनुमान जी भी थे। सुग्रीव ने दो राजकुमारों को देखा तो वे डर गए। सुग्रीव ने सोचा कि बाली ने मुझे मारने के लिए इन्हें यहां भेजा है। सुग्रीव ने हनुमान जी से कहा कि आप देखिए वहां दो राजकुमार दिख रहे हैं, वहां जाकर मालूम करो कि कहीं ये हमारे शत्रु तो नहीं हैं। अगर वे शत्रु हैं तो वहीं से इशारा कर देना, हम यहां से कहीं और भाग जाएंगे। अगर वे मित्र हैं तो वहीं से इशारा करना, हम यहीं रुक जाएंगे। हनुमान जी सुग्रीव की आज्ञा पाते ही उन दोनों राजकुमारों के सामने पहुंच गए। हनुमान जी वेष बदलकर गए थे। हनुमान जी ने बुद्धिमानी का उपयोग करते हुए अपना सही परिचय बताए बिना राम-लक्ष्मण की परख की। जब हनुमान जी को मालूम हुआ कि ये राम-लक्ष्मण हैं तो वे अपने असली रूप में आ गए और सुग्रीव को इशारा कर दिया कि ये हमारे शत्रु नहीं हैं। हनुमान जी ने राम-लक्ष्मण से कहा कि आप मेरे राजा सुग्रीव के पास चलिए और उनसे मित्रता कर लीजिए। हनुमान जी राम-लक्ष्मण को लेकर सुग्रीव के पास पहुंचे और इनकी मित्रता कराई। हनुमान जी समझ गए थे कि इन दोनों की समस्याएं एक-दूसरे की मदद से हल हो सकती हैं। इस मित्रता के बाद श्रीराम ने बाली वध किया और सुग्रीव को राजा बना दिया। इसके बाद सुग्रीव ने अपनी पूरी वानर सेना सीता की खोज में लगा दी।

अंतर्मन

आज की पाती

मजदूरों को सेवानिवृत्ति के बाद मिले पेंशन

एक मई को हर साल मजदूर दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर कई प्रोग्राम होते हैं, लेकिन मजदूरों की वास्तविक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है। कारण यह है कि उन्हें मेहनत के अनुसार पगार नहीं मिलती है। इसलिए मजदूरों को उनके बुढ़ापे में सरकार की ओर से प्रति माह 15,000 हजार रुपए की पेंशन दी जानी चाहिए। इससे सरकारी कोष पर कुछ बोझ जरूर पड़ेगा, लेकिन जब कुछ राज्यों में सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस दी जा सकती है, तो मजदूरों के कल्याण के लिए सरकारों को यह बोझ भी वहन कर लेना चाहिए। इससे मजदूरों को बुढ़ापे की जो चिंता होती है, वह खत्म हो जाएगी और उनके चेहरों पर मुस्कान फैलेगी। ऐसी स्थिति में मजदूर अपने बच्चों की मनचाही पढ़ाई करवा सकेंगे। – *सचिन पाठक, महासमुंद*

करंट अफेयर

कोलंबिया के सैन्य अड्डे से 37 मिसाइलें चोरी हुई

कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने कहा कि देश के दो सैन्य अड्डों से हजारों गोलों (ग्रेनेड) और गोलियों की चोरी हुई है। पेट्रो ने एक संक्षिप्त बयान में कहा कि सेना ने इस माह निरीक्षण किया और पाया कि हजारों गोलियां, हजारों गोले और तोप रोधी 37 मिसाइलें सैन्य अड्डों से चुराई गई हैं। इन सैन्य अड्डों में से एक देश के मध्य भाग में जबकि दूसरा कैरेबियाई तट के निकट स्थित है। राष्ट्रपति ने कहा कि हो सकता है कि ये गोला-बारूद कोलंबियाई विद्रोही संगठनों के हाथ लगे हों या उन्हें अन्य देशों में आपराधिक समूहों को अवैध रूप से बेच दिया गया हो जिनमें हैती के विद्रोही भी शामिल हैं। उन्होंने कहा, 'जो सामान गायब है उसके संबंध में यही कहा जा सकता है कि सशस्त्र बलों में भी ऐसे लोगों के नेटवर्क हैं जो हथियारों की अवैध खरीद-फरोख्त में शामिल हैं।' राष्ट्रपति ने कहा कि सशस्त्र बलों को किसी भी आपराधिक संगठन से दूर रखने के लिए सैन्य अड्डों का निरीक्षण जारी रहेगा। सैन्य अडडों की जांच ऐसे वक्त हुई है जब कोलंबिया ने देश के दक्षिण-पश्चिम में विद्रोही संगठन 'एफएआरसी-ईएमसी' के खिलाफ लड़ाई फिर से शुरू की है।

ऑफ बीट

क्या न्यूज़ीलैंड का स्कूल फोन प्रतिबंध काम करेगा?

गठबंधन सरकार द्वारा न्यूजीलैंड के स्कूलों में इस सप्ताह छात्रों के मोबाइल फोन इस्तेमाल पर प्रतिबंध की प्रतिक्रिया सामने आई है और यह शंकालु से लेकर आशावादी तक हो सकती है। ऐसी दुनिया में जहां लगभग हर किसी के पास स्मार्टफोन है, यह उम्मीद की जाती है कि इस बारे में लगभग हर किसी की एक राय होगी। होना यह चाहिए कि जल्दबाजी में कोई भी फैसला करने से पहले सही गलत का अंतर समझ लिया जाए। दरअसल, जिन स्कूलों ने समय सीमा से पहले प्रतिबंध लागू किया, उन्होंने बच्चों के ध्यान और सीखने में सकारात्मक बदलाव की सूचना दी है। क्राइस्टचर्च में हॉर्नबी हाई स्कूल की हेड गर्ल ने कहा कि मैदान अब अंतराल और लंच के दौरान शोरगुल से भरा होता है। स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा, 'काश हमने फोन पर प्रतिबंध पांच साल पहले लगाया होता।' दूसरी ओर, स्कूलों में फोन पर प्रतिबंध लगाने के पक्ष में मिले सबूत 'कमजोर और अनिर्णायक' पाए गए हैं। हालांकि इस नीति का उद्देश्य एक 'सकारात्मक वातावरण बनाना है जहां युवा न्यूजीलैंडवासी उस चीज़ पर ध्यान केंद्रित कर सकें जो सबसे महत्वपूर्ण है'।

ट्रेंड

युवतियों के लिए क्या किया

ओडिशा में 5 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद बी. गंजम जिले के एंटदिशाल और हिन्जिली उनका मुख्य मुख्यालय बने। मुख्यमंत्री ने हिंजिली के लिए याचिका दायर की। इस पर एक श्वेत पत्र प्रकाशित लाना चाहिए कि उनके 24 वर्षों के शासन के दौरान हिंजिली की युवतियों के रोजगार के लिए क्या किया।
-धर्मेन्द्र प्रधान, केंद्रीय मंत्री

कब्रों की रिपोर्टों से चिंतित

गाजा में सामूहिक कब्रों की रिपोर्टों से चिंतित हूं। स्वतंत्र जांचकर्ताओं को पहुंच की अनुमति दी जानी चाहिए। मृतकों के परिवारों को यह जानने का अधिकार है कि क्या हुआ। दुनिया को अंतरराष्ट्रीय कानून के उल्लंघन के लिए जवाबदेही का अधिकार है।
-एंटोनियो गुतरेस, यूएन महासचिव

मोदी ने चुप्पी साध ली

कर्नाटक में महिलाओं के साथ हुए वीभत्स अपराध पर भी नरेंद्र मोदी ने चुप्पी साध ली है। प्रधानमंत्री को जवाब देना होगा- सिर्फ वोटों के लिए उन्होंने सैकड़ों बेटियों का शोषण करने वाले हैवान का प्रचार क्यों किया?आखिर इतना बड़ा अपराधी देश से फरार कैसे हो गया?
-राहुल गांधी, कांग्रेस नेता

जीवन को मुस्कुराहट से गिनें

अपने बगीचे को फूलों से गिनें, कभी पत्तों के गिरने से नहीं; अपने दिनों को सुनहरे घंटों से गिनें, बादलों को बिल्कुल याद मत करो! रात को तारों से गिनें, परछाइयों से नहीं अपने जीवन को मुस्कुराहट से गिनें-आंसुओं से नहीं।
-आनंद महिंद्रा, उद्योगपति

अपने विचार

हरिभूमि कार्यालय
टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-4242222, 23 पर या सीधे मेल से **hbcgpati@gmail.com** पर भेज सकते हैं।

https://t.me/AllNewsPaperPaid